

आधुनिक सहकारिता

—सहकारिता और उसके आधार पर राष्ट्र की नव-रचना—

विद्यासागर शर्मा



१९६०

सस्ता साहित्य मण्डल-प्रकाशन

प्रकाशक
मार्तण्ड उपाध्याय,
मन्त्री, सस्ता साहित्य मंडल,
नई दिल्ली

पहली बार १९६०
मूल्य
दो रुपये

मुद्रक
बालकृष्ण, एम० ए०,
युगान्तर प्रेस,
डफरिन पुल, दिल्ली

प्रकाशकीय

सहकारिता के महत्व एवं उपयोगिता के विषय में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। सब जानते हैं कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है और बिना पारस्परिक सहयोग के न उसका जीवन चल सकना संभव है, न समाज का अस्तित्व ही रह सकता है। समाज का उद्देश्य कुछ भी हो, उसकी पूर्ति मनुष्यों के सामूहिक प्रयत्न से ही हो सकती है।

सहकारिता का विधिवत् प्रयास ससार के अनेक देशों में हो रहा है। कहीं-कहीं तो उसका आंदोलन प्रौढावस्था को प्राप्त हो गया है। हमारे देश में भी उसका श्रीगणेश हो चुका है और उसकी जड़ें चारों ओर फैलती जा रही हैं।

प्रस्तुत पुस्तक के लेखक ने इस विषय का बड़ी वारीकी से अध्ययन और चिन्तन किया है। उनकी दो पुस्तकें 'भारतीय सहकारिता का इतिहास' और 'सहकारिता का उदय और विकास', जो 'मण्डल' से प्रकाशित हुई हैं, पाठकों को बड़ी लाभदायक सिद्ध हुई हैं।

हमें विश्वास है कि उस माला की इस अंतिम पुस्तक से सहकारिता के वर्तमान रूप और प्रयोग को समझने में बहुत सहायता मिलेगी। हिन्दी में इस प्रकार के साहित्य का बड़ा अभाव है। लेखक ने उस दिशा में निस्संदेह अच्छी सेवा की है।

हम आशा करते हैं कि इस पुस्तक का सर्वत्र स्वागत होगा।

—मंत्री

दो शब्द

हमारे देश में सहकारिता-सवधी साहित्य बहुत कम है। जो है, उसमें भी अधिकांश अंग्रेजी में है। भारत के कोटि-कोटि निवासियों के जीवन से इस विषय का घनिष्ठ सवध होने के कारण आवश्यक है कि हिन्दी में ऐसे साहित्य का अधिकाधिक सृजन हो।

हमने अपने सविधान में भारत को समाजवादी सहकारी सघीय राज्य घोषित किया है। आरवडी के कांग्रेस-अधिवेशन में उसके सिद्धान्त इस प्रकार निश्चित किये गए हैं —

“भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य भारतवासियों की भलाई और उन्नति करना तथा भारत में शान्तिमय एव वैध उपायों से ऐसे समाजवादी सघीय सहकारी स्वराज की स्थापना करना है, जिसका आधार सवके लिए समान अवसर और समान राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक अधिकार हो और जिसका लक्ष्य विश्व-शान्ति एव विश्व-बन्धुत्व की स्थापना करना हो।

समाजवादी तथा साम्यवादी भी सहकारिता की ओर झुक रहे हैं। आचार्य विनोबा ने तो शासन-निरपेक्ष समाज के चरम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सहकारिता को आवश्यक अंग माना है। सहयोग साम्ययोग की प्रथमावस्था है। ऐसी अवस्था में सहयोग तथा सहकारिता के मूल स्वरूप तथा उसके प्रयोग को समझना, उस पर विचार करना और उन विचारों का प्रचार करना वाछनीय है। प्रस्तुत पुस्तक उसी दिशा का एक विनम्र प्रयास है।

‘सहकारिता का उदय और विकास’ तथा ‘भारतीय सहकारिता का इतिहास’ लिखने के बाद जब मैं इस क्रम की अन्तिम पुस्तक लिखने लगा तो उसमें विशेष कठिनाई मालूम हुई। सहकारिता नए युग में प्रवेश कर रही थी और उसकी धारणाएँ नित्य-प्रति विकसित हो रही थी। इसके अतिरिक्त सहकारिता-सवधी जो साहित्य उपलब्ध था, उसकी मूल प्रेरणा विदेशों से ली गई थी।

इस पुस्तक में सहकारिता के विवरणात्मक भाग के लिखने में अधिक कठिनाई नहीं हुई, परन्तु देश की परिस्थितियों तथा परम्पराओं के अनुकूल किस

प्रकार विभिन्न क्षेत्रों में सहकारी रूप में कार्य हो, यह बताना बड़ी मुश्किल काम था। इसमें मुझे अपने इस क्षेत्र के अनुभवों, अपने मित्रों, देशी-विदेशी लेखकों, भारत सरकार की नीतियों, रिजर्व बैंक की रिपोर्टों आदि से बहुत सहायता मिली है। किसानों के साथ विचार-विनिमय से भी बड़ी लाभप्रद सामग्री प्राप्त हुई। इन सब स्रोतों का मैं आभारी हूँ। श्री खेमौराम (असिस्टेंट रजिस्ट्रार, सहकारी विभाग एजुकेशन, हिमाचल प्रदेश) का तो बहुत ही ऋणी हूँ, जिनके साथ अनेक विषयों पर मैं विचार-विमर्श कर सका। इसमें सन्देह नहीं कि कई बातों में मेरा उनसे अभी तक मतभेद है, परन्तु विचारों के स्पष्टीकरण तथा परिमार्जन में उनकी सहायता अमूल्य रही।

सहकारिता की परिभाषा, इसके प्रयोग, आन्दोलन, विभागीय संगठन तथा विभाग एवं आन्दोलन के पारस्परिक सम्बन्धों के बारे में कुछ नये-नये दृष्टिकोणों को अपनाया गया है। इन सुझावों पर श्री चेस्टर, सी० डेविस, श्री डार्लिंग, तथा आचार्य विनोबा के विचारों की गहरी छाप है। अतः इन महानुभावों का भी मैं हृदय से आभारी हूँ।

—विद्यासागर शर्मा

विषय-सूची

- १ सहकारिता की परिभाषा
२. सहकारी समिति
- ३ सहकारिता और ऋण
- ४ सहकारिता और कृषि
- ५ सहकारिता और उद्योग
- ६ सहकारी-भण्डार
७. सहकारिता और व्यापार
८. सहकारी अधिकोषण या बैंकिंग
- ९ बहुदेशीय-सहकारिता
१०. सहकारिता और सामाजिक विकास
- ११ सहकारी-संगठन
- १२ सहकारी-विभाग
- १३ सहकारिता और पंचायत
- १४ उपसंहार



आधुनिक सहकारिता .

आधुनिक सहकारिता

: १ :

सहकारिता की परिभाषा

यह तो सर्व विदित ही है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसमें सृष्टि के प्रारम्भ से समाज तथा दोस्तों के संसर्ग में रहने की एक भूख विद्यमान रही है। यही भूख विभिन्न प्रकार के संगठनों में प्रकट होती रही। इसी भूख के प्रभावाधीन परिवार की सृष्टि हुई, वर्ग तथा जातियाँ बनी, राष्ट्रों का निर्माण हुआ; सेनाएँ संगठित हुई, युद्ध हुए, कई प्रकार के सामाजिक व आर्थिक ढाँचे बने। और जहाँ यह भूख मानव-समाज को एकत्र होने की प्रेरणा देती रही वहाँ इसी भूख ने संगठित हुए समूहों अथवा राष्ट्रों को आपस में लड़ाया। एक शक्ति-सम्पन्न समूह ने दूसरे निर्बल समूह को अपने अधीन करके उसे दुखी और त्रस्त कर उसका शोषण किया। ऐसी ही बातें राष्ट्रों के संघर्ष में हैं। आर्थिक जगत में भी वर्गों तथा समूहों की रचना हुई। शोषक तथा शोषित वर्गों का एक ऐसा चक्र चला कि सारा संसार एक भयंकर षड्यंत्र का अंग-सा दीखने लगा और मजदूर मानव सहसा काप-सा उठा।

ऐसी ही भयावह परिस्थितियों से मानव को बचाने के लिए ही भारत के ऋषियों ने काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष की पद्धति का निर्माण किया। धर्म का एक ऐसा अनुशासन बना दिया था जहाँ मानव को प्रथम मानव समझा जाता था और इस ही एक आधार पर समाज के समस्त संगठनों का निर्माण होता था।

इस अनुशासन ने भारत में समाज को राजा की क्रूरता तथा धनवानों के अत्याचार से बचाने की पर्याप्त सफलतापूर्वक चेष्टा की। परन्तु शनैः-शनैः धर्म

का यह अक्रुश धन तथा राजबल के आगे क्षीण होता गया और जहा राजनीतिक शोषण के विरुद्ध विभिन्न विचारधाराओं का प्रादुर्भाव हुआ वहा आर्थिक जगत में भी साम्य तथा समाजवाद की पद्धतियां चली। परन्तु यह विचारधाराएं राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति के बिना अपनी सफलता में विश्वास नहीं करती थी। और यह श्रेय उन कतिपय मौलिक कार्यकर्ताओं को ही रहा जिन्होंने कम तथा सीमित आय वाले लोगों को आवश्यकता की शक्ति के अधीन स्वावलम्बन के मूलभूत सिद्धान्त पर संगठित किया। क्योंकि यहा मजदूर तथा निर्वल लोग आपस में मिल-जुलकर कार्य करते थे, अतः इसका नाम 'सहकार' पड़ गया। इसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अधीन सहकार की परिभाषा का भी निर्माण हुआ और वह भी समय की गति के अनुसार परिवर्तित होता रहा। सहकारिता की परिभाषा लेखकों, राजनीतिज्ञों तथा विधान बनाने वालों ने की। इन्हीं परिभाषाओं के संक्षिप्त विवरण का उल्लेख इस परिच्छेद का आशय है।

श्री होली ओक सहकारिता की व्याख्या करते हुए लिखते हैं

“यह एक ऐच्छिक संगठन किसी भी कार्य या व्यवसाय करने के लिए है जिसमें सम्बन्धित व्यक्ति न्यायपरता से भाग लेते हैं और उन पर न्यायसंगत नियंत्रण रहता है।”

यूरोप में सहकारिता का जन्म उस युग में हुआ जब कि वहा धन से ही सब मूल्य आके जाते थे। मानव का समस्त जीवन वस्तुतः धन की कृपा पर निर्भर था। इसीलिए उस काल की सहकारिता की परिभाषाओं में निर्धनता से दबे हुए असहाय मानवों की आर्त पुकार सुनाई पड़ती है। सहकारिता के गहन विचारक तथा सुप्रसिद्ध लेखक श्री सी आर फे “सहकारिता” की परिभाषा करते हुए लिखते हैं

“दान तथा सहकारिता का पारस्परिक सम्बन्ध ऐसा ही है जैसे कि इलाज का पथ्य अथवा बचाव का विधि के साथ। इसका ध्येय है निर्वलों को ऊपर उठाना। सहकारिता का सम्बन्ध व्यापार से न होकर व्यापार-विधि से होता है और इसी कारण इसका क्षेत्र इतना विस्तृत हो जाता है जितना कि जीवन-व्यापार का।”

आगे चलकर यही महोदय लिखते हैं

“सहकारिता में व्यापार के सब अंग शामिल हैं। यह एक ऐसी

सहकारिता की परिभाषा

व्यापारिक सस्था है जिसका जन्म निर्बलो मे होता है, जहा सब कुछ निस्वार्थ भावना से किया जाता है, और जहा लाभ उक्त सगठन के अनुपात से बटता है ।”

सहकारिता की शोधित परिभाषा करते हुए यही महोदय लिखते है :

“सहकारी सभा आर्थिक तौर पर निर्बलो का साँभे व्यापार हेतु निस्वार्थ भाव से कार्य करने वाला सगठन है जिसमे सब सदस्य काम की जिम्मेदारी सभालते है ।”

फिनलैण्ड की सहकारिता की व्याख्या करते हुए एक लेखक ने यो लिखा है

“सहकारी सस्था व्यक्तियों का एक ऐसा सगठन है जहा सब समता की भावना से सम्मिलित होते है । जहा सदस्य-सख्या पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होता । जिसका उद्देश्य यह होता है कि मिलकर सदस्यों की आर्थिक स्थिति सुधारी जाए और पारस्परिक सहायता तथा स्वावलम्बन के सिद्धांतो पर काम करे । जहा लाभ व्यवसाय मे कार्य-भाग लेने के अनुपात से वितरित होता है, न कि लगाई गई धनराशि के अनुपात पर ।”

श्री हैरिक्क ने इसी विचार को और भी पुष्ट किया है

“सहकारिता स्वेच्छा से सगठित हुए व्यक्तियों का अपनी शक्तियों तथा अपने साधनों को एक दूसरे के हित के हेतु प्रयोग मे लाने का कार्य है ।”

सर हौरेस प्लकिट ने सहकारिता की परिभाषा यो की है .

“सहकारिता सगठन द्वारा स्वावलम्बन को प्रभावपूर्ण बनाने की विधि है ।”

ग्राम विकास पर लिखते हुए आईसलैण्ड के एक लेखक ने लिखा है

“सहकारी सस्था की परिभाषा मे कहा जा सकता है कि यह व्यक्तियों का स्वेच्छापूर्वक सगठन है, जो कि अपने आर्थिक तथा सामाजिक विकास हेतु मिलकर धन प्राप्ति के साधनों का साँभे स्वामित्व तथा लोक-तंत्री पद्धति के अधीन प्रबन्ध करते है ।”

सर्व श्री एच एच वेक्कन तथा एम ए. शार अपनी पुस्तक मे लिखते है —

“आर्थिक पद्धति के फलस्वरूप ही सहकारी सगठन का प्रादुर्भाव

हुआ है। यह योजना सम्पन्न आर्थिक तथा खुले व्यापार के वाछित गुणों का सम्मिश्रण है। इसमें इन पुरानी दोनों पद्धतियों के अवाछनीय दुर्गुणों का यथासम्भव निराकरण किया गया है। सहकारिता लोकतंत्र की भित्ति को विस्तृत करती है। उसे अर्थ तथा समाज के क्षेत्रों में प्रयुक्त करके उन सबको, जिनमें मनुष्यों के कार्यों को पारस्परिक सम्बन्ध पर आयोजित करने की क्षमता है, लाभ पहुंचाती है।”

कहना नहीं होगा कि पंजाब के भूतपूर्व सहकारी विभाग के रजिस्ट्रार श्री कैलवर्ट महोदय सहकारिता के क्षेत्र में विश्व-विख्यात व्यक्ति हैं। उनका कहना है :

“सहकारिता एक प्रकार का संगठन है जहां व्यक्ति स्वेच्छा से मानवता के आधार पर बराबरी के नाते से अपने आर्थिक हितों के विकास हेतु शामिल होते हैं।”

श्री एम माथुर ने इन सब परिभाषाओं का निष्कर्ष निकालते हुए अपनी परिभाषा यों की है :

“सहकारिता, पारस्परिक सहायता द्वारा स्वावलम्बन के ध्येय की उपलब्धि हेतु किया गया एक जनतंत्री संगठन है, जिसमें सम्मिलित व्यक्ति अपने साम्प्रदायिक हितों का संरक्षण तथा संवर्धन कर सकते हैं।”

उपरिलिखित विशेषज्ञों द्वारा की गई सहकारिता की परिभाषाओं के उद्धरणों पर ही सतोष करते हुए इसी विषय पर सहकारी अधिनियमों आदि का एक विहंगम अवलोकन भी लाभप्रद ही रहेगा क्योंकि समय के साथ जो परिवर्तन सहकारिता की धारणा में होते रहे हैं, उनकी छाप इन विधानों तथा अधिनियमों में दी गई परिभाषाओं में प्रत्यक्ष दिखाई देती है। सन् १९२१ के जापान के सहकारी विधान में सहकारी समिति की परिभाषा यों की गई है :

“सहकारी समिति एक संगठन है, जिसका वैध अस्तित्व है और जिसमें सीमित साधनों वाले व्यक्ति इसलिए शामिल होते हैं कि वे सामूहिकता के सिद्धान्तों पर काम करके अपने आर्थिक स्तर को विकसित तथा उन्नत कर सकें।”

सन् १९११ के ब्रिटिश-कोलम्बिया कृषि सघ के अधिनियम में लिखा है

“वह संगठन सहकारिता के सिद्धान्तों पर निर्मित समझा जायगा जिसके नियन्त्रण-पत्र तथा उपविधियों में सदस्य उत्पादकों को लाभ में

से उस उत्पादन को जो सगठन को दिया गया हो, के अनुपात पर भागीदार रखा गया हो तथा जहाँ भागो की पजी पर ६ प्रतिशत से अधिक लाभ न बाट जाता हो।”

आस्ट्रिया के विधान में इसी सगठन की व्याख्या यों की है •

“सहकारी समिति एक ऐसा सगठन है जिसमें सदस्यों की सख्या पर कोई प्रतिबन्ध न हो और जिसका ध्येय ऋण द्वारा उद्योग तथा व्यापार को विकसित करना हो।”

रूमानिया के विधान में लिखा है •

“सहकारी समिति एक ऐसा सगठन है जिसकी पूजी परिवर्तनशील होती है, सदस्य सख्या पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होता और जो जब चाहे इसमें शामिल और जब चाहे पृथक् हो सकता है। इसका ध्येय यह होता है कि सब एक निश्चित योजनानुसार काम करे जिससे सदस्यों का सामाजिक तथा आर्थिक विकास हो।”

स्विटजरलैंड के विधानाधीन सहकारी सभा की व्याख्या इस प्रकार है

“सहकारी समिति अनिश्चित सख्या के सदस्यों का सगठन होता है।

जिसका ध्येय यह होता कि सदस्यों का सामूहिक प्रयत्न द्वारा आर्थिक विकास हो।” भारतीय सहकारी विधान की धारा ४ में सहकारी समिति की व्याख्या करते हुए लिखा है

“सहकारी समिति सदस्यों के आर्थिक हितों के संरक्षण तथा विकास हेतु बनाई जाती है और वह सहकारिता के सिद्धान्तों पर कार्य करती है।” समय की प्रगतियों के साथ भारत में भी इस परिभाषा में विकास होता रहा है और भिन्न-भिन्न राज्यों ने इस परिभाषा में कुछ परिवर्तन किये हैं। यह परिभाषा हर अधिनियम की भूमिका में मिलती है। भारतीय सरकारी अधिनियम १९१२ की भूमिका में लिखा है •

“कृषको, कलाकारों, श्रमिकों तथा सीमित आय वाले लोगों में वचत तथा स्वावलम्बन के भाव उत्पन्न करने के लिए सहकारी समितियों के सगठन को सुलभ बनाने के लिए यह विधान बनाया जाता है।”

सन् १९२५ के बम्बई के सहकारी अधिनियम में विधान के ध्येय की व्याख्या यों की गई है

कृषको तथा अन्य साझे हितो वाले जनसमूहों में वचत, स्वावलम्बन तथा पारस्परिक सहायता के भाव विकसित व उन्नत करने और उनमें उत्कृष्ट जीवन, श्रेष्ठ व्यापार और उत्पादन के बेहतर उपाय प्रयोग में लाने के लिए सहकारी समितियों के संगठन तथा संचालन हेतु यह अधिनियम बनाया जाता है।”

सन् १९३२ के मदरास के सहकारी अधिनियम की भूमिका में उद्देश्य प्रदर्शित करते हुए लिखा है

“कृषको तथा साझे आवश्यकताओं वाले अन्य व्यक्तियों में वचत, स्वावलम्बन तथा पारस्परिक सहायता के भावों को उन्नत करने, जीवन को अच्छा बनाने, व्यापार को सुचारु रूप प्रदान करने के लिए तथा उत्पादन के श्रेष्ठ उपाय प्रयोग में लाने के लिए सहकारी समितियों को संगठित किया जाय।”

सन् १९४० के बंगाल सहकारी अधिनियम में इसी विषय पर लिखा है

“मध्यम वर्ग के साधनों वाले तथा साझे हितो वाले व्यक्तियों में वचत, स्वावलम्बन तथा पारस्परिक सहायता के भावों को जागृत करके, उनमें उत्कृष्ट जीवन तथा उत्पादन व व्यापार हेतु श्रेष्ठ उपाय प्रयोग में लाए जाय।”

अभी तक सहकारिता कम आमदनी वाले तथा साझे हितो वाले वर्गों तक ही सीमित समझी जाती थी। भारत में तो केवल कृषकों के लिए ही इस की उपयोगिता शुरू-शुरू में समझी गई थी, परन्तु समय के परिवर्तन के साथ सहकारिता का क्षेत्र विस्तृत होता जा रहा है। यहाँ तक कि जो आन्दोलन केवल कम आय वाले व्यक्तियों के लिए ही समझा जाता था, उसमें बम्बई के सुरैया सरीखे धनाढ्य शामिल हुए और आन्दोलन को पर्याप्त शक्ति प्रदान की। ऐसा होना भारतीय परम्परा के अनुकूल ही था, क्योंकि भारत में धनिक को समाज का अमानतदार समझा जाता रहा है। और सहकारिता ने धनिक को एक ऐसा साधन दिया है जिससे कि वह किसी प्रकार की हानि की आशका उठाये बिना अपना धन कम आय वाले तथा आर्थिक तौर पर उत्पीड़ित व्यक्तियों की सहायता तथा उन्नति के लिए प्रयोग में ला सकता है।

आवश्यकता ने सहकारिता के आन्दोलन को जन्म दिया। अतः विभिन्न देशों

व्ययक सोपान है और इसी सम्बन्ध में विनोबा जी की शिष्या विमला वहन ने एक स्थान पर कहा है—

“मनुष्य मात्र समान है। यह भावना आस्तिकता से पैदा होती है। उससे दूसरी अवस्था निष्पन्न होती है जिसे हम ‘सहयोग’ कहते हैं। उसका मूलभूत सिद्धान्त यह है कि जीवन का तत्त्व आपसी सघर्ष नहीं, वरन् सहयोग है। जीवन का विकास विद्वेष से नहीं प्रेम से होता है। यह सहयोग वृत्ति ही वास्तविक जीवननिष्ठा है। विद्वेष और सघर्ष से क्रान्ति नहीं होती, स्थिति में अन्तर पड़ता है। परन्तु वह चिरकाल तक नहीं टिकता। ऐसी क्रान्ति प्रतिक्रान्ति को जन्म देती है और अपने आत्मघात की योजना स्वयं करती है। इसलिए स्नेह और सहयोग की भावना तथा आचार अहिंसात्मक प्रक्रिया की दूसरी अवस्था है।”

पूर्व लिखित पक्षियों में हमने जिस शब्द सहकारिता की परिभाषा पर ऊहापोह की है, उसके शब्दार्थ पर भी थोड़ा विचार करना लाभप्रद ही रहेगा। सहकार शब्द ‘सह’ और ‘कार्य’ दो शब्दों से मिलकर बना है जिसका अर्थ है— मिलकर कार्य करना। अंगरेजी शब्द को-ऑपरेशन का भी लगभग यही अर्थ है। ‘सहयोग’ इसका अधिक पर्यायवाची होगा। इस सहयोग की भावना का उदय होता है स्नेह में, और स्नेह की उत्पत्ति होती है समस्त मानवों की मौलिक समानता की भावना में, जहाँ पर जीवन के लिए “आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्” के सिद्धान्त का प्रयोग स्वाभाविक तथा आवश्यक हो जाता है।

वर्तमान युग में सहकारिता का उदय एक बड़ी सीमित धारणा से हुआ, जैसा कि पूर्व पृष्ठों में दी गई परिभाषाओं से प्रकट है। इसमें सन्देह नहीं कि सहकारिता का उदय इस सत्य का पोषक है कि जब अमानवीय तथा आक्रान्त करने वाली शक्तियों से विवश श्रमिक और किसान को कहीं कोई सहायता तथा आश्रय न मिला तो इस विचारधारा ने ही विवश और त्रस्त मानव समुदाय को आशा की किरण दिखाई।

इस प्रकार एक सीमित वातावरण तथा असाधारण परिस्थितियों में जन्म लेकर सहकारिता की धारणा विकसित होती गई और आज यह समाजवाद, साम्यवाद तथा पूँजीवाद के सघर्ष में मानव समाज को आशा का सन्देश सुनाकर एक सफल मध्यवर्ती मार्ग का स्थान प्राप्त कर चुकी है।

अब वह समय नहीं रहा कि हम पूर्वकाल की सहकारिता की सकीर्ण परिभाषाओं पर सन्तोष करके बैठ जाय । फ्रांस के सुप्रसिद्ध लेखक तथा विचारक रूसो ने अपने ग्रन्थ 'सोशल कांटेक्ट' में सहकार्य के मौलिक विकास का वर्णन करते हुए इसके उपादेय स्वरूप का वर्णन किया है । मानव स्वभाव के इस प्राकृतिक गुण की व्याख्या विभिन्न विचारक तथा लेखक भिन्न-भिन्न नाम देकर भिन्न-भिन्न भाषा में कर चुके हैं । इस विचारशैली की परिभाषा भी इसलिए इतनी ही उदात्त, उदार तथा वैसे ही सर्वांगीण होनी चाहिए जितना व्यापक इसका स्वरूप है । अतः इसकी परिभाषा निम्न शब्दों में ही मुक्त होगी

“सहकार अथवा सहकारिता एक ऐसी पद्धति है जो मानव की मानव के प्रति स्वाभाविक स्नेह की भावना को पुष्ट करके 'सबके बहुत भले' के पावन सिद्धान्त को कार्यान्वित करने की क्षमता रखती है ।”

और यदि हम इसी मूलभूत धारणा का सामने रखें तो हमें 'सहकारी समिति' की परिभाषा का भी परिमार्जन करना पड़ेगा । और यदि आज तक सहकारिता एक आन्दोलन के रूप में वाञ्छित सफलता प्राप्त करने में असमर्थ रही तो इसका कारण केवल यही है कि हमने इस उदात्त तथा उदार भावना को सकीर्ण तथा दलगत विचारों की कैद में बन्द करके इसकी प्रगति को स्वयं कुण्ठित कर दिया । हमने समाज को छोटे-छोटे टुकड़ों तथा वर्गों में बाटने की कुचेष्टा की । खाइयाँ पाटने के स्थान पर हमने उनको और बढ़ाया । वर्गों तथा व्यक्तियों के बीच हमने सहकारिता के नाम पर दीवारे खड़ी कर दी । हमने एक-एक जाति व वर्ग को प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध पृथक्-पृथक् सहकारी समितियों में बाटा । हमने एक वर्ग, जाति, व्यवसाय व ग्राम की सहायता करने से रोका । अब समय की मांग है कि हम सत्य को पहचानें और सकीर्णता से बाहर निकलकर प्रकृति की खुली स्वास्थ्यदायक वायु में विचरे । इन विचारों के अनुसार हमें अपने अधिनियमों की प्रस्तावना तथा सहकारी समितियों की व्याख्या को भी बदलना होगा ताकि उसमें वस्तुतः सहकारी तत्वों का समावेश हो सके । जिससे यह आन्दोलन एक निर्मल तथा स्वच्छ झरने व जल-स्रोत की भाँति निरन्तर प्रगतिशील रहकर व्यक्तिरूपी बूद-बूद का समावेश करके एक बड़ी नदी का रूप धारण करता हुआ अन्त में सागराकार हो जाय ।

: २ :

सहकारी समिति

सहकारिता तथा सहकारी समिति की परिभाषा पूर्व पृष्ठों में दी जा चुकी है। परन्तु सहकारिता के विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोग पर विचार करने से पूर्व यह आवश्यक है कि सहकारी समिति के तन्त्र पर भी विचार कर ले। क्योंकि इस तन्त्र को समझे बिना हम आन्दोलन के क्रियात्मक रूप को ध्यान में नहीं ला सकते। सहकारी समिति का संगठन प्रतिदिन एक ही अधिनियम तथा एक ही प्रकार के नियमों के अधीन होता है। कार्य-पद्धति, कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व भी एक से ही होते हैं। भारत में सर्व प्रसिद्ध तथा प्रचलित भावना ऋण सवधी ही है। अतः इस अध्याय में इसी से सवधित जानकारी दी गई है।

ऋण सवधी सहकारी संस्था के प्रारम्भिक स्तर दो प्रकार के होते हैं—एक असीमित उत्तरदायित्व वाली और दूसरी सीमित उत्तरदायित्व वाली।

(१) असीमित उत्तरदायित्व वाली समिति वह होती है जिसका हर सदस्य अपनी कुल सम्पत्ति की सीमा तक समिति के ऋण के लिए उत्तरदायी होता है। इस प्रकार की समितियाँ आज तक ग्रामों में कोयम होती रही। ऋण सवधी कार्य के लिए आज तक ऐसी समितियों के पक्ष में ही विचार रहा। क्योंकि यह ख्याल किया जाता है कि इस प्रकार का उत्तरदायित्व रखने से समिति के सदस्य ऋण के आदान-प्रदान में सावधानी बरतते हैं और ऋण की वापसी में भी सुविधा रहती है।

(२) सीमित उत्तरदायित्व वाली समितियों में हर सदस्य की जिम्मेदारी एक निश्चित सीमा तक अर्थात् अपने भाग के मूल्य तक अथवा उसके निर्दिष्ट गुणात्क सीमित होती है। अर्थात् समिति का हर सदस्य ऋण के लिए एक निर्धारित सीमा तक उत्तरदायी होता है। उसकी समस्त सम्पत्ति उसके लिए उत्तरदायी नहीं होती।

इस प्रकार की समितियाँ या तो समितियों के मिलने से बनती हैं अथवा स्टोरी में इस शैली का अनुकरण किया जाता है। परन्तु अब संगठित ऋण अनुसरण करने पर ग्रामों की प्रारम्भिक समितियाँ भी सीमित उत्तर-

स्थान पर पृथक् किया गया है।

चूँकि भारतीय किसान गरीब होता है, अतः यह भी विधान रखा जाता है कि भाग धन-राशि अर्थात् हिस्से का रुपया किस्तों द्वारा अदा किया जाय। अधिक से अधिक १० वर्ष की अवधि रखी जाती है। और यह इसलिए भी होता है कि सहकारी समिति व्यक्तियों का एक संगठन है, न कि धन का, इसलिए यह प्रतिबन्ध रहता है कि कोई व्यक्ति निर्धारित राशि से अधिक हिस्से नहीं खरीद सकता ताकि सस्था पर मानवता का प्रभाव रहे, न कि धन का।

मत—सहकारी समिति में हर सदस्य का एक मत होता है, भले ही उसने कितने ही हिस्से खरीद रखे हों।

ऋण—ऊपर लिखा जा चुका है कि हिस्से अथवा शेयर बेचकर समिति के पास जो धन-राशि जमा होती है वह पर्याप्त नहीं होती। इस राशि को बढ़ाने का एक उपाय होता है अमानत जमा करना। यह अमानत मामूली व्याज के दर पर जमा कर ली जाती है और समिति की ऋण प्रदायक शक्ति को बढ़ाती है। अमानतों पर ३% से ४% व्याज दिया जाता है। और जब अमानत पर इतना व्याज हो तो समिति सदस्यों से ६% से ९% तक व्याज लेती है। अमानत जमा करने से सदस्य एक ओर वचन के स्वभाव को पुष्ट करते हैं और दूसरी ओर समिति के सहकारी कार्यों को शक्ति प्रदान करते हैं। बैंक साधारणतया ६% व्याज पर सहकारी समितियों को ऋण देते हैं। ग्रामीण किमान की ऋण सवधी समस्या को सुलझाने के लिए ग्रामीण साख समिति के प्रस्तावानुसार सहकारी बैंकों को रिजर्व बैंक ११% पर ऋण देगा जो ६% तक समिति के सदस्यों को मिल सकेगा।

हर ऋण के प्रार्थना-पत्र पर प्रबन्धक-समिति विचार करती है। वह यह देखती है कि आवश्यकता उचित है या नहीं और माग उनकी अधिक से अधिक ऋण देने की सीमा के अंदर-अंदर है या नहीं? समिति का सदस्य बनने पर हर सदस्य की सम्पत्ति के आधार पर उसे अधिक से अधिक ऋण देने की सीमा निर्धारित की जाती है क्योंकि ऐसा करना आवश्यक होता है। इस अधिकतम ऋण एक रजिस्टर समिति में रहता है। परन्तु इस विषय पर विचार करने के लिए यह है कि समिति के सम्बन्ध में प्रारम्भिक वैधानिक आवश्यकताओं

पर विचार किया जाय क्योंकि इनका ज्ञान हर सहकारी विभाग के कर्मचारी तथा कार्यकर्ता के लिए आवश्यक है।

पंजीकरण (Registration)—जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है कि दस आदमी मिलकर सहकारी समिति की स्थापना कर लेते हैं। जब ऐसा निर्णय दस या इससे अधिक व्यक्ति कर लेते हैं, तो वह स्थानीय सहकारी विभाग के सब-इन्सपेक्टर से परामर्श प्राप्त करते हैं। फिर वह प्रार्थना पत्र के साथ उप-नियमों की प्रति लगाकर रजिस्ट्रार अथवा उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी के पास भेजते हैं। उक्त अधिकारी के विभाग में प्रार्थना की पडताल की जाती है कि वह अधिनियम में लिखित प्रतिबन्धों को पूरा करती है या नहीं, अर्थात् वह उनके अनुकूल है या नहीं। उसमें कोई अनुचित बात तो नहीं, वह सहकारिता के सिद्धान्तों की पूर्ति में सहायक है या नहीं, वह सदस्यों के आर्थिक हित की भावनाओं से प्रेरित है या नहीं। अगर इन सब कसौटियों पर वह ठीक उतरती हैं तो रजिस्ट्रार महोदय इसे रजिस्टर कर लेते हैं।

कार्य-क्षेत्र—समिति का कार्य-क्षेत्र कितना व्यापक हो, यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर किसी माप-तोल से नहीं दिया जा सकता। इसके स्थूल सिद्धान्त तो यह है कि कार्य-क्षेत्र न तो इतना बड़ा होना चाहिए कि सदस्यों की एक दूसरे से परिचिति ही न हो सके, और न इतना कम कि वित्तीय दृष्टिकोण से वह अनुपयुक्त हो। सदस्यों का एक दूसरे से परिचय रहना बहुत आवश्यक है। पुरानी विचारधारा यह थी कि समिति में एक-सी आर्थिक समस्याओं वाले व्यक्ति शामिल होने चाहिए। इस प्रकार एक ग्राम के लिए एक सहकारी समिति की धारणा बनी और फिर आवश्यकताओं की कसौटी ने एक-एक ग्राम में ब्राह्मणों, राजपूतों, हरिजनों तथा शिल्पियों आदि की विभिन्न समितियों को जन्म दिया। इस तरह दो-दो, चार-चार घरों वाले ग्रामों के लिए एक समिति बनी और एक-एक ग्राम में पाच-छ समितियों का निर्माण होने लगा। यह छोटी समितियाँ पुष्ट न हो सकी और आर्थिक तौर पर असफल ही रही। प्रयोग कहीं सफल भी रहे। प्रारम्भ में साधारणतया यह समितियाँ अच्छी चलती रही परन्तु समय के साथ-साथ चार-पाच वर्षों में यह ढीली पड़ती जाती। इस समस्या पर गहन विचार करने पर विचारक इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि जिस प्रकार ग्रामीण साहूकार ग्रामीण जीवन की सब आवश्यकताओं का प्रबन्ध करके ही

सफल आर्थिक जीवन व्यतीत कर पाता है, इसी प्रकार सहकारिता में भी इसी प्रकार की नीति का अवलम्बन करना पड़ेगा और इसी विचारधारा ने सगठित तथा एकीकृत सहकारी पद्धति को जन्म दिया। वस्तुतः यह सगठित तथा एकीकृत सहकारी पद्धति अनेक उद्देश्य वाली सहकारी समिति का एक वैज्ञानिक ढंग से विकसित तथा परिष्कृत रूप है। इस पर विशेष विचार इससे संबंधित अध्याय में होगा। परन्तु हमें प्रारम्भिक सहकारी समिति के क्षेत्र की धारणा अवश्य बदलनी होगी। अतः प्रारम्भिक सहकारी समिति के कार्य-क्षेत्र की निर्भरता जन-संख्या तथा फैलाव पर होनी चाहिए। अतः ५००० तक की जन-संख्या तथा ५ मील के व्यास से अधिक ऐसी समिति का कार्य-क्षेत्र नहीं होना चाहिए। इस तरह अधिक से अधिक १००० परिवार समिति में शामिल होंगे। वे एक दूसरे के आचार-व्यवहार तथा आवश्यकताओं से परिचित होंगे। दरम्यानी दूरी भी इतनी रहेगी कि बैठक के लिए इकट्ठा होना कठिन नहीं होगा। जहाँ आबादी बिखरी हुई होगी वहाँ दूरी बढ़ जायगी और जहाँ आबादी घनी होगी वहाँ दूरी स्वयमेव कम हो जायगी।

सदस्यों की संख्या—सहकारी समिति प्रारम्भ करने के लिए शुरू में अधिक सदस्य जरूरी नहीं। शुरू में थोड़े हो तो इसलिए ठीक रहता है कि उनमें सहकारिता के सिद्धान्तों को हृदयगम कराना सहज होता है। शनैः-शनैः संख्या बढ़ाई जा सकती है, ताकि जो भी सदस्य बने उसकी सहकारिता में अभिरुचि जागृत हो चुकी हो और वास्तविक कार्यकर्ता आगे आ सकें। साधारणतया एक सहकारी समिति के १०० के लगभग सदस्य होने चाहिए।

सदस्यों की योग्यता—सदस्य वही लोग बनने चाहिए जिनका आचार-व्यवहार अच्छा हो अर्थात् सदाचारी हो। थोड़ी संख्या वाले ईमानदार, सदाचारी तथा विचारशील सदस्य हमेशा इन गुणों से विहीन अधिक संख्या वाले सदस्यों की अपेक्षा अधिक लाभप्रद होते हैं। अविश्वासी, सदाचार रहित व शरारती, चार या पांच सदस्य हो जाय तो समिति समाप्त हो जायगी वह कभी पनप नहीं सकती क्योंकि सहकारिता तो सेवावृत्ति से ही पनपती है। अतः सदस्यों के आचार का पहलू बड़ा ही आवश्यक है क्योंकि सहकारिता का आधार-स्तम्भ तो आचार तथा सेवावृत्ति है। और सभा का समूचा कार्य अधिकतर सेवा भाव से 'पतये' की निस्वार्थ सेवा द्वारा ही चलता है।

समिति की साख कायम करने के लिए यह भी आवश्यक होता है कि उसके कुछ सदस्य धनाढ्य भी हो। इनके सदस्य बनने में दूसरा लाभ यह होता है कि धनिकों का धन निर्धनों की स्वावलम्बन-परक सेवा में इस्तेमाल होता है। परन्तु समिति की वास्तविक साख और सदस्य की वास्तविक जमानत तो सदस्य का आचार, नेकचलनी, प्रतिज्ञा-पालन, स्वावलम्बन की भावना आदि ही हैं।

सफलता के लिए आवश्यक बातें—सहकारी समिति की सफलता के लिए सर्वप्रथम आवश्यकता होती है सहकारी भावनाओं को जागृत करने की। इसके बिना जो समिति बनती है उसकी नींव ही बालू पर रखी गई समझी जानी चाहिए। इसमें सन्देह नहीं कि ऐसी भावना जब अन्दर से जागती है तभी वह दृढ होती है। परन्तु जब राजकीय नीति सहकारिता-परक हो और एतदर्थ विशेष विभाग हो, तब उस विभाग के कर्मचारियों के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वे जनता में ऐसी भावनाएँ जागृत, सुदृढ तथा उन्हें विंकसित करें। परन्तु यह शोक से लिखना पड़ रहा है कि भारत में अभी इस प्रकार के कर्म-चारी वर्ग का अभाव-सा ही है।

तो भी यह काम हमें सरकारी तथा जनता दोनों पक्षों की ओर से करना होगा। कार्यकर्ता वर्ग को चाहिए कि सदस्यों को नीचे लिखी बातें अच्छी तरह समझाकर उनके मानस-पटल पर अंकित कर दें

(१) मितव्ययी होना, दूसरों से सहानुभूति रखना तथा अपने पावों पर खड़े होना।

(२) जो सदस्य बनें उनका एक-दूसरे से पूर्ण-परिचय की आवश्यकता।

(३) सदाचार, पारस्परिक विश्वास तथा ईमानदारी की आवश्यकता।

(४) असीमित उत्तरदायित्व वाली समिति में सदस्य की अपनी समस्त सम्पत्ति की सीमा तक तथा सीमित उत्तरदायित्व वाली समिति में हिस्से के नामांकित मूल्य तक समिति के ऋण के लिए जिम्मेदारी।

(५) प्रबन्धक समिति के कर्तव्य तथा उनका उत्तरदायित्व।

(६) सदस्यों को ऋण केवल उपयुक्त आवश्यकता अथवा उत्पादक कार्यों के लिए ही देना।

(७) यह देखना कि ऋण का रुपया उसी कार्य पर लगाया गया है जिसके लिए वह ऋण प्राप्त किया गया था।

(८) जिस सस्था (केन्द्रीय बैंकादि) से रुपया आता हो उसके नियमों का सदस्यो को ज्ञान ।

(९) ऋण की वापसी अपनी वचत से जमा करके देना, किसी से ऋण लेकर नहीं और प्रतिज्ञानुसार समय पर ऋण लेकर लौटाना ।

यदि इन बातों पर सदस्य पूरा आचरण करे तो कोई भी समिति असफल नहीं हो सकती ।

पजीकरण की पूर्वावश्यकताएँ—जैसा कि पूर्व लिखा जा चुका है सहकारी समिति का वास्तविक ध्येय यह है कि आपस में मेल-जोल करके 'सबके बहुत भले' के सिद्धान्त को क्रियान्वित किया जाय । इस प्रकार यह आवश्यक हो जाता है कि सहकारी समिति के प्रमाणीकरण से पूर्व यह भली प्रकार देख लिया जाय कि

(१) सभा के हर सदस्य को सहकारिता के सिद्धान्तों से पूर्ण परिचय प्राप्त हो चुका है ।

(२) सब सदस्य ईमानदार हैं ।

(३) ऋण केवल सदस्यों को ही दिए जाने का प्रावधान है ।

(४) ऋण केवल ऐसे कामों के लिए दिया जाने का प्रावधान है जिससे उत्पादन बढ़े और जीवन की आवश्यकताएँ पूरी हों ।

(५) इस बात का प्रबन्ध है कि ऋण जिस मतलब के लिए लिया गया है उसी पर व्यय होगा, और यदि ऐसा न हो तो ऋण वापस ले लिया जायगा ।

(६) ऋण का जामिन भी लिया जायगा ।

(७) सेक्रेटरी को छोड़ समिति के अन्य पदाधिकारी नि शुल्क काम करेंगे ।

(८) प्रबन्धक-समिति से उपर सब अधिकार साधारण सभा को होने चाहिए ताकि सब सदस्य समिति के कार्य में दिलचस्पी लें ।

(९) समिति का संचालन लोकतंत्री ढंग पर हो और साधारणतया निर्णय निर्विरोध हो ।

(१०) एक सदस्य को एक ही वोट देने का अधिकार हो ।

(११) समिति के सब कार्य खुले हों, छिपे रूप से न हों ।

बन्ध—समिति का प्रबन्ध तीन अंगों पर निर्भर होता है, साधारण सभा,

प्रबन्धक समिति तथा कार्यकर्ता अथवा कर्मचारी वर्ग । इनका सक्षिप्त विवरण नीचे दिया जाता है ।

साधारण सभा—जो व्यक्ति समिति के नियमानुसार एक या इससे अधिक भाग गरीबे और समिति उसे सदस्य श्रेणी में प्रविष्ट करने की स्वीकृति दे, तो वह सभा का सदस्य बन जाता है । इस तरह नव सदस्यों के समूह को साधारण सभा अथवा समिति कहते हैं । समिति के सत्र में सर्वोपरि अधिकार साधारण सभा को ही होते हैं और इस सभा में हिस्सों का विचार रखते बिना हर सदस्य का एक मत होता है । बैठक बैठक के लिए आवश्यक होता है कि उपनियमों में लिखे अनुसार उतने सदस्य अवश्य उपस्थित हों तथा बैठक नियमानुसार बुलाई गई हो । परन्तु साधारण सभा बहुत बार नहीं हो सकती । अधिनियम के अधीन साधारण सभा की वर्ष में एक बार बैठक होनी आवश्यक है । इस बैठक में वर्ष के कार्य पर विचार तथा हिसाब-किताब का व्योरा साधारण सभा लेती है और अगले वर्ष के लिए चुनाव करती है । यह अनिवार्य कार्य है । इनके अतिरिक्त सभा को उचित है कि वह गत वर्ष के कार्य की विवेचना करे और अगले वर्ष के लिए कार्य-क्रम निर्धारित करे । क्योंकि साधारण सभा दैनिक कार्यों के लिए जुटती नहीं हो सकती, अतः दैनिक कार्य के लिए सभा की एक प्रबन्धक समिति होती है ।

प्रबन्धक-समिति—प्रबन्धक-समिति साधारण सभा द्वारा उपनियमों के अनुसार निर्वाचित होती है । प्रबन्धक-समिति के सदस्यों की संख्या उपनियमों के अधीन निश्चित होती है । यह संख्या ५ से ११ तक यथावश्यकता हो सकती है । यह सब सदस्य साधारण सभा द्वारा चुने जाते हैं । यह यदि चुनाव बहुमत के स्थान पर सर्व संमति से हो तो अधिा नफल रहते हैं ।

प्रबन्धक-समिति में साधारणतया एक प्रधान, एक उपप्रधान, एक मंत्री तथा एक कोषाध्यक्ष होते हैं । गारूडिड तौर पर प्रबन्धक-समिति सभा के समस्त संचालन के लिए साधारण सभा के निर्देश के अनुसार उत्तरदायी होती है और साधारणतया निम्न कार्य करती है—

- (१) पूँजी संग्रह ।
- (२) पूँजी का उपनियमानुसार आर्जन-प्रदान ।
- (३) हिसाब का टोक और पर रक्ता ।

- (४) सभा के दैनिक कार्य की देखभाल ।
 (५) साधारण सभा के निर्देशों का पालन तथा निश्चयों को कार्यान्वित करना ।

प्रवधक-समिति को नीचे लिखे कार्य नहीं देने चाहिए—

- (१) प्रवधक-समिति का चुनाव ।
 (२) रजिस्ट्रार को भेजने से पूर्व साधारण सभा द्वारा की गई जाच ।
 (३) सदस्यों को पृथक् करना आदि ।

ऊपर लिखा जा चुका है कि प्रवधक-समिति में कुछ पदाधिकारी होते हैं । उनके कार्यों का सक्षिप्त विवरण देना भी लाभप्रद होगा—

प्रधान व उपप्रधान—यह साधारण सभा द्वारा निर्वाचित होते हैं और उनके यह कार्य होते हैं—

प्रवधक-समिति तथा साधारण सभा की बैठकों की अध्यक्षता करना तथा पदाधिकारियों के कामों पर निगरानी रखना । विशेष परिस्थितियों में जब कोई विशेष अडचन हो तो प्रवधक-समिति प्रधान को विशेष अधिकार दे सकती है । उपप्रधान प्रधान की अनुपस्थिति में प्रधान का तथा प्रधान की सहायता का काम करता है ।

मंत्री—समिति के कार्य संचालन के लिए एक मंत्री की आवश्यकता होती है । यह आम तौर पर सभा का सदस्य होता है । यदि सदस्यों में कोई उपयुक्त व्यक्ति न मिले तो बाहर से भी किसी उपयुक्त व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है । परन्तु सदस्य मंत्री सदा लाभप्रद होता है । नियमानुसार मंत्री को वेतन सब समितियाँ देने की क्षमता नहीं रखती । अतः मंत्री को वर्ष के अंत में पुरस्कार अथवा भत्ता देना ठीक रहता है । स्थानीय व्यक्ति इस काम के लिए इसलिए अधिक अच्छा होता है कि उसे सब लोग जानते हैं और विश्वास भी अधिक होता है । वह भी सबको जानता है । स्थानीय स्कूल का अध्यापक इस काम के लिए अच्छा हो सकता है । परन्तु शीघ्र स्थानांतरण इसमें बाधा डालता है । स्थानीय पचायत का सचिव अधिक उपयुक्त हो सकता है । मंत्री को कभी प्रवधक-समिति के अधिकार नहीं देने चाहिए कि वह उसके निर्णयों तथा निर्देशों को चालू करे । क्योंकि अधिक अधिकार प्राप्त करके मंत्री समिति का

मानिक वनकर उसकी मानिकता को समाप्त कर देता है। मंत्री के आमतौर पर निम्न कार्य होते हैं—

- (१) समिति की कार्यवाही को नियमपूर्वक निखना।
- (२) समिति के वास्ते पत्र-व्यवहार करना।
- (३) समिति के सदस्यों से प्रवेश-शुल्क तथा खरीदे गए हिस्सों का रुपया प्राप्त करके जमा करना।
- (४) प्रबन्धक-समिति के निष्चयों को क्रियान्वित करना।
- (५) समिति के हित में दैनिक कार्य की देखरेख।

कोषाध्यक्ष—सभा की आय को सभालने का कार्यभार उठाने के लिए कोषाध्यक्ष की नियुक्ति होती है। सभा की जितनी आय हो चाहे वह हिस्सों की बिक्री द्वारा हो, या प्रवेश शुल्क द्वारा या अमानत द्वारा या ऋण द्वारा, यह सब आय कोषाध्यक्ष के पास जानी जरूरी है। कोषाध्यक्ष का कर्तव्य है कि वह समस्त आय प्राप्त करे और उसे रोकट-बन्दी में दर्ज करे और उसको प्रबन्धक-समिति के निर्णय से अनुसार निकालने के लिए प्रयोग के लिए है। आजकल आमतौर पर कोषाध्यक्ष समिति का रुपया सहकारी बैंक में रखते हैं। इस जमा बिये धन को बैंक से निकालने के लिए प्रबन्धक-समिति प्रस्ताव द्वारा एक या इससे अधिक सदस्यों को अधिकार प्रदान करती है। और वही सदस्य अपने हस्ताक्षरों द्वारा धन राशि निकालवा सकते हैं।

आवश्यक रजिस्टर—हर समिति के लिए अधिनियम, नियम तथा उपनियमों के अधीन कुछेक रजिस्टर रखने आवश्यक हैं। यदि यह रजिस्टर न रहे जाय तो सभा की तरफ से नियमों की व्यवहारात्मकता नमनी जाती है। यह रजिस्टर इस प्रकार है —

रोज धनावशेष निकालकर उसका मिलान करना पड़ता है ।

खाता-वही—इसमें हर सदस्य के हिसाब का पृथक् खाता खोलना पड़ता है तथा समिति के विभिन्न हिसाबों के भी खाते रखने पड़ते हैं । खाते के हर इन्दराज में प्राप्तव्य का अथवा देय राशि तथा अवशेष निकालना पड़ता है । और रोकडवही के मव इन्दराज खातों में बैठने जरूरी होते हैं ।

रजिस्टर-किश्तवन्दी—इसमें दिये गए कर्जों की जितनी रकम जिस तारीख को देनी हो वह दर्ज रहनी चाहिए । इसमें यह भी स्पष्ट दर्ज रहना चाहिए कि कर्जों की किश्त मिली या नहीं ।

रजिस्टर-अमानत—इस रजिस्टर में वह सब धन-राशियाँ अमानतदार के नाम के साथ खातेवार दर्ज रहती हैं, जिन्होंने समिति के पास अमानत जमा कराई हो । इनके आदान-प्रदान का भी व्योरा दर्ज रहता है ।

रजिस्टर-कार्यवाही—इस रजिस्टर में प्रबन्धक व साधारण सभा की कार्यवाही का व्योरा दर्ज रहता है । कार्यवाही रजिस्टर में हर उपस्थित सदस्य के हस्ताक्षर होते हैं तथा हर विषय तथा बैठक में हुए निश्चय दर्ज रहते हैं । यदि सभा बड़ी हो तो प्रबन्धक व साधारण सभा के कार्यवाही-रजिस्टर पृथक् रखे जाते हैं । समिति के निश्चयों का यह प्रामाणिक लेख संग्रह होता है और इसमें लिखे विषयों की प्रामाणिक प्रतिलिपि मंत्री दे सकता है ।

धन का उपयोग—हर समिति को आवश्यक है कि धन को साधारण व्यक्ति की-सी होखारी के अनुसार ठीक ढंग से, मितव्ययता से तथा उपनियमों के अनुसार प्रयोग में लाय । साथ ही इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि समिति की नीति का कहीं यह फल तो नहीं कि सदस्यों को आवश्यकता पूर्ति तथा आवश्यक ऋण प्राप्ति के लिए विवग होकर गांव के साहूकार अथवा दूकानदार का आश्रय तो नहीं लेना पड़ता ।

ऋण-प्रदान—यह समितियाँ धन का उपयोग ऋण के लेन-देन पर ही करती हैं । आमतौर पर यह देखा गया है कि ऐसी समितियों में ऋण दिया तो जाता है, परन्तु वसूली में इतनी ढील रहती है कि धीरे-धीरे समिति की दशा पतली होती जाती है, और कड़्यों को तो शीघ्र ही परिसमापन की कार्यवाही का मुह देखना पड़ता है । प्राप्ति ऋण देने में समिति को बड़ी सावधानी तथा सतर्कता से काम करना चाहिए ताकि समिति उत्तरोत्तर उन्नति करती जाय । इस काम

मे निम्न बातों का ध्यान रखना लाभदायक होता है—

(१) हर सदस्य को यदि आवश्यकता पड़ने पर सभा से रुपया न मिले और उसे साहूकार का मुह देखना पड़े तो उसे समिति के सदस्य होने का कोई लाभ नहीं होगा और इस तरह सदस्य समिति से विमुख होते जायेंगे। अतः आवश्यकता पड़ने पर सदस्य को समिति से ऋण मिल जाना चाहिए।

(२) कई बार ऐसी आवश्यकताएँ आ पड़ती हैं जिनके लिए व्यक्ति प्रतीक्षा नहीं कर सकता यथा मृत्यु आदि। ऐसी परिस्थितियों पर प्रधान अथवा अन्य सदस्य को प्रबन्धक-समिति के प्रस्तावानुसार ऋण देने का इस प्रतिबन्ध सहित अधिकार रहना चाहिए कि बाद में उसे प्रबन्धक-समिति द्वारा अनुमोदित करवा लिया जायगा।

(३) सभाको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कहीं प्रबन्धक समिति के सदस्य अपने मित्रों व सम्बन्धियों को या आपस में ही तो ऋण नहीं बाँट लेते। अतः यह उपनियम चाहिए कि प्रबन्धक-समिति के सदस्य सभा के ऋणी न हों। और ऋण देने की अधिकतम सीमा नियत की जाय जिससे अधिक ऋण किसी को न दिया जा सके, ताकि न तो रुपया मित्रों आदि में बाँट सके और न ही किसी एक पर इतना ऋण का बोझ हो जाय कि वह आखिर दिवालिया होने पर विवश हो।

(४) इस बात के परीक्षण के लिए कि किसी सदस्य को उसकी हैसियत से अधिक ऋण न दिया जाय, क्योंकि हैसियत से अधिक ऋण दिए जाने में सदस्य कठिनाई में पड़ जाता है, इस तरह हर सदस्य की भी अधिकतम ऋण-सीमा उसकी हैसियत के अनुसार निर्धारित कर देनी चाहिए।

अधिकतम ऋण-सीमा—ऋण-प्राप्ति के लिए अधिकतम ऋण-सीमा असीमित उत्तरदायित्व वाली सहकारी समितियों में हैसियत के अनुसार ही होती है। अभी तक हैसियत उसकी भूमि तथा अन्य सम्पत्ति से आकी जाती थी, परन्तु ऐसी पद्धति में काश्तकार घाटे में ही रहता था। वह फसल उगाता परन्तु उसे फसल के बदले भी सहकारी समिति से ऋण न मिल सकता था परन्तु साहूकार दे देता था। अब ग्रामीण साख-सर्वेक्षण रिपोर्ट के प्रस्तावानुसार एक ओर तो अधिनियम के अधीन फसल पर सहकारी ऋण का सभार किया गया है और सदस्य की अधिकतम ऋण-सीमा के निर्धारण में काश्तकार की

फसल का भी विचार रखा जाता है ।

सीमित उत्तरदायित्व वाली सहकारी समितियों में हैसियत के अनुसार ऋण-सीमा की अधिकतम मात्रा आककर फिर उसे हिस्से के धन पर अव-लम्बित उत्तरदायित्व की मात्रा तक अर्थात् हिस्से में धन के निर्धारित खण्ड तक फिर सीमित कर दिया जाता है । इस तरह ऋण की महत्तम सीमा निर्धारित कर दी जाती है ।

ऋण की अवधि—सहकारी प्रणाली में ऋणों को तीन भागों में विभक्त किया जाता है अर्थात् (१) अल्पकालिक, (२) मध्यकालिक और (३) दीर्घ कालिक ।

(१) अल्पकालिक ऋणों की अवधि १५ मास तक होती है । यह ऋण साधारण-तया फसलों के उत्पादन में सहायता के लिए दिये जाते हैं । प्रबन्धक समिति को ऐसे कार्यों का व्योरा निश्चित कर लेना चाहिए । उदाहरण के लिए ऐसी आवश्यकता इस प्रकार होती है—

(१) बीज खरीदना, (२) छोटे-छोटे उपकरण (औजार) खरीदना, (३) खाद और चारा-घास आदि का क्रय, (४) कृषि के लिए मजदूर लगाना व बैल आदि का किराये पर उपयोग, (५) उत्पादन को मण्डी तक ले जाने के लिए प्रबन्ध, (६) लगान का देना, (७) सिचाई-कर का देना, (८) उपज को उपयुक्त समय पर विक्रय के लिए रोकने के आंतरिक काल में आवश्यकताओं की पूर्ति आदि-आदि ।

इस ऋण की अदायगी दो या एक किस्त में ही सदस्य को करनी पड़ती है ।

(२) मध्यकालिक ऋणों की अवधि ३ वर्ष तक होती है और इनकी वापसी के लिए छमाही किस्तें की जाती हैं । यह ऋण उन आवश्यकताओं पर दिए जाते हैं जिनकी आवश्यकता उत्पादक कार्यों में सहायक होती है, और जिनकी वापसी कृषक अपनी आय के साधनों से शीघ्र चुकाने की क्षमता नहीं रखता—

(१) कृषि उपकरणों का क्रय, (२) बैलों का क्रय, (३) भूमि का सुधार, (४) और स्रोतों से प्राप्त ऋण की अदायगी, (५) शिक्षा, (६) आवश्यक मुकदमावाजी, (७) आवश्यक सस्कार, (८) ग्रामोद्योगों आदि के लिए ।

(३) इससे अधिक अवधि में लौटाए जाने वाले ऋण दीर्घकालिक ऋण कहलाते

है। ऐसे ऋण साधारणतया छोटी प्रारम्भिक समितियां नहीं देती। यह ऋण— (१) मकान बनाने, (२) भूमि खरीदने, (३) बगीचा लगाने, (४) मशीनरी आदि लगाने, सिचाई का प्रबन्ध करने आदि के लिए दिए जाते हैं। इनके लिए भूमि-बन्धक-अधिकोष प्रबन्ध करते हैं। परन्तु जहां ऐसे बैंक नहीं होते वहां यह ऋण सहकारी बैंक से रुपया प्राप्त करके समितियां भी दे सकती हैं। इन ऋणों के देने में कई बार अधिकतम ऋण सीमा का उल्लंघन करना पड़ता है और ऐसी दशा में इस ऋण से खरीदी जाने वाली सम्पत्ति को सभा बन्धक रूप में रखती है।

सदस्यों में नियत समय पर ऋण लौटाने का स्वभाव डालना इस पद्धति की सफलता के लिए बड़ा आवश्यक है।

ऋण-पत्र (प्रोनोट)—ऋण को सुरक्षित रखने तथा उसके लौटाने के प्रतिबन्धों को निश्चित करने व दर व्याज आदि को लिखितस्वरूप देने के लिए हर ऋण का एक ऋण-पत्र लिखा जाता है। यह ऋण-पत्र दो प्रकार के होते हैं— तमस्सुक तथा प्रोनोट। प्रोनोट शैली को अधिक लाभदायक समझा जाता है, क्योंकि उसमें शर्त नहीं होती, यह दूसरे व्यक्ति को हस्तान्तरित किया जा सकता है अथवा किसीके नाम बदला जा सकता है। इसमें कर्जों की मांग पर उसके लौटाये जाने की प्रतिज्ञा होती है। जबानी शहादत की आवश्यकता नहीं रहती। परन्तु इस प्रकार के ऋण-पत्र अल्पकालिक ऋणों में ही प्रयुक्त हो सकते हैं क्योंकि जहां किस्तों की शर्त हो वहां प्रोनोट की शैली प्रयुक्त नहीं हो सकती। क्योंकि प्रारम्भिक समितियों में कानून जानने वाले कम होते हैं, अतः यह आवश्यक है कि प्रोनोट और तमस्सुक आदि सहकारी विभाग की सलाह से छपवा लिए जाय।

जामिन—ऋण देते समय सदस्य से जामिन अथवा उसकी जमानत देने वाला भी लेना चाहिए या नहीं? वस्तुतः समिति का सदस्य अपना जामिन स्वयं होता है। सहकारी पद्धति में असली जमानत तो सदस्य की विश्वासपात्रता तथा उसका सदाचार होती है। फिर समिति को ऋण की वापसी की इतनी चिन्ता नहीं होती जितनी कि सदस्यों की आर्थिक दशा को वचत आदि का स्वभाव पैदा करके सुधारने की होती है। जहां साधारण लेनदेन में जामिन इसलिए लिया जाता है कि ऋण की वापसी सुरक्षित रहे, वहां सहकारी समिति ऋण की वापसी

सुरक्षित करने के साथ-साथ इसलिए भी जामिन लेती है कि ऋण उसी काम में प्रयोग लाया जाय जिसके लिए वह लिया गया है और ऋण लेने वाला सदस्य वचत आदि द्वारा रुपया वुचाकर लौटाने का प्रयत्न करे। क्योंकि ऋणी के ऋण न लौटाने पर वह रुपया जामिन से वसूल किया जा सकता है, इसलिए जामिन ऋण के प्रयोग तथा वचत के स्वभाव को अपनाने आदि के क्रम पर अधिक ध्यान रखेगा। इस ध्येय के समक्ष जामिन लिया जाना उपयुक्त ही होता है।

व्याज—प्रबन्धक-समिति को चाहिए कि व्याजों की दर नियत रखे। यह दर सबके लिए समान होनी चाहिए। इसमें इन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है—

- (१) दर बाजारी दर से कम हो।
- (२) दर इतनी कम भी न हो कि सभा अपने लिए कुछ भी न वचा सके।
- (३) दर-व्याज बैंक से समिति जिस दर पर ऋण प्राप्त करती है उससे कुछ अधिक होनी चाहिए। साधारणतया १% से २% बढ़ोतरी होनी चाहिए।
- (४) व्याजदर इतनी अधिक नहीं होनी चाहिए कि सदस्य समिति को छोड़कर अन्य स्थान से ऋण प्राप्त करने का यत्न करे, परन्तु इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कहीं साहूकारी-वृत्ति रखने वाले समिति के सदस्य समिति से कम दरो पर ऋण लेकर गरीब कृषकों को अधिक दरो पर तो ऋण नहीं देते।

ऋण की समय पर वापसी—सहकारी समिति का वस्तुतः प्रथम कर्तव्य यह है कि सदस्यों में सदाचार भावना को पुष्ट करे। वचत सिखाये तथा समय पर ऋण लौटाने का उनमें स्वभाव डाले। ऋण की समय पर वापसी सभा के अपने प्रगतिशील जीवन के लिए परमावश्यक है। क्योंकि रुपया समय पर वापस न आये तो रुपया फसा रह जाता है और समिति के पास शेष सदस्यों की आवश्यकता-पूर्ति के लिए कुछ रह नहीं जाता। इतना ही नहीं सहकारी बैंक का कारोबार भी इस अवहेलना से ठप्प हो सकता है। इसलिए ऋण के इस पक्ष की ओर प्रबन्धक-समिति का विशेष ध्यान रहना चाहिए अन्यथा समिति निर्वल होकर समाप्त हो जायगी। यदि ऋण लेने वाला समय पर ऋण वापस न करे तो उसके लिए व्याज-दर अधिक हो जाने का डर रहना चाहिए ताकि

समय पर ऋण की वापसी के स्वभाव को प्रोत्साहन मिले। ऐसी ढील करने वाले ऋणी तथा जामिन को पुनः ऋण मिलने में रुकावट रहनी चाहिए। इससे समय पर ऋण-वापसी के स्वभाव को प्रोत्साहन मिलेगा। परन्तु यह बहुत आवश्यक है कि समिति की प्रबन्धक-समिति इस कार्य में बहुत सतर्क रहे।

सहकारी विभाग—विभाग के जिम्मे भी कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें यदि तत्परता से न किया जाय जो सहकारी समितियों का काम शिथिल पड़ जाता है। उनकी ओर भी सक्षिप्त सकेत किया जाना अनुपयुक्त नहीं होगा। सहकारी विभाग के जिम्मे अधिनियमाधीन दो ही कार्य हैं—उनका पंजीकरण तथा हिगाव की जाच-पड़ताल परन्तु सरकार द्वारा प्रोत्साहन प्राप्त तथा राज्य की नीति को क्रियान्वित करने वाला यह आन्दोलन सहकारी विभाग पर आवश्यकता से अधिक आश्रित रहता है। परन्तु यहाँ पर तो उतना ही लिखना पर्याप्त होगा कि सहकारी विभाग का उपनिरीक्षक तो समितियों के संगठन करने का, और यह ध्यान रखने का उत्तरदायी होता है कि वह ठीक से चल रही है। इसका कर्तव्य होता है कि हर समिति में वह एक महीने में एक बार जाय। उसके बाद निरीक्षक की श्रेणी आती है। यह समिति के कार्य को देखकर उसकी भूलें सुधारने तथा सत्रणा देने के लिए होता है। हर समिति का वर्ष में एक बार निरीक्षण करना आवश्यक है। तृतीय श्रेणी लेखा परीक्षको की होती है। उनका कर्तव्य है कि वर्ष में कम से कम एक बार हर सभा समिति के हिगाव की जाच-पड़ताल करे। हर समिति को चाहिए कि सहकारी विभाग के उन कर्मचारियों से पूरी-पूरी सहायता प्राप्त करे। इनके सहयोग तथा सहायता से कार्य की सफलता की संभावनाएँ बढ़ सकती हैं। और सहकारी विभाग के कर्मचारियों को भी चाहिए कि उनकी वृत्ति ऐसी हो कि वे उस लोक-तंत्री आन्दोलन को बढ़ावा दें और बंसी ही अभिरुचि लें।

निर्णायक या सलिस—जब कोई सदस्य ऋण न लौटाएँ अथवा कोई अन्य विवाद समिति में हो तो ऋण की वसूली के लिए समिति को जचहरी में नहीं जाना पड़ता। वरन् वह अपना मामला प्रिन्सिपल रजिस्ट्रार के नाम से रख कर उसके निर्णय के लिए एक मासिक (मॉनिंग) नियुक्त करवा दिया जाता है। सहकारी अधिनियम में प्रदीप्त ऐसे निर्णय देने के पूर्ण अधिकार होते हैं। और उसका निर्णय न्यायालय से नान्य लोग उसकी उजराएँ बना हो सकती हैं।

समिति के प्रबन्धक को आवश्यक अवसरो पर डम अधिकार का प्रयोग कर लेना चाहिए ।

समिति की असफलता के कारण—यदि सहकारी सगठन की प्रबन्धक समिति के सदस्य स्वार्थी या लापरवाह हो तो वे अपनी आय का ही ध्यान रखेंगे, सभा के कार्य की ओर ध्यान नहीं देगे । इसका फल यह होगा कि समिति के सदस्यों को ऋण मिलने में असुविधा होगी, वह निष्पक्ष रूप से नहीं बाटा जायगा । वापसी के लिए प्रयत्न नहीं होगा । इस प्रकार समिति का कार्य शिथिल होता जायगा, इसकी असफलता के प्रधान कारण इस प्रकार होते हैं—

- (१) देख-रेख की कमी,
- (२) बिना सोचे-समझे ऋण देना,
- (३) ऋणी लोगो का प्रबन्धक समिति के सदस्यों की आज्ञा न मानना,
- (४) समय पर ऋण न लौटाया जाना,
- (५) सदस्यों को ऋण देने में पक्षपात,
- (६) समिति के कार्यकर्त्ताओं की बेइमानी और अयोग्यता,
- (७) सदाचारहीन अनुचित व्यक्तियों का सदस्य होना,
- (८) समिति के क्षेत्र का बहुत कम या बहुत अधिक विस्तृत होना,
- (९) सदस्यों द्वारा अपने पुराने ऋणों को छिपाकर रखना,
- (१०) सभा के उपनियमों में भूलें और उनकी अवहेलना,
- (११) समिति में आन्तरिक वैमनस्य,
- (१२) रुपया या सदस्यों की न्यूनता,
- (१३) एक सदस्य का समिति पर छा जाना,
- (१४) सदस्यों का समिति के कार्य में रुचि न लेना,
- (१५) सहकारी विभाग के कर्मचारियों तथा समिति के सदस्यों में विरोध ।

अतः सबसे आवश्यक बात है रजिस्ट्रार तथा उसके अधीन कर्मचारी समिति की निगरानी रखें और यह देखभाल रचनात्मक तथा शिक्षात्मक होनी आवश्यक है । सहकारी विभाग के कर्मचारी कई बार ध्वसात्मक प्रवृत्तियों को अपना कर केवल यही बूढ़ते हैं कि किस प्रकार प्रबन्धक-समिति के किसी सदस्य किसी छोटी भूल के लिए फौजदारी मुकदमों में फसाया जा सकता है । रजिस्ट्रार को चाहिए कि विभाग के कर्मचारियों की ऐसी वृत्तियों को रोकता

रहे और निगरानी द्वारा सभा के प्रगतिशील जीवन को सुरक्षित करे। कई बार उपनियमों को ठीक करने अथवा प्रबन्धक समिति में थोड़ा हेर-फेर करने से समिति की दशा सुधर जाती है। रजिस्ट्रार को परिस्थितियों के अनुसार प्रबन्धक-समिति को स्थगित अथवा बरखास्त करने के भी अधिकार होते हैं। समिति की दशा बहुत ही खराब हो तो उसको समाप्त कर देना ही एकमात्र इलाज रह जाता है। साधारण सभा को चाहिए कि प्रबन्धक समिति चुनते समय विशेष ध्यान रखे कि निस्वार्थ तथा रचनात्मक वृत्ति वाले सदस्य प्रबन्धक-समिति में रहे अन्यथा समिति का संचालन सुचारु रूप में नहीं हो सकेगा। परन्तु सब बातों के साथ-साथ कर्मचारियों तथा समिति के सदस्यों का निरन्तर प्रशिक्षण बहुत आवश्यक होता है। इसके बिना ऊपर लिखी कमजोरियाँ या बुराइयाँ दूर नहीं होंगी।

समिति का लाभ—जब समिति सफल होती है तो कुदरती तौर पर उसे लाभ होता है। परन्तु यह पहले लिखा जा चुका है कि सहकारी समिति लाभ कमाने का नहीं बल्कि मानव-सेवा का उपकरण है। इतना होने पर भी यह एक व्यवसायिक संगठन है। अतः कुछ लाभ के बिना इसका निरन्तर चलते रहना सम्भव नहीं। अतः समिति को जो लाभ होता है उसके वितरण में बड़ी सूझ-बूझ से काम लेना पड़ता है ताकि यह सस्था भी दूसरी कम्पनियों जैसी न हो जाय। अतः यह कानून है कि—

(१) कोई सहकारी समिति खरोदे गये हिस्से के धन पर १०% से अधिक सदस्यों को लाभ वितरण न करेगी।

(२) २५% अनिवार्य तौर पर सुरक्षित कोष में जमा होगा।

कहना न होगा कि सुरक्षित कोष एक बड़ा ही उपयोगी कोष है और यदि यह नियमपूर्वक पुष्ट होता जाय तो कुछ वर्षों के पश्चात् समिति के पास अपना इतना धन हो जाता है कि उसे अन्य कहीं से धन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रहती। इसके अतिरिक्त सभा—

दान-कोष, पारस्परिक सहायता-कोष, अप्राप्तव्य ऋण-पूर्ति कोष, घाटा-कोष, भवन-कोष आदि में लाभ को जमा करती रहती है।

सभा का मौलिक आधार—आमतौर पर देखा गया है कि हर समिति की कोई न कोई ऐसी सम्पत्ति होनी चाहिए जिससे समिति को कुछ आय भी हो,

और उसका कृषिपरक गुण बना रहे तथा वह दृढ बनी रहे। श्री लोवो प्रभु ने इस पक्ष पर बहुत जोर दिया है।

नगरो मे समिति का अपना मकान इस प्रकार की सम्पत्ति सुझाई गई है। परन्तु हर समिति का भवन के साथ यदि एक स्वावलम्बी कृषि-क्षेत्र हो, जहाँ समिति की प्रबन्धक-समिति के सदस्य ग्रामीण प्रथानुसार कार्य करके समिति के लिए उत्पादन करे तो समिति का जीवन सुरक्षित हो जाता है। उसकी आयु बढ़ जाती है तथा रचनात्मक पद्धति के परिचालन में पर्याप्त सहायता प्राप्त हो सकती है।

हम ऊपर देख चुके हैं कि किसी भी प्रकार की सहकारी समिति हो उसकी सफलता के लिए कुछेक बातें जरूरी हैं। पर सबसे जरूरी समिति का एक ऐसा केन्द्रीय तथा मौलिक आधार होना चाहिए जो कि उसका साधारण खर्च निकाले, उसे स्थिर जीवन प्रदान करे, उसके प्रति जनता की दिलचस्पी पैदा करे तथा जिस प्रकार की भी समिति हो उसके कार्य में सहायक हो।

इस अध्याय को समाप्त करने से पूर्व यह लिखना आवश्यक है कि आम-तौर पर हर सहकारी समिति का ढाँचा प्रारम्भिक स्तर पर इसी प्रकार का होता है, परन्तु अन्य प्रकार की सहकारी समितियाँ सीमित उत्तरदायित्व वाली होती हैं। ऋण का अग हर समिति में किसी न किसी ढंग में होता ही है। अतः ऊपर बताई गई बातों की ओर हर समिति को ध्यान रखना चाहिए ताकि उसकी अममय मृत्यु न हो।

: ३ :

सहकारिता और ऋण

अतीत में ज्यो-ज्यो व्यवित्यों के सामाजिक जीवन का प्रारम्भ हुआ और पारस्परिक सम्पर्क बढ़ा, तो व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तुओं आदान-प्रदान होने लगा। अभी मुद्रा अर्थात् सिक्के का जन्म नहीं हुआ था एक वस्तु दूसरी वस्तु के बदले ली जाती थी। मुद्रा का विकास पहले पशु,

फिर अनाज तदनन्तर सिक्के के रूप में हुआ। इस आदान-प्रदान में कई बार ऐसी परिस्थितियाँ भी पैदा हो जाती थी जहाँ लेने वाला बदले में उसी समय कुछ नहीं दे सकता था, अतः ली हुई वस्तु के बदले कोई दूसरी चीज देने में उसे कुछ समय की आवश्यकता होती थी। इस तरह ली हुई वस्तु अथवा मुद्रा ऋण पर ली गई समझी जाने लगी। और कुछ काल तक प्रतीक्षा के लिए जो कुछ अधिक दिया जाता था उसी को व्याज कहा जाने लगा।

यों तो ऋण की आवश्यकता सभी प्रकार के व्यक्तियों को पड़ती है, परन्तु किमान को इसकी जरूरत अधिक रहती है क्योंकि उसकी उपज प्रायः वर्षा पर निर्भर होती है और फिर उपज एक अवधि के बाद प्राप्त होती है। अतः इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए ऋण देने का भी एक व्यवसाय बन गया। चूँकि ऋण लेने वाला विवशता की हालत में होता है, अतः ऋण देने वाले ने शर्त-शर्त अपने लाभ के लिए उसपर कड़ी शर्तें लादनी शुरू कर दी। शाईलॉक की कथा से हम सब परिचित हैं, जबकि मानव जीवन से धन का मूल्य अधिक आका जाने लगा था। इन स्वार्थ पूर्ण नीति को रोकने के लिए नियम बने। भारत में ऐसा कानून प्रणिद्ध था कि जहाँ व्याज द्वारा मूल धन दो गुणा से नहीं बढ़ सकता था। अवधि सम्बन्धी कोई कानून नहीं होता था जिस के कारण ऋण-पत्रादि नये नहीं करने पड़ते थे, और इस नवीनीकरण द्वारा व्याज बढ़ने की नभावना से भी बचत हो जाती थी।

यह सर्व विदित बात है कि भारत में इस प्रकार ऋण देने वाले लोग इनने विद्यमान होते थे कि लोग उनसे एकान्त में ऋण लेते और वापस करने थे। केवल उनकी वही पर हिमाय हुआ करता था और ऋणपत्रादि नहीं निरखे जाते थे। शर्त-शर्त इस ईमानदारी तथा दिव्यमान में कमी आई और ऋणपत्र अथवा हिमाय निगने के बाद अन्त में ऋण लेने वाला बलम को छू लेता। फिर निशानी डालने लगा, उनके बाद हस्ताक्षर अथवा अगुठा लगाने की बारी आई। अगिर में हम ऐसी दगा में पड़ गए जहाँ नाधी डालने पड़ने और कई और बातें करनी पड़नी। उभय अर्थात् का कानून था कि जिनमें हर तीसरे वर्ष ऋण-पत्र नया होने पर व्याज मुद्रा में निरूपित जाता और उनपर भी व्याज लगना आरंभ हो जाता। यह एक बहुत बड़ा बात है कि जहाँ-जहाँ इस कानून का प्रयोग करने हैं ईमानदारी, दिव्यमान तथा ईश्वर का भय बन होने लगता है। यह सब हुआ और ऋण-दान ने लोग

तथा स्वार्थपरायणता में पड़कर निर्धन, अनपढ़ तथा भोले-भोले किसान तथा ऋण लेने वाले अन्य लोगों को नृशंसता से लूटना शुरू किया। इससे अमीर अधिक अमीर और गरीब अधिक निर्धन हो गया। यह हालत विश्व के हर भाग में हुई। समाज को इससे बचाने के लिए कई आन्दोलन चले, कई कानून बने और कई विचार पद्धतियाँ विकसित हुईं। इसमें सन्देह नहीं कि अभी तक हम किसी भी उपाय द्वारा अपने ध्येय को प्राप्त करने में सफल नहीं हो सके। इस सम्बन्ध में सबसे अधिक सफल तथा अधिक आशा प्रदान करने का गौरव आज की सहकारिता को प्राप्त है।

किसान ही हमारे समाज की रीढ़ है। इसी किसान द्वारा अधिक उत्पादन से ही समाज सुखी होता है। अतः किसान की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए जरूरी है कि वह स्वस्थ और सुखी हो। परन्तु हम कुछ ऐसे समाज का निर्माण कर चुके हैं जहाँ—

घरती का जो सीना चीरे, आखिर मुह की खाय।

जल की खातिर खून बहाए, लेकिन खाक न पाय।

सब की भोली भरने वाला, और दामन फैलाय,

हरे भरे खेतों का आका, और फाँको मर जाय।

किसान को बीज के लिए, उत्पादन बेचने के लिए, कपड़ा तथा अन्य आवश्यकता की वस्तुएँ खरीदने के लिए, विवाह तथा मरण सम्बन्धी खर्च के लिए, ऋण लेने के लिए समाज के किसी और अंग का मुह देखना पड़ता। उसे ऋण मिलता परन्तु ऋण उसका सहायक न होकर शोषक तथा ध्वंसक बन जाता। और किसान के सामने विवशता, निर्धनता, बीमारी, अकाल, निरक्षरता आदि का समुद्र ही डुबकिया खा-खाकर मरने के लिए रह जाता। इसी समस्या पर अधिक व्यावहारिकता तथा व्योरेवार विचार करने के लिए देश की स्वतंत्रता के बाद कृषि-वित्तीय उप समिति १९४५, तथा सहकारी योजना समिति १९४६ तथा ग्राम्य वित्तानुसन्धान समिति १९४६ वनी और उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। फरवरी १९५१ रजिर्व बैंक ने भारत के सहकारी कार्यकर्ताओं, रजिस्ट्रारों ग्रामीण ऋण अधीक्षण समिति तथा अर्थ शास्त्रियों का सम्मेलन बुलाया, जिस में इन सब रिपोर्टों तथा सहकारिता के भविष्य पर विचार किया गया। इस सम्मेलन ने कई सिफारिशें की, परन्तु इन सब में महत्वपूर्ण सिफारिश दीर्घ-

कालीन कार्यक्रम के लिए थी। सम्मेलन ने कहा कि वस्तु स्थिति के सम्बन्ध में आकड़ों के अभाव के कारण ऋण सम्बन्धी नीति का ठीक तौर पर निर्धारण कठिन है अतः रिजर्व बैंक ग्राम्य-ऋण समस्या का सर्वेक्षण करे।

विचार यह था कि इस अध्ययन में ग्राम्य-ऋण सम्बन्धी समस्त वर्तमान समस्याओं को ध्यान में रखा जाय और ऐसी सामग्री उपलब्ध हो जिससे ऋण सम्बन्धी नीति का निर्धारण वास्तविक परिस्थितियों पर अवलम्बित हो।

रिजर्व बैंक की केन्द्रीय परिषद् ने सुभाव स्वीकार करके एक कमेटी नियुक्त की और उसके कार्यक्रम को काफी उदार तथा सरल रखा कि—

- (१) कमेटी सर्वेक्षण की योजना बनाकर कार्य का पर्यवेक्षण करती रहेगी,
- (२) उसके फलों से निष्कर्ष निकालेगी तथा अपने सुभाव देगी। इस साकेतिक कार्यक्रम का विश्लेषण रिजर्व बैंक के गवर्नर ने सरकार को लिखे गए अपने पत्र में किया है, जिसमें कहा गया था—

“इस प्रकार वह समस्याएँ, जिनसे कमेटी सम्बन्धित है तथा वह सामग्री जिसके आधार पर उनकी पूर्ति की जा सकेगी, केवल आकड़ों से सम्बन्धित ही नहीं है बल्कि वह आर्थिक तथा प्रशासनिक भी है।” और यह रिजर्व बैंक ने ससद् की मांगों (जिनमें रिजर्व बैंक द्वारा इन समस्याओं के सम्बन्ध में अधिक रचनात्मक नीति का अवलम्बन वांछित था) के उत्तर में, ग्राम्य-ऋण समस्या की नीति तथा कार्यक्रम में नूतनीकरण से उत्पन्न हुई हैं। इसलिए रिजर्व बैंक द्वारा जो कार्यक्रम बनाया गया है वह त्रिविध है। प्रथम, वह पण जो लम्बे काल के प्रोग्राम तथा सगठन की प्रतीक्षा किए बिना उठाए जा सकते हैं, द्वितीय वह जिनके लिए लम्बे काल के कार्यक्रम की प्रतीक्षा की आवश्यकता तो नहीं परन्तु जिनकी निर्भरता सगठन-सम्बन्धी विकास तथा सुधार पर अवलम्बित है, जैसे उच्चस्तरीय बैंक का सगठन, जहाँ वह नहीं है। कुछेक राज्यों में प्रारम्भिक तथा माध्यमिक ऋण-सगठन का पुष्टिकरण तथा सहकारी विभाग तथा सहकारी संस्थाओं के कर्मचारियों का प्रशिक्षण। तृतीय प्रश्न है ग्राम्य-ऋण के सम्बन्ध में दीर्घकालीन नीति। इसका भीधा सम्बन्ध उपरिलिखित दो पणों से है। निर्देशन समिति का काम केवल इतना ही है कि ऐसी सामग्री का भण्डार करे जिसमें भविष्य के लिए नीति निर्धारण सुगम हो। मैंने एक छोटी-सी कमेटी का निर्माण

विचार में रखा है, ताकि प्रशासनिक तथा विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन सुलभ हो। यह भी प्रावधान रखा है कि रिजर्व बैंक के तन्त्र, उसके अनुसन्धान-विभाग तथा स्थायी मन्त्रणा समिति से सम्बन्ध स्थापित रहे जिसमें कि निर्देशन समिति के सदस्य भी शामिल हैं। तदनुसार कमेटी के उद्देश्य पर्याप्त मात्रा में उदार रखे गए हैं जैसा कि था भी जरूरी, और इसे केवल आकड़े सम्बन्धी अनुसन्धान का साधन नहीं रखा गया।”

इस कमेटी ने एक प्रश्नावली तैयार की जिसके उत्तर प्राप्त हुए तथा देश के विभिन्न प्रतिनिधि क्षेत्रों में विशेष अनुसन्धान किया गया। इसके लिए देश को निम्न १३ क्षेत्रों में विभक्त किया गया—

सं०	नाम	क्षेत्र
१	असम-बंगाल	त्रिपुरा, असम तथा साथ के जिले, बंगाल के—लखीमपुर, कचार, त्रिपुरा तथा जलपाइगुडी।
२	बिहार-बंगाल	बिहार तथा साथ के बंगाल तथा दक्षिणी उत्तर-प्रदेश के जिले—मालदा, बर्दवान, मिदनापुर, भागलपुर, मुधेर, हजारी बाग, पालामऊ तथा मिर्जापुर।
३	पूर्वी उत्तर-प्रदेश	पूर्वी उत्तर-प्रदेश के जिले—बलिया, देवरिया, जौनपुर, सुलतानपुर तथा सीतापुर।
४	पश्चिमी उत्तर-प्रदेश	पश्चिमी उत्तर-प्रदेश के जिले—कानपुर, हमीरपुर, शाहजहापुर, आगरा, अलीगढ़, नैनीताल तथा मेरठ।
५	पंजाब—पेप्सू	पंजाब, पेप्सू, हिमाचल प्रदेश—सिम्रौर, होशियारपुर, जालंधर, हिसार, भटिन्डा तथा महेन्द्रगढ़।
६	राजस्थान	राजस्थान—चूरु, बाडमेर, सिरोही, जयपुर, सवाई माधोपुर तथा चिन्नीगढ़।

७. मध्य भारत मध्यभारत, विध्यप्रदेश तथा उत्तरी मध्य प्रदेश के जिले—भाबुआ, शिवपुरी, शाजापुर, भेलसा, रायसेन, सतना, रीवा तथा सोनगर ।
८. उडीसा व पूर्वी मध्य-प्रदेश उडीसा तथा पूर्वी व दक्षिणी मध्यप्रदेश के जिले—सामलपुर, पुरी, कारापट, विलासपुर, द्रुग तथा चान्दा ।
९. पश्चिमी कपास क्षेत्र मध्यप्रदेश के कपास पैदा करने वाले जिले—बम्बई, हैदराबाद तथा सौराष्ट्र । नागपुर, अकोला, सौराष्ट्र, अहमदाबाद, भडोच, पश्चिमी-खानदेश तथा परभनी ।
१०. उत्तरी-दक्खन बम्बई के दक्षिणी जिले, हैदराबाद, मद्रास, पूना, कोल्हापुर, बीजापुर, उस्मानाबाद, महबूब नगर तथा कुरनूल ।
११. दक्षिणी-दक्खन मैसूर तथा मद्रास के साथ के जिले—हसन, बगलौर, कोयम्बटूर तथा कोडापा ।
१२. पूर्वी-तटवर्ती क्षेत्र पूर्वी-तटवर्ती जिले, मद्रास व हैदराबाद के जिले, निजामाबाद, पश्चिमी गोदावरी, चिंगलपट तथा रामनाथपुरम् ।
१३. पश्चिमी-तटवर्ती क्षेत्र त्रावणकोर-कोचीन तथा पश्चिमी-तटवर्ती मद्रास व बम्बई के जिले । रत्नागिरि, मालाबार तथा क्विलोन ।

उपरिलिखित तालिका में उन जिलों के नाम भी दिये गए हैं जहाँ सर्वेक्षण किया गया ।

वस्तुतः भारत में होने वाली यह अपने विस्म की पहली जाच-पडताल थी । पडताल द्वारा जो सामग्री प्राप्त हुई उसमें कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तैयार की । इसमें नन्देह नहीं कि मैकलेगन कमेटी की रिपोर्ट के बाद यही एक ऐसी रिपोर्ट

है जिसने भारतीय सहकारी क्षेत्र में बहुत ही महत्व प्राप्त किया, और सन् १९४५ की सहकारी योजना समिति की रिपोर्ट से भी वाजी ले गई। यह भारत में पहला ही अवसर था जबकि ग्राम्य-ऋण की समस्या पर या उससे सम्बन्धित सब पहलुओं को सामने रखकर विचार किया गया। विचार एकांगी न था इसीलिए इसके प्रस्तावों की उपयोगिता भी बढ़ गई। यह रिपोर्ट दिसम्बर १९५४ में प्रकाशित हुई। इस रिपोर्ट का सक्षिप्त विवरण दिए बिना भारतीय ऋण समस्या तथा सहकारिता के विचार को परिपूर्णता प्राप्त होना कठिन है। सारी रिपोर्ट तीन भागों में विभक्त है। पहले भाग में सार है, दूसरे में रिपोर्ट और तीसरे में सामग्री। रिपोर्ट में सामाजिक, आर्थिक तथा ग्राम्य पृष्ठ-भूमि का बड़ी सहृदयता से अध्ययन किया गया है और अपने सुझाव रखे हैं। इन सब बातों का हवाला देना तो इस पुस्तक में कठिन है परन्तु अधिकृत सार का संक्षेप इस प्रकार है।

‘क’ भाग में क्रम संख्या ३ तक तो कमेटी बनने आदि का विवरण है। अंत भाग ‘ख’ से ही इस संक्षेप का प्रारंभ किया गया है—

ख—पृष्ठभूमि, उद्देश्य तथा आवश्यकताएँ

(४) भारत की ३६ करोड़ की जनसंख्या में से ३० करोड़ ग्रामों में रहते हैं, और ७० प्रतिशत का व्यवसाय कृषि या उस पर आधारित व्यवसाय है। ग्रामीण जनता का ८०% तो कृषि पर आश्रित है और शेष २०% का २/५ भाग ग्रामोद्योगों पर। इस प्रकार भारत वास्तविक तौर पर ग्रामीण भारत है और ग्राम्य-भारत के अर्थ है काश्तकार, ग्रामीण कारीगर तथा कृषि पर आश्रित मजदूर।

(५) प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि के उत्पादन पर पर्याप्त जोर दिया गया है। आगामी योजना में इसके बढ़ने की और भी अधिक सभावना है। तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या इस बात की आवश्यकता को और भी व्यक्त करती है। उपभोग के वर्तमान मान के अनुसार सन् १९५१ के ७०० लाख टन के अन्नोत्पादन को १९६१ में ८५० लाख टन तक बढ़ाना पड़ेगा। अन्न के उत्पादन में वृद्धि का कार्यक्रम इसी अनुपात से कृषि-ऋण व्यवस्था के विस्तार के बिना संभव नहीं होगा।

(६) भारत में भूमि के बड़े-बड़े टुकड़ों का स्वामित्व कम है। और सरकार की भूमि सम्बन्धी नीति से और भी कम होने की संभावना है। यह नीति सामाजिक न्याय की उपलब्धि की दृष्टि से अपनाई गई है। मध्यमवर्गीय तथा छोटे भूस्वामियों की संख्या कुल जनसंख्या के ७०% के लगभग है और कृषि-ऋण व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्नों, समस्याओं तथा नीति के निर्धारण में, इन्हीं आवश्यकताओं को ध्यान में रखना तथा उनका अध्ययन करना महत्वपूर्ण है। मध्यमवर्गीय तथा छोटे भू-स्वामी इस समय लगभग ४१% उत्पादन करते हैं। क्योंकि बड़े-बड़े भू-स्वामियों की संख्या कम होगी, उनका स्थान मध्यमवर्गीय तथा छोटे-छोटे भू-स्वामी ले लेंगे, अतः उत्पादन में इनका भाग महत्वपूर्ण होता जायगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना की समाप्ति पर काश्त की हुई भूमि का क्षेत्रफल एक करोड़ एकड़ बढ़ जायगा, परन्तु इससे खेती के अधीन नई भूमि बहुत कम होगी। नई भूमि की उपलब्धि की संभावनाएँ कम होने के कारण उत्पादन वृद्धि वर्तमान भूमि से ही प्राप्त करनी होगी और उसका ढग गहन कृषि ही होगा। इसके लिए आवश्यकता होगी अच्छे बीजों की, सिंचाई के साधनों की, सुधरे हुए उपकरणों की तथा सुधरे हुए कृषि प्रयोगों की। इन सबके लिए पर्याप्त मात्रा में धन तथा प्रयत्न की आवश्यकता होगी। इसमें से सिंचाई आदि के लिए तो कुछ सहायता शासन देगा परन्तु शेष के लिए कृषक को उत्पादन बढ़ाने तथा भूमि सुधारने के लिए ऋणरूपी सहायता को विस्तृत करना पड़ेगा। यह सहायता उस ७५० करोड़ रुपये के अतिरिक्त होगी जो वह वर्तमान प्रयत्नों को चालू करने के लिए मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन ऋण द्वारा प्रति वर्ष प्राप्त करता है।

(७) कृषकों की बहुत बड़ी संख्या अपने साधनों से हर फसल के बाद अगली फसल के आने तक अपने परिवार के लिए आवश्यक धन जुटाने में असमर्थ होती है। इस तरह उसे साधारण तौर पर गुजारा चलाने तथा उत्पादन हेतु ऋण की आवश्यकता होती है। उसे कई बार विवाह, मृत्यु तथा इस प्रकार के संस्कारों पर भी खर्च करना होता है। उसकी भूमि जितनी कम हो, उतना ही अधिक उसे अन्य बंधों पर आश्रित होना पड़ता है। बहुधा वह कृषि-सम्बन्धी श्रम को आय का साधन बनाता है। भले ही उसकी

भूमि अल्प, मध्यम अथवा कुछ अधिक हो, उसे कोई न कोई धधा अपनाना पडता है और यह काम धान कूटना, गुड बनाना, रूई तैयार करना, गोपालन तथा अन्य पशुपालन आदि हो सकते हैं। फलतः कुटीर-उद्योगों का इस क्षेत्र में बड़ा महत्व है। अतः ग्रामीण ऋण की सन्तोषजनक योजना में इन सब आवश्यकताओं का ध्यान रखना जरूरी है। समस्या को सवैधानिक दृष्टि तथा ग्राम की आर्थिक और सामाजिक पृष्ठभूमि में अध्ययन करने पर कृषकों की प्रतिभूति देने की क्षमता के समक्ष अल्पकालिक, मध्यकालिक तथा दीर्घकालिक ऋण की शैली के निर्धारण के लिए तथा कृषकों के सस्थात्मक ऋण जुटाने के लिए निम्न आवश्यकताओं की पूर्ति करनी आवश्यक है —

- क यह शासन की उन नीतियों से सम्बन्धित तथा उनके अनुकूल होना चाहिए जो विशेषतया ग्रामीण उत्पादन की वृद्धि के लिए निर्धारित की गई हो।
- ख वह, ऋण के व्यक्तिगत साधनों का प्रभावशाली विकल्प होना चाहिए, भले ही उसका पूरा बदल न हो।
- ग इसमें साधनों तथा भली प्रकार प्रशिक्षित कर्मचारी वर्ग का बल होना चाहिए, और वह वित्तीय, प्रशासनिक तथा पर्यवेक्षण की उन निर्वलताओं से मुक्त होनी चाहिए जो वर्तमान सहकारी ऋण का विशेष दोष है।
- घ केवल आन्तरिक तौर पर अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन ऋण को ही सम्बन्धित नहीं करना है, बल्कि क्रय-विक्रय, निर्माण तथा कृषक के अन्य आर्थिक कार्यों के साथ भी सगठित करना होगा। और इस में यह क्षमता भी होनी चाहिए कि वह सरकार तथा उन अन्य सस्थारूपी साधनों से अपने कार्य को सम्बद्ध करे, जो ग्रामीण को कृषि साधनों के विकास, उनके प्रयोगों के पर्यवेक्षण तथा हानियों से बचाने में सहायता देता हो।
- ङ उसे छोटे तथा मध्यमवर्गीय कृषकों को ऐसे ढंग की प्रतिभूति पर सहायता देने का प्रबन्ध करना चाहिए, ताकि हर कृषक उस सहायता का लाभ उठा सके। दूसरे शब्दों में इसे ऋण केवल भूमि की प्रतिभूति पर ही नहीं देना चाहिए बल्कि अन्य प्रकार की प्रतिभूति तथा आने वाली फसलों पर भी देना चाहिए।

च ऋण स्वनात्मक ढंग से उत्पादक ध्येयो तथा उत्पादन के लाभ हिन बाटना चाहिए। ऋण के प्रयोग का सही प्रकार पर्यवेक्षण करने रहना चाहिए और ऋणी की आवश्यकताओं तथा हिनो का भी सर्वदा ध्यान रखना चाहिए।

द यह सब कार्य ऐसे ढंग से होना चाहिए कि सहकारी ढंग के संगठन में ग्राम और उस संगठन का विकास हो।

(८) उन विभागों को मन में रखकर समिति ने विभिन्न ऋण के माधनों के रिकार्ड का परीक्षण किया। जागत सवधी तथा निजी माधनों को भी देखा नाहि पुरानी उपाधियों तथा भावी सम्भावनाओं को आंका जा तके।

ग—वर्तमान ऋण-माधनों का रिकार्ड

(९) नीचे लिखे गतान अनुपात उन बात के द्योतक हैं कि ऋण के प्रधान माधनों का कुल सम्बन्ध-ऋण में किनना भाग रहा है—

गहन माधन	कुल सम्बन्ध ऋण में अनुपात
१ जागत	३३%
२ सहकारी	३१%
३ व्यापारिक नालोंप (बैंक)	०.२%
४ सम्प्रदा	१४.२%
५ समिति	१५.०%
६ गहन माधन	२६.२%
७ सहकारी	४६.६%
८ व्यापारी तथा उद्योग	५.५%
९ अन्य	१.२%
योग	१००%

अन्नोत्पादन से सम्बन्धित किया जा सकता है। परन्तु सहकारी व्यापार स्वयं ही बड़ा नगण्य तथा प्रभावहीन है। सहकारी ऋण सहकारी व्यापार से अधिक विकसित है, परन्तु इसके बावजूद कृषकों की बहुत बड़ी सख्या इसके क्षेत्र से बाहर है।

देश के कई बड़े भाग अभी ऐसे हैं जहाँ सहकारिता अभी नहीं पहुँची है। उस क्षेत्र में जहाँ सहकारिता पहुँची है, वहाँ भी कृषकों की एक बड़ी सख्या इसके बाहर है। सदस्यों के लिए भी ऋण की बहुत बड़ी मात्रा सहकारिता से बाहर के साधनों से प्राप्त होती है। ऐसी परिस्थिति को, पूर्णतया नहीं तो मात्रा के दृष्टिकोण से, असफलता ही कहा जा सकता है।

(१०) सस्थात्मक ऋण जो किसी गिनती में आ सकता है वह शासन द्वारा है।

चाहे वह केन्द्रीय हो या राज्यों से सम्बन्धित, जो तकावी तथा “अधिक उत्पादन करो” की योजना के अधीन वितरित होता है। परन्तु इस ऋण की मात्रा भी सहकारिता द्वारा प्राप्त ऋण की मात्रा के लगभग बराबर ही है। तकावी के सम्बन्ध में भी कमेटी का मत यही है कि वह अपर्याप्त रही है क्योंकि—

(क) यह राशि मात्रा की कमी, बटवारे की असमानता तथा प्रतिभूति की अनुपयुक्तता के कारण अपर्याप्त रही है।

(ख) समय की असुविधा, स्वीकृति में देर तथा ऋणियों पर अन्य शर्तों के लादे जाने के कारण भी अपर्याप्त रही है तथा

(ग) सगठन की अपूर्णता व पर्यवेक्षण की ढील ने भी उसे अपर्याप्त रखा है।

शासकीय तथा सहकारी ऋण भी बड़े भूस्वामियों तक ही जा सके हैं, मध्यम-वर्गीय तथा छोटे भूस्वामियों तक नहीं पहुँच सके। न ही इनके पास पर्यवेक्षण हेतु पर्याप्त मशीनरी है, जो यह देख सके कि ऋण उत्पादन के लिए ही प्रयोग में लाया गया है।

(११) सीधे ऋण-प्रदान करने में व्यापारी बैंकों का भाग नगण्य-सा ही है। यह १% से भी कम ऋण देते रहे हैं। हा, यह ठीक है कि टेबे तौर पर तो वह साहूकारों को काफी ऋण देते रहे हैं, जो कृषकों को पहुँचता है। यह सस्थाएँ इम्पीरियल बैंक सहित बड़े-बड़े व्यापारी क्षेत्रों में केन्द्रित हैं और

अल्प-विकसित क्षेत्र अभी उपेक्षित ही है। ऐसे क्षेत्रों से ऋण प्राप्त करना कठिन ही नहीं वरन् बहुत महंगा भी है। ऐसे क्षेत्रों में सहकारी संस्थाएँ भी अल्प विकसित ही हैं।

(१२) अतः कृषक को अपनी ६४% कर्जों की आवश्यकता के लिए अन्य व्यक्तिगत साधनों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। रिश्तेदारों (सगे-सम्बन्धियों) को छोड़ उसे साहूकार, व्यापारी तथा भूस्वामी से भी ऋण लेना पड़ता है। कृषक की ७०% ऋण की मांग को साहूकार तथा व्यापारी पूरा करते हैं। इस बात पर कोई ध्यान नहीं देता कि ऋण किसलिए लिया जा रहा है। साहूकार व्याज की दर इतनी महंगी लगाता है, जितनी उससे सम्भव हो सके। व्यापारी उत्पादन पर पेशगी देता है परन्तु उसका मूल्य इतना सस्ता देता है जितना सम्भव हो सके। निर्वल आर्थिकस्थिति तथा गुजारे वाले क्षेत्रों, अर्थात् जहाँ अपनी आवश्यकताओं के अन्त के सिवा और कोई उत्पादन नहीं होता, वहाँ साहूकार का हाथ अधिक रहता है। और जहाँ रुपया कमाने के विचार से उपज अधिक होती है, वहाँ व्यापारी आ उपस्थित होता है, परन्तु प्रभुत्व साहूकार का ही रहता है।

(घ) भावी नीति का आधार

(१३) कमेटी का यह विचार है कि जो ऋण कृषक को विभिन्न साधनों से मिलता है वह न तो ठीक ढंग का होता है, न वह आवश्यकता तथा साख की कसौटी पर पूरा उतरता है, और न ही वह उचित व्यक्तियों तक पहुँचता ही है। अतः भविष्य के लिए ग्राम्य-ऋण अधिक उत्पादन के लिए ही दिया जाना चाहिए। वह दीर्घ, मध्यकालीन तथा अल्पकालीन आवश्यकताओं का पूरक होना चाहिए, इसका पर्याप्त पर्यवेक्षण होना चाहिए और यह साख वाले कृषकों को मुनासिब दर पर प्राप्त होना चाहिए।

भारतीय परिस्थिति में इसका अर्थ है ऋण का असंख्य छोटे-छोटे कृषकों तक पहुँचना, उनकी प्रतिभूति तथा ऋण-पत्रों पर उसका दिया जाना तथा उसका उपयुक्त पर्यवेक्षण, ताकि वह उचित कार्यों पर व्यय हो। इसलिए सहकारी समिति के अतिरिक्त और कोई संस्था उपयुक्त नहीं हो सकती। अधिक उत्पादन की योजना के दृष्टिकोण से प्राइवेट साहूकारों द्वारा ऋण अनुपयुक्त ही रहेगा। और

सस्थाओं द्वारा दिया गया ऋण आदि वह सहकारी सभाओं द्वारा न दिया जाय तो बड़े-बड़े भूमिपति कृषको तक ही सीमित रह जायगा। अतः कमेटी के आगे सर्व प्रथम प्रश्न यह है कि ऐसे हालात पैदा किए जाय कि सहकारिता की सफलता के लिए उचित सभावनाएँ पैदा की जाय। इसके लिए असफलता के कारणों पर विचार आवश्यक है।

(ड) सहकारी ऋण की असफलता के कारण

(१४) इसके कई कारण दिए जाते हैं परन्तु असफलता के सामूहिक चित्र को सामने रखकर यह काम नहीं किया गया। कार्य, सस्था तथा प्रशासन सबधी त्रुटियाँ, योग्य कर्मचारियों की कमी, प्रशिक्षण की न्यूनता, जनता की अशिक्षा, सड़को आदि का अभाव तथा भण्डारों व अन्य आर्थिक साधनों आदि की असुविधा, सुसंगत कारण हैं। और यह सब सामाजिक तथा आर्थिक है। इनका सम्बन्ध ग्राम्य-संगठन की मौलिक कमजोरियों के साथ है। इन कमजोरियों के कुछेक कारण यथा वर्णभेद सर्वदा रहे हैं। कुछेक कमजोरियाँ तो ऐसी हैं जो कृषि व्यवसाय में हर जगह रही हैं। इनमें विशेषता उन कमजोरियों की है जो व्यापारियों के प्रभाव, औद्योगीकरण तथा नगरों के बढ़ते जाने से पैदा हुई है। मुद्रा-प्रभावित इस अर्थ-नीति को इस प्रकार पुष्टि प्राप्त होती रही, विशेषतया वित्तीय सस्थाओं से जो इनकी सहायक रही। औपनिवेशिक शासन में परिवर्तन होते रहे। यह अधिक मात्रा में कल्याणकारी तथा लोकतंत्री होता गया और अन्ततोगत्वा देश स्वतन्त्र हो गया। परन्तु उसके अधीन पनपती हुई वित्तीय सस्थाएँ अपरिवर्तनशील रही। इनका ग्राम्य अर्थव्यवस्था, सम्बन्धों तथा हितों से व्यवहार पूर्ववत् ही रहा और शक्तिशाली औद्योगिक व्यापारी तथा वित्तीय सस्थाओं में कोई परिवर्तन नहीं आया।

(च) ग्रामीण अर्थव्यवस्था की कमजोरियाँ

(१५) ग्राम्य अर्थव्यवस्था की निर्बलताओं को दो भागों में बाटा जा सकता है

(१) आन्तरिक तथा बाह्य आन्तरिक दुर्बलताओं के अग्र सामाजिक, आर्थिक, शिक्षात्मक तथा औद्योगिक हैं। इनका सम्बन्ध शासकीय इकाई, सिचाई के साधनों तथा अन्य सुविधाओं की उपलब्धि, सहायक व्यवसायों का

अस्तित्व, उपयोग में लाई जाने वाली कृषि-विधियाँ, कृषक की उत्पादन के प्रति अभिवृत्ति, उसके वचन तथा अपव्यय के स्वभाव तथा मार्ग-प्रदर्शन की मात्रा व उससे प्राप्त लाभादि का है। बाह्य दुर्बलताओं का सम्बन्ध ग्राम्य संगठन तथा नगर की अर्थ-नीति के संघर्ष से है। हमारा वित्तीय संगठन प्रधानतया नगरीय है। इसके अग्रे बहुत से हैं—व्यापारी बैंक, अन्य बैंक सम्बन्धी संगठन, बीमा कम्पनियाँ, स्थानीय अधिकारी तथा साहूकार आदि। इन सबका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से व्यापारी अथवा केन्द्रीय बैंक से सम्बन्ध होता है। यह नगरीय व्यापारी संगठन केन्द्रीय व्यापारी तथा बैंक संगठनों से सम्बन्धित है। परन्तु इसमें से कोई सस्था ग्राम्य-अर्थ-व्यवस्था के हित में काम नहीं करती। सामूहिक तौर पर इनका बल ग्राम्य-अर्थव्यवस्था के लिए किये गए सब कामों से अधिक है।

(१६) उपरिलिखित दोनों अग्रे का आपस में सम्बन्ध है। आन्तरिक निर्वलताएँ कुछ तो ऐसी हैं जो कृषि अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत हैं। परन्तु कुछ ऐसी हैं जो भारत की परिस्थितियों में विशिष्ट हैं, जिनके कारण बाह्य साधनों—यथा बैंकों आदि से वहाँ सहायता नहीं पहुँच सकती। बाह्य साधन ऐतिहासिक तथा वंशपरम्परागत अभिवृत्तियाँ केवल ग्राम्य जनता की ऊपरी सतह तक ही पहुँच पाते हैं।

यह बाह्य उपकरण अपने बल के कारण ग्राम्य अर्थव्यवस्था को पुष्ट करने वाले सब आन्तरिक साधनों को सबल नहीं होने देते। यह व्याकर्षण अशत निर्वल साधनों के मुकाबले में सबल साधनों के होने तथा साहूकार द्वारा ग्राम में नगरीय साधनों को प्रवेश कराने से होता है। यह ग्रामों में निवास तथा सहकारी सभा व पंचायतों आदि ग्राम्य-संस्थाओं की कार्यकारिणी समितियों की सदस्यता द्वारा होता है। इस तरह इन संस्थाओं में भी शक्तियाँ प्रवल होती हैं, जो नगरों से बल तथा प्रेरणा प्राप्त करती हैं। यही तत्त्व ग्रामीण संस्थाओं में सबसे आगे रहते हैं—चाहे वह संस्थाएँ निर्वाचित हों या मनोनीत। इनको कई प्रकार के लाभ होते हैं—यथा भूमि का स्वामित्व, ऋण-प्रदान में अधिक साधनों की प्राप्ति, शिक्षा, सरकारी भाषा का ज्ञान तथा सरकारी कर्मचारियों के सम्पर्क से प्रभाव। इन्हीं बातों से गाव में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, जिससे उन्हें भला-बुरा करने का अनुचित बल प्राप्त हो जाता है। दूसरे लोगों, लेखकों, प्रकाशकों और कमेटियों

५०

आधुनिक सहकारिता

ने शिक्षात्मक तथा वर्ण-भेद-मूलक सामाजिक दुर्बलताओं की ओर पर्याप्त ध्यान दिया है। परन्तु समस्या ने जो रूप धारण कर लिया है उसका इलाज ग्राम के आन्तरिक साधनों से नहीं हो सकता, उनमें इतना बल नहीं।

(१७) इस विवरण से यह प्रकट हो जाता है कि बाह्य तथा आन्तरिक कारणों को इकट्ठा देखा जाय तो सहकारी ऋण व्यवस्था की असफलता प्रकट होती है। क्योंकि यह सस्थाएँ न तो अधिक जिम्मेदारी लेना चाहती हैं और न ही सदस्य बढ़ाना। बाह्य बैंक-सम्बन्धी तथा अन्य वित्तीय-तंत्र का मुकाबला भी इनके लिए कठिन है। स्वभावतः नगरीय वृत्ति वाले व्यक्तियों की ग्रामीणों से सहानुभूति भी कम होती है और न वे उनकी समस्याओं को समझ सकते हैं। यह बात भी सहकारिता को कमजोर करने का एक प्रधान कारण बन जाती है।

(१८) इसलिए ग्राम्य-ऋण भारत की परिस्थितियों में एक बड़ी महत्वपूर्ण समस्या बन जाती है। क्योंकि इसका केन्द्र-स्थान ग्राम है, परन्तु इसके कारण तथा प्रतिकार ढूँढने के लिए ग्रामों से बाहर जाना पड़ता है। इस मात्रा तक समस्या केवल मात्र ग्रामीण नहीं रहती। समस्या केवल ऋण पर ही सीमित नहीं रहती, क्योंकि इन आवश्यकताओं की पूर्ति के पीछे एक सामाजिक पृष्ठभूमि तथा इतिहास है, जिसका सम्बन्ध राज्य तथा उसकी वित्तीय सस्थाओं से है। इस तरह प्रश्न और भी विस्तृत हो जाता है। और इस तथ्य का भी विचार करना आवश्यक हो जाता है कि आज के युग में सत्ता तथा महत्त्व अधिकतर नगरों और राजधानियों में एकत्रित है, इसीलिए ग्राम्य-ऋण की समस्या की पूर्ति के लिए नागरिक सस्थाओं तथा अभिवृत्तियों की विवेचना आवश्यक हो जाती है।

(१९) अतः नीति का प्रथम दोहरा ध्येय यह होना चाहिए कि ग्राम्य-संगठन की निर्वलताओं को दूर किया जाय तथा बाह्य कुचक्रों का प्रतिकार जाय। इस प्रकार ग्रामीण ऋण की समस्या ग्रामों के सामाजिक पुनः संगठन में पृथक् हो जाती है। भले ही यह विचित्र लगे परन्तु ऋण की समस्या प्रधानतया ऋण-समस्या न रह कर ग्रामीण वाली साख या ऋण की समस्या बन जाती है।

पूर्व जो भी इलाज किये गए वह वस्तुतः आन्तरिक निर्वलताओं को

कम करके कमजोर का बलवान से मुकाबला कराने के रहे । उन परिस्थितियों में उनकी सफलता की कोई सम्भावना न थी । इसलिए वह प्रयत्न वचत, जीवन-सुधार आदि पर ही केन्द्रित रहे, जिनमें दो अर्थावस्थाओं के समायोजन का कोई प्रावधान न था । कमजोर और बलवान की इस लड़ाई के लिए मैदान साफ किया गया परन्तु नियम बलवान के पक्ष में थे । अतः प्रथम कार्य यह हो जाता है कि इस दशा का सुधार किया जाय, ताकि सहकारी समितियाँ ठीक ढंग से काम कर सकें । इसके बिना यह आशा करना कि ग्रामीण ढाँचा स्वयमेव ठीक हो जायगा, एक विडम्बना है । बहुदेशीय समितियों का विचार कितना ही व्यापक बनाया जाय परन्तु वह तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि अधिक बड़ी तथा सगठित समितियाँ किसी विशेष ध्येय के लिए न बनाई जाय । जीवन-सुधार का ध्येय बाद की बात होगी । भारतीय कृषि बहुधा व्यापारिक प्रक्रिया से अलग समझी जाती रही है, जिसे कई पश्चिमी देशों में जीवन का एक तरीका समझा जाता है । अतः समस्या यह बन जाती है कि इसे जीवन का एक तरीका बनाया जाय और तत्पश्चात् जीवन-सुधार के ध्येय की प्राप्ति की जाय । इसलिए ऋण का क्रय-विक्रय, निर्माण तथा अन्य सम्बन्धित कार्यों के साथ ही विचार करना पड़ेगा । यह सब बातें एक साथ चलेगी । बड़ी-बड़ी समितियाँ इसलिए आवश्यक हैं । अनुकूल परिस्थितियाँ पैदा करनी पड़ेगी और इनमें सम्मिलित होंगे—(१) वित्त, (२) वित्त का लचीलापन तथा (३) व्यापार विधि । इस विषय में सबसे आवश्यक बात यह है कि जो सामर्थ्य अथवा प्रभाव इनमें पैदा हो, वह व्यक्तिगत व्यापारी तथा अन्य व्यक्तिगत हितों के मुकाबले में अधिक प्रभावशाली होना चाहिए । सहकारी सगठन के आन्तरिक साधनों से इसकी प्राप्ति संभव नहीं ।

(छ) समाधान का साधन—राजकीय भागीदारी

(२१) कमेटी की राय है कि प्रारम्भिक दशा के मुकाबले और शक्तिशाली होने के लिए जरूरी है कि उचित और आवश्यक मात्रा में सरकार की तरफ से सहायता मिले । यह सहायता केवल प्रशासनिक ही नहीं होनी चाहिए । अभी तक राज्य की सहायता का यह तरीका रहा है कि प्रशासन की ओर ध्यान अधिक रहे और वित्तीय सहायता कम रहे । परन्तु यह पर्याप्त नहीं,

जबकि समस्या केवल मात्र ग्रामीण स्थिति के अनुसार ऋण की ही नहीं, वरन् कृषि-विकास तथा कृषि-उत्पादन के क्रय-विक्रय की भी है। मारे प्रोग्राम में प्रशासनिक तथा प्रशासनिक-संगठन को बदलने की आवश्यकता है। इसमें ग्राम्य-आत्मा तथा ग्राम्य-निदर्शन का संगठित होना वांछित है। इस प्रकार का संगठन सरकार तथा सरकार की शक्तिशाली संस्थाओं से ही प्राप्त हो सकता है। इस समय सहकारी ढांचे की नींव में एक निर्वलो का संगठन है। सरकार शिखर पर से निर्वलो के हित के लिए इसमें सम्बन्धित रहनी चाहिए। प्रभावशाली कार्यक्रम तभी बन सकता है जब एक मिरे पर सहकारी समितियों से सरकार इसलिए सवधित होती है कि ग्राम में विकास-मनोवृत्ति पैदा हो, जो सफलता के लिए परमावश्यक है।

- (२२) इस प्रकार कमेटी की सिफारिशों में एक महत्वपूर्ण मौलिक मत यह है कि सरकारी परामर्श तथा सरकारी सहायता ही नहीं, वरन् सहकारी-ऋण, क्रय-विक्रय तथा निर्माण में सरकारी हिस्सेदारी भी होनी चाहिए। चूँकि बैंकिंग के ढांचे के कार्यों का सहकारी ऋण पर विशेष प्रभाव पड़ता है, अतः सहकारी ऋण तथा भण्डारों का संस्थात्मक विकास, निर्माण और क्रय-विक्रय आदि से सजीव रूपेण सम्बन्ध है। दो और मौलिक रूप में विचारणीय विषय हैं जिनका कमेटी की सिफारिशों से गूढ़ सम्बन्ध है। वह हैं सरकार का व्यापारी बैंकों के विशिष्ट भाग से दृढ़ सम्बन्ध की स्थापना तथा राजकीय सूत्रपात द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर भण्डारों की संस्था का राजकीय हिस्सेदारी द्वारा प्रोत्साहन और निर्माण। इसके साथ ही होगा अखिल-देशीय सब स्तरों पर प्रशिक्षण हेतु व्यापक कार्यक्रम का बनाया जाना।

(ज) ग्राम्य ऋण की एकीकृत योजना

- (२३) ग्रामीण ऋण की एकीकृत योजना, जो पूर्व विश्लेषण के फलस्वरूप निकलती है, के तीन मौलिक सिद्धान्त हैं—(क) विभिन्न स्तरों पर सरकारी हिस्सेदारी, (ख) ऋण तथा अन्य आर्थिक कार्यों का समन्वय तथा (ग) ग्रामीण लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारी वर्ग।

ऋण या साख—सहकारी ग्रामीण ऋण सस्थाओं में सरकारी हिस्सेदारी, जिसमें वित्तीय हिस्सेदारी भी शामिल है ताकि यह ऋण-सस्था पुष्ट और विस्तृत होकर उत्पादन के ध्येय की पूर्ति हेतु ग्रामीण उत्पादक को उचित और आवश्यक लाभ पहुंचा सके ।

निर्माण, क्रय-विक्रय तथा भण्डार—राजकीय हिस्सेदारी, जिसमें वित्तीय हिस्सेदारी शामिल होगी, ग्रामीण उत्पादक के लाभ के लिए निर्माण तथा क्रय-विक्रय तथा भण्डारों के सहकारी संगठन में करनी आवश्यक होगी । इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय सहकारी विकास तथा भण्डार परिषद्, अखिल भारतीय भण्डार निगम तथा राज्यों की भण्डार सम्बन्धी कम्पनियां शामिल होगी, ये वित्तीय हिस्सेदारी सहित राजकीय हिस्सेदारी, सरकारी संगठन के प्रोग्राम में ग्रामीण उत्पादक के लाभ के लिए उन कार्यों में सहायक होगी जो कि उसे काश्तकार की हैसियत में अथवा कृषि मजदूर की हैसियत में अथवा शिल्पकार की कोटि में महत्वपूर्ण होते हैं । और इन कार्यों में कृषि, सिचाई, बीज, खाद-प्रबन्ध, मछली-पालन, गोपालन, दुग्ध उत्पादन आदि ग्रामोद्योग भी शामिल होंगे ।

व्यापारिक अधिकोष—देश के व्यापारी बैंकों का एकीकरण करके उसके एक निर्दिष्ट भाग में सरकार की हिस्सेदारी इसलिए रखना कि इस तरह बनी हुई साख भी जितना अधिक सम्भव हो सके, उतना ग्रामीण सहकारी बैंक के कार्य को सहायता दे । यह उन सब संभव तरीकों से इस कार्य में सहायता देगी जितने उसे प्राप्य हो । विशेष रूप से इस सहायता के ढंग ऐसे होंगे जिनसे ग्रामों के अथवा देश के उन भागों को लाभ पहुंचेगा जहाँ अब तक बैंक सबधी सुविधाएं नहीं पहुंच पाईं ।

प्रशिक्षण—इस प्रकार सरकार पर जो नया भार आ पड़ा है उसके लिए आवश्यक है कि ग्रामीण जनता के हित के लिए ऐसे लोगों को प्रशिक्षण दिया जाय जो ग्रामीण मनोवृत्ति का सम्मान करते हैं और समझते हैं ।

राजकीय हिस्सेदारी तथा राजकीय हस्तक्षेप पर प्रतिबंध—राजकीय हिस्सेदारी की मात्रा तथा ढंग का इस प्रकार निर्धारण करना होगा कि नई नीतियों के लिए उचित वातावरण पैदा हो । परन्तु इस बात का विशेष ध्यान रखा जाय कि आन्दोलन का मौलिक स्वरूप न बदले, और न सहकारी समितियों के कार्यों में राज्य का दैनिक हस्तक्षेप हो । जहां तक सहकारी ऋण तथा सहकारी

आर्थिक क्षेत्र में जो सरकारी हिस्सा हो उसकी मात्रा निर्धारित की जाय कि—
 (क) मूल की ग्रामीण सरकारी मस्थाएँ निश्चित काल में राजकीय हिस्सेदारी को सदस्यों के बड़े हुए हिस्से द्वारा प्रतिस्थापित करके पूर्णरूपेण सहकारी हो जाय, (ख) इससे ऊपर के स्तर में यह सहायता उस समय तक चलती रहे, जब जब तक कि मूल की ग्रामीण सहकारिता पर्याप्त रूप में विकसित हो कर पुष्ट नहीं होती, और जब तक उसे व्यक्ति तथा निहित स्वार्थों से मुकाबिले की आवश्यकता रहेगी तथा अन्य कई कारणों से जब तक वित्तीय तथा व्यावसायिक दृष्टि से सहायता की आवश्यकता रहे।

वित्त तथा निधियाँ—कमेटी ने यह भी प्रस्ताव किया है कि इस पुनर्संगठन के लिए तथा नियमपूर्वक वित्तीय सहायता देने के लिए कुछ कोष बनाए जाय और वे यह हैं—

(१) रिज़र्व बैंक के अधीन (क) नैशनल एग्रीकल्चरल क्रेडिट अर्थात् राष्ट्रीय कृषि ऋण निधि (दीर्घकालीन कार्यों के लिए)।

५ करोड़ रुपये वार्षिक, प्रारम्भिक ५ करोड़ की अप्रत्यावर्ती, अशदान के अतिरिक्त।

(ख) दी नैशनल एग्रीकल्चरल क्रेडिट फण्ड अर्थात्, राष्ट्रीय कृषि-ऋण स्थायीकरण कोष (१ करोड़ रुपया वार्षिक)।

(२) अन्न तथा कृषि मंत्रालय के अधीन ही नैशनल एग्रीकल्चरल क्रेडिट (रिलीफ फण्ड गारंटी) फंड अर्थात् राष्ट्रीय कृषि-ऋण (प्रतिकार तथा प्रतिभूति) निधि। (१ करोड़ रुपया वार्षिक)

(३) राष्ट्रीय सहकारिता विकास तथा भण्डार के अधीन—(क) दी नैशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट फंड, अर्थात् राष्ट्रीय सहकारी विकास-निधि। (ख) दी नैशनल वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट फंड अर्थात् राष्ट्रीय भण्डार विकास-निधि।

[५ करोड़ रुपये वार्षिक जो (क), (ख) में बटेगा जिसके अतिरिक्त (ख) के लिए प्रारम्भिक अप्रत्यावर्ती ५ करोड़ का अशदान होगा।]

(४) स्टेट (राजकीय) बैंक के अधीन—एकीकरण तथा विकास-निधि।

(५) हर राज्य के अधीन—(क) दी स्टेट एग्रीकल्चरल क्रेडिट (रिलीफ-
 २८) फंड तथा राज्य कृषि-ऋण (प्रतिकार तथा प्रतिभूति) निधि।

(ख) दी स्टेट कोऑपरेटिव डेवलपमेंट फंड अर्थात् राज्य सहकारी विकास निधि ।

(६) हर राज्य सहकारी बैंक अथवा केन्द्रीय सहकारी बैंको के अधीन—दी एग्रीकल्चरल क्रेडिट फंड—अर्थात् कृषि-ऋण निधि । इन निधियों में पांच राष्ट्रीय निधियां बड़े महत्व की हैं । यह प्रस्तावित किया गया है कि निधियों के लिए प्रस्तावित राशि पर ५ वर्षों के पश्चात् पुनः विचार किया जाय ।

यदि इस रिपोर्ट के सारे सुझावों को यहाँ उद्धृत किया जाय तो एक बड़ी पुस्तक बन जायगी । अतः उपरोक्त सुझावों के बहुत संक्षिप्त विवरण पर ही संतोष किया गया है । उक्त कमेटी की या एकीकृत योजना में ऋण समस्या को शेष समस्याओं से पृथक् न समझ कर योजना में उन सब कार्यों का समावेश किया गया है । प्रथम के लिए ऋण की आवश्यकता होती है, द्वितीय के द्वारा उसकी वापसी होती है और तृतीय के द्वारा भविष्य में ऋण की आवश्यकता नहीं रहती ।

रजिस्ट्रार सम्मेलन—इस रिपोर्ट के पश्चात् रजिस्ट्रारों का सम्मेलन हुआ, और उसमें रिपोर्ट की प्रायः सभी सिफारिशों का समर्थन किया गया । केन्द्रीय सरकार और उसके कृषि मंत्रालय ने भी इस ओर विशेष ध्यान दिया । लोक-सभा ने इसको कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक अधिनियम बनाए और प्रचलित करने के लिए पर्याप्त तेजी से काम किया । स्टेट बैंक बन चुका है । सभी राज्यों में बड़े सहकारी अधिकोषों—बैंकों की स्थापना हो चुकी है । लोकसभा ने राष्ट्रीय-निधि तथा भण्डार-नियमन-संस्था की स्थापना हेतु आवश्यक अधिनियम बना दिये हैं । प्रशिक्षण हेतु रिजर्व बैंक ने समितियों का स्वयमेव अथवा आर्थिक सहायता देकर पर्याप्त प्रबन्ध कर दिया है और कर रहा है । परन्तु सारी रिपोर्ट तथा इसके प्रस्तावों में दो विशेष त्रुटियाँ हैं, जिनका समाधान हुए बिना यह कार्य सफल नहीं हो सकता । प्रथम तो यह कि जो वणिज्य शताब्दियों से समाज की सेवा करता आया है, जिसकी भारत में प्राचीन धारणा यह थी कि वह समाज का केवल अमानतदार है, जिसके ऋण की मात्रा आज भी ६०% के लगभग है । क्या हम इन सब उपायों के बिना कोई और व्यवसाय दिये बिना वनियों का पूर्ण वहिष्कार करके सफल हो जायेंगे ? और क्या हम कृषक में इस तरह साहकारी मनोवृत्ति पैदा करके गरीब कृषक के लिए जौक के स्थान

पर एक भेड़िये के आगे नहीं फेंक देगे ? जो कि स्वर्गीय प्रो० वृजनारायण के कथनानुसार हड्डियों को भी चबा जाता है । गत अर्द्ध शताब्दी के अनुभव से इसका उत्तर नकरात्मक मिला है । द्वितीय त्रुटि यह है कि राजकीय हिस्सेदारों द्वारा नियंत्रण तथा हस्तक्षेप का अधिकार जिस कर्मचारी वर्ग को होगा, उसका अपना तो कोई वैयक्तिक हित उसमें न होगा, तो क्या उनमें परोपकार, सेवा तथा ग्रामीणों से सहानुभूति के भाव केवल मात्र प्रशिक्षण द्वारा पैदा किये जा सकेंगे । इतिहास तथा स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद के वर्षों का अनुभव इसके भी विरुद्ध है । इन त्रुटियों के सम्बन्ध में हमें क्या करना चाहिए । इस समाधान में मैं अपने सुभाव उपयुक्त स्थल पर पाठकों के सामने रखूंगा ।

फोर्ड फाउंडेशन और ग्राम्य ऋण—स्वतन्त्रता के पश्चात् अमरीका से हर प्रकार की सहायता मिली है और इस कार्य में सबसे प्रमुख हाथ फोर्ड फाउंडेशन का रहा है । राष्ट्रीय विस्तार योजना तथा सामुदायिक विकास योजना इसी सस्था की देन है । उसकी कार्यपद्धति की मौलिकता इस बात में है कि इस में विशेष वैज्ञानिक तथा अन्य ज्ञान का सीधा संबंध उस क्षेत्र तथा ग्रामीण या कृषक के साथ जोड़ दिया जाता है, अर्थात् जिसके लिए वह ज्ञान उपयोगी है । अतः इस सहायता के दो प्रमुख अंग हैं—एक अन्वेषण और दूसरा उससे संबंधित क्षेत्र में उसका प्रयोग । यह सामयिक ही था कि सामूहिक विकास योजनाओं को परिचालित करने के लिए, जो अमरीकन आए उनको ग्रामीण ऋण की समस्या सब से बड़ी व आवश्यक लगी । अतः इस समस्या पर फाउंडेशन ने चेस्टर सी डेविस को नियुक्त किया । इनकी रिपोर्ट भी पठनीय है और विचारणीय सामग्री तथा सुभाव प्रस्तुत करती है । इसके कुछ अंशों का संक्षेप में उद्धृत किया जाना समस्या के समझने के लिए लाभप्रद होगा । इनका कहना है कि अखिल भारतीय ग्रामीण-ऋण प्रबन्ध के लिए एक सतोषप्रद ढांचा एकदम तैयार नहीं हो सकता । यह शनै-शनै विकसित होगा और इसके परिवर्धन के लिए एक प्रभावशाली संगठित—केन्द्रीय और राज्यों के—प्रयत्न की आवश्यकता होगी ।

(१) केन्द्रीय वित्तसस्था के विकास कार्य में पहले ग्रामीण ऋण-सस्था की एक संगठित योजना बनानी चाहिए । और फिर वित्तीय सस्था का उपयुक्त ढांचा तैयार किया जाय और विकसित किया जाय ।

वाले गरीब किसानों की संख्या अधिक है। उनकी सहायता केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा ही होनी उचित है ताकि इनका वित्तीय स्तर उन्नत किया जाय।

- (६) रिजर्व बैंक तथा प्रशिक्षित कर्मचारी वर्ग की आवश्यकता के सम्बन्ध में ग्रामीण ऋण अनुसंधान समिति तथा इनके विचार समान ही हैं। परन्तु प्रशिक्षण के सम्बन्ध में इनका सुझाव है कि कर्मचारीवर्ग ग्रामों में सहकारी कार्य के संगठन की ओर विशेष ध्यान दे।

इस रिपोर्ट में सबसे अद्भुत तथा सहकारी इतिहास व पाठकों को प्रति-गामी जान पड़ने वाला सुझाव ग्रामीण साहूकार को साथ लेने का है। कहना नहीं होगा कि ग्रामीण साहूकार के शोषण द्वारा ही किसान का आर्थिक आधार जर्जरित हुआ और सहकारी पद्धति की ओर ध्यान गया, परन्तु इसका प्रधान उत्तर-दायित्व साहूकार पर न होकर सरकार के उन नये कानूनों पर भी रहा, जिन्होंने समाज से मौलिक ईमानदारी को समाप्त किया। इसमें सन्देह नहीं कि सहकारी ऋण उत्पादक व्ययों के लिए ही देना चाहिए। परन्तु किसान की आवश्यकताएँ तो और भी होती हैं। यदि उसकी सब आवश्यकताएँ सहकारी-ऋण द्वारा पूरी नहीं होती तो बेचारे किसान को साहूकार का आश्रय लेना पड़ जाता है। और साहूकार, जो कल किसान को अपना जीवन-स्रोत समझता था, आज के प्रचार से आशंकित हो उठा है और वह किसान से अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहता है।

श्री डार्लिंग का मत—यदि ५० वर्षों के प्रयत्न द्वारा भी हम सहकारी तथा सरकारी साधनों द्वारा ५% तक ही किसान की ऋण-आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके हैं, तो यह स्पष्ट है कि हमने समस्या का वास्तविकता के दृष्टिकोण से अध्ययन नहीं किया। ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति की रिपोर्ट पर इस सम्बन्ध में श्री डार्लिंग के लेख के निम्न उद्धरण पठनीय है —

“अगला प्रश्न यह उपस्थित होता है कि यदि ऋण अधिक मात्रा में प्रवाहित होने लगे तो इस बात की क्या गारंटी होगी कि वह ऋण श्रमिक को ही जायगा, या इस बात की कि अधिक धन-सम्पन्न कृषक रुपये की वापसी समयानुसार कर देगा, वह अधिक सतर्क होगा और कम लापरवाह होगा। एक अरब लोकोक्ति है कि अरब की अपनी और

समस्याएँ होती हैं और ऊट की अपनी। सरकार तथा किसान की भी ऐसी परिस्थिति रही है और अब भी ऐसी अवस्था हो सकती है। रिपोर्ट ने भारतीय कृषक के मौलिक आचार पर बहुत कम ध्यान दिया है, जो कि इतना अतिथि-भक्त, इतना धीर तथा इतना कठोर काम करने की क्षमता रखने वाला है, परन्तु जो व्यापारिक ढंग से पूर्णतया अपरिचित है, और साधारणतया अपनी परम्परागत आवश्यकता पूर्ण होने पर वह अधिक धन की लालसा नहीं रखता। वह प्रथाओं का दास है तथा धार्मिक भावनाओं के अधीन उसे पूर्णतया निरर्थक पशुओं की हत्या से और बन्दरो तथा चूहों से फसल बचाने तक की भी मनाही है।

क्या यह सब बातें सरकारी भागीदारी से तब्दील हो जायगी? नये कर्मचारियों की भरती तथा उनके प्रशिक्षण से बहुत-सी आगाएँ रखी जा रही हैं। परन्तु बड़ी मात्रा में कर्मचारी वर्ग की वृद्धि से क्या यह कठिन नहीं होगा कि हम चाहे कितने ही उत्कृष्ट कर्मचारी न हों, उन्हें अफसर बनने से बचाया जाय?

कमेटी ने अधिक ऋण देने के लिए कम से कम कागजी तौर पर, एक मजबूत बात तैयार की है परन्तु मैं प्रोफ़ेसर कारवर के इस निष्कर्ष को नहीं भूल सकता, “किसान जो कि ठीक हिसाब नहीं रख सकता (और भारत में भला कितने ऐसा करते हैं?) और जिन्हें मूल्यों के सम्बन्ध में कोई विशेष धारणा नहीं है, को ऋण से प्लेग की तरह बचना चाहिए।” परन्तु यह योजना के युग से पूर्व लिखा गया था, और कठिनाई यह है कि एक योजना से दूसरी योजना की आवश्यकता पैदा होती है और इसी कारण वर्तमान योजना में सब से अधिक। परन्तु जो भी विचार कोई इस सम्बन्ध में रखे, कमेटी इस महत्वपूर्ण रिपोर्ट के लिए बधाई की पात्र है और यह उन सब देशों को ध्यान देने योग्य है जो बढ़ती हुई जनसंख्या के विचार से उत्पादन की वृद्धि के लिए प्रयत्नशील हैं।”

समस्या का निष्कर्ष—सहकारिता के आगे ऋण-पक्ष में जो समस्या है उसको यदि सूनबद्ध किया जाय तो उसके द्येय इस प्रकार कहे जा सकते हैं—

(१) किसान बचत सीखे।

(२) उमें उत्पादक प्रयोजनों तथा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऋण उपलब्ध हो।

(३) ऋण पर व्याज के दर उचित हों।

(४) ऋण लौटाया जाय ।

(५) शनै-शनै किसान ऋण-मुक्ति की ओर अग्रसर हो ।

हम देख चुके हैं कि ५५ वर्ष के परिश्रम के पश्चात् सहकारी समितिया तथा सरकार मिलकर ६८% मात्रा में किसान की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके हैं, और बनिया अब तक भी ६६१% ऋण उन्हें देता है। इस असफलता का कारण है मानव की स्वाभाविक वृत्तियों को समझने तथा उनका आदर करने से इन्कार। श्री चेस्टर सी डेविस ने इसी दृष्टिकोण की ओर ध्यान देकर साहूकार का प्रयोग करने तथा ऋण के दर उपयुक्त रखने, और बहुत न घटाने की सलाह दी है। श्री डार्लिंग महोदय ने भी इसी ओर संकेत किया है जब कि वह कहते हैं कि 'अरब की समस्या अपनी है और ऊट की अपनी।' ग्रामीण ऋण-मवर्क्षण समिति ने भी संगठित सहकारी पद्धति का सुझाव देकर समस्या के एक महत्वपूर्ण पक्ष को पकड़ने का प्रयत्न किया है।

सहकारी समितियों के इस पक्ष में असफलता के सम्बन्ध में श्री लोवो प्रभु ने लिखा था कि जब वह जिला गोरखपुर (यू० पी०) में थे तो उन्होंने देखा कि समितिया प्रथम श्रेणी दर्जे से शुरू होती हैं। हर वर्ष उनका दर्जा गिरता जाता है और ६-७ वर्ष में उनको समाप्त करना पड़ता है। इसलिए उन्होंने सुझाया कि हर सहकारी समिति का एक केन्द्रीय आधार होना चाहिए और उसे केवल ऋण कार्य पर ही आश्रित नहीं रहना चाहिए। इसी क्रम पर कइयो ने भण्डार आदि का कार्य अपनाया परन्तु वह भी कंट्रोल के कारण ही पनपा, अन्यथा नहीं। किसान की इस समिति का मौलिक आधार भी जब तक कृषि न होगा वह पनपेगी नहीं। लेखक ने हिमाचल प्रदेश में हर समिति के लिए कृषि-क्षेत्र का मौलिक आधार बनाने का यत्न किया, परन्तु समयाभाव से इस प्रयोग का परीक्षण न हो सका। समस्या के इस पक्ष पर उपयुक्त स्थल पर विचार करेंगे। यहाँ पर ऋण-सम्बन्धी प्रश्न पर ही विचार करना ठीक है। इस सम्बन्ध में श्री चेस्टर सी डेविस की मन्त्रणा बड़ी व्यावहारिक मालूम देती है, क्योंकि ग्रामीण बनिया व साहूकार अभी तक किसान के विश्वास का पात्र बना हुआ है। वह श्री डार्लिंग महोदय द्वारा संकेतित कृषक की आवश्यकताओं को पूरी करता है। उससे ऋण प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती। बनिया अपनी दूकानदारी, किसान को ऋण दिए बिना चला नहीं सकता, और बनिये

के लिए और कोई व्यवसाय भी सहज प्राप्य नहीं, जो वह अपने वर्तमान व्यवसाय को छोड़कर अपनाए।

ऐसी परिस्थिति में यदि साहूकार को सहकारी परिवार में शामिल करके हम अपना ध्येय प्राप्त कर सकें तो कोई अनुचित बात नहीं। हम यह एक भ्रान्त-धारणा कर बैठे हैं कि साहूकार व बनिये को रचनात्मक वृत्ति की ओर आकर्षित नहीं किया जा सकता। मानव स्वभावतः दुष्ट नहीं है। समुचित वातावरण पैदा करके उसकी दैवी प्रकृति को जागृत किया जा सकता है और उसे समाज-सेवी बनाया जा सकता है। क्या यह ठीक नहीं कि हमने अवधि का कानून बनाकर व्याज-दर-व्याज की प्रथा जारी की और प्राचीन क्रम को गवाया? यही वातावरण और परम्पराएँ यदि बदल जाय तो बनिया हमारा वास्तविक कल्याणकारी बैंकर बन सकता है। इसलिए उपयुक्त होगा कि ऋण के आदान-प्रदान के कार्य को इस प्रकार आयोजित किया जाय कि—

- (क) सहकारी समिति के क्षेत्र में बसने वाले समस्त बनियो व साहूकारों को समिति का सदस्य बनाया जाय।
- (ख) समिति यह निश्चय करे कि कोई भी सदस्य ऋण का आदान-प्रदान सभा से अनुमति-पत्र प्राप्त किये बिना न कर सके, और उसमें लिखी शर्तों का पालन करे।
- (ग) कोई भी लाइसेंस-प्राप्त समिति की अनुमति बिना तथा समिति द्वारा निर्धारित प्रयोजनों के अतिरिक्त ऋण न दे सके।
- (घ) व्याज के दर तथा किस्त की मात्रा भी समिति निर्धारित करे।
- (ङ) ऋण के लिए यदि रुपया बनिये की महत्तम ऋण सीमा के अन्दर समिति दे तो बनिया १% प्राप्त करे और जब रुपया बनिये का हो तो सभा उससे १% प्राप्त करे।

यह मोटे-मोटे सुझाव हैं। इन्हें परिष्कृत तथा परिमार्जित किया जाय तो यह अल्पज्ञान में नभव हो सकेगा कि ८०% किसानों का ऋण सहकारी समितियों द्वारा तथा सहकारिता के उद्देश्यों के अनुरार प्रवाहित होने लगे। और इसलिए कि किसान ऋण, उत्पादक, कृषि के लिए लाभप्रद, अधिक ऋण लेने के स्वभाव की समाप्ति तथा वृद्धि के स्वभाव की क्रियात्मक प्रोत्साहन देने के लिए ही प्राप्त कर सके। यह आवश्यक है कि सारा ऋण सहकारिता की

मध्यस्थता द्वारा ही दिया जाय और ऋण एक भयावनी तथा हानिकर वस्तु के स्थान पर सामाजिकता की पुष्टि में सहायक हो। इसका कही और किसी स्तर पर भी दुरुपयोग न हो सके। मूलतः ऋण तो उस सामाजिक पारस्परिक सहायता का प्रतीक है, जहाँ सहानुभूति के भावों से अभिप्रेरित होकर एक मानव दूसरे को आर्थिक पतन से बचाने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार सहायता करता है। अतः इसका यह मूल ध्येय तभी पूर्ण हो सकता है, और होगा जब शत-प्रतिशत ऋण सहकारिता द्वारा ही प्रवाहित हो।

: ४ :

सहकारिता और कृषि

ससार को सभ्यता के युग में लाने वाला प्रारम्भिक व्यवसाय कृषि है। कन्द-मूल के जगत से आगे निकलकर मानव ने अन्नोत्पादन का कार्य जब प्रारम्भ किया तभी मानव जगत में उन्नति के एक नये इतिहास का श्रीगणेश हुआ। इस आरम्भिक-व्यवसाय में कतिपय विशेषताएँ हैं, जिनको ध्यान में रखे बिना कृषक की समस्याओं पर सफलतापूर्वक विचार नहीं किया जा सकता। कृषि एक ऐसा कार्य है, जहाँ—

- (१) कृषक को प्रकृति पर आश्रित रहना पड़ता है।
- (२) कृषक को कभी-भी किसी अनुपात से उपज प्राप्त नहीं होती।
- (३) शेष जितने भी व्यवसाय करने वाले हैं, उनका मूल आधार यही व्यवसाय है क्योंकि शरीर-रक्षा के साधन यही जुटाता है।
- (४) क्योंकि हरेक मनुष्य के जीवन का आधार अन्न है, अतः हरेक चाहता है कि अन्न के भाव सस्ते रहे, जिससे प्राकृतिक तौर पर कृषक घाटे में रहता है।
- (५) अन्नोत्पादन हमेशा घाटे का काम होता है और इसी तरह उपरोक्त कारणों से कृषक ने हिसाब रखना छोड़ रखा है अथवा उसकी प्रवृत्ति ही नहीं।
- (६) कृषि रचनात्मक व्यवसाय होने के कारण उत्पादक को पौधों के सृजन व

परिवर्धन में आनन्द मिलता है। ज्यों ही उनमें हिसाब की वृत्ति आ जायगी, वह अन्न के स्थान पर भाग, अफीम आदि के अधिक लाभप्रद उत्पादन को अपनायगा।

(७) कृषि में उपज के वितरण से कृषक प्रायः एक सेवा का-सा आनन्द अनुभव करता है।

(८) कृषि में काम व्यक्ति का नहीं वरन् समुदाय का होता है। अतः त्याग-युक्त स्नेह की भावना-जनित सहकार्य की भावना इस व्यवसाय के मूल में स्वयमेव निहित होती है।

इन मौलिक धारणाओं को ध्यान में रखकर ही कृषि तथा सहकारिता के सम्बन्धों तथा कृषि में सहकार्य की चेष्टा आगामी पन्नों में की जा रही है। 'यह तो सर्वविदित ही है कि ससार में कृषि पर निर्भरता रखने वालों की एक बहुत बड़ी संख्या है। भारत में तो ७०% लोग गावों में बसते हैं। इन सबका प्रधान व्यवसाय कृषि ही है। क्योंकि गावों में जो और व्यक्ति भी काम करते हैं वे सब भी कृषि पर ही आश्रित होते हैं।

भारत के विकास व उन्नति के अर्थ हैं—भारत के ग्रामीणों का विकास तथा उन्नति। और भारत के ग्रामीणों की उन्नति का प्रधानतया अर्थ है, कृषकों और कृषि की उन्नति, जिसके लिए जहाँ उन्नत कृषि के उपायों, अच्छी खाद, विकसित बीजों, क्षेत्र-एकीकरण, बटवन्दी आदि की आवश्यकता है। वहाँ सब से अधिक आवश्यकता है एक ऐसे संगठन की जिससे कृषक-समुदाय पुष्ट और विकसित होकर अपनी बेहतरी के लिए काम कर सके। यह सर्व सम्मत मत है कि सहकारी पद्धति ही इसके लिए परमोपयोगी साधन है।

भारतीय सहकारिता के इतिहास में होशियारपुर(ऊना) के पजौर नामक ग्राम की एक सहकारी सभा का वर्णन एक अन्य पुस्तक में किया जा चुका है। भैंयाचारी ग्राम, शामिलात साभा प्रबंध, लगान की साभी जिम्मेदारी, ऋणों का साभा उत्तर-दायित्व आदि उस समूचे ग्राम की सहकारी सभा की प्रधान विशेषताएँ थीं। और यह क्रम था भी भारतीय परिस्थितियों के पूर्णतया अनुकूल। परन्तु इसका रुढ़िवादी सहकारी विभाग ने ध्यान न दिया और आज भी नहीं दिया जा रहा। हालांकि आचार्य विनोबा का भूमिदान और ग्रामदान इसी विचित्र कार्य-पद्धति की ओर सकेत है। शासन-निरपेक्षता का सिद्धान्त आर्थिक क्षेत्र में सहकारिता

द्वारा और राजनीतिक क्षेत्र में पचायती द्वारा ही निष्पन्न हो सकता है।

कृषि क्षेत्र में जहाँ ऋण-पक्ष को पुष्ट करने के लिए काम करना पड़ता है, और जिसके लिए सहकारिता के भाग का पूर्व-पृष्ठों में वर्णन है, वहाँ इस क्षेत्र के और भी पक्ष हैं जिनमें सहकारिता ने सेवा की है। खेती की सक्षित समस्याएँ इस प्रकार हैं —

क बहुत से किसान कृषि का कार्य नहीं करते हैं परन्तु उनकी अपनी भूमि नहीं होती।

ख. कुछ तो बड़े-बड़े जमींदार हैं और कइयों के पास भूमि के बहुत छोटे-छोटे टुकड़े हैं।

ग भूमि आमतौर पर बटी तथा बिखरी हुई होती है, जिसमें एकीकृत कृषि-कार्य नहीं हो सकता।

घ किसानों को अच्छे बीज प्राप्त करने की सुविधा नहीं है, आर्थिक निर्बलता के कारण वह छाटा हुआ हुआ उत्तम बीज रख नहीं सकते और बनिये या बड़े जमींदार से वह जो बीज लेते हैं वह मिश्रित तथा घटिया होता है।

ङ सुधरे हुए कृषि-उपकरण उन्हें आर्थिक अमुविधा के कारण प्राप्त नहीं होते।

च पशुवश के विकास तथा दुग्धादि के विक्रय का समुचित प्रबंध नहीं है।

छ भूमि के छोटे-छोटे टुकड़े होने के कारण वह नई मशीनें आदि प्रयोग में नहीं ला सकते।

ज सिचाई में कठिनाई होती है, जो वह व्यक्तिगत रूप से हल नहीं कर पाते।

झ. कृषि की उपज के उन्हें अच्छे दाम नहीं मिलते क्योंकि वह उन्हें अपनी मजबूरी के कारण दूकानदार को उसके भावों पर बेचनी पड़ती है और वह उसे अच्छे भाव की प्रतीक्षा में जमा नहीं रख सकते।

ञ. अच्छे गोदाम या भण्डार न होने के कारण अन्न का बहुत नुकसान होता है।

ट रसायनिक खाद आदि का क्रय उनकी सामर्थ्य के बाहर होता है।

ठ. उन्हें कृषि के नए सुधरे हुए तथा वैज्ञानिक तरीकों का परिचय नहीं होता आदि।

इन समस्याओं के हल करने के लिए आमतौर पर निम्न प्रकार की समितियाँ बनाई जाती हैं—

उन्नत कृषि सहकारी समिति—इस प्रकार की सहकारी समिति में सदस्यों की भूमि पृथक्-पृथक् होती है। वह काश्त भी अलहदा-अलहदा करते हैं परन्तु वह आपस में इस बात का समझौता करते हैं कि सहकारी समिति द्वारा बनाई गई योजना के अनुसार कृषि-कार्य करेंगे। समिति साम्प्रदायिक पर अच्छे बीज, खाद तथा सुधरे हुए कृषि-उपकरण प्राप्त करने का प्रबन्ध करती है। इसके साथ-साथ यह समिति सहायक व्यवसाय ग्रामोद्योगादि के लिए ऋण प्रदान कर सकती है। यह भूमि-सुधार बट-बन्दी तथा सिचाई आदि के कार्य भी कर सकती है। ऐसी सभा के उपनियमादि एक बहुद्देशीय सहकारी समिति जैसे होते हैं। आमतौर पर उत्तरदायित्व सीमित होता है। और शेष सब पूर्व अध्याय में वर्णित समिति के ढंग की ही होती है। उसी तरह तो यह समिति सदस्यों के लाभ हेतु ट्रैक्टर, बेलने आदि तथा भण्डारों का भी प्रबन्ध कर सकती है। परन्तु ऐसी समितियाँ साधारणतया बीज, खाद तथा छोटे उपकरणों का प्रबन्ध करती हैं। सिचाई के लिए बहुधा एक ही ध्येय वाली समितियाँ बनाली जाती हैं। भण्डारों का तो अब एक पृथक् विषय बन गया है। इसी तरह कृषकों की उपज के विक्रय तथा उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति आदि का प्रबन्ध भी पृथक् प्रकार की समितियाँ किया करती थीं। अब बहुद्देशीय समितियों का प्रचलन हो रहा है। सिचाई के लिए भी कई बार कृषक इकट्ठे होकर कुआँ आदि बनाने के लिए समिति बना लेते हैं। ऐसी समितियों में सदस्यों का उत्तरदायित्व भाग-मूल्य से कुछ गुना रहता है। सदस्य योजना में स्वयं भी काम करते हैं। सरकार से भी सहायता मिल जाती है। समितियाँ सिचाई के साधन जुटाकर सिचाई शुल्क लगाकर शनैः-शनैः धन जुटाती हैं, जो ऋण लौटाने में सहायक होता है। ऐसी समितियों की सफलता कम ही हो पाती है। यह समितियाँ भी उन्नत कृषि सहकारी समिति की श्रेणी में पड़ती हैं।

संयुक्त कृषि सहकारी समिति—इस प्रकार की सहकारी समिति में भूमि का स्वामित्व तो व्यक्तिगत सदस्यों का ही रहता है परन्तु कृषि के लिए समिति के सब सदस्यों की भूमि को एक इकाई मान लिया जाता है। इस तरह खेतों का कृषि के लिए एकीकरण हो जाता है। कृषि करने वालों को मजदूरी दी जाती

है। सारे सदस्यों की भूमि पर इस तरह सयुक्त प्रणाली से कार्य होता है। और अन्त में भूमि-स्वामित्व के अनुपात से लाभ का एक निश्चित भाग विभाजित होता है। जो उपज होती है उसका विन्य भी सहकारी पद्धति के अनुसार सांकेतिक पर किया जाता है और लाभ का अधिक भाग श्रम के अनुसार उपनियमाधीन बांट लिया जाता है। इसमें सन्देह नहीं कि लाभ अर्जित भूमि तथा श्रम के मूल्य के १०% से अधिक नहीं दिया जा सकता। शेष अन्य कोषों में बांट दिया जाता है। सदस्यता इच्छानुसार होती है परन्तु योजना प्रबन्धक समिति बनाती है।

सहकारी काश्तकारी समिति—इस प्रकार की सहकारी समिति में भूमि मूल्य अथवा ठेके पर प्राप्त की जाती है। उनको उचित टुकड़ों में विभक्त करके वह टुकड़े काश्त के लिए सदस्यों में बांट दिए जाते हैं। प्रारम्भ में यह वार्षिक लगान देते हैं परन्तु प्रबन्धक-समिति द्वारा बनाई गई योजना के अनुसार कृषि-कार्य करना पड़ता है, जैसा कि उपरिलिखित प्रकार की सहकारी समिति में। इस प्रकार की सहकारी समिति में लाभ का विभाजन सदस्यों द्वारा दिए जाने वाले लगान के अनुपात से होता है।

सामूहिक कृषि सहकारी समिति—इसमें सदस्यता ऐच्छिक होती है। प्रबन्धक समिति लोकतंत्री सिद्धान्तों के अनुसार निर्वाचित होती है—और लाभ का सदस्यों के श्रम-मूल्य के अनुपात से बांट दिया जाता है।

इस शैली में कृषि सामूहिक होती है और सारे कार्य भी सामूहिक होते हैं। इस प्रकार की समिति में केवल भूमि ही सामूहिक स्वामित्व में नहीं होती बल्कि उत्पादन के साधन भी समिति के सामूहिक स्वामित्व में होते हैं। सदस्य केवल श्रमिक रूप से कार्य करते हैं। व्यक्तिगत स्वामित्व के सिद्धान्त को पूर्णरूपेण हटा दिया गया है। रूस की सामूहिक कृषि और इस प्रणाली में केवल इतना भेद है कि यहाँ नीति तथा योजना पर नियंत्रण समिति का होता है और रूस में सरकार का।

कृषि में सहकारिता का उपयोग एक तो सरल और सीधा है दूसरा सहायक है। कृषि से सीधा सम्बन्ध रखने वाले कार्यों में सहकारिता का किस प्रकार उपयोग हो सकता है? इस प्रश्न पर विचार उपरिलिखित पक्तियों में किया गया है। भारत में काफी प्रयत्न इस ओर किया गया है। बम्बई में कैप्टन मोहार्डट

१९४७ में इस समस्या के अध्ययन के लिए नियुक्त हुए थे। उनकी सिफारिशों के अनुसार १९४९ में ११२ सहकारी कृषि समितियाँ बनाने की योजना बनी। इन समितियों को निम्न सुविधाएँ देने का भी निश्चय हुआ—

- (१) प्रशिक्षित कृषि-स्नातकों द्वारा निःशुल्क सलाह या परामर्श,
- (२) एक वर्ष के लिए लगान की माफी,
- (३) बीज, खाद तथा उपकरणों के लिए निम्न प्रकार से आर्थिक सहायता—

प्रथम वर्ष अधिकतम	१५००) रु०
द्वितीय वर्ष "	७५०) रु०
तृतीय वर्ष अधिकतम	७५०) रु०
- (४) भारी तथा मूल्यवान् यंत्र खरीदने के लिए दीर्घकालीन सस्ते दर पर ऋण, जो कि पिछड़े हुए क्षेत्र में भाग-धन के रूप में प्रयुक्त हो,
- (५) गोदान बनाने और पशुओं की हिफाजत के लिए भवन निर्माण तथा बजर भूमि को पुनः कृषि योग्य बनाने के लिए ऋण।

इसलिए बम्बई के सहकारी अधिनियम में भी सुधार करके यह कानून बनाया गया कि गाँव के जब ६६% परिवार जिनके पास ७५% भूमि हो सहकारी कृषि करने को तैयार हो जाय, तो शेष को इसमें सम्मिलित होना अनिवार्य होगा। अन्य सुविधाएँ भी अधिनियम में शामिल की गईं। अब इसी आधार पर अन्य राज्यों ने भी अधिनियम सन्निहित कर लिए हैं। सन् १९४९-५० में बम्बई में ७९ ऐसी समितियाँ बनीं जिनके २६६८ सदस्य थे और जिनके पास ११९५० एकड़ भूमि थी। इनमें ३० संयुक्त कृषि और १९ काश्तकारी सहकारी समितियाँ तथा ३० सामूहिक कृषि समितियाँ थीं।

मद्रास में छोटी-छोटी काश्तकारी सहकारी समितियों का चलन है जिनके पास ३ से ५ एकड़ तक भूमि होती है। यह सदस्यों की अन्य आवश्यकताएँ भी पूरी करती है। सरकार भी इन्हें दयासम्भव सहायता देती है। उत्तरप्रदेश में गंगा-खादर व नैनीताल में नई भूमि पर सहकारी ढंग से काम हुआ है।

कृषि में सहकारिता का विषय इतना विशद है कि यदि ससार में इसके प्रचलन का संक्षिप्त चित्र भी देना हो तो एक स्वतंत्र पुस्तक चाहिए। परन्तु आज तक इस दिशा में जो कुछ हुआ है, उससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सिद्धांत रूप से सहकारिता और कृषि का अद्भुत सम्बन्ध होने पर भी यह स्पष्ट है कि अभी

तक इस क्षेत्र में सहकारिता का पर्याप्त मात्रा में प्रचलन नहीं हो सका। जेप देशों की समस्या में न उलझते हुए हम यह कह सकते हैं कि भारत में इस पद्धति की सफलता अभी नहीं के बराबर है।

ग्राम तौर पर इसका प्रधान कारण यह बताया जाता है कि हमारा भूस्वामी भूमि के स्वामित्व का परित्याग करने को तैयार नहीं। और इसकी सफलता के लिए सरकारी सहायता की अधिक आवश्यकता है।

परन्तु इतना ही पर्याप्त नहीं। वस्तुतः कारण यह है कि हम भारत की परम्परा को भूलकर विदेशों का अनुकरण करके इस पद्धति को चलाना चाहते हैं। भारत में सहकारी कृषि का अनुपम प्रयोग गत शताब्दी के अन्त में पंजाब के होशियारपुर जिला के पजौर नामक ग्राम में हुआ था। इसका वर्णन 'सहकारिता का उदय और विकास' में किया गया है। उस समय सहकारिता का कोई अधिनियम नहीं बना था। और अधिनियम बनने के बाद यह समिति उक्त सफलता से नहीं चल सकी। इस समिति की विशेषताएँ यह थी—

- (१) ग्राम के सब भूस्वामी इसके सदस्य थे,
- (२) उत्तरदायित्व असीमित था,
- (३) समिति का लाभ लगान देने, कृषकों का ऋण चुकाने, उनके मकान पक्का करने तथा कुएँ आदि बनाने में लगता था।

अर्थात् जब तक सारा ग्राम एक-इकाई नहीं समझा जाता तब तक ऐसी समितियाँ सफल नहीं हो सकती। जमींदारी-उन्मूलन कानून बनाने पर यदि व्यक्तिगत स्वामित्व को प्रधानता देने के स्थान पर ग्राम को प्रधानता दी जाती और होशियारपुर के भैयाचारी ग्रामों की तरह भूमि ग्राम को मिलती, तो हर ग्राम में सहकारी कृषि का प्रचलन अधिक सुलभ तथा सफल होता। जब तक ग्राम की समस्त भूमि ग्राम की मलिकयत नहीं बनती तब तक वास्तविक सहकारी कृषि के कार्य का सफल होना दुष्कर ही दीखता है। आचार्य विनोबा भावे का भूदान-यज्ञ आन्दोलन इस कार्य को सफल बना सकता है। सहकारिता का सजीव स्वरूप ग्राम-राज्य की स्थापना से ही विकसित होगा। इस विषय पर अधिक विस्तार से अन्य स्थानों पर लिखा गया है, क्योंकि सहकारी कृषि एक सगठित सहकारी पद्धति के अधीन ही विकसित होकर पनप सकती है।

सहकारी कृषि के प्रश्न पर आज देश में एक ऐसा राजनीतिक ज्वार-भाटा

आ गया। कि इसके सम्बन्ध में कुछ अधिक लिखना आवश्यक हो गया है। इस हलचल से प्रभावित होकर इस विषय पर और प्रकाश डाला गया है ताकि भ्रम पर आधारित सहकारी कृषि के विरोध का निराकरण हो सके।

सहकारिता तथा सहकारी खेती—कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन (१९५६) के सहकारी कृषि-सम्बन्धी प्रस्ताव तथा प्रधानमंत्री के वक्तव्यों के फलस्वरूप सहकारिता तथा सहकारी खेती का प्रश्न एक प्रमुख विषय बन गया है। देश के कई एक नेताओं तथा विचारकों ने इस पर विभिन्न मत प्रकट किये हैं। राजा जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि भूमि पत्नी की तरह है। वह सांभाली का विषय नहीं बनाई जा सकती। कुछेक अर्थ-शास्त्रियों का कहना है कि जब गत अर्थ गताब्दी में सहकारिता सफलता का मुह नहीं देख सकी, तो कृषि में इसका प्रयोग संभवतः उत्पादन को कम कर देगा। कड़्यों ने इस ओर द्रुतगति से चलने में सावधानी करने की मन्नणा दी है। हालांकि प्रस्ताव करने वालों तथा प्रधान-मंत्री ने स्वयं इस बात का स्पष्टीकरण कर दिया है कि न वह कानून द्वारा इस पद्धति को परिचालित करना चाहते हैं और न उनकी इच्छा इस कार्य में अभावधाननापूर्ण गीघ्रता करने की है। इन बातों के होते हुए भी यह वकण्डर क्यों? यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर धैर्य पूर्ण विचार करने की आवश्यकता है।

भारत में सहकारिता की एक मौलिक परम्परा है और एक उसका वैधानिक स्वरूप है। दोनों में कुछ भेद है। परम्परागत सहकारिता की सफलता तो इति-हास सिद्ध है जैसा कि नयुक्त परिवार प्रणाली, चिट-फण्ड, अन्न-भण्डार तथा भैयाचारी आदि के उदाहरणों तक सफल संचालन से प्रकट है। और वैधानिक सहकारिता की असफलता ग्राम-नाय-सर्वेक्षण की रिपोर्ट से प्रकट है। इन सफलता तथा असफलता के क्या कारण हैं?

उसी प्रश्न के उत्तर में सहकारिता के प्रश्न पर खड़े विवाद का उत्तर निहित है परन्तु उन उत्तर पर विचार करने में पूर्व उक्त प्रस्ताव पर उत्पन्न विवाद का निक्षेप विमर्शना सामर्थ्य होगा। प्रस्ताव के आलोचकों को निम्न श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है—

(१) यह ग्रामनाय तथा पूँजीवादी, जिनको सहकारी कृषि ने अपने व्यक्तिगत हितों तथा स्वार्थों का हनन होता दिखता है।

- (२) वह सत्ता चाहने वाले राजनीतिक नेता, जिनको यह भय होता है कि सहकारी कृषि के प्रचार से वह उन सामन्तो तथा पूंजीवादियों की सहायता खो बैठेंगे जिनके हाथों में मत होते हैं।
- (३) रूढ़िवादी सहकारी कार्यकर्ता, जो सहकारिता जैसी उदात्त विचार-पद्धति को कानून की चेरी समझते हैं।
- (४) भावुकता सम्पन्न व्यक्ति।
- (५) जिन को यह भय है कि सहकारिता के प्रयोग में उत्पादन कम हो जायगा।

प्रथम श्रेणी के आलोचक छद्म रूप से दूसरों को आगे करके आलोचना करवाते हैं। उनके समाज-विरोधी स्वार्थों का हनन सहकारी कृषि से होना स्वाभाविक है। और वे हैं भी इतने होशियार कि कई बार तो समाजवादियों को भी अपने चंगुल में फसा लेते हैं। आज के युग में उन प्रतिगामी शक्तियों के प्रभाव में आकर कोई कदम उठाना समाज के लिए अहितकर ही नहीं वरन् भयानक है। उनको स्वयं भी यह समझ लेना चाहिए कि यदि वह भवितव्यता को देखने का यत्न नहीं करेंगे तो भूदान आन्दोलन से पूर्व की तेलगाना वाली परिस्थितियाँ उन्हें किसी वक्त भी घेर सकती हैं। समाज अब किसी प्रकार का शोषण सहन करने के लिए तैयार नहीं। यदि वह स्वयं न्याय-परक परिवर्तन के लिए तैयार नहीं होंगे तो प्रकृति उनको मजबूर करेगी। सहकारिता के विरुद्ध इस श्रेणी के षड्यन्त्र को भापना तथा रोकना सब अग्रगामी समाज-कल्याण-परक शक्तियों का कर्तव्य है। अब रुपये से रुपया कमाने की पद्धति के स्थान पर श्रम की श्रेष्ठता प्रतिष्ठित करनी है। अतः इस श्रेणी की आलोचना से तो सारे समाज को सतर्क रहना है।

दूसरी श्रेणी में वह लोग आते हैं जिनमें आदर्शवाद का अभाव है। नेतृत्व और मत-प्राप्ति में भेद यही है कि एक तो किसी आदर्शवाद के पथ पर जनता को चलाते हैं परन्तु दूसरे कई बार जनता की कमजोरियों तथा हीन भावनाओं को उभार कर मत प्राप्त करते हैं। यह लोग ऐसे एजेण्टों का मत-प्राप्ति हेतु पोषण करते हैं जिन्होंने शोषण के पजों में निःसहाय जनता को बांध रखा होता है। इस श्रेणी में आने वाले लोग अपनी आदर्शहीनता को छिपाने के लिए बड़ी-बड़ी आकर्षक युक्तियाँ पेश करते हैं। परन्तु यह तो अवसरवादिता है जिससे देश

एक मत रूसो का है जिसने 'सांशल काट्रेक्ट' में लिखा है कि मनुष्यों का पारस्परिक व्यवहार एक सामाजिक सविदा है जिसमें एक व्यक्ति कुछ व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करने के लिए अपने कतिपय अधिकारों का दूसरे के हित विसर्जन करता है अथवा अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करता है। यथा वासना की पूर्ति के लिए पुरुष स्त्री को कुछ अधिकार देता है। परन्तु भारत की परम्परा में सहयोग सविदा नहीं। वह कोई साक्षीदारी नहीं वरन् मानव-मानस के विकास में एक अवश्यम्भावी सोपान है। ज्योंही मानव यह समझना प्रारम्भ करता है कि सभी मानवों की मूल शक्ति जीव अथवा आत्मा एक ही है, तब इस एकता की भावना से ही प्रेम तथा स्नेह की सृष्टि होती है। स्नेह की भावना का यह एक स्वाभाविक गुण है कि एक व्यक्ति दूसरे के लिए बिना कुछ बदले में प्राप्त किए त्याग करके सुख तथा प्रसन्नता अनुभव करता है। इसी भावना के अधीन ही इस आदान-प्रदान के क्रम से सहयोग की सृष्टि होती है। आचार्य विनोबा ने भी ऐसा ही विश्लेषण किया है। स्नेह की भावना से प्रभावित होकर तथा त्याग-पूर्ण इस आदान-प्रदानपरक सहयोग से ही अन्ततोगत्वा साम्ययोग की स्थिति प्राप्ती है। इस विश्लेषण में सहयोग व साम्ययोग मानव विकास की परिस्थितियाँ हैं न कि वादों द्वारा भगडों से लाई जाने वाली हालतें। माता वच्चे से स्नेह करती है और आयु पर्यन्त वच्चे के लिए सस्नेह त्याग उसका परम प्रिय कार्य रहता है। इस मौलिक, मानव की एवता के भाव के विकसित होने से स्नेह के पावन भाव में बीज वाली सहयोग की भावना की परम्परा हमारे देश में आज से सदियों पहले जागृत हुई। हम व्यक्ति से कटुम्ब, कटुम्ब से परिवार तक पहुँचे। हम आगे बढ़ रहे थे। कौटिल्य ने लिखा है कि भूमि ग्राम की होनी चाहिए। जो ठीक-काश्त करे उसे काश्त-हेतु ग्राम के प्रबन्धक भूमि दे। जो ठीक काश्त न करे उससे ले ले। भूमि का क्रय-विक्रय पाप था। अतः हमारा परिवार विस्तृत हो रहा था। और वह समय आने वाला था जब सारे ग्राम का प्रबन्ध एक संयुक्त परिवार की तरह होता। परन्तु यह विकास बाहरी आक्रमणों से रुक गया। यहाँ तो इतना ही लिखना पर्याप्त है कि भारत की सहकारी परम्परा पश्चिमी सहकारी परम्परा से भिन्न है। अतः देखना यह है कि कौन-सी परम्परा सिद्धान्त की कसौटी पर खरी उतरती है।

पद्धति में स्टेट कंट्रोल के कारण व्यापार जनता का तथा जनता के लिए तो होता है परन्तु जनता द्वारा नहीं। केवल सहकारिता ही लोकतंत्र के सब सिद्धान्तों को अपनाती है। अतः हम कह सकते हैं कि “सहयोग या सहकारिता एक ऐसी कार्य-पद्धति है जहाँ जनता का कार्य, जनता के लिए, जनता द्वारा होता है।”

यदि सहकारिता की उपरोक्त परिभाषा हम समझ ले तो लोकतन्त्रीय पद्धति में विश्वास रखने वालों में से कौन होगा जो यह कहे कि वह कार्य-पद्धति भ्रान्त अथवा अवाञ्छनीय है ?

अब प्रश्न यह है कि सहकार का कार्य आज तक क्यों असफल रहा। एक स्पष्ट परिभाषा का अभाव, सहयोग की प्राचीन परम्परा का विरोध व समाप्ति, तथा विदेशी राज्य की ग्रामों को निर्बल रखने की नीति ही इसका कारण रहे हैं। सहकारिता सम्बन्धी अधिनियमों पर भी उक्त परिभाषा तथा परम्परा-विरोधी कारणों का प्रभाव अभी तक चला आ रहा है। अतः यह सिद्ध ही है कि सहकारिता की भावना कानून, सस्ते ऋण अथवा आर्थिक सहायता देने से जागृत नहीं हो सकती। यह तो मानव स्वभाव के मानसिक विकास की एक दशा है। और यह विकास एक वास्तविक शिक्षा द्वारा ही संभव है। इसलिए आवश्यकता इस बात हो जाती है कि सहकारिता की व्याख्या और पूर्ण शिक्षा व प्रचार का प्रबन्ध हो। कानून के दबाव तथा धन के प्रलोभन से बनने वाली सहकारी समितियाँ तो केवल भ्रममात्र होंगी और उनका असफल होना स्वाभाविक ही है।

अतः सहकारी समितियों के आयोजन में मनुष्यों के जागृत सहयोग की भावना को सक्रिय बनाना हमारा ध्येय होना चाहिए न कि किसी विशेष कार्य में उक्त पद्धति का उपयोग। अर्थात् जिस-जिस आवश्यकता-पूर्ति के लिए एक मानव समूह सहयोग करने के लिए कामना करे, उन सब कार्यों का समावेश संघठन में होना आवश्यक होगा। और वे कार्य हैं क्या, किस-किस क्षेत्र में कौन-कौन से होंगे, ग्रामों में साधारणतया क्या काम होंगे, इनको ढूँढ़ने के लिए हमें ग्रामवासियों की ओर निहारना होगा। उनकी परम्पराएँ, उनकी आवश्यकताएँ, उनकी कामनाएँ देखनी होंगी। यह कार्य वेतन भोगी कर्मचारियों से संभव नहीं। इसके लिए तो आदर्श सेवा-भावी प्रेरणा का होना आवश्यक है।

यह तो ठीक ही है कि सहकारी कृषि के प्रयोग की पूर्वावस्था होगी कृषक-

समितियों को इस्तेमाल कर लेना परन्तु उपनियमों को ऐसे बनाना कि हर नये काम के जारी करने पर बारबार उनके सशोधन की आवश्यकता न रहे ।

- ७ प्रथमावस्था में कृषक-सेवी कार्य हर सहकारी समिति के कार्यक्रम में समाविष्ट हो जाना चाहिए, जो ग्राम में कार्य करती है और उनका समावेश आवश्यकतानुसार होना जरूरी है ।
- ८ सहकारिता को कृषि की ओर आकर्षित करने के लिए सरकार की ओर से यह प्रोत्साहन मिलना चाहिए कि कृषि विभाग जितने दीजवर्धक, अथवा फलोत्पादक क्षेत्र चालू करता है, वह कृषि-विभाग की सलाह से सहकारी समितियाँ करे ।
- ९ हर सहकारी सभा को मूल केन्द्र के रूप में एक कृषि-क्षेत्र (फार्म) रखना चाहिए जो प्रबन्धक समिति के नि शुल्क सामूहिक श्रम द्वारा चले ।
- १० सहकारी समितियों को कम्पोस्ट-खाद बनाने का प्रबन्ध रखना चाहिए जो ग्रामीणों को सस्ती मिल सके ।
- ११ सहकारी समितियों के पास अन्न-भण्डार हो, जहाँ ग्रामीण उत्पादन जमा रख सके और उत्पादन के क्रय-विक्रय का प्रबन्ध हो ।
- १२ हर सहकारी समिति "अनाज गोले" का प्रबन्ध करे जहाँ से ग्रामीणों को अनाज इस गत पर मिल सके कि वह अपनी फसल पैदा होने पर $1\frac{1}{2}$ लौटा देगे ।
- १३ हर समिति के साथ एक सूचना केन्द्र हो, जो ग्रामीण कृषकों को हर प्रकार की सूचना व सलाह दे सके ।

यह सूची सकेतात्मक है । ज्योंही प्रारम्भिक सेवाओं से उत्साह, विश्वास तथा प्रेरणा प्राप्त होगी तभी दूसरी अवस्था में प्रवेश का समय आयगा और दूसरी अवस्था में उदाहरणरूपेण निम्न कार्य लेने उपयुक्त होंगे—

- १ व्यक्तिगत भूमिपतियों से काश्त के लिए भूमि लेकर उसमें वैज्ञानिक ढंग से खेती करके अधिक उत्पादन करना ।
- २ गामलात चरागाह, धार व नालों, जलाशयों, रास्तों आदि का सामूहिक प्रबन्ध सहकारी समिति द्वारा करना ।
३. हर सहकारी समिति में उसकी परिस्थितियों के अनुसार ऐसे ग्रामोद्योग

-चालू करना, जो कि कृषि से होने वाली आय को सहायता दे और काम ऐसे हो जिनके करने के लिए कृषि-व्यवसाय छोड़ना ही न पड़े ।

४ सामूहिक पशुशालाओं, पशुवशोन्नति फार्मों, दुग्धशालाओं आदि का प्रबन्ध करना ।

५ ग्रामीणों को फलों के नए पौधे प्राप्त करने आदि के विभिन्न कार्यों में सहायता देना ।

जब दूसरी अवस्था सफलता से पूरी हो जाय तो सामयिक तथा अन्य बेकारी को हटाने के लिए उद्योग चल निकलेगे । शनैः शनैः सारी ग्राम्य-भूमि की काश्तकार सहकारी समिति हो जायगी तभी सहकारी कृषि का क्रियात्मक रूप विकसित होगा ।

गोपालन

कृषि-कार्य में सहायता देने के लिए एकोद्देशीय समितियाँ बीज प्राप्त करने, उपज विक्रय करने, आढत का प्रबन्ध करने के लिए भी बनाई जाती हैं । परन्तु कृषक का जीवन है गोवश, अतः गोवश सम्बन्धी समितियों के बारे में संक्षेप से कुछ लिखना उपयुक्त समझा गया है । किसान को कृषि के लिए बैल चाहिए और बैलों के उत्पादन के लिए गोपालन आवश्यक है । साथ ही गोवश से खाद की प्राप्ति होती है और दूध तथा तज्जनित पदार्थ प्राप्त होते हैं । परन्तु एक ओर तो कमजोर और छोटे-छोटे बैल काश्त में पूरी सहायता नहीं दे सकते और इस प्रकार की गौएँ भी कम दूध देती हैं । साथ ही दुग्धादि के विक्रय का समुचित प्रबन्ध न होने के कारण कृषक घाटे में ही रहता है । ऐसी समितियाँ आमतौर पर नगरों में शुद्ध तथा सस्ता दूध प्राप्त कराने के लिए बनाई जाती हैं । ग्रामों में इनका प्रचलन कम है । नगर की दुग्ध-प्रापक सहकारी समितियाँ कृषि-कार्य में सहायक केवल इतनी मात्रा में ही हो सकती हैं कि या तो वह ग्रामीण कृषकों से दूध लेकर, उन्हें उचित दाम प्राप्त करवा सकती हैं, या वहाँ पैदा होने वाले बैल शक्तिशाली होते हैं और वह उचित दामों पर किसानों को मिल सकते हैं । इस प्रकार की एक या दो समितियों का संक्षिप्त विवरण पाठकों के लिए मनोरंजक तथा लाभप्रद होगा । यूँ तो दुग्धोत्पादन तथा दुग्धजनित पदार्थों के उत्पादन तथा विक्रय हेतु विश्व में बड़ी-बड़ी सहकारी समितियाँ हैं और डेनमार्क जैसा छोटा-सा देश तो इनके लिए विश्वविख्यात है, परन्तु भारत में इस दिशा में सफल प्रयोग थोड़े ही हुए हैं । आमतौर पर जनता को

विश्वास-सा हो गया है कि डेयरी का काम लाभप्रद होता ही नहीं। परन्तु जिन दो एक प्रयोगों का सक्षिप्त विवरण यहां दिया जा रहा है, वह इस बात के उदाहरण अवश्य है कि यह कार्य सफल तथा लाभप्रद हो सकता है। विष्वविस्थात तथा एगिया का सबसे बड़ा प्रयोग इस दिशा में जो हो रहा है वह है बम्बई की आरे मिल्क कालोनी। यह सहकारी ढग का प्रयोग नहीं बरच बम्बई नगरनिगम के अधीन चल रहा है। इस कार्य की पद्धति अवश्य ऐसी है जिसका नगरो में सहकारी ढग पर सफलता से अनुकरण किया जा सकता है। कार्यपद्धति इस प्रकार की है कि कारपोरेशन ने अपनी आधुनिक ढग की गोशालाएं तथा गोपालों के लिए निवासस्थान बनाए हैं। गौए गोपालों की होती हैं। उनको उचित तथा निश्चित किराये पर स्थान दिए जाते हैं। कारपोरेशन गौओं के लिए चारा तथा दाना आदि भी मुहैया करता है। गौओं का दुग्धदोहन कारपोरेशन वैज्ञानिक ढग से करता है और सारा दूध निश्चित दरों पर खरीद लिया जाता है। वह मशीनों द्वारा कीटाणुमुक्त किया जाकर बोतलों में बंद किया जाता है और बम्बई नगर में नागरिकों को सुभीते के स्थान पर खुले डिपुओं में बेचा जाता है। इस प्रकार सस्था की ओर से तो पशुवश उन्नति, सरक्षण, पालन, दुग्धोत्पादन तथा विक्रय आदि की सहायता मिलती है, परन्तु पशुवश पर स्वामित्व गोपालों का ही रहता है। इस तरह सस्था आकस्मिक घाटों से सुरक्षित रहती है। इस सस्था की सफल कार्यपद्धति की भूरि-भूरि प्रशंसा विदेशियों ने भी की है। वहां सारा काम मशीनों द्वारा होता है। परन्तु इस पद्धति में जो व्यक्तिगत स्वामित्व तथा सामाजिक सहयोग का अपूर्व समन्वय है वह सहकारिता की पद्धति के अनुकूल है। अतः उसका कहीं भी अनुकरण किया जा सकता है। आरे मिल्क कालोनी के विस्तार का अनुमान (रोजाना ४२०० मन दूध), तो उसको देखने से ही लग सकता है। करोड़ों रुपया खर्च हुआ है। विचित्र भवन हैं। दुग्धशोधक मशीनें, लाखों रुपयों का दूध लाखोंबन्द बोतलों में नित्यप्रति बम्बई के नागरिकों को मिलता है। और वह भी उचित दरों पर। रूस के महामना श्री खुश्चेव तथा बुलगानिन ने भी इसको जब देखा तो मुक्तकंठ से प्रशंसा की थी।

सहकारी ढग से सफल गोपालन का कार्य करने वाली अयना मिल्क मद्रास नाम की गोपालक सहकारी समिति है। यह समिति आरे मिल्क कालोनी की तरह नहीं है। आरे मिल्क कालोनी तो सरकारी तथा पूँजीवादी संगठन है, जिसमें

४० दूध देने वाली भैंसों से कम जिसके पास हो वह सप्लायर नहीं बन सकता, और बहुतों के पास तो ५०० तक पशु हैं जिसका अर्थ है ५०,०००) रु० से लेकर ५००,०००) रु० तक की पूँजी।

परन्तु उपरोक्त सहकारी समिति एक सघ है जिसका प्रारम्भ १३ सदस्य सहकारी समितियों से हुआ और पूँजी थी केवल २४२) रु०। इस समय इसकी १५१ समितियाँ सदस्य हैं और भाग-धन, जोकि सघ को दिया जा चुका है, १,८६,१८७) रु० है। यह आज तक दुग्ध-उत्पादकों की सस्था है तथा उन परिवारों की कृषि को छोड़ अन्य आय के साधन जुटाती है। कृषि प्रधान व्यवसाय के तौरपर तो चलती ही है। मद्रास राज्य सरकार ने इस सघ की पर्याप्त सहायता की है। और उसकी शक्ति तथा स्रोत के कारण सघ ४०,००,०००) रु० दूध देने वाले पशु खरीदने के लिए ऋण दे सका है।

सघ की अपनी मिल्क-बार है, दूध बेचने के डिपू है, दुग्ध-शोधक यंत्र है। मुर्गी पालन का धधा है। साइ सस्ते दामों में विक्रय करने का क्रम है। पशुओं के इलाज का प्रबन्ध है। समिति के कार्य का अनुमान इसी बात से हो सकता है कि अब यही समिति लाखों रुपये का कारोबार करती है।

स्पष्ट है कि यदि सूक्ष्म-वृक्ष से योजनापूर्वक काम किया जाय तो गोपालन सम्बन्धी सहकारी समिति की सफलता हो सकती है और यह एक बहुत ही उपयोगी सहकारी सस्था कृषि व्यवसाय को सहायता देने वाली है।

कृषि के क्षेत्र में भण्डार, विक्रय तथा उद्योग का बड़ा घनिष्ट सम्बन्ध है। परन्तु इनका विवरण स्वतन्त्र अध्यायों में किया जाना उचित होगा, क्योंकि वह कार्य पूर्ण-रूपेण कृषि-जनित नहीं, वह केवल सहायक है और सहायता के साथ-साथ उनका स्वतन्त्र अस्तित्व भी है। इस अध्याय को इन शब्दों के साथ समाप्त किया जाना उचित है—

“समस्त विश्व का जीवन-प्रदायक व्यवसाय कृषि है। कृषि को लाभ-प्रद तथा मानव-प्रिय बनाने के लिए उसका समाजीकरण आवश्यक है। कृषि का मानवीय समाजीकरण सहयोग अथवा सहकारिता द्वारा ही सम्भव है।”

: ५ :

सहकारिता और उद्योग

यह विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि उद्योग तो मानव के माथ ही पैदा हुआ। यदि उसने भोजन के लिए शिकार के व्यवसाय को अपनाया तो, पत्थर से ही सही, उसे हथियार बनाने पड़े। इनके बनाने के साथ ही उद्योग की उत्पत्ति हुई। यदि उसने कृषि आरम्भ की तो हल-कुदाल बनाने का उद्योग उसकी सहायता के लिए प्रस्तुत रहा। इस प्रकार जहाँ हर उत्पादन अथवा उदर-पूर्ति के कार्य के वास्ते उद्योग की आवश्यकता थी, वहाँ उद्योग का एक और स्वरूप शनैः शनैः विकसित हुआ। वह था उद्योग का स्वतन्त्र अस्तित्व। अर्थात् केवल उद्योग से ही जीविका के उपार्जन के साधन जुटाए जाने लगे। गाम-ग्राम में बढ़ई, मोची, कुम्हार, लुहार आदि ऐसे व्यक्ति हो गए जो केवल अपना औद्योगिक कार्य करते और इसके बदले में उनको अन्न-वस्त्रादि प्राप्त हो जाता था। यह उद्योग किसान तथा ग्रामीण को प्रिय था क्योंकि यह अन्योन्याश्रित था। और उसका सीधा तथा तात्कालिक लाभ ग्रामीण किसान को दिलाई देता था। परन्तु समय आगे बढ़ा। समाज ने परिवार से आगे बढ़कर कबीले तथा अन्त-तोगत्वा देश की रचना की। अपने देश पर न्योछावर होने की बावली भावना के वशीभूत होकर हमने मूलभूत मानवता के नाते को भूलना आरम्भ कर दिया। जो देश शक्तिशाली हो गए वह निर्बल देशों पर आधिपत्य जमाकर अपने देश के लाभ के लिए उनका शोषण करते रहे। यह शोषक नीति समस्त साम्राज्यवादी देशों का मूलमंत्र रही। परन्तु इस शोषक नीति ने इन साम्राज्यवादी देशों के विरुद्ध एक द्वेष भावना को पैदा किया। जहाँ यह सब स्वदेश प्रेम की भावना के अधीन साम्राज्यवादी देशों ने किया—उसके साथ-साथ ही एक और कारण भी था। वह यह था कि औद्योगिक क्रान्ति के फलस्वरूप बड़ी मात्रा में उत्पादन तथा बड़ी-बड़ी मशीनों के प्रयोग ने बहुत सा औद्योगिक उत्पादन कतिपय देशों में केन्द्रीभूत कर दिया, और हाथ के उद्योग की उपयोगिता जाती रही। इस प्रकार उत्पादक देशों से कच्चा माल औद्योगिक

सहकारिता और उद्योग

देशों को जाता और वहाँ से वस्तु निर्माण होकर पुनः कच्चा माल पैदा करने वाले देशों में विकता। इस बड़े पैमाने पर मशीनों द्वारा औद्योगिक कार्य ने भूमि पर काम करने वाले किसान तथा ग्रामों में काम करने वाले बढ़ई व लुहार को मशीनों से काम के लिए आकर्षित किया। उन देशों में भूमि पर काम करने वालों की संख्या में कमी होने पर वहाँ भी मशीनों की आवश्यकता पड़ी जिससे ट्रैक्टर आदि के आविष्कार हुए। यह सब तो हुआ उन देशों में जहाँ औद्योगिक क्रान्ति हुई, परन्तु कच्चा माल पैदा करने वाले देशों की हालत पतली होती गई। गाव में होने वाले उद्योग यथा चरखा, करघा, गुड निर्माण आदि के कार्य दिन-प्रति-दिन समाप्त होने लगे।

ग्रामीणों को मिल के कपड़े, बूट-जूते व चीनी खाड़ आदि ने अपनी ओर खींचा। गाव का चमार, लुहार, बढ़ई, धोबी, चित्तरे आदि या तो गाव छोड़ भागे या उन्होंने भी भूमि पर किसान की तरह कृषि-कार्य करना आरम्भ कर दिया। इस तरह एक तरफ तो भूमि पर भार बढ़ गया और दूसरी तरफ ग्राम के उद्योग-धंधे समाप्त हो गए और किसान ग्रामीण व ग्रामीण स्त्रियों के अवकाश के समय का कोई धंधा नहीं रह गया। वे कुटेव सीखने लगे और उनको आवश्यकताओं की प्राप्ति का अभाव भी खटकने लगा। उधर जो ग्रामीण कारखानों में गए वे परिवार साथ न रख सके। विरादरी तथा गाव वालों के सारकृतिक प्रभावों से वह दूर हो गए। उन्होंने कई कुटेव व दुर्व्यसन वहाँ सीख लिए। इस प्रकार जहाँ तक ग्रामीण का सम्बन्ध है वह दोनों ओर से घाटे में तथा प्रताड़ित रहा।

मशीनों के इस युग में ग्रामों के लिए उद्योग तथा ग्रामीणों के खाली समय के लिए धंधे जुटाने का कार्य दुरूह तथा दुष्कर हो गया। यह समस्या सारे विश्व में थी परन्तु भारत के लिए विशेष-रूपेण भयंकर सिद्ध हुई। यदि भारत ने जीना है तो उसके ग्राम पुष्ट होने चाहिए। ग्राम सजीव और पुष्ट तभी हो सकते हैं जब कि ग्रामों में इतना व्यवसाय हो कि ग्रामीणों को ग्राम छोड़कर जीविका-हेतु नगरों को न भागना पड़े। केवल मात्र कृषि से यह सम्पादित होना संभव नहीं था। और ग्रामोद्योगों को, वह सरकार जो अपने देश की मिला के लिए पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल चाहती थी, पनपने नहीं देती थी। इस प्रकार भारतीय स्वतन्त्रता का आन्दोलन साथ ही साथ ग्रामों के पुनरुद्धार का आन्दोलन भी बन गया। महात्मा

गांधी ने तो चर्खे और खादी को ही स्वतंत्रता आन्दोलन का मूल-मन्त्र बना दिया। चर्खा और खादी ग्रामोद्योग के प्रतीक थे। महात्मा जी के स्वतंत्रता आन्दोलन के साथ-साथ ग्रामोद्योगों के पुनरुत्थान का आन्दोलन चला, और आदरणीय श्री कुमारप्पा के अधीन ग्रामोद्योग मण्डल की स्थापना हुई। इस प्रकार जब ग्रामीणों की आर्थिक समस्याओं की ओर स्वतंत्रता प्राप्ति के आन्दोलन का विशेष ध्यान गया तो विदेशी शासन ने प्रयत्न किया कि ग्रामीण उस आन्दोलन में शामिल न हों, और स्वयं ग्रामोद्योगों के प्रोत्साहन का ढोंग रचा। परन्तु इस कार्य के लिए भी कोई ऐमा तंत्र चाहिए था जिसमें शासन पर व्यय का अधिक भार पड़े बिना चल निकलना नभव नहीं था। और फिर विदेशी शासक यह कार्य ऐसे ढंग से करना चाहते थे कि एक निश्चित पड़्यत्र के अधीन वह असफल हो और उस असफलता का उत्तरदायित्व भी भारतीयों पर ही पड़े। इसलिए उन्होंने भी सहकारिता की पद्धति का आश्रय लिया। जिस प्रकार जेप क्षेत्रों में सहकारिता का आश्रय व्यजना पूर्ण व्ययों से लिया गया था इसी प्रकार यहाँ भी किया गया और आन्दोलन सफल न हो सका। इसमें मन्देह नहीं कि ग्रामोद्योगों की सफलता की एकमात्र पद्धति सहकारिता ही है। परन्तु जब तक सहकारिता देश की मौलिक परम्पराओं के अनुकूल नहीं होती तब तक इसका किसी भी क्षेत्र में सफल होना संभव नहीं।

ग्रामोद्योग में सहकारिता ही क्यों एकमात्र सफल साधन है ? एक सीधा-सा प्रश्न है और इसका उत्तर भी सरल है। ग्रामोद्योग की निम्न विशेषताएं हैं —

- (क) यह गांवों में ही हो सकता है,
- (ख) यह कृषि तथा घर के अन्य कार्य से अवकाश के समय किया जा सकता है ;
- (ग) हर परिवार के भिन्न-भिन्न कार्य हो सकते हैं,
- (घ) उत्पादन के भिन्न अंग भिन्न स्थानों या परिवारों में होने के कारण उनके एकीकरण तथा निर्माण के लिए ऐसे सगठन की आवश्यकता है जो उत्पादकों का प्रतिनिधि होकर उनके हित में कार्य कर सके,
- (ङ) उनके विक्रय का तथा कच्चे माल की उपलब्धि के लिए भी सामूहिक प्रयत्न की आवश्यकता होती है,
- (च) समय परिवर्तन के साथ-साथ इन कामों में उन्नत उपकरणों के प्रयोग तथा

उन्नत पद्धतियों के अनुसरण हेतु प्रशिक्षण का उचित तथा सामूहिक प्रबन्ध होना आवश्यक होता है ।

उपरोक्त विशेषताओं से यह प्रकट है कि इस प्रकार के कार्यों के लिए ग्रामीणों के एक सगठन की जरूरत भी है । जब तक कोई ऐसा सगठन न हो तब तक न तो ग्रामोद्योग ग्रामीण के हित में कार्य कर सकते हैं और न ही वह इस मशीन के युग में एक नैतिक तथा आर्थिक सगठन के बिना जीवित ही रह सकता है । ग्रामोद्योग तथा सहकारिता का चोली-दामन का साथ है । और सहकारी पद्धति बिना ग्रामोद्योगों का जीवन तथा उनका पनपना असंभव ही है । मूलतः यह बात होने पर भी हमारा अनुभव यह है कि सहकारिता आज तक भी इस क्षेत्र में सफल नहीं हो सकी । इसका कारण यह है कि सहकारी पद्धति बड़ी सकीर्ण तथा मानवता के मूल स्वभाव के अनुकूल नहीं बनाई गई । गाव के बटई, मोची, चितेरा, धोबी, नाई तथा कृषक अन्योन्याश्रित होते हैं । एक का निर्वाह दूसरे के बिना नहीं हो सकता । वहां पारस्परिक स्पर्धा के स्थान पर सहयोग होता है । वहाँ मेरे हित के लिए दूसरे के अहित का भाव मन में नहीं आ सकता, क्योंकि वहां दोनों का हित साझा है । परन्तु अन्य क्षेत्रों की तरह हमने ग्राम के भिन्न-भिन्न श्रेणी के औद्योगिक कार्य-वर्ताओं की पृथक्-पृथक् समितियां बनाने की योजना बनाई । इस योजना का सफल होना प्रत्यक्षतः असंभव ही था, क्योंकि हमने अन्योन्याश्रय के भाव के विपरीत एक कृत्रिम मुकाबले की भावना को जन्म देने का प्रयत्न किया । हमने एक और भूल की । वह यह थी कि व्यक्ति तथा समिति के क्षेत्रों की सीमा निर्धारित करके उनका नामजस्य नहीं किया । हमने सहकारी कार्य पद्धति को कम्पनी की तरह व्यापारिक सगठन बनाने की चेष्टा की । वस्तुतः यह कार्य इस प्रकार होना चाहिए था कि एक ग्राम या ग्राम-समूह के लिए एक औद्योगिक सहकारी समिति होती । उसका काम व्यक्तिगत तौर पर काम करने वाले मोची, बटई, नुहार आदि सब को मददगार बनाना होता । वे सब अपने-अपने काम में उन्नति के लिए उचित सलाह और सहायता समिति से प्राप्त करते । जिन-जिन मनुष्यों को उनको आवश्यकता होती वह उन्हें समिति उचित मूल्य तथा सुविधा से प्राप्त करवाती । जो माल तैयार होता उसे विक्रय करने का प्रबन्ध समिति करती । जिस प्रकार हर ग्राम का प्रगल्भ अन्न में स्वावलम्बी तथा बुद्धि प्रचिक्र पैदा करना होना

चाहिए, उसी प्रकार इन ग्रामोद्योगों का ध्येय भी स्व.वलम्बन होना चाहिए। जो सदस्य इन उद्योगों को नए तरीकों से करना चाहते हैं उन्हें नई-नई तथा छोटी-छोटी मशीनें तथा अन्य उपकरण प्राप्त करने की सुविधाएं जुटानी चाहिए। मशीनों को मगवाना, उनका मूल्य उचित ऋस्तों में प्राप्त करना आदि-आदि इस किस्म की सुविधाएं हो सकती हैं। यदि हम ग्रामों में समितियां बनाकर सारा काम उन्हीं द्वारा ही करें और उनमें पूरे दिन के वैतनिक कर्मचारी रखें तो ग्रामोद्योगों का वास्तविक ध्येय ही नष्ट हो जाता है। क्योंकि तब वह अवकाश का व्यवसाय नहीं रह जाता। ग्रामोद्योग इसलिए नहीं बनना जहां पर उपरोक्त पद्धति को अपनाया गया—यथा स्वीडन, नार्वे, डेनमार्क आदि। भारत में इसकी असफलता में यही मूल कारण था।

कल्पना कीजिए कि हम एक ग्राम में घड़ियां बनाने का काम सहकारी ढंग पर करना चाहते हैं। और घड़ियों के विभिन्न पुर्जें बनाने की विभिन्न मशीनें हैं तो हम एक क्षेत्र के कुछ परिवारों की सहकारी समितियां बनाएंगे। हर परिवार को एक-एक प्रकार की मशीन के कार्य में प्रशिक्षण देकर पुर्जें बनाने का काम सौंप देंगे। समिति उन्हें मशीनें खरीद करने में आर्थिक तथा प्रशिक्षणात्मक सहायता देगी। समिति अपना एक केन्द्रीय वर्कशॉप बनायेगी जहां पर विभिन्न साइज के पुर्जों को खरीदकर घड़ियां जोड़ी जायगी और फिर विक्री होगी। घड़ियों के विक्रय से जो लाभ होगा वह पुनः सदस्यों में वितरित होगा। सदस्यों को दिया गया ऋण सुरक्षित रखने के लिए उनकी मशीनें बन्धक रखी जा सकती हैं। इसमें सदेह नहीं कि हर सदस्य परिवार को सहकारी समिति का भाग खरीदना पड़ेगा, परन्तु ऐसा किये बिना समिति चलेगी नहीं। ग्रामोद्योग की एक और विशेषता है कि उसका मूल्यांकन कार्य में समय लगने से नहीं, बरन् अवकाश की उपयोगिता से आका जाता है।

यदि हम ग्रामोद्योग में भी श्रम के घंटों का हिसाब लगाकर शहरी दर से उजरत निकालें तो कोई ग्रामोद्योग नहीं चल सकता। यहां तो कुछ कार्य वन में पशु चराते समय हो सकते हैं। रात को गप्पे हाकने के साथ ग्रामीण काम सकते हैं, बुन सकते हैं। सैकड़ों ऐसे कार्य हैं जो ग्राम के प्रधान व्यवसाय के साथ-साथ चल सकते हैं। लुहार, बढई आदि के प्रधान व्यवसाय के साथ अन्य कार्य वह भी कर सकते हैं। अतः वहां मूल्यांकन की शैली पृथक् होगी। इस

तरह ग्राम के लोगो की सहकारी समिति जब बन जायगी तो प्रश्न यह रह जायगा कि किसानो का इनके साथ जो मौलिक सम्बन्ध होता है उसको कायम रखने के लिए ग्राम की ऋण सम्बन्धी तथा बहुदेशीय सभा से तालमेल कैसे रखा जाय । इसका विवक्षित किसी अन्य अध्याय मे मिलेगा । परन्तु यहा पर इतना लिख देना पर्याप्त होगा कि ग्रामोद्योगो का पुनरुत्थान सहकारी ढंग के बिना नही हो सकता । और सहकारी पद्धति इस कार्य मे तब तक भारत मे पनप नही सकती जब तक कि वह इस देश की मौलिक परम्परा तथा मानव के मौलिक स्वभाव के अनुकूल नही होती । कहना नही होगा कि इस समय भारत मे जिस प्रकार की औद्योगिक समितियो का प्रचार है वह तो परतन्त्रता के समय की गलत पद्धति के अनुसार ही है और शनै-शनै वे क्षीण होकर समाप्त होती जा रही है ।

मद्रास मे प्रचलित औद्योगिक सहकारिता सबसे अधिक सफल है । मद्रास मे अम्मापेट स्थान की वुनकरो की सहकारी समिति ने उत्साहजनक तथा अनुकरणीय सफलता के लिए ख्याति प्राप्त की है । कहना नही होगा कि यह सभा तथा अन्य, जो सफल औद्योगिक सहकारी समितिया है, उन्होने उपरिलिखित पक्तियो मे वर्णित पद्धति का अनुसरण किया है । और जो ग्राम्य जीवन की मौलिक एकता को भूलकर तथा ज्वाइट स्टाक कम्पनियो का अनुसरण करके बनाई जाती है, वह सफलता का मुह नही देख सकी ।

मद्रास की औद्योगिक सहकारी समिति का सक्षिप्त विवरण पाठको के लिए लाभप्रद होगा ।

यह समिति इस समय मद्रास की बड़ी समितियो मे से एक है । यह २४ सितम्बर १९३८ को रजिस्टर्ड हुई । उस समय ५३ सदस्य तथा ११०७ रु० भाग-धन था । ३० जून १९५६ को इसकी सदस्य संख्या १५७३ हो गई और भाग-धन १,९७,६७५ रु० हो गया । सब सदस्यो के अपने-अपने करवे है । केवल २० सदस्य बिना करवे वाले है । यह समिति सफेद तथा रगदार, हर किस्म के कपडे बनाती है । लेसदार धोतियो तथा अन्य वस्त्रो नतो काफी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली है । समिति सारे वर्ष एक-सी मजदूरी देती है । १—७—५५ से ३०—६—५६ तक समिति ने ६, ४६,०५- $\frac{३}{४}$ गज कपडा १६,८०,६७४।।) रु० का पैदा किया और ६,१५,४४५- रु० मजदूरी दी । वुनकरो की मासिक आय

औसतन ५०) रु० रही। समिति ने रगने के लिए भी अपना प्रबन्ध रखा हुआ है। समिति ने एक और फण्ड जारी किया है जिससे बुनकरो के लिए अच्छे मकानों का निर्माण किया जा रहा है। भूमि प्राप्त करली गई है और योजना भी स्वीकार हो चुकी है। सरकार से ६०,००० रु० ऋण मिलने पर ५० मकानों के निर्माण का कार्य आरम्भ हो जायगा। पुस्तकालय आदि की भी सुविधा दी जा रही है तथा बुनकर सदस्यों को वच्चा पैदा होने पर १०) की सहायता दी जाती है।

उपरोक्त विवरण से प्रकट है कि सहकारिता की सफलता इस क्षेत्र में हो सकती है और इसी पद्धति के अपनाने से छोटे-छोटे उद्योग पनप सकते हैं।

बड़े पैमाने के उद्योगों में सहकारिता के कतिपय प्रयोग भारत में हुए हैं। पंजाब में कुछेक खाड के कारखाने लगाए हैं। उत्तरप्रदेश में भी प्रयोग किए हैं। बम्बई में रुई का कार्य होता है। परन्तु बड़े पैमाने के उद्योगों में सहकारिता के प्रयोग से पूर्व हमें यह विचार करना चाहिए कि हम सम्बन्धित कार्य केवल आयकर आदि से वचने के लिए ही तो नहीं कर रहे? बड़े-बड़े कारखाने यदि सहकारिता के आधार पर चलाने ही हो तो हमें सहकारिता के मौलिक भावों को भूलकर उसे दब बनाने से हमें बचें रहना चाहिए। बड़ा कारखाना चलाने के लिए धन चाहिए। बुद्धि तथा तजस्व चाहिए और श्रम चाहिए। यह हर जगह दरकार होते हैं। ग्रामोद्योग में भी इनकी आवश्यकता होती है। परन्तु स्पर्धा से परिपूर्ण आज के युग में बड़े-बड़े कार्यों में पूँजी तथा कार्य-कुशलता का मूल्य तथा आवश्यकता बढ़ गई है। सहकारी कारखाने में यदि हम पूँजी वालों से ही पूँजी जमा करें, तो वह एक पूँजीवादी सस्था बन जायगी। अतः बड़े-बड़े कार्य इस पद्धति द्वारा करने पर इन बातों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि—

- (१) कारखाने के लिए धन विशेषतः सहकारी सस्थाओं से ही जुटाया जाय।
- (२) व्यक्तिगत सदस्य भी अवश्य लिए जाय।
- (३) प्रबन्धक-समिति में प्रतिनिधित्व यों निर्धारित किया जाय कि सहकारी सस्था सदस्यों से ६०%, पूँजी लगाने वालों से २०%, श्रमिकों से २०% सदस्य हों।
- (४) व्यवसाय सम्बन्धी कार्यकुशलता लाने के लिए मैनेजर आदि कुशल व्यक्ति

वैतनिक कर्मचारी रखने होंगे ।

- (५) लाभांश में से कारखाने में काम करने वाले श्रमिकों को बोनस देना अथवा उनके लिए सुविधाएं जुटानी चाहिए ।
- (६) योजना ऐसी होनी चाहिए कि १० वर्ष में कारखाने को ऋण लेने की आवश्यकता न रहे और कार्य-संचालन के लिए हिस्सों का धन तथा सुरक्षित कोष ही पर्याप्त हो ।

सहकारी पद्धति पर आधारित बड़े पैमाने पर उद्योगों की एक और सफल श्रेणी हो सकती है । वह ऐसे कार्य हो सकते हैं जिनको विभिन्न अंगों में विभक्त किया जा सकता हो । एक-एक अंग एक स्वतंत्र सहकारी समिति द्वारा संचालित हो और इन अंगों का काम करने वाली सहकारी समितियाँ मिलकर अपनी एक केन्द्रीय समिति बना ले, जो केन्द्रीय कार्य उन सब सहकारी समितियों के लिए उन अंगरूप कार्यों को संगठित करे तथा हर सदस्य सहकारी समिति को मंत्रणा तथा सहायता दे । इस पद्धति में सहकारिता के भावों का अधिक समावेश रहता है ।

मानवता के मूलभूत स्वभावों पर अवलम्बित यह आन्दोलन मानव के साथ हर स्थान तथा हर स्थल पर सफलता से चलता है । और यह तभी असफल हो जाता है जब हम इसके बुनियादी स्वभाव से विचलित होकर, सहयोग की मूल भावना को भूलकर तथा व्यक्तिगत अथवा अन्य विधियों द्वारा अधिक धन कमाने की लालसा से आकर्षित होकर उनके तरीकों का सहकारिता में अनुसरण प्रारंभ कर देते हैं ।

: ६ :

सहकारी-भण्डार

‘भण्डार’ और ‘स्टोर’ शब्दों से कई बार भ्रम हो जाता है क्योंकि यह अंग्रेजी के दो शब्दों के पर्यायवाची हैं । यह दो शब्द हैं ‘स्टोर’ तथा ‘वेयरहाउस’ । सह-

कारिता में 'स्टोर' आमतौर पर उपभोक्ता सामग्री बेचने वाले स्थान के लिए प्रयोग में लाया जाता है। और जहाँ कोई वस्तु जमा रखी जाती हो उसे वेयर-हाउस कहते हैं। जहाँ तक विक्रय-भण्डारों का सम्बन्ध है, उनका विवरण 'सहकारी व्यापार' के अध्याय में मिलेगा। इस अध्याय में भण्डार शब्द से उस प्रकार के भण्डारों से आशय है जिन्हें अंगरेजी में वेयरहाउस कहा जाता है।

इस प्रकार के गोदामों अथवा भण्डारों का चलन व्यापारी क्षेत्र में तो है ही। या तो यह बाहर से आने वाली वस्तुओं को क्रेता के प्राप्त करने तक बैंको आदि द्वारा जमा रखने के लिए इस्तेमाल होते हैं, या व्यापारी अनाज आदि को इनमें इसलिए जमा रखते हैं कि भाव चढ़ने पर वे उसे बेच सकें। पहले प्रकार का उपयोग तो ऐसा है जो व्यापार में आवश्यक और मानवीय है। इस क्षेत्र में तो सहकारिता का प्रवेश शनै-शनै होगा जब कि व्यापारी यह समझना शुरू कर देगा कि उसे भी अपने कार्य में सहकारी पद्धति को अपनाना चाहिए। परन्तु दूसरे प्रकार के गोदाम तो अन्नोत्पादक के लिए घातक हैं। क्योंकि आम दूकान-दार यो ही फसल पैदा होने पर अनाज खरीद लेता है और उसे जमा रखता है। फिर जब कुछ समय बीत जाता है तो उसी अनाज को महंगा करके उसी किसान को बेच देता है। और केवल अनाज को जमा रखकर किसान से अनुचित लाभ उठाता है। किसान इसलिए विवश होता है कि उसके पास अनाज को जमा करने की सामर्थ्य नहीं होती। परन्तु जब यही कार्य मण्डियों में बड़े-बड़े आदतों करते हैं तो सारे देश पर आपत्ति आ जाती है और एक करोड़पति आदती जनता के जीवन से खिलवाड़ कर सकता है। अनाज के भाव घटाना-बढ़ाना उसके वश में आ जाता है। शासन ने अन्न पर अकुश लगा कर इसका प्रबन्ध किया परन्तु अकुश से भ्रष्टाचार बढ़ा और उपरोक्त शक्ति या वृत्ति का उचित विकेन्द्रीकरण न हो सका और किसान की शक्ति नहीं बढ़ी। इसका यदि कोई सफल इलाज है तो सहकारी भण्डारों का आयोजन। ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण रिपोर्ट में सरकार का ध्यान भी इस समस्या की तरफ खींचा। उस रिपोर्ट में एक अखिल भारतीय सहकारी भण्डारों की योजना की सिफारिश की गई। रिपोर्ट में सुझाया गया कि एक राष्ट्रीय भण्डार विकास-कोष की स्थापना की जाय। इसके नियंत्रण के लिए एक परिषद् की स्थापना का भी सुझाव दिया। इसकी सदस्यता के लिए कहा गया था कि कृषि-मन्त्री (प्रधान)

और कृषि-सचिव (उप-प्रधान) हो। तथा वित्त मन्त्रालय, विकास मण्डल, रेलवे बोर्ड, कन्सल्टिंग इंजीनियर, चेयरमेन फार्वर्ड मार्केट कमीशन, रिजर्व बैंक का प्रतिनिधि, स्टेट बैंक का प्रतिनिधि, एक अर्थशास्त्री, दो सहयोगी, दो गैर-सरकारी व्यक्ति इसके सदस्य हो।

यह भी सिफारिश की गई है कि सहयोगी तथा अर्थशास्त्री विशेष योग्यता-सम्पन्न तथा प्रसिद्ध होने चाहिए। बोर्ड की एक स्थायी कमेटी होनी चाहिए जो जाल में काफी बार बैठक करके नीति आदि का निर्धारण करती रहे। उक्त कमेटी के कार्यों के सम्बन्ध में सिफारिशें इस प्रकार हैं —

१. (क) सारे देश में कृषि-सम्बन्धी उपज तथा ग्रामीणों के लिए आवश्यक वस्तुओं के सहकारी निर्माण तथा व्यापार के योजना-सम्पन्न विकास को उन्नत करना।

(ख) कृषि-उपज को सहकारी ढग के अनुसार योजनापूर्ण पद्धति पर विकसित करना तथा कृषि-उपज के कार्य में छोटे-छोटे सिचाई-साधनों को प्रोत्साहन तथा दुग्ध एवं गोपालन आदि के सहायक कार्यों को सहायता देना।

२ (क) कृषि-उपज तथा तत्सम्बन्धी वस्तुओं के एकत्रीकरण तथा जमा करने के लिए अखिल देशीय स्तर पर एक योजना के अनुसार भण्डारों की सुविधाओं का प्रवन्ध करना तथा सस्थाओं द्वारा एतदर्थ प्रवन्ध करके गोदामों तथा लाइसेंस प्राप्त भण्डारों एवं सहकारी समितियों के स्वामित्व का जाल विछाना।

(ख) सहकारी ढग से सुविधाओं के साथ-साथ कृषकों के लिए बीज, खाद, रासायनिक खाद, कृषि उपकरणों, औजारों, ग्रामोद्योगों आदि का प्रवन्ध करना, जिनकी कि कृषक को आवश्यकता होती है तथा अन्य आवश्यकताओं यथा मिट्टी का तेल, खाण्ड, दियासलाई आदि की सप्लाई का प्रवन्ध करना।

३. उपरोक्त ध्येयों की पूर्ति के लिए जहां तक कि उनकी पूर्ति राज्य-शासनो तथा सहकारी सस्थाओं के कार्य-क्षेत्र में पड़ती है, राज्य-सरकारों को तथा उनके द्वारा सहकारी सस्थाओं को यथा-सम्भव मात्रा में आर्थिक सहायता का प्रवन्ध करना तथा इन्हीं ध्येयों की पूर्ति के लिए अन्य सहायता का

प्रबन्ध करना ।

- ४ अखिल भारतीय भण्डार-निगम का निर्देशन करना तथा उक्त निगम तथा राजकीय-भण्डार कम्पनियो द्वारा दिये जाने वाले ऋण तथा अन्य सहायता के प्रतिबन्धों का निर्धारण करना ।
- ५ राष्ट्रीय भण्डार, विकास-निधि तथा राष्ट्रीय सहकारिता विकास-निधि का प्रशासन, और इन दोनों निधियों का आवश्यकतानुसार पारस्परिक सतुलन तथा वितरण करना ।

परिषद् के कार्यालय के लिए प्रशासन सम्बन्धी विशेषज्ञ, कार्यवाहक तथा अन्य प्रकार के कर्मचारी समुदाय के प्रबन्ध के लिए कृषि मन्त्रालय पर उत्तरदायित्व डालने की सिफारिश की गई है। और यह भी सिफारिश की गई है कि इस कार्य में समिति राज्य-सरकारों से मन्त्रणा आदि द्वारा पर्याप्त ताल-मेल रखे ।

इस कार्य के लिए धन जुटाने के लिए दो निधियों के निर्माण करने की सिफारिश की गई है—जिनके नाम होंगे राष्ट्रीय सहकारिता-विकास-निधि तथा राष्ट्रीय भण्डार विकास-निधि । भारत सरकार प्रारम्भ में ५ करोड़ रुपया देगी जो राष्ट्रीय भण्डार विकास-निधि में जायगा और इसके बाद हर वर्ष भारत सरकार कम से कम ५ करोड़ रुपया डालेगी जिसमें से ३ करोड़ राष्ट्रीय सहकारिता विकास-निधि में जायगा और २ करोड़ राष्ट्रीय भण्डार विकास-निधि में जायगा । इनके लिए अन्य साधन भारत सरकार द्वारा प्रदत्त अन्य राशियाँ होंगी तथा विदेशी सहायता भी शामिल होगी । इन निधियों के उपयोग के लिए तत्तन् उद्देश्य प्रस्तुत किए गए हैं —

राष्ट्रीय सहकारिता-विकास-निधि—

- (क) राज्य-सरकारों को दीर्घकालीन ऋण बिना प्रतिबन्धों के इसलिए देना कि वह सहकारी सस्थाओं में भाग-धन दे सकें ।
- (ख) निधि के उद्देश्यों के अधीन तथा परिषद् द्वारा निर्धारित प्रतिबन्धों के अधीन राज्य-सरकारों द्वारा सहकारी समितियों को एक बार अथवा बार-बार दी जाने वाली आर्थिक सहायता देना ।

उपरोक्त आर्थिक सहायता के लिए यह प्रस्ताव किया गया है कि यह सहा-

यता कुल खर्च का एक निश्चित भाग होना चाहिए जो साधारणतया २५% से कम न हो ।

राष्ट्रीय भण्डार-विकास-निधि—

- (क) अखिल भारतीय भण्डार निगम के हिस्से खरीदने के लिए,
- (ख) परिपद द्वारा निर्धारित प्रतिबन्धों के अधीन राज्य-सरकारों को इसलिए ऋण देना कि वह राजकीय भण्डार कम्पनियों के हिस्से खरीद सकें ।
- (ग) परिपद द्वारा निर्धारित प्रतिबन्धों के अधीन अखिल भारतीय भण्डार निगम को तथा उसके द्वारा राजकीय भण्डार कम्पनियों को, तथा राज्य-सरकारों द्वारा सहकारी समितियों को ऋण देने के लिए ।
- (घ) एक बार अथवा बार-बार दी जाने वाली आर्थिक सहायता देने के लिए जो उपरिलिखित स्रोतों द्वारा दी जायगी ।

आगे चलकर आयोग ने अखिल भारतीय भण्डार निगम तथा राजकीय भण्डार कम्पनियों के निर्माण के लिए कुछ प्रस्ताव दिए हैं कि उनका भाग-धन कैसे बनेगा तथा उसके निर्देशन-मण्डल के कौन-कौन सदस्य होंगे । इसमें सहकारी प्रतिनिधियों को छोड़ (स्टेट बैंक) भारत राजकीय बैंक, कम्पनियों, बीमा कम्पनियों आदि के प्रतिनिधि भी रखे गए हैं ।

उपरिलिखित भण्डार निगम के कार्यों के सम्बन्ध में उनके मुभाव यह है कि परिपद की योजना के अधीन भूमि प्राप्त करके अखिल भारतीय महत्व के स्थानों पर गोदाम बनवाना, लाइसेंसों के अधीन भण्डारों का प्रबन्ध करना, मण्डियों का नियंत्रण, सरकारी भण्डार कम्पनियों के हिस्से खरीदना, परिपद के एजेंट के रूप में काम करना आदि-आदि । सरकारी कम्पनियों के कार्य तथा कर्तव्य भी इसी प्रकार के उनके अपने क्षेत्र में प्रस्तावित हैं । इस बात पर विशेष जोर दिया गया है कि भण्डारों का प्रबन्ध सहकारी समितियों द्वारा हो । राजकीय कम्पनियों के गोदाम तो जिला तथा तहसीलों तक हो और इनमें आगे सहकारी समितियों के हो । उनके लिए कर्मचारी समुदाय के प्रशिक्षण पर भी बहुत जोर दिया है ।

उपरिलिखित परिपद तथा निधियों का निर्माण हो चुका है । हर राज्य ने भण्डार निर्माण योजना बना ली है । कृषकों ने भण्डार कम्पनियाँ भी बनाई हैं परन्तु जो प्रशिक्षण कर्मचारी समुदाय को दिया जा रहा है वह निदान्तो

तक ही है क्रियात्मक नहीं। सहकारी समितियों में व्यापारिक क्षमता की कमी है। नियमादि की कागजी कार्रवाई कार्य की गति व उसके विस्तार में अड़चन आदि बाधा के रूप में खड़ी हो जाती है। यह कार्य एक उत्तरदायित्व को निभाने की मूल भावना से उत्पन्न तथा व्यवहार-कुशलता से पुष्ट होकर ही सफल हो सकते हैं। इसके लिए पहली आवश्यकता है उन भावों के जगाने की जिनकी ओर प्रथम अध्याय में संकेत किया गया है। नियमादि में इतनी स्वतन्त्रता तथा छूट चाहिए कि स्थान, परिस्थिति तथा आवश्यकतानुसार उनमें परिवर्तन किया जा सके।

परन्तु सब से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न तो यह है कि भण्डारों का संचालन ऐसी सुचारुता से हो कि वह घाटे में न चले। क्योंकि कोई भी इस प्रकार की सस्था पर्याप्तकाल तक नहीं चल सकती, जब तक कि उसका आर्थिक पक्ष पुष्ट और स्वावलम्बी न हो। भारत की सहकारिता का जो अनुभव इस वक्त तक हुआ है उससे तो हमें यह स्वीकार करना पड़ता है कि अभी तक सहकारी कार्यकर्ताओं में पर्याप्त व्यावहारिक योग्यता नहीं आई। और साधारण वर्गिक के मुकाबले में सहकारी संस्थाएँ सफल नहीं हो पाईं। इसके कारण संक्षेप से इस प्रकार हैं—

- (क) भारत में शताब्दियों की पराधीनता ने सामाजिक भावों को शिथिल करके व्यक्ति को ज्यादा महत्व दिया है।
- (ख) हमारे राष्ट्रीय भाव शिथिल होने के कारण हम अपने व्यक्तिगत लाभ को राष्ट्रीय लाभ से अधिक महत्व और प्राथमिकता देते हैं।
- (ग) लोकतंत्रीय भावनाएँ निर्बल होने के कारण हम में सामूहिक उत्तरदायित्व के भाव जागृत नहीं हो सके।
- (घ) सहकारी समिति के सम्बन्ध में हमारी धारणाएँ अस्पष्ट तथा स्वप्निल हैं और यह समझते हैं कि सहकारी समिति अपने वैतनिक कर्मचारियों के वेतन निकालने के लिए भी लाभ न कमाएँ।
- (ङ) वर्गिक-वर्ग के संपर्क इतने विस्तृत हैं कि वह सहकारी समितियों के विरुद्ध झूठा प्रचार भी सफलतापूर्वक कर सकते हैं।
- (च) कतिपय वर्गिकवृत्ति वाले व्यक्ति सहकारी समितियों में प्रवेश करके उनका दुरुपयोग करते हैं।

(छ) सहकारी कार्यकर्ताओं तथा कर्मचारी वर्ग में न तो सहकारिता में पक्का विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं और न ही उनका पर्याप्त प्रशिक्षण हो सका है ।

(ज) प्रशिक्षण के लिए अभी तक उपयुक्त प्रबन्ध नहीं हो सका ।

(झ) सहकारी समितियों के सदस्य भी उद्योग में सहकारी समितियों को प्राथमिकता नहीं देते ।

(ञ) सरकारी सहायता भी स्वावलम्बन की भावनाओं को पुष्ट करने के स्थान पर उन्हें पगु बनाने में सहायक होती है ।

इन परिस्थितियों के होते हुए तथा हर भण्डार पर होने वाले खर्च के समक्ष इस योजना की सफलता में काफी कठिनाइयाँ नजर आती हैं । अतः प्रारम्भिक दशा में यह अधिक लाभदायक होगा कि हम इस प्रकार कार्यारम्भ करें कि उपरोक्त परिस्थितियाँ हमारे कार्य में बाधक भी न हों तथा समाज के समस्त व्यक्ति सहकार्य की भावनाओं को अपनाते चले जायँ और एक निश्चित योजना के अधीन तथा निर्धारित अवधि के अन्दर पूर्णतया सहकारी पद्धति पर भण्डार योजना चल सके ।

यहाँ तक तो ठीक ही है कि सब भण्डार ग्राम-स्तर पर सहकारी समितियों के स्वामित्व में हों और उनके निर्माण के लिए जो दीर्घकालीन ऋण मिलें वह भी सहकारी समितियों को ही, परन्तु उनका दिन-प्रतिदिन का प्रबन्ध वैतनिक कर्मचारियों को यदि सौंपा गया तो इस कार्य का जीवन लम्बा नहीं हो पायगा, क्योंकि कार्य को इतनी व्यवहार-कुशलता से नहीं किया जा सकता जिसका कारण ऊपर बतलाया जा चुका है । हमारे वैतनिक कर्मचारी समय बिताना चाहते हैं कार्य करना नहीं । और वेतन में समय का मूल्य समझा जाता है काम का नहीं । अतः कार्य में कुशलता लाने के लिए काम के लिए वेतन देने की पद्धति को अपनाना पड़ेगा । इसलिए भण्डार हर क्षेत्र में एक ऐसे मैनेजर के अधीन देने पड़ेंगे जो,

(क) स्थानीय सहकारी समिति का सदस्य हो, जिसके प्रबन्ध में वह भण्डार हो ।

(ख) सदस्य एक निश्चित राशि तक अपनी जमानत दे ताकि रखे जाने वाले माल की हिफाजत रहे ।

(ग) उक्त सदस्य को, जितना सामान रहे, उसके हिसाब से तथा उनके आयात-

निर्यात के अनुपात से उसको पारिश्रमिक दिया जाय । यह पारिश्रमिक उस कमीशन या शुल्क का एक निश्चित भाग होना चाहिए, जो कि उसी कार्य पर सहकारी समिति ले ।

(घ) भण्डार का उपयोग वस्तु-श्रेणी विशेष तक ही सीमित नहीं होना चाहिए वरन् काफी उदार रहना चाहिए ताकि भण्डार का ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो सके ।

(ङ) यदि सम्बन्धित सहकारी समिति व्यापार भी करती हो तो एक ही व्यक्ति दोनों काम कर सकता है ।

यह तो रही प्रबन्ध के सम्बन्ध में कुछ बातें, परन्तु भण्डारों का विशेष उद्देश्य तो यह है कि जहाँ यह भण्डार उत्पादकों को जमा रखने की सामर्थ्य प्रदान करेगा, वहाँ यह अन्न के भण्डार स्थान-स्थान पर एकत्रित करके देश में अन्न के सकट का पर्याप्त मात्रा में वचाव करेगा ।

यदि हम हर ग्राम अथवा पंचायत क्षेत्र में ऐसे भण्डारों का निर्माण करके उनमें वहाँ की सम्भावित सकटकालीन स्थिति से मुकाबिला करने के लिए अन्न भण्डार रख सके और उसके अन्न का फसल-फसल पर नवीनीकरण होता रहे तो भाव भी ठीक रखे जा सकते हैं और रुपया कमाने के लोभ से अन्न को निकालने की प्रथा पर कानू पाकर हम एक तरफ तो कृत्रिम अकाल से बच सकेंगे और दूसरी तरफ वास्तविक सकट पर भी यह भण्डार काफी सहायता दे सकेंगे ।

अतः रिजर्व बैंक की ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति के प्रस्तावों के अनुसार अखिल भारतीय स्तर पर भण्डारों का निर्माण भारतीय कृषि, कृषक तथा अन्न समस्या के हल के लिए एक बड़ा ही अनुपम साधन होगा । हाँ, उसके प्रचलन में वस्तुस्थिति तथा क्रियात्मकता के विचार से कुछ सशोधन करने पड़ेंगे ।

अतः आवश्यक है कि कृषि के विकास, उपज के सही लाभ तथा उनके वितरण के आवश्यक प्रवर्ध के लिए सहकारी-भण्डारों की ओर अवश्य ध्यान दिया जाय । भण्डारों का यह भी कर्तव्य है कि वे कृषकों की प्रतिदिन की अन्य आवश्यकताओं की ओर भी ध्यान दें ।

: ७ :

सहकारिता और व्यापार

व्यापार शब्द के शाब्दिक अर्थ भले ही कुछ हो परन्तु आज हम इस शब्द से समझते हैं—वह कार्य जिसमें मुद्रा की मध्यस्थता द्वारा वस्तुओं अथवा द्रव्यों को एक स्थान से दूसरे स्थान अथवा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुँचाया जाय । भारत की प्राचीन परम्परा में इस व्यवसाय को करने वाले जन-समुदाय को समाज के उदर से तुलना दी गई थी । कितनी विचित्र तुलना थी यह । देह के पालन के लिए मनुष्य जो कुछ खाता है वह सब पेट में जाता है । और पेट उसका गोधन करके उसमें से धातु-रक्त बनाकर हृदय के पम्प द्वारा उस शुद्ध रक्त को देह के हर अवयव के पोषण हेतु भेज देता है और स्वयं केवल पोषण के लिए ही दिमाग की आज्ञा से कुछ भाग प्राप्त करता है ।

व्यापार के कार्य तथा कर्तव्य भी ऐसे ही हैं । वह संग्रह करता है तो केवल समाज को सेवा तथा समाज के पोषण के लिए । इस भाव को पुष्ट तथा हृदयगम करने के लिए एक ओर तो धार्मिक भावना द्वारा इसे प्रोत्साहित किया गया, दूसरी ओर समाज तथा शासन के प्रतिबन्ध इसे सजीव रखने में सहायक रहते रहे । परन्तु विदेशियों के आक्रमणों तथा विदेशी परम्परा के आघातों ने हमारी इस प्राचीन परम्परा को जर्जरित कर दिया । पराधीनता ने तो इसे मृतप्राय कर दिया और व्यापारी समाज-सेवक होने के स्थान पर समाज का शत्रु बन गया । उसने संग्रह केवल अपने पोषण के लिए प्रारम्भ कर दिया, जिससे समाज के उत्पादक अंग क्षीण होने लगे । समाज की तोड़ बढी और शेष अंग कृश हो गए । ऐसे व्यापार और व्यापारी के विरुद्ध समाज में एक क्रान्तिकारी भावना का जागरण स्वाभाविक था । व्यापारी तथा साहूकार के ऐसे कुकृत्यों को रोकने के लिए आन्दोलन चले । ऐसे आन्दोलनों से एक तरफ वैमनस्य तथा मनमुटाव बढा दूसरी ओर विचारक लोग व्यापार की नवीन पद्धति की खोज में लग गए । साम्यवादी रूस ने सारे व्यापार को शासनाधिकृत करने की योजना बनाई और जहाँ व्यापारी वर्ग का जोर शासन में अधिक था, वहाँ उत्पादक वर्ग ने सह-

कारिता की पद्धति का अवलम्बन किया। मूलतः ध्येय दोनों का यही रहा कि व्यापार समाज के हित में हो। कोई एक वर्ग इसका ठेकेदार बनकर समाज का शोषण न करे। जब भी यह कार्य प्रतिकार भावना तथा हिंसा का आश्रय लेकर हुआ तब इसका पुनः प्रतिकार हुआ और वह हिंसा द्वारा लाई गई अच्छी पद्धति भी स्थायी न रह सकी। अतः इस कार्य का इलाज अहिंसात्मक उपायो द्वारा ही स्थायी हो सकता है। और यह अहिंसात्मक उपायो द्वारा ही सफल होने वाली पद्धति है। सहकारिता में स्वेच्छा से शामिल होना इसका प्रारम्भिक लक्षण है, उसमें हिंसा का अभाव आवश्यक तथा प्राकृतिक है।

व्यापार के दो पहलू होते हैं—आयात तथा निर्यात। हर ग्राम से लेकर देश तक व्यापार की यह दो कोटियाँ चलती हैं। तीसरी कोटि सग्रहात्मक व्यापार की होती है, जहाँ स्थानीय उपज को कुछ काल तक सग्रह रखकर पुनः वही विक्रय कर देते हैं। इसमें सब प्रकार के व्यापार में समाज के हित की भावना को सर्वोपरि रखने के लिए सहकारिता की भावना का प्रादुर्भाव हुआ है। इंग्लैंड की राशडेल पायोनियर संस्था, जिसका १८४० में श्रीगणेश हुआ, और जिसका वर्णन 'सहकारिता का उदय और विकास' में किया गया है, सहकारी व्यापार के सफल प्रयोग का एक विशिष्ट नमूना है। इस प्रकार के कतिपय स्टोर भारत में भी सफल हुए हैं। परन्तु बहुधा देखा गया है कि सहकारिता पर अवलम्बित पण्यशालाएँ या स्टोर सफल नहीं होते। प्रचलित पद्धति के अनुसार इसके निम्न प्रकार हैं —

(१) नागरिक उपभोक्ता स्टोर—ग्राम तीर पर देखा गया है कि वणिज जो चीजें लाकर बेचते हैं वह एक तो कई आढतियों के हाथों से गुजरती हैं। जितने अधिक हाथों से वे गुजरती हैं उतना ही उनका मूल्य बढ़ जाता है, क्योंकि हर आढती अपना मुनाफा काटता है। फिर अधिक लाभ प्राप्त करने की इच्छा से कम तोलने का आश्रय लिया जाता है और बहुधा उनमें मिलावट भी कर दी जाती है। अन्य कई प्रकार के उपाय प्रयोग में लाए जाते हैं, ताकि उन पर अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो। एक व्यक्तिगत दूकानदार के पास न तो इतनी धन-राशि होती है न ही वह विक्री के लिए निश्चिन्त होता है। परन्तु यदि नगर वाले सब या एक मुहल्ले के या एक ग्राम के व्यक्ति इकट्ठे हो जाय, अपनी सारी जरूरतों की इकट्ठी सूची बना लें और इकट्ठा माल मगवा लें तो

किराये में बचत होगी। फिर माल उत्पादक अथवा मिल या कारखाने से सीधा आवे तो बीच के आदतियों की कमीशन आदि की बचत होगी। फिर जो कुछ बचत होगी वह भी उनके लाभ में शामिल होगी।

अतः साधारणतया ऐसे स्टोर चलाने के लिए एक छोटे तथा सगठित क्षेत्र के लोगों को एक सहकारी समिति में मिला लिया जाता है। यह समिति उसी ढंग से सगठित की जाती है जैसे कि साधारण ऋण-सम्बन्धी समिति, जिसका उल्लेख पूर्व पृष्ठों में किया जा चुका है। परन्तु यह समिति—आमतौर पर सीमित उत्तरदायित्व की होती है। समिति को एक वैतनिक मैनेजर रखना पड़ता है। समिति सब सदस्यों की आवश्यकता की गणना करके तदनुसार माल मगवाती है। आमतौर पर माल बेचने के भाव नियत कर लिए जाते हैं। यह भाव बाजार के भाव के लगभग बराबर इसलिए रखे जाते हैं ताकि सहकारी पण्यशाला को हानि पहुँचाने के लिए वह अपने निरख बहुत नीचे न गिरा दे। परन्तु माल शुद्ध तथा अच्छा और समय पर मिल जाने का प्रयत्न किया जाता है। फिर जो लाभ होता है वह किसी एक व्यक्ति की जेब नहीं भरता। वरच वह सब सदस्यों अर्थात् समाज का होता है। और वह भी उन्हें केवल नकदी के रूप में प्राप्त नहीं होता, वरच कई सामाजिक हित के कार्यों तथा सरक्षणों के स्वरूप में प्राप्त होता है। इन पण्यशालाओं से जन-साधारण को बहुत लाभ होते हैं, जिनमें से कुछेक इस प्रकार हैं—

- १ माल शुद्ध तथा खालिस प्राप्त होगा, जो आम दूकानदार से नहीं मिल सकता।
- २ साधारणतया वस्तुएँ सस्ती प्राप्त होगी और फलतः दूकानदार को भी मूल्य सस्ते करने पड़ेंगे।
- ३ सहकारी पण्यशाला से माल खरीदने पर सदस्यों को अतिरिक्त लाभ प्राप्त होगा जो दूकानदार से प्राप्त नहीं होगा।
- ४ सहकारी नियमों के अनुसार निधियाँ आदि निर्माण होने से सुरक्षित निधि बढ़ जाने से सदस्यों को अथवा समिति को माल मगवाने के लिए पर्याप्त धन-राशि बिना व्याज प्राप्त हो सकेगी।
- ५ सहकारी कार्य-पद्धति से सदस्यों को परिचय हो जायगा और सहकारी सिद्धान्त आगे बढ़ेंगे।

अभी तक पद्धति के अनुसार यही समझा जाता है कि भण्डार का माल सदस्यों को ही बेचा जाय, माल नकदी पर बेचा जाय उधार न दिया जाय, लाभ वितरण तो भाग-धन के अनुसार किया जाय परन्तु लाभ का प्रधान अंश समिति से माल खरीदने के अनुपात पर अतिरिक्त लाभ बांटा जाए। लाभ से उपनिधियों के अनुसार निधियां बनाई जाय ताकि स्टोर स्वावलम्बी हो जाय।

परन्तु शनै-शनै अब यह हो रहा है कि ऐसे स्टोर उन लोगों को भी माल बेचते हैं जो सदस्य नहीं। सदस्यों को, जहां वह काश्तकार आदि होते हैं, कुछ उधार भी दिया जाता है।

इस तरह असदस्यों को लाभ देने से उन लोगों में भी सहकारी समितियों के सदस्य बनने की प्रेरणा होती है। इस प्रकार के सहकारी स्टोर प्रायः नगरों में चलते हैं, परन्तु ग्रामों में यह कार्य बहुद्देशीय ढंग से चलता है। क्योंकि कार्यक्षेत्र जरा विस्तृत होता है और जनता कम होती है। इसलिए वहां पर यह कार्य बहुद्देशीय ढंग से होने लगा है। इसके सम्बन्ध में विस्तार से अन्यत्र लिखा जायगा। यहां इतना ही लिखना पर्याप्त होगा कि साधारणतया यह कार्य उपरोक्त ढंग से ही किया जाता है, परन्तु इन समितियों में केवल यही काम नहीं होता अन्य काम भी किए जाते हैं। भारत में इस प्रकार के स्टोरों का पर्याप्त प्रयोग है और सन् ५४ के आकड़ों के आधार पर राज्यवार इनका विवरण इस प्रकार है—

सं०	नाम राज्य	भण्डारों की संख्या	कुल सदस्य	कुल पूंजी
१	मद्रास	२०५३	५,६७,११४	२,३८,१७,३३६
२	बम्बई	१,२०७	२,६२,७४५	२,६२,८६,१०६
३	पं० बंगाल	४००	५६,६६७	१६,६६,२६२
४	उत्तर प्रदेश	५१४	३,०२,०१०	६६,७६,६३७
५	मध्य प्रदेश	१,७१२	२,१३,३१३	१,२६,८४,२५३
६	पंजाब	५८६	३४,८७८	५२,८१,६२
७	बिहार	५०००	२,७२,५५६	६६,६४,११०
८	उड़ीसा	४३५	६५,६१०	७२,२०,२६१
९	मैसूर	१,६६५	२,३४,६०६	८१,१६,७५५
१०.	हैदराबाद	२६६	५,६१,०६३	१,७६,४०,११६
	मध्य भारत	२१२	१४,५६३,	१०,५८,७४३

ग्रामीण-ऋण-पर्वक्षण समिति ने, जो कि रिजर्व बैंक ने नियुक्त की थी, भी इस प्रश्न पर विचार किया है। प्रधानतया उनका कहना यह है कि ऋण सबधी समस्या की असफलता का कारण यह रहा कि ग्रामीणों की आवश्यकताएँ विविध होती हैं और जब उनकी प्रधान आवश्यकताओं का प्रबन्ध सहकारिता द्वारा नहीं होता तब तक ऋण की समस्या का भी समाधान नहीं हो सकता। उनके अन्वेषण से यह निष्कर्ष है कि अन्न की पैदावार, जो ग्रामीण किसान ने बनाया करीबतः है, उनका ७५% भाग वह ग्राम में ही आवश्यकता के समुपयोग देता है। इस कार्य में सहकारिता का भाग केवल १% से अधिक नहीं है। यही कारण है सहकारी समितियाँ उत्पन्न होने वाले अन्न के बदले ऋण नहीं दे सकती और सहकारी समिति सब तरफ ग्रामीण वर्गों का ध्यान नहीं दे सकती और न ही प्रभावशाली हो सकती है। इस विषय में राज्य वाटन रोड मोनोपॉली, जो कन्स्टीट्यूट में है, का नाम उल्लेखनीय है। यह १९१० में रजिस्टर हुई। वर्ष १९२० में यह ने एक नये, अधिक व्यापक रूप में व्यापक किया, जिससे (५८,४६०) रु० वर्षीय आय प्राप्त। यह ५६% लाभ दावती नहीं आई है। यह चीज बेचने का लाभ भी नहीं है।

रूप का क्रमशः व्यापार किया। चूँहो से सुरक्षित इस समिति के दो बड़े-बड़े गोदाम हैं।

परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि ऐसी समितियों की संख्या बहुत ही कम है। कुछ ऐसी भी हैं जो व्यापार सम्बन्धी सहकारी समितियों की भावी सफल विधियों की ओर संकेत करती हैं। उक्त रिपोर्ट में यह सुझाव दिया गया है कि निर्दिष्ट क्षेत्रों के लिए बड़ी-बड़ी सहकारी समितियाँ बनाई जाय। और इनके पुष्ट करने के लिए इनमें भी सरकारी भाग रखा जाय। उनका कथन है कि इनमें ५१% सरकारी हिस्सा होना चाहिए। ऐसी समितियों के जिला स्तर पर वस्तु-विभाजन के अनुसार बनाए जाने का प्रस्ताव है। यह भी सुझाव है कि हिस्सों के धन की महत्तम तथा न्यूनतम मात्रा नियत कर दी जाय।

उक्त रिपोर्ट के सुझावों पर अमल करने का प्रयोग द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्रारम्भ हो गया है। राज्य-सरकारें हिस्सों की खरीद में ५१% लगाने लग गई हैं। इस प्रयोग का पूर्ण मूल्यांकन तो ५ वर्षों के उपरान्त हो सकेगा परन्तु जो कुछ इस थोड़ी अवधि में दृष्टिगोचर हुआ है वह पर्याप्त शिक्षाप्रद है।

कार्य प्रारम्भ होने पर रुपया केन्द्र से प्राप्त करके विभाग के कर्मचारी सहकारी समितियों के हिस्से खरीद रहे हैं। हर ऐसी समिति की प्रबन्धक समिति में सरकार अपने तीन सदस्य मनोनीत कर देती है। परन्तु अभी तक इस धन का सदुपयोग नहीं हो सका है। इसके कारण कई हैं। इनका संक्षेप से उल्लेख किया जाना पर्याप्त मात्रा में शिक्षाप्रद होगा—

- (१) विभाग के कर्मचारी कुछ प्रशिक्षण तो प्राप्त करते हैं, परन्तु न तो इनका प्रारम्भिक प्रवेश इस बात पर निर्भर होता है कि वह ग्रामीण जनता तथा किसान समुदाय के हों, और न ही उनकी पद-वृद्धि उनकी क्षेत्रीय सफलता पर निर्भर होती है। इससे उनमें वास्तविक सहकारी भावना न तो जागृत होती है, और न ही पनपती है।
- (२) पुलिस तथा रेवेन्यू आदि विभागों के कर्मचारियों को देखकर सहकारी विभाग के कर्मचारियों में भी जनता के साथ एक होने के स्थान उसपर रोव जमाने की भावना बढ़ रही है। जिसका फल यह है कि उक्त कर्मचारी वर्ग दिन-प्रतिदिन ग्राम जनता का विश्वास खो रहा है।
- (३) जनता में सहकारी भावनाओं के जागरण तथा प्रचार हेतु कार्य नहीं हो

- रहा, और यह कार्य एक सेवा की भावना से सम्पन्न कर्मचारी-वर्ग ही कर सकता है ।
- (४) सहकारी समितियों में भी ईमानदार तथा सहकारी भावना-सम्पन्न व्यक्तियों को प्रोत्साहन देने का कोई प्रबन्ध नहीं है ।
- (५) सहकारी सभाओं के कर्मचारियों को न तो प्रशिक्षण मिलता है और न ही उनके पद में कोई स्थायित्व है ।
- (६) वेतनों का स्तर ऊँचा होने पर और उसी अनुपात में सहकारी समितियों की आय में वृद्धि न होने के कारण वह प्रचलित अनुपात के अनुसार अपने कर्मचारियों को वेतन नहीं दे सकती ।
- (७) कुछ ऐसी धारणा बन गई है कि सब लोग सहकारी कार्य से ऐसी अनहोनी आशाएँ रखते हैं कि वहाँ प्रबन्ध सुचारु हो, दिन-रात कार्यकर्ता काम करें, वेतन न ले और रोटी घर से खाय । ऐसी धारणाओं में सहकारी सस्थाओं का पनपना संभव नहीं ।
- (८) जिन कार्यों को शेष व्यापार सस्थाओं में भूल समझा जाता है उन्हें सहकारी समितियों में गबन बताकर उन्हें बदनाम किया जाता है ।
- (९) सहकारी समितियों से भी सरकारी कर्मचारी उसी प्रकार की खातिर व सत्कार की आशा करते हैं जैसे कि व्यक्तिगत व्यापारियों से ।
- (१०) इन सब बातों का यह प्रभाव होता है कि सहकारी समितियों में भी उसी प्रकार के व्यक्ति आगे आ जाते हैं जो किसी न किसी ढंग से कर्मचारी वर्ग की खातिर, सत्कार, चाय-पार्टी आदि के लिए धन निकाल सकें । और जब इस प्रकार के कार्यों के लिए धन निकालने की छूट दी जाती है तब फल वही होते हैं जो स्वाभाविक हैं । ऐसे व्यक्ति इसी तरह अपने लिए भी धन निकालते हैं । और परिणाम वही होता है जो सामने आ रहे हैं ।

नतीजा यह है कि बहुत-सी समितियाँ घाटे में जा रही हैं । कहीं गबनों की तहकीकातें चल रही हैं और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रणों के वावजूद सहकारी समितियों की सफलता अनिश्चित जैसी ही नजर आती है । जहाँ तक विभाग का सम्बन्ध है उसके बारे में तो पृथक् अध्याय में लिखा जायगा और यहाँ पर केवल प्रारम्भिक दशा में जो प्रबन्ध में आवश्यकताएँ हैं, उनके बारे में

सकेत किया जाना आवश्यक है ।

जिस समय तक पर्याप्त मात्रा में समितियों के लिए कर्मचारी समुदाय प्रशिक्षित नहीं हो जाते और सहकारी समितियों की सहायता हेतु सरकार धन दे रही है, तब तक यह जरूरी है कि प्रबन्ध ऐसे हाथों में न हो जो काम तो जानते न हो परन्तु रुपया ऐंठने की भावना प्रबल हो, और जो कर्मचारी समुदाय को चाय आदि पिलाकर तथा सत्कार आदि करके अपना रुपया ऐंठने का काम जारी रखे । यदि व्यापार-कुशल वंश-परम्परागत व्यापारियों को उक्त कार्य पर रख लिया जाय तो वे शनैः-शनैः सारे काम पर अपना आधिपत्य जमा लेंगे और सहकारिता का विकास कुण्ठित हो जायगा । अतः व्यापार-कार्य को कुशल तथा सहकारिता-परक बनाने के लिए कुछ साकेतिक सुभाव यह है—

प्रारम्भिक स्तर—जैसा कि पहले लिखा जा चुका है कि ग्राम्य-स्तर पर व्यापार का कार्य विशेष श्रेणी की पृथक् समितियाँ नहीं करती, एक ही बहुद्देश्यीय सहकारी सभा सब कार्य करती है । और इसकी कार्य-पद्धति इस तरह होती है कि या तो यह समिति एक वैतनिक विक्रेता रख लेती है, जो क्रय-विक्रय का काम करता है । परन्तु साधारणतया यह देखा गया है कि वैतनिक कर्मचारी केवल अपने पैसे कमाने के लिए समय लगाते हैं, समिति के हित की ओर उनका ध्यान नहीं होता । इस प्रकार वे घाटे में चली जाती हैं । दूसरी पद्धति यह है कि समितियाँ अपनी वस्तुओं के विक्रय के लिए एक दूकानदार को कमीशन पर नियुक्त कर लेती हैं । ऐसा दूकानदार बहुधा इस कार्य को अपने शेष व्यापार को चलाने के लिए उपयोग में लाता है । समिति के रुपये तथा उसके सदस्यों के द्वारा उसे शेष दूकानदारों पर प्रभुता प्राप्त हो जाती है । उसका व्यापार चमक उठता है । उसमें अहंकार बढ़ता है । वह अपने लाभ के लिए समिति की प्रबन्धक-समिति के सदस्यों को कई प्रलोभनों द्वारा वंश में करने के प्रयत्न में लगा रहता है । इस पद्धति द्वारा आर्थिक हानि तो बच सकती है परन्तु समिति बदनाम हो जाती है । उसका कार्य विस्तृत नहीं हो पाता । सहकारिता के मौलिक भावों को धक्का पहुँचता है और इस तरह शनैः-शनैः सहकारिता की प्रगति रुक जाती है । ऐसी परिस्थिति में कार्य-पद्धति सहकारिता के मौलिक उद्देश्यों को सामने रखकर और वास्तविक स्थिति का अध्ययन करके ही सोची जा सकती है, ताकि

वह व्यावहारिक होने के साथ-साथ सहकारिता के उद्देश्यों की पूर्ति में भी सहायक हो ।

इसलिए सुभाष यह है कि प्रारम्भिक बहुदेशीय सहकारी समिति के क्षेत्र के सब दूकानदार समिति के सदस्य हों । परन्तु प्रबन्धक-समिति में उनका प्रतिनिधित्व उनकी क्षेत्रीय जनसंख्या के अनुपात से अधिक नहीं होना चाहिए और प्रबन्धक-समिति में वह व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो इस प्रस्तावित योजनाधीन समिति से लाभ उठाता हो अथवा उसके व्यापार में मुकाबिला करता हो । मुकाबिला करने वाला तो समिति का सदस्य भी नहीं रहना चाहिए ।

समिति को अपना एक भण्डार रखना चाहिए और स्थान की आवश्यकता के अनुसार सब माल थोक भाव से मगवाना चाहिए । थोक माल मगवाने का सब काम समिति के वतनिक कर्मचारियों द्वारा प्रबन्धक-समिति की योजना द्वारा सम्पन्न होना चाहिए । सदस्य दूकानदार इस योजना द्वारा लाभ उठाना चाहते हों तो उन्हें व्यापार के लिए ग्राम बाट देने चाहिए । यह दूकानदार निश्चित मूल्यों पर माल भण्डार से ले और समिति द्वारा निश्चित दरों पर आगे बेचें । अर्थात् परचून दर भी समिति द्वारा निर्धारित हो । जो सदस्य ऋण पर सौदा खरीदना चाहें उनके लिए भी नियमादि तथा महत्तम ऋण सीमा समिति द्वारा निर्धारित रहनी चाहिए । यह दूकानदार थोक माल केवल समिति की मध्यस्थता द्वारा ही खरीद सकेंगे । उन तरह व्यापार में व्यवहार-कुशलता रहेगी, मूल्यों पर पूर्ण नियंत्रण रहेगा, उत्पादक तथा उपभोक्ता श्रेणी का व्यापार पर पूरा नियंत्रण रहेगा, कोई एक दूकानदार डेकेंडार नहीं बन सकेगा; सहकारी भावनाएँ पनपेंगी । समिति कभी घाटे में नहीं रहेगी, मुकाबिला समाप्त हो जाएगा और मधुर में कमी होगी । उसी तरह उत्पादन सबकी व्यापार भी संगठित हो सक्ता है । स्वतन्त्रता सहकारी विचारों तथा विभागों के कार्यकर्ता इस विचार में सम्भव महत्तम न हो सकें, परन्तु किसी भी नये विचार को निदान तथा व्यावहारिकता की कमीटी पर परगना पड़ता है । उसने विचार-सकीर्णता दो स्थान नहीं मिलना चाहिए ।

है। कई राज्यों में ताल्लुका अथवा तहसील स्तर पर सहकारी समितियों के सघो अथवा मण्डलो का आयोजन किया है। ग्राम्य-स्तर पर व्यापार करने वाली संस्थाओं की सहायता तथा पोषण यह करेगी, इस संगठन के पीछे ऐसी धारणा रहती है। परन्तु यहाँ पर एक आपत्ति की जाती है कि हम इस कार्य में जितने अधिक दर्जे कायम करते हैं, उतना ही वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है।

परन्तु इस आपत्ति में जहाँ कुछ सार्थकता है वहाँ इसमें भ्रान्ति यह है कि हर ग्राम का सीधा सम्बन्ध उत्पादक केन्द्रों से होना संभव नहीं। और फिर ग्राम का उत्पादन अन्नादि की शक्ल में, जो अपनी आवश्यकता से अधिक हो, का वितरण अर्थात् विक्रय पहले अपने ताल्लुका में ही होना चाहिए। जहाँ तक मूल्य में वृद्धि का सम्बन्ध है, उसमें नियन्त्रण लाना कोई कठिन काम नहीं। और फिर यह आवश्यक नहीं है कि माल जब बड़ी मात्रा में मनो कपड़ा, गाँठों में आना हो तो वह भी माध्यमिक स्तरों पर रुके, वह सीधा उत्पादन केन्द्र से ग्राम भण्डार को जा सकता है। इसी तरह ग्राम के उत्पादन का निर्यात भी होगा। वस्तुतः यह तहसील व ताल्लुके का संगठन ग्रामों के लिए आयात-निर्यात वाली वस्तुओं की आवश्यकताओं का लेख संग्रह करके उनका प्रवन्ध करेगा। अतः प्रकट है कि इस माध्यमिक स्तर के संगठन का होना आवश्यक है। हाँ, रही मूल्य-वर्धन की बात। उसके लिए उत्पादन केन्द्र से लेकर उपभोक्ता केन्द्र तक जो व्यय डालना हो वह अखिलदेशीय संस्था द्वारा निर्धारित हो जाना चाहिए और उसका भाग अखिल देशीय राज्य, जिला व ताल्लुका या तहसील संगठन तक बाँट लेना चाहिए। और कुल इस प्रकार के व्यय के ५०% तहसील संगठन, ३०% जिला संगठन, १५% राज्य संगठन तथा ५% अखिल देशीय संगठन को जाना चाहिए। ताल्लुका या तहसील संगठन के इस संक्षिप्त विवरण के बाद जिला, राज्य तथा अखिल देशीय संगठन के विवरण की आवश्यकता नहीं रहती क्योंकि इन उपरोक्त संगठनों के कार्य भी स्तर के अनुकूल ग्राम्य संगठनों के अनुकूल ही होंगे। ऊपर के स्तरों के कार्य सहायता-परक तथा मंत्रणा आदि के होंगे। सारे सहकारी संगठन का एक मूर्तिमान चित्र अन्य अध्याय में मिलेगा। यहाँ पर केवल व्यापारिक संगठन का एक विहंगम वर्णन मात्र ही व्यर्थ है। व्यापार में व्यक्ति की कार्य-कुशलता का पूर्ण उपयोग होने के साथ-साथ व्यक्ति के आधिकारों तथा उसके महत्त्व का समाज-हित में प्रयोग होना ही सहकारिता का चरम

लक्ष्य है। समान और व्यक्ति का पारस्परिक सम्बन्ध जीव और देह के सम्बन्ध की तरह है। एक के बिना दूसरे का अस्तित्व ही नहीं रहता। एक दूसरे का पूरक है। और सहकारिता ही इन वास्तविक नाते को व्यवहृत करने की क्षमता रखती है। अतः उपरिलिखित ढंग से व्यापार को आयोजित करने से व्यापार व्यक्ति तथा समाज का नेत्रक बन सकता है, अन्यथा तो व्यापार मानव का श्वार्मा बनकर मानव के नोपण का एक आन्तुरी माधन मात्र ही बनकर रह जाता है।

: ८ :

सहकारी अधिकोपण या बैंकिंग

के लिए भी यह आवश्यक होता है कि हम व्यक्ति और समाज के नाते को भली प्रकार समझ कर ऐसी सस्थाओं का निर्माण करें जो स्वयमेव व्यक्ति तथा समाज को सत्य पथ पर चलाती रहे।

बैंकिंग—इस कार्य में भी ऐसे ही हुआ। भारत में हुड्डियों का प्रचलन था। परन्तु उसका लाभ धनिक ही उठा सका। इसी प्रकार पश्चिम में भी बैंक धनिकों की ही सम्पत्ति रहे। यह बैंक व्यक्तिगत व्यापारी व साहूकार के लिए उसके गोपण के कार्यक्रम में सहायक बन गए। आज भी ऐसी परिस्थिति है कि कई साहूकार बैंकों से सस्ते दर ऋण पर रुपया लेकर उसे किसानों या अन्य विवश व्यक्तियों को भारी दरो पर देकर अनुचित रूप से बहुत लाभ कमाते हैं। अतः समाज के लिए वरदान रूप बैंक किसान, मजदूर तथा दीन व विवश के लिए एक अभिशाप बनकर रह गये। ग्रामीण को इनसे कोई लाभ न हो सका। किसान के ऋण के दर को यह न घटा सके। उसके उत्पादन को कुछ काल जमा रखने की क्षमता भी इनकी कृपा से न आ सकी। मजदूर, किसान आदि पूर्ववत् ही साहूकार के वश में रहे। यहाँ ही यह कसूर गाथा समाप्त नहीं हो जाती। यह बैंक उन सहकारी समितियों को भी आर्थिक सहायता नहीं दे पाए जो कि किसान व मजदूर की सेवा करती थीं।

सहकारी अधिकोषण का प्रादुर्भाव सहकारी समितियों की उपरोक्त आवश्यकता ने किया। प्रारम्भिक स्तर पर तो यह कार्य ऋण-सम्बन्धी सहकारी समिति ही करती है परन्तु सहकारी समितियों को धन जुटाने के लिए बैंकों की आवश्यकता होती है जिन्हें आमतौर पर केन्द्रीय बैंक कहा जाता है। मैक्लेगन कमेटी ने इन बैंकों को निम्न तीन श्रेणियों में विभक्त किया है —

- (१) वह बैंक जिनके सदस्य केवल व्यक्ति ही बन सकते हैं।
- (२) वह बैंक जिनके सदस्य केवल सस्थाएँ या समितियाँ ही बन सकती हैं।
- (३) वह बैंक जिनके सदस्य व्यक्ति व समितियाँ दोनों बन सकते हैं।

प्रथम श्रेणी के बैंक ज्वाइंट स्टॉक बैंकों से बहुत मिलते हैं। उपरोक्त कमेटी ने इन बैंकों को सहकारिता के अनुकूल न बताकर इनको रजिस्टर न करने की सिफारिश की है। इसी कारण इनकी संख्या बहुत कम हो गई है। इस प्रकार के बैंक अब कतिपय नगरों में ही पाए जाते हैं। परन्तु ज्यों-ज्यों सहकारिता का क्षेत्र बढ़ रहा है, नगरों में इनकी आवश्यकता को फिर से अनुभव

किया जाने लगा है। क्योंकि ज्यो-ज्यो व्यापार पूर्वोक्त क्रम से आयोजित होगा, त्यो-त्यो व्यापारियों को सहकारी बैंक द्वारा कई प्रकार की सुविधाओं की आवश्यकता पड़ेगी, और अन्य प्रकार के सहकारी बैंक इस कार्य में प्रचलित नीति के अधीन सहायता नहीं दे सकेंगे। और यदि प्रारम्भिक नागरिक सहकारी समिति से सम्बद्ध व्यापारी समुदाय को सहायतार्थ ज्वाइंट स्टॉक बैंक का आश्रय लेना पड़ा तो उनका सहकारी समितियों से नाता गिथिल होता जायगा और सहकारी व्यापार पद्धति पुष्ट न हो सकेगी। इनका शेष प्रबन्ध उसी प्रकार का होगा जैसा कि अन्य अधिकोषों का।

दूसरी श्रेणी के अधिकोषों के सदस्य केवल सहकारी समितियाँ ही होती हैं। वास्तविक रूप में यह सहकारी बैंक होते हैं। इनकी हिस्सेदार भी समितियाँ ही होती हैं। इसका अर्थ यह होता है कि समितियाँ अपनी वचत से ही ऋण प्राप्त करती हैं। पहले इन बैंकों का क्षेत्र बहुत छोटा रखा जाता था और अधिक रुपये की भी आवश्यकता नहीं होती थी। कुछ सहकारी संघ मिलकर ऐसे बैंकों का निर्माण कर लेते थे। परन्तु व्यक्तियों को इनसे लाभ न पहुँचाने के कारण जनता से अमानत का रुपया भी कम जमा होता है। जनता की इसमें रुचि कम होती है। परन्तु अब तो ग्रामीण ऋण-सर्वेक्षण समिति ने यह सिफारिश की है कि केन्द्रीय बैंक बहुत छोटे क्षेत्र के लिए न हो, और जहाँ राज्य छोटा हो वहाँ एक ही राजकीय अधिकोष संगठित किया जाय और उपयुक्त स्थानों पर उसकी शाखाएँ हों। जहाँ राज्य बड़ा हो वहाँ जिले के स्तर पर केन्द्रीय बैंक संगठित किये जाय और जिला अधिकोष राज्य के निम्नरीय अधिकोष में संगठित किए जाय। परन्तु यह अधिकोष भी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा नहीं करेंगे, अतः श्रेणी (१) के अधिकोषों का संगठन प्रारम्भिक स्तर पर एक प्रारम्भिक सहकारी समिति के रूप में आवश्यक होगा, जो कि जिला अथवा बड़े अधिकोष का हिस्सेदार बनकर उनसे यथावश्यक सहायता प्राप्त कर सकेंगे। इन बैंकों को रिजर्व बैंक तथा सरकार से सहायता प्राप्त हो सकेगी।

तीसरी श्रेणी में जो अधिकोष पड़ते हैं उनके सदस्य व्यक्ति तथा समितियाँ दोनों हो सकते हैं। पहले इस प्रकार के सहकारी बैंक काफी बड़े होते थे। परन्तु भारत में अब इस कोटि के अधिकोषों को प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा। अभी

तक इस प्रकार के अधिकोष है, परन्तु शनै-शनै यह प्रयत्न किया जा रहा है कि सहकारी केन्द्रीय अधिकोषों के व्यक्तिगत सदस्य न रहने दिए जाय। केवल वही व्यक्तिगत सदस्य रहेंगे, जिन्हें मत देने का अधिकार न होगा। ग्रामीण ऋण-सर्वेक्षण समिति ने प्रस्ताव करते समय इस बात का ध्यान रखा है कि ये संस्थाएँ इतनी छोटी न हो कि इनका खर्च अधिक हो जाय और इतनी बड़ी भी न हो कि समिति और उसका उपयोग करने वालों में कोई सम्पर्क ही न रह सके।

१९५१-१९५२ में भारत में कुल मिलाकर ५०९ केन्द्रीय अधिकोष अथवा संघ थे जिनकी व्यक्तिगत सदस्य-संख्या १,१८,४०६ तथा १,१२,९१२ सहकारी समितियाँ थी। इन अधिकोषों की दशा निर्वल तथा क्षीण ही कही जा सकती है। कई राज्यों में ऐसे अधिकोषों की संख्या अत्यधिक है और सदस्य सहकारी समितियों की संख्या बहुत कम। इन अधिकोषों के कर्मचारी समुदाय को न तो पर्याप्त प्रशिक्षण मिला है और न ही इनकी संख्या पर्याप्त है। इस कारण उनका ऋण आदान-प्रदान कार्य भी सुचारुता तथा कुशलता से नहीं होता रहा। ग्रामीण ऋण-सर्वेक्षण समिति ने इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय प्रस्ताव रखे हैं, परन्तु उनका विवरण एक साधारण केन्द्रीय बैंक के संगठन तथा संचालन के वर्णन के पञ्चाङ्ग देना ही उचित होगा। एक केन्द्रीय अधिकोष आमतौर पर तो एक सहकारी समिति ही का रूप है। उसी तरह इनका संचालन होता है। केवल इनके कार्य विशिष्ट होते हैं।

पूँजी का निर्माण - अधिकोष में पहली समस्या होती है पूँजी निर्माण करने की। इन अधिकोषों के भी पूँजी निर्माण के वही साधारण साधन हैं यथा (१) हिस्से, (२) अमानते, (३) ऋण, (४) सुरक्षित कोषादि।

हिस्से—बैंकों के हिस्से भी उसी प्रकार बेचे जाते हैं जैसे अन्य समितियों के। परन्तु लोगों को बैंकों के हिस्से खरीदने की प्रेरणा देने के लिए कुछ हिस्सों को प्राथमिकता दी जाती थी। इन भागों के अधिलाभ तथा विघटन के समय इनको सर्वप्रथम सुरक्षित रखा जाता था। परन्तु इस तरह करने से प्रधानता रुपये को मिलती है मानव को नहीं, और व्यक्तिगत हिस्सेदार बढ़ जाने की संभावना रहती है। अतः इस प्रथा को शनै-शनै निरुत्साहित किया जा रहा है। प्रारम्भिक नागरिक बैंकों में ऐसा हो सकता है। हिस्से के मूल्य के सम्बन्ध

मे कोई कड़ा नियम नहीं। यह सब स्थानीय परिस्थिति पर निर्भर होता है। परन्तु जहाँ व्यक्तिगत सदस्य हो, हिस्से का मूल्य इतना होना चाहिए कि कम आय वाले लोग भी सदस्य बन सकें और बैंक धनिकों की ही ठेकेदारी न बन जाय। जहाँ बैंक की सदस्य समितियाँ हो वहाँ शेयर का मूल्य क्षेत्र की छोटी सहकारी समिति की क्षमता के अनुसार होना चाहिए। सहकारी अधिनियम के अधीन कोई भी व्यक्ति (१०,०००) रु० के मूल्य से अधिक के हिस्से नहीं ले सकता। और आमतौर पर उपरोक्त सीमा के साथ-साथ यह भी सीमा रखी जाती है कि कोई भी हिस्सेदार १०० से अधिक हिस्से न खरीदे। साथ ही कोई भी व्यक्ति कुल पूँजी के १/५ से अधिक हिस्से नहीं खरीद सकता।

बैंको में सीमित उत्तरदायित्व की पद्धति को ही अपनाया जाता है। यह उत्तरदायित्व कई स्थानों पर हिस्सों के नामांकित मूल्य तक और कई स्थानों में शेयरों के एक निश्चित गुणन तक रखा जाता है। परन्तु मेक्लेगन कमेटी की राय में अधिकोषों की सामूहिक जिम्मेदारी हिस्सों के असली मूल्य से अधिक नहीं होनी चाहिए।

लाभ वितरण—अधिकोष जो रुपया अपने कारोबार से कमाता है उसे लाभ कहते हैं। इस लाभ में से २५ प्रतिशत राशि सुरक्षित कोष में जमा करली जाती है। उर्रा तरह तो जो लाभांश सदस्यों या हिस्सेदारों में बाँटा जाता है उसपर शेयर के मूल्य के १० प्रतिशत की सीमा कानून के अधीन लागू होता है। परन्तु अधिकोष अपने उपनियमों में इससे कम एक सीमा नियत कर लेते हैं जो ६ से लेकर ८ प्रतिशत तक होती है। प्रारम्भिक समितियों की तरह अन्य निधियाँ भी होती हैं। और सबसे प्रावश्यक कोष होता है क्षतिपूर्ति कोष। क्योंकि ऋण कई बार न ठिनता से प्राप्त होता है या अप्राप्य हो जाता है, तो इस प्रकार के घाटे के लिए निधि का होना जरूरी होता है। इस प्रकार निधियों के बन जाने से अधिकोष पुष्ट तथा स्थायी हो सकता है।

अमानतें—जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है कि अधिकोषों के धन-संग्रहण एक नाधन अमानतें भी होती है। अमानतों की प्रथा एक ओर तो अधिकोष को धन उपलब्ध करानी है, और दूसरी ओर समितियों तथा अन्य व्यक्तियों में दान्त के स्वभाव को प्रोत्साहन देती है। इसी कारण इन अमानतों का व्याज दर ऐसा रखा जाता है कि जनता को उस आदत को प्रोत्साहन मिलता रहे। फिर

यह अमानते निश्चित समय के लिए होती है अतः इनका उपयोग समितियों को ऋण देने में सुगमता हो सकता है। समितियों को भी कई राज्यों में यह हिदायत रहती है कि वे अपना रिजर्व फंड (सुरक्षित कोष) अधिकोष में जमा रखें। हर राज्य ने समितियों से ऋण पर व्याज के दर तथा अमानतों के व्याज दर में परिस्थितियों के अनुसार भेद रखा है। यह भेद इसलिए आवश्यक है कि अधिकोष को अपना सारा खर्च निकालने के लिए आय चाहिए। यह भेद समितियों के लिए आमतौर पर तीन प्रतिशत होता है। और इन्हें ऐसे स्तर पर रखा जाता है कि समितियाँ अपने सदस्यों को नौ प्रतिशत प्रति वर्ष पर ऋण दे सकें।

चालू-हिसाब—प्रारम्भिक ऋण देने वाली समितियों की तरह केन्द्रीय अधिकोष भी साधारणतया चालू हिसाब नहीं खोलते थे, क्योंकि इससे अधिकोष का खर्च बढ़ जाता है, धोखा-धड़ी का भय रहता है, व्यापारी-बैंकों से सघर्ष आरम्भ हो जाता है, कर्मचारियों को कानून से परिचय की आवश्यकता अधिक हो जाती है, आदि-आदि। इस प्रकार के हिसाब पर कोई व्याज नहीं दिया जाता बल्कि चैकबुक आदि के व्यय के उपलक्ष्य में अधिकोष छमाही कुछ लेते हैं। पहले इस प्रकार के हिसाब वही केन्द्रीय अधिकोष खोलते थे जहाँ अन्य व्यापारी अधिकोष नहीं होते थे। परन्तु अनुभव से यह सिद्ध हुआ है कि अधिकोष में अधिकोषण की सब सुविधाएँ प्राप्त न हो तो अधिकोष जनप्रिय नहीं हो पाते। अतः अब इस प्रकार के सब कार्य सहकारी अधिकोष करने लग गए हैं।

* **वचत बैंक**—पहले आमतौर पर यह ख्याल था कि यह काम डाकखाने के पास ही रहने दिया जाय। परन्तु शनैः-शनैः वचत बैंक की परिपाटी देश में इतनी फैल गई है कि हर अधिकोष यह काम करता है, और इसके बिना अधिकोष अपूर्ण समझा जाता है।

ऋण-प्राप्ति के साधन—हर अधिकोष को ऋण देने का अपना कार्य चलाने के लिए स्वयं भी ऋण चाहिए। यह ऋण मिलना भी चाहिए पर्याप्त मात्रा में और सस्ते दरों पर। अतः सहकारी अधिकोषों को यह ऋण व्यापारी अधिकोषों से तो प्राप्त नहीं हो सकता। जिला अथवा इससे भिन्न स्तर पर जो केन्द्रीय सहकारी अधिकोष होते हैं वह राज्य के केन्द्रीय सहकारी अधिकोष से अपनी निश्चित महत्तम ऋण-सीमा के अन्दर ऋण प्राप्त करते हैं। राज्य के केन्द्रीय

सहकारी अधिकोष अब प्रायः सभी राज्यों में स्थापित हो चुके हैं। यह राज्य के केन्द्रीय सहकारी अधिकोष-ऋण रिजर्व बैंक तथा राज्य शासन से प्राप्त करते हैं। राज्य-सरकार तो इस प्रकार का ऋण विशेष कार्यों के लिए देती है। परन्तु रिजर्व बैंक इस सगठन को चालू रखने के लिए ऋण देता है। रिजर्व बैंक का 'कृषि साख विभाग' यह कार्य करता है। और जो सहायता उक्त बैंक के उपरिलिखित विभाग ने केन्द्रीय सहकारी बैंक को, विशेषतया नये सहकारी आन्दोलन को साधारणतया दी है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। काश्तकार के ऋण पर व्याज-दर कम करने के अभिप्राय से इसी बैंक ने करोड़ों रुपये १½ प्रतिशत प्रति वर्ष के व्याज पर राज्यों के केन्द्रीय सहकारी अधिकोषों को दिया है। शासन आमतौर पर ३½ प्रतिशत प्रति वर्ष के व्याज दर पर ऋण देता है।

प्रवाहशील पूजी—अधिकोषों को आमतौर पर रुपये की आवश्यकता रहती है। और यदि वह सारी धनराशि को दीर्घकाल के लिए ऋण आदि में लगा दे तो उनको आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन जल्दी ही उपलब्ध नहीं हो सकता। इसलिए अधिकोष कुछ पूजी ऐसी रखते हैं जो एकदम वसूल की जा सके और शीघ्र अदायगी के लिए प्रयोग में लाई जा सके। ऐसी पूजी को अधिकोष की प्रवाहशील पूजी कहते हैं। केन्द्रीय अधिकोषों की प्रवाहशील पूजी में इतना रुपया होना चाहिए कि यदि किसी समय ऋण आदि का रुपया वसूल न किया जा सके, तो भी अधिकोष अपने कारोबार को चला सके और सदस्य-समितियों की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। कई बार ऐसा हो जाता है कि फसल खराब हो जाती है, या अचानक भाव गिर जाते हैं, या बीमारी पड़ जाती है। ऐसी अवस्था में समितियाँ ऋणों की किश्त समय पर नहीं दे सकती तथा उन्हें और रुपये की आवश्यकता होती है। इस मौके पर यदि बैंक के पास पर्याप्त मात्रा में प्रवाहशील पूजी न हो तो काम में रुकावट पड़ सकती है। कुल कार्यगत पूजी का कितना अंश प्रवाहशील पूजी रहे, इसके सम्बन्ध में नियमों आदि में विधान रहते हैं। उनकी सूची बनाकर बड़े बैंक तथा विभाग में भेजनी पड़ती है।

अतिरिक्त-निधि—सहकारिता का प्रधान उद्देश्य यह है कि लोग वचत का स्वभाव पैदा करे, ऋण न ले और स्वावलम्बी हो जाय। अतः जब केन्द्रीय

अधिकोष अपने क्षेत्र में ठीक रूप से काम करते हैं तो इन अधिकोषों के पास समय पर किश्त प्राप्त होने तथा समितियों को ऋण की अधिक जरूरत होने के कारण केन्द्रीय अधिकोषों के पास अतिरिक्त राशि जमा हो जाती है। यह धन-राशि जब अस्थायी रूप से जमा होती है तो वह राज्य के निखरीय अधिकोष, और जहाँ ऐसे अधिकोष न हों तो भारत के स्टेट बैंक में अस्थायी अमानत में जमा करते हैं, और यदि स्थायी हो तो स्थायी अमानत में। स्वतंत्रता से पूर्व ऐसी परिस्थिति जिला होशियारपुर (पंजाब) के कुछ केन्द्रीय अधिकोषों में हो गई थी। परन्तु ऐसी दशा तब ही हो सकती थी जब सहकारिता अपना मुख्य उद्देश्य ऋण तक ही सीमित रखती थी तथा अन्य कार्यों को ऋण के साथ संगठित नहीं किया गया था। अब नगठित कार्य-पद्धति को अपनाने से जहाँ ऋण, भण्डार, व्यापार, उद्योग तथा कृषि-सुधार को एक दूसरे पर आश्रित समझा जा रहा है, ऐसे अतिरिक्त-धन के जमा होने की संभावना कम हो गई है।

पूँजी का उपयोग—केन्द्रीय अधिकोष का मुख्य ध्येय तो यह होता है कि वह समितियों को ही रुपया दे, व्यक्तियों को नहीं। परन्तु व्यक्तियों के लिए और अधिकोष न होने पर, तथा व्यक्तियों के साथ व्यवसाय द्वारा आय-प्राप्ति अथवा सदस्यों को या प्रबन्धक-समिति के मित्रों को अनुगृहीत करने के लिए केन्द्रीय अधिकोष व्यक्तियों को ऋण अभी तक देते हैं। वस्तुतः होना तो इस तरह चाहिए कि जिस नगर में ऐसे कार्य की आवश्यकता हो वहाँ नागरिक-सहकारी-अधिकोष खोल दिया जाय। यह सहकारी अधिकोष केन्द्रीय अधिकोष का सदस्य बनकर ऋण प्राप्त कर सकेगा और स्वयं एक प्रारम्भिक सहकारी समिति की तरह समाज की सेवा कर सकेगा। इस प्रकार केन्द्रीय सहकारी बैंक को कोई ऐसा कार्य करने की आवश्यकता न रहेगी। जहाँ भूमि बन्धक बैंक न हो वहाँ केन्द्रीय बैंक सहकारी समितियों द्वारा दीर्घकालीन ऋण भी दे सकता है। वहाँ जो बन्धक पत्र समिति के नाम होंगे वही पत्र केन्द्रीय अधिकोष के पास बन्धक के रूप में रखे जा सकते हैं।

सदस्य समितियों की साख का परीक्षण—केन्द्रीय बैंक का वास्तविक ध्येय ग्रामीण समितियों को आर्थिक सहायता देना है। ग्रामीण सहकारी समितियाँ भी अब केवल शुद्ध ऋण सम्बन्धी समितियों को छोड़कर सीमित उत्तरदायित्व

वाली होती है। आमतौर पर देखा गया है कि सहकारी विभाग के कर्मचारियों की सिफारिश पर केन्द्रीय बैंक समितियों को ऋण दे देते हैं। परन्तु इस पद्धति में एक निर्वलता है कि विभाग के कर्मचारीगण तबदील होते रहते हैं। उनका अधिकोष के आर्थिक हित से कोई घनिष्ठ सम्बन्ध नहीं होता। उनकी उन्नति की निर्भरता आन्दोलन की सफलता पर नहीं होती। उनके अन्तःकरण में अभी आन्दोलन के लिए विश्वासजनित श्रद्धा का प्रादुर्भाव नहीं हुआ। इन कारणों से उनकी सिफारिशों में उस सजीव उत्तरदायित्व की भलकें नहीं दिखाई पड़ती जिसके बिना आन्दोलन का पनपना कठिन होता है। फल यह होता है कि इस प्रकार प्रदत्त ऋणों की वसूली में कठिनाइयाँ होती हैं। जहाँ तक केन्द्रीय अधिकोषों के संचालक परिषदों के निर्णयों का सम्बन्ध है, वहाँ भी आँकड़ों के तथ्यों को भूलकर कई अन्य कारणों से प्रभावित होकर ऋण प्रदान कर दिए जाते हैं।

अतः आवश्यक है कि अधिकोषों के पास अपना कोई ऐसा प्रबन्ध होना चाहिए कि वे ऋण देने से पूर्व समिति की ऋण को समय पर लौटाने की शक्ति का अनुमान लगा सकें। अधिकोष को इस ज्ञान की भी आवश्यकता होती है कि ऋण लेने वाली समिति के सदस्य अपने उत्तरदायित्व को कहाँ तक अनुभव करते हैं। वह सभा के ऋण लौटाने में कैसे है, आदि आदि। इन बातों को जानने के लिए अधिकोष एक नक्शा तैयार करता है। इसमें हर सदस्य की चल तथा अचल सम्पत्ति, एवं समिति की समस्त सम्पत्ति को दर्ज किया जाता है। ऋणों की वापसी में नियामकता का व्यौरा भी रहता है। जहाँ सदस्य-समितियों का उत्तरदायित्व असीमित होता है, वहाँ सदस्यों की कुल सम्पत्ति के तीसरे भाग तक, आमतौर पर ऋण मिलता है। जहाँ उत्तरदायित्व सीमित हो वहाँ सामूहिक उत्तरदायित्व अथवा उपरोक्त तीसरे भाग से जो भी कम मात्रा हो, वहाँ तक ऋण दिया जाना चाहिए। जहाँ केन्द्रीय अधिकोष अथवा अधिकोषण सघन न हो, और एक ही सहकारी शिखरीय अधिकोष सारे राज्य का हो, वहाँ इस प्रकार की तालिकाएँ अधिकोष की हर शाखा में होनी चाहिए। सदस्य-सभाओं की इस प्रकार साख-निरीक्षण से अधिकोष सतर्क होकर काम कर सकता है। वह यह भी देख सकता है कि कौन समिति कितने तथा कितने समय के लिए ऋण की पात्र है। इतना ही नहीं, अधिकोष को चाहिए कि

जिन समितियों को ऋण दिया गया हो उनका अपने कर्मचारी समुदाय में किसी योग्य व्यक्ति द्वारा समय-समय पर निरीक्षण करवाए, ताकि इस बात का पता रहे कि ऋण का ठीक उपयोग हो रहा है या नहीं, और वही धन का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा।

हर ऋण एक निर्दिष्ट नमूने के फार्म पर लिखे प्रार्थना-पत्र पर विचारणीय होना चाहिए, जिसमें ऋण किस काम के लिए चाहिए, कितना चाहिए, कितनी किस्तों में वापस होगा, कितना पहले ऋण है, महत्तम ऋण-सीमा क्या है, समिति का प्राप्तव्य ऋण कितना है, अवधि के अन्दर न प्राप्त होने वाला ऋण कितना है, आदि। बैंक अपने कर्मचारियों द्वारा समितियों का जो निरीक्षण कराए उसमें हिसाब के पक्ष पर विशेष ध्यान देना चाहिए। बैंक के लिए हिसाब पर ध्यान देने की जितनी आवश्यकता होती है उसके लिए अधिकोप को विभाग पर अत्यधिक आश्रित नहीं रहना चाहिए।

केन्द्रीय अधिकोषों को इसमें साधारणतया यह आपत्ति होती है कि उनके पास इतने कर्मचारी रखने के लिए धन नहीं होता कि यह सब काम हो सके, परन्तु सूक्ष्म-वृक्ष से काम किया जाय तो इस कार्य के लिए न तो उनको बहुत स्टाफ की आवश्यकता होती है, और न अधिक धन की। यह कार्य इतना आवश्यक है कि यदि यह न किया जाय तो अधिकोष को बहुत हानि की सम्भावना रहती है।

जिस तरह केन्द्रीय अधिकोष को आवश्यक है कि सदस्य-समितियों की देख-रेख रखे, इसी तरह राज्य के सहकारी बैंक के लिए सदस्य केन्द्रीय अधिकोषों की निगरानी करना आवश्यक है। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि इस देख-रेख के बाद विभाग का कोई उत्तरदायित्व नहीं रहता। निरीक्षण तथा हिसाब की जांच अब तो विभाग के कानूनी कर्तव्य बन गये हैं और उनके लिए यह करना अनिवार्य तथा आवश्यक है।

अवशेष पत्र—हर केन्द्रीय अधिकोष को अपना बेलेंस-शीट हर वर्ष छपवाना पड़ता है। यह अवशेष-पत्र सहकारी वर्ष की समाप्ति पर अर्थात् ३० जून के पश्चात् तैयार होता है। इसकी एक प्रति रजिस्ट्रार को भेजनी आवश्यक होती है। परन्तु इसकी प्रति सदस्यों, और यदि संभव हो सके तो अमानतदारों को भी भेजनी चाहिए। इस अवशेष-पत्र पर ऑडिटर का प्रमाण-पत्र होता है और

अधिकोष के मैनेजर, अकाउंटेंट तथा तीन डायरेक्टरों के उस पर हस्ताक्षर होते हैं। अवशेष-पत्र में यह स्पष्ट होगा कि अधिकोष की सम्पत्ति व दायित्व कितने हैं। भाग-मूल्य कितना चुकाया जा चुका है। स्थायी सम्पत्ति का मूल्य क्या है। कुल कितने हिस्से हैं। कितने ऋण दातव्य हैं और कितने प्राप्तव्य हैं, आदि।

वार्षिक व त्रैमासिक तालिकाएं—यह जानने के लिए अधिकोष की परिस्थिति किस तरह की है और वह कैसे उन्नति कर रहा है, विभाग केन्द्रीय अधिकोषों से वार्षिक व त्रैमासिक तालिकाएं मगवाता है। इन तालिकाओं में सम्पत्ति व उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त प्राप्तव्य ऋणों का भी व्योरा रहता है तथा उसकी प्रवाहशील पूंजी कितनी है और ठीक ढंग से प्रयुक्त होती है या नहीं। इन तालिकाओं से विभाग केन्द्रीय अधिकोषों की गतिविधि से परिचित रहता है और उन्हें यथासमय उपयुक्त मंत्रणा तथा सहायता दे सकता है।

संचालक-परिषद—हर केन्द्रीय अधिकोष के प्रबन्ध के लिए एक संचालक परिषद निर्वाचन द्वारा नियुक्त की जाती है। इस निर्वाचन में अधिकोष के हिस्सेदार भाग लेते हैं। इन अधिकोषों में कई बार प्रधान चुना जाता है और कई बार सरकारी कर्मचारी उपनियमानुसार मनोनीत होता है। कई राज्यों में राज्य के सहकारी अधिकोष का प्रधान रजिस्ट्रार और जिले के केन्द्रीय अधिकोषों का प्रधान अपने पद के नाते डिप्टी-कमिश्नर होता है। संचालक-परिषद के सदस्यों की संख्या परिस्थिति के अनुसार रखी जाती है। और फिर संचालक-परिषद कार्य चलाने के लिए अपने आपको उपसमितियों में विभक्त कर लेती है। दैनिक प्रबन्ध सम्बन्धी कार्य के लिए भी समिति बना ली जाती है। यह समिति थोड़े व्यय में केन्द्रीय अधिकोष का दिन-प्रतिदिन का कार्य चला लेती है। जहाँ केन्द्रीय अधिकोष के सदस्य समितियाँ व व्यक्ति दोनों होते हैं, वहाँ संचालक-परिषद में व्यक्ति तथा सभा-प्रतिनिधियों की संख्या निर्धारित कर दी जाती है। ताकि अधिकोष पर व्यक्तियों का ही अधिकार न हो जाय।

हर एक सहकारी समिति की तरह इनमें भी पूर्ण अधिकार तो माधारण अधिवेशन को ही होते हैं। हर सदस्य का एक ही मन होता है।

जैसा कि पहले लिखा जा चुका है कि अधिवेशन के कार्य के सम्बन्ध में अभीरा मान समिति के बड़े ही मूल्यवान् प्रस्ताव हैं। उन प्रस्तावों का मंथन विवरण इस प्रकार है—

राज्य सहकारी बैंक

सदस्यता—इन अधिकोषों के सदस्य क्षेत्र के सभी केन्द्रीय अधिकोष होने चाहिए। वह प्रारम्भिक सहकारी समितियाँ भी सदस्य बन सकती हैं जिनका लेन-देन सीधा राज्य-सहकारी बैंक से हो। जहाँ राज्य-सहकारी अधिकोष का सीधा सवध प्रारम्भिक सहकारी समितियों से हो, वहाँ दूरस्थ समितियों की सेवा के लिए उक्त अधिकोष की शाखाएँ होनी चाहिए। व्यक्तिगत सदस्यों की संख्या बहुत ही सीमित होनी चाहिए।

संचालन—यद्यपि यह एक साधारण परिणाम मालूम देता है कि राज्य के भाग की मात्रा अधिक (५१%) होने पर राज्य को मत प्रदान का अधिकार बहुमत में होना चाहिए। परन्तु साधारणतया कमेटी का प्रस्ताव यह है कि संचालकों में $\frac{1}{2}$ से अधिक राज्य के प्रतिनिधि नहीं होने चाहिए।

कहना न होगा कि इस प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर गैर-सरकारी हल्कों में बहुत विरोध हुआ। और वह चाहते थे कि सरकार का एक मनुष्य—एक मत—के आधार पर एक ही मत होना चाहिए। आखिर रजिस्ट्रार-सम्मेलन ने यह निर्णय किया है कि सरकारी संचालकों की संख्या ३ या कुल का $\frac{1}{3}$ होनी चाहिए।

कमेटी की यह भी सिफारिश है कि कुछ मामलों में सरकार को ऐसे अधिकार रहने चाहिए कि वह संचालक परिषद के निर्णय को बदल सके। यह अधिकार मोटे तौर पर निम्न विषयों पर होने चाहिए—

- (१) वित्त सम्बन्धी नीतियों का ठीक होना,
- (२) ऋण सम्बन्धी नीति के उद्देश्य व ध्येय,

राज्य के प्रतिनिधियों में रजिस्ट्रार तथा वित्त विभाग के अधिकारी व अधिकोषण विशेषज्ञ होने चाहिए। अधिकोष के प्रबन्ध-संचालक (मैनेजिंग-डायरेक्टर) की नियुक्ति पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, और इसकी नियुक्ति पर राज्य की स्वीकृति आवश्यक रहनी चाहिए।

भाग-धन—राज्य द्वारा हिस्सों के लिये जाने के अतिरिक्त दो और भाग-धन जुटाने के साधन सुझाये गए हैं, यथा—सदस्य केन्द्रीय अधिकोषों तथा सहकारी समितियों को प्रेरित करना कि वह अपने भाग-धन के एक निर्दिष्ट भाग के मूल्य

के हिस्से खरीदे और सदस्यों को ऋण-प्राप्त करने के अधिकार को उनके भाग-धन से सम्बन्धित किया जाय । परन्तु इन उपायों को प्रयोग करते वक्त इस बात का ध्यान रखा जाय कि कहीं इस आन्दोलन की उदार नीतियों को हानि तो नहीं पहुच रही । राज्य सहकारी अधिकोषों के उपनियमों में यह प्रावधान रहना चाहिए कि राज्य सहकारी अधिकोष केन्द्रीय सहकारी अधिकोषों में भाग ले सके ।

ऋण-कार्य—ऋण देने में प्राथमिकता कृषि सम्बन्धी कार्यों के लिए दी जानी चाहिए । व्यक्तियों तथा व्यापारियों को ऋण देना समाप्त ही कर देना चाहिए, या उनकी स्थायी अमानतों की जमानत पर बहुत ही कम मात्रा में दिया जाना चाहिए । अल्पकालीन-ऋण के लिए प्राप्त धन-राशि को दीर्घकाल के ऋणों के लिए प्रयुक्त नहीं करना चाहिए ।

परिणामस्वरूप इन अधिकोषों को आन्दोलन के मूल स्तम्भ के रूप में काम करना चाहिए । इनके सदस्य अधिकोषों से पर्याप्त घनिष्ठ सम्बन्ध होने चाहिए । और सदस्य सस्थाओं के अतिरिक्त कोष इनके पास जमा रहने चाहिए ।

केन्द्रीय भूमि-बन्धक अधिकोष

साधारण—कमेटी का प्रस्ताव यह है कि हर राज्य में एक इस प्रकार का अधिकोष होना चाहिए, और हर राज्य को चाहिए कि वह अपने रयतदारी व काश्तकारी सम्बन्धी कानूनों को पडताल करके सशोधित करे ताकि भूमि-बन्धक अधिकोषों का कार्य सफलतापूर्वक चलता रहे । इनकी रजिस्ट्री आदि करने का कार्य सादा, सुगम तथा सस्ता हो ।

भाग-धन—सरकार को इनके भाग-धन में कम से कम ५१ प्रतिशत लगाना चाहिए । और संभवतः उनमें सरकार को और भी अधिक भाग लेने पड़े क्योंकि आवश्यकता अधिक है । भूमि-सुधार की योजनाएँ इतनी व्यापक हैं कि इनके लिए काफी धन चाहिए । और साथ उक्त भू-सुधार योजनाएँ केन्द्रीय तथा प्रारम्भिक भूमि-बन्धक अधिकोषों के बिना सफल नहीं हो सकेंगी । केन्द्रीय भूमि-बन्धक अधिकोषों के उपनियमों में यह प्रावधान रखना ठीक रहेगा कि वह प्रारम्भिक अधिकोषों में भाग ले सके ।

ऋण-नीति में परिवर्तन—आज तक ऋणों की बहुसंख्या पुराने ऋणों

अथवा बन्धको की मुक्ति हेतु दी जाती थी। परन्तु अब यह आवश्यक हो गया है कि इन अधिकोषों की ऋण-दान नीति भू-सुधार योजना के पूर्णतया अनुकूल होनी चाहिए जिसमें बाध बनाना, कुए खोदना, पम्प प्राप्त करना, कृषि-यन्त्रों का क्रय आदि भी शामिल हो।

प्रारम्भिक अधिकोषों को मन्त्रणा दी जानी चाहिए कि वे विकासात्मक ऋणों को प्राथमिकता दे। (५०००) से अधिक ऋण भू-विकास कार्यों के सिवा अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं दिया जाना चाहिए।

इसलिए कि ऋण-प्रदान कार्य का उत्पादन तथा विकास से सीधा सम्बन्ध रहे, प्रशासन में भी कुछ सशोधन करने पड़ेगे, यथा—

- (१) हर क्षेत्र के लोगों को इस बात का ज्ञान कराना कि ऋण-योजना क्या है और ऋण किस प्रकार प्राप्त हो सकते हैं।
- (२) सम्बन्धित तथा उपयुक्त विभागों से पूर्ण ताल-मेल।
- (३) जहाँ भूमि-बन्धक अधिकोषों में आवश्यक हो कर्मचारी समुदाय में वृद्धि की जाय, विशेषतः पर्यवेक्षण के लिए। इस कर्मचारीवर्ग का भली प्रकार प्रशिक्षित होना बड़ा आवश्यक है।
- (४) यह जरूरी है कि भू-सुधार के लिए पर्याप्त धन प्राप्त हो। यह भी आवश्यक होगा कि बन्धक भूमि के मूल्य का कुछ भाग ऋण-रूप में देने के समय, मूल्य जो सुधार के पश्चात् हो, उसको ध्यान से रखना चाहिए। उसकी जमानत लेनी पड़ेगी कि यदि सुधार न हो तो जमानत जिम्मेदार होगी। यह जमानत सरकार को ही देनी उचित होगी।
- (५) रूषया प्राप्ति में देरी का कारण आमतौर पर अधिकार प्रलेख का प्रमाणीकरण होता है। शीघ्रता के लिए इसके लिए भी जमानत ली जा सकती है, जो अधिकार प्रलेख के प्रमाणित होने पर मुक्त हो जायगी। हर प्रारम्भिक भूमि-बन्धक अधिकोष के पास (२५,०००) रु० का और गिर-रीय अधिकोष के पास ५ लाख का गारंटी फंड होना चाहिए।
- (६) यही अधिकोष सरकार के भू-सुधार हेतु दिये जाने वाले ऋणों की एजेंसी होनी चाहिए।
- (७) इन अधिकोषों के ऋण १५ से २० वर्ष तक के लिए आयोजित होने चाहिए।

- (द) केन्द्रीय अधिकोषो को ऋणों के प्रयोजनों के अनुसार १५ से २० वर्ष के लिए डिबेचर जारी करने चाहिए ।
- (६) राज्य की ओर से निम्न सहायताएं मिलनी चाहिए —
- (क) केन्द्रीय भूमि-बन्धक अधिकोषों के ऋण-पत्रों के मूलधन तथा व्याज की जमानत देना ;
- (ख) भूमि के मूल्यांकन तथा भू-सुधार योजनाओं के परीक्षण के लिए कर्मचारी वर्ग का प्रबन्ध ,
- (ग) इनको अधिक धन प्राप्त करने की सुविधाएं देना, जब तक कि वह पर्याप्त मात्रा में बन्धक प्राप्त कर सकते हों और जिनकी जमानत पर ऋण-पत्र या डिबेचर जारी कर सकें ,
- (घ) स्टाम्प तथा प्रमाणीकरण रजिस्ट्रेशन शुल्क से छूट ;
- (ङ) इन अधिकोषों के सुगमतापूर्वक संचालन के दृष्टिकोण से विशेष कानून बनाना, नियमों के साथ यह भी ध्यान रखना कि प्राप्तव्य-ऋण शीघ्र वसूल हो सके ,
- (च) अविकसित क्षेत्रों में ऐसे अधिकोषों को विशेष सहायता देनी चाहिए जिससे प्रशासनिक व्यय में सहायता भी शामिल हो ।

केन्द्रीय सहकारी कोष

जिला स्तर पर कमेटी की राय है कि राज्य के गिखरीय अधिकोष की शाखा के स्थान केन्द्रीय अधिकोष की स्थापना श्रेयस्कर होगी । परन्तु कम विकसित क्षेत्रों में राज्य के सहकारी अधिकोष की शाखा अधिक लाभप्रद रहेगी । परन्तु नीति का आधार यह होना चाहिए कि अन्त में उक्त शाखा जिला केन्द्रीय अधिकोष का स्वरूप ग्रहण कर ले ।

जहां तक दीर्घकालीन ऋण का प्रश्न है कइयों की राय यह है कि जिला-स्तर पर यह कार्य भी केन्द्रीय सहकारी-अधिकोष ही करे । परन्तु मद्रास के अनुभव से यह सिद्ध है कि जब राज्य-स्तर पर केन्द्रीय भूमि बन्धक अधिकोष हो तो जिला-स्तर पर भी ऐसी सस्था का होना उपयुक्त है । परन्तु जब तक इस प्रकार के भूमि-बन्धक अधिकोष की स्थापना न हो, तब तक केन्द्रीय सहकारी-अधिकोष को एक पृथक् विभाग रखना चाहिए, जिससे वह केन्द्रीय भूमि-बन्धक अधिकोष के एजेण्ट के तौर पर काम करे । ऋण प्राप्त करने वाले केन्द्रीय

भूमि-बन्धक अधिकोष के सदस्य होने चाहिए। जब यह काम बढ जाय तो उक्त विभाग को शाखा मे परिवर्तित किया जा सकता है। परन्तु इसे केन्द्रीय सहकारी अधिकोष के भवन मे ही रहना चाहिए। जब यह कार्य और प्रगति कर जाय तो यही शाखा प्रारम्भिक भूमि-बन्धक अधिकोष मे बदल जायगी।

जो राज्य छोटे है, वहा राज्य के सहकारी अधिकोषो की शाखाए ही पर्याप्त होगी, केन्द्रीय अधिकोषो की स्थापना की आवश्यकता नहीं रहेगी।

कमेटी का मत है कि हर राज्य के अधिकोषण की पुष्टि हेतु योजना बनानी चाहिए। उन्होंने केन्द्रीय सहकारी अधिकोष के महत्व पर बहुत जोर दिया है और आवश्यकतानुसार जिला जसे छोटे स्थान के लिए भी ऐसे बैंक की स्थापना को भी आपत्तिजनक नहीं बताया। परन्तु सिफारिश यह है कि बहुत छोटी इकाइया नहीं होनी चाहिए। उनका कहना है कि प्रदत्त भाग-धन ३ लाख और कार्य-वाहक पू जी २०-२५ लाख होनी चाहिए। शासन को अधिकार होना चाहिए कि सचालक-परिषद के निर्णय जब कभी आवश्यकता हो बदल सके और परिषद मे बहुत ज्यादा सदस्य न हो। राज्य कर्मचारी प्रधान, नियम नहीं बरन् अपवाद रूप मे होना चाहिए। रानीय स्टेट बैंक का एजेण्ट अवश्य सचालक-परिषद पर मनोनीत होना चाहिए। केन्द्रीय अधिकोषो के उपनियमो मे यह नियम चाहिए कि वह प्रारम्भिक सहकारी समितियो मे भाग ले सके।

इन केन्द्रीय सहकारी अधिकोषो का प्रधान कार्य यह होना चाहिए कि कृषि साख सहकारी समितियो को ऋण दे। व्यक्तिगत किसानो की मददस्यता इन अधिकोषो मे केवल अन्तरिम काल के लिए होनी चाहिए।

नागरिक अधिकोष

इनके सम्बन्ध मे कमेटी के सुझाव यह है कि वह केवल उन्ही जगहो मे प्रारम्भिक सहकारी समितियो से ऋण का आदान-प्रदान करे जहा केन्द्रीय सहकारी अधिकोष या राज्य सहकारी अधिकोष की शाखा न हो, और वह भी ५ मील की परिधि मे। इनका अतिरिक्त-धन केन्द्रीय सहकारी अधिकोष या राज्य सहकारी अधिकोष मे जमा होना चाहिए।

इन सिफारिशो से यह बात तो प्रकट है कि सहकारी अधिकोषण के पुष्टि-करण की महत्ता पर उक्त कमेटी ने बडा जोर दिया है। और इसमे कोई सदेह नहीं कि बिना इस अंग की पुष्टि के सहकारी आन्दोलन सफल नहीं हो सकेगा।

परन्तु यह एक विचारणीय प्रश्न है कि क्या शासन के ५१ प्रतिशत हिस्से तथा शासन के बढ़ते हुए नियंत्रण से सहकारिता के जनतंत्री आन्दोलन को वास्तविक पुष्टि मिल सकेगी या नहीं ? दूसरा प्रश्न यह है कि क्या इन अधिकोषों को प्रारम्भिक अवस्था में ही सहकारी समितियों से पर्याप्त काम मिल सकेगा जिससे वह स्वावलम्बी हो सके । शासन का इस प्रकार का भाग तथा नियंत्रण उसी अवस्था में आन्दोलन के लिए सहायक सिद्ध होगा जब कि शासन के कर्मचारी सहकारिता के सिद्धान्तों से पूर्णतया परिचित हो तथा उसके मूल भाव उनके हृदयगम होकर उनका एक विश्वास बन चुके हों । क्योंकि सहकारिता का केन्द्र वस्तुतः रजिस्ट्रार होता है, अतः रजिस्ट्रार की छांट व नियुक्ति बड़े विचार से होनी चाहिए । उपयुक्त व्यक्ति की नियुक्ति के उपरान्त उसे पर्याप्त प्रशिक्षण मिलना चाहिए और फिर उसका इसी पद पर काफी काल के लिए रहना बहुत ही आवश्यक है । यदि आज जनता में सहकारी भावों से ओत-प्रोत व्यक्तियों का अभाव है तो कर्मचारी समुदाय में यह अभाव और भी अधिक है । आन्दोलन मूलतः जनता का आन्दोलन होने के कारण शासन का इतना अधिक भाग कुछ उपयुक्त नहीं दीखता । अतः इसमें यदि रिजर्व बैंक के ही राज्य के स्थान पर भाग रखे जाय, सरकार की समस्त सहायता रिजर्व बैंक द्वारा जाय, उनके ही मनोनीत व्यक्ति प्रबन्धक-समितियों पर हों, तो संभवतः अधिक व्यावहारिक होगा । इस तरह रिजर्व बैंक शनैः-शनैः सहकारी अधिकोषण संस्थाओं को स्वावलम्बी बनाता चला जायगा ।

प्रारम्भिक दशा में सहकारी समितियों से इन अधिकोषों को पर्याप्त काम नहीं मिल पायगा । और इन अधिकोषों को स्वावलम्बी बनाने के लिए इन्हें साधारण बैंकिंग कार्य करने की छूट देनी पड़ेगी । परन्तु यह ठीक है कि केन्द्रीय अधिकोष यह कार्य कम से कम करे । इस कार्य के लिए नागरिक सहकारी अधिकोषों का एक जाल बिछाना पड़ेगा । यह सब नागरिक अधिकोष केन्द्रीय अधिकोषों के सदस्य होंगे । इस तरह व्यापारी वर्ग जो शनैः-शनैः सहकारिता को अपनाता चला जायगा, इन अधिकोषों से सहायता प्राप्त कर सकेगा । कृषि सहायक कार्य को व्यापार से पूर्णतया पृथक् रखकर सफल नहीं किया जा सकता । यह बात तो अब सर्वमान्य है ही । अतः ज्यों-ज्यों व्यापार सहकारी क्षेत्र में आता चला जायगा, इस तरह की बैंकिंग की आवश्यकता बढ़ती जायगी और व्यक्तियों

से पर्याप्त मात्रा में धन सहकारी बैंक को प्राप्त हो सकेगा ।

सहकारी अधिकोषण का आधार इस प्रकार निर्मित होगा कि आरम्भ में ग्राम-स्तर पर प्रारम्भिक सहकारी समितियाँ होगी और नगर-स्तर पर नागरिक सहकारी अधिकोष होंगे । इनसे ऊपर साधारणतया केन्द्रीय सहकारी अधिकोष होंगे, जिनका आर्थिक ढाँचा पर्याप्त पुष्ट होगा । अर्थात् जिनका प्रदत्त भाग-धन ३ लाख से कम न हो और कार्यवाहक पूँजी २०-२५ लाख होगी । जहाँ राज्य छोटे हो वहाँ प्रारम्भिक स्तर के बाद सीधा राज्य सहकारी अधिकोष होगा । और जिला-स्तर पर राज्य सहकारी अधिकोष की अन्तरिम काल में केवल शाखाएँ होगी ।

इन केन्द्रीय सहकारी अधिकोषों की सदस्यता से राज्य के सहकारी अधिकोष का निर्माण होना चाहिए । इन अधिकोषों में व्यापार का कार्य जैसा कि गत महा-युद्ध में होता रहा, नहीं होना चाहिए । वह कार्य व्यापार सम्बन्धी अथवा बहुदेशीय सहकारी समिति के ही अधीन रहना चाहिए । विभाग का कार्य केवल मन्त्रणा, निरीक्षण तथा हिसाब की जाँच रहना चाहिए । और भाग-धन तथा मनोनीत सदस्य रिजर्व तथा स्टेट अधिकोष द्वारा ही आने चाहिए ।

यदि आन्दोलन को पुष्ट करने के साथ-साथ उसके जनतंत्री गुण तथा सैद्धान्तिक पुष्टि का संरक्षण करना है तो उपरोक्त सुझाव अवश्य ही विचारणीय तथा प्रयोग में लाने योग्य है ।

: ६ :

बहुदेशीय-सहकारिता

इंग्लैंड की प्रसिद्ध औद्योगिक क्रान्ति के पश्चात् समस्त कार्यों में एक नई पद्धति का प्रादुर्भाव हुआ । हर काम में विशेषता आने लगी । यो तो पहले भी ऐसा क्रम था जैसा कि भारत के वर्ण-व्यवस्था द्वारा कार्य-विभाजन से प्रकट है, परन्तु उपरोक्त क्रान्ति के पश्चात् उद्योग तथा व्यापार में और भी विशिष्टता

आने लगी । इसी कार्य-विभाजन की पद्धति का प्रभाव सहकारिता के आन्दोलन पर भी स्वाभाविक था । यदि इस आन्दोलन के मूल पर विचार किया जाय तो यह प्रत्यक्ष दीखता है कि यह आन्दोलन प्रधानतया तो ग्रामीणों का है, जिनकी छोटी-छोटी सामूहिक आवश्यकताएँ होती हैं । मानव का शरीर अपने पोषण के लिए कई वस्तुओं का ग्राहक होता है । और ग्राम में इसकी इन आवश्यकताओं को पृथक्-पृथक् दूकानों द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता । पृथक्-पृथक् दूकानों तो नगरों के जीवन के नखरे हैं । अतः ऐसे आन्दोलन को सकीर्ण तथा सकुचित करके एकोद्देशीय बनाने का प्रयास इस आन्दोलन के मूल स्वभाव से ही विपरीत मालूम देता है । ऋण के लिए पृथक्, व्यापार के लिए पृथक्, कृषि के लिए पृथक् तथा उद्योग के लिए पृथक् समिति का निर्माण हर ग्राम के लिए करना सहकारी भावनाओं से खेलना मात्र है । इतना ही नहीं, जब यह सकीर्णता बढी तो एक-एक ग्राम में ब्राह्मणों, राजपूतों, भीवरों व चमारों आदि की पृथक्-पृथक् समितियों का निर्माण होने लगा । पर यह सब समितियाँ ऋण देने का ही कार्य करती थी । इस सम्बन्ध में अब भी पृथक्-पृथक् विचार है । रूढ़िवादियों का कथन है कि यह समितियाँ पृथक्-पृथक् होनी चाहिए और यह पृथक्ता केन्द्रीय समितियों तथा सघों तक चलती है । इस पद्धति का फल यह होता है कि एक ध्येय वाली सहकारी समितियों को पर्याप्त काम नहीं मिलता और सहकारी समितियाँ पुष्ट तथा शक्तिशाली नहीं हो पाती । साथ ही ग्रामीणों की एक प्रकार की आवश्यकता-पूर्ति का प्रयत्न करने वाली समिति ग्रामीणों को शेष आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों की शरण लेने को मजबूर करती है । इसका फल यह होता है कि सामूहिक रूप से ग्रामीण सहकारिता के लाभों का अनुभव नहीं कर सकता । शाही कृषि कमीशन (रायल कमीशन और एग्रीकल्चर) ने सन् १९२८ में रूढ़िवादी पक्ष का समर्थन करते हुए एकोद्देशीय सहकारी समितियों को उत्तम रास्ता बतलाया था, परन्तु भारतीय रिजर्व बैंक के कृषि-विभाग ने अपने पत्रक में ही अनेक उद्देश्यों वाली सहकारिता का समर्थन किया । इसमें कुछ प्रगति हुई और सन् १९५२ में उनकी परिस्थिति यह थी—

कुल सख्या

३६,६३०

सदस्यता

२१,४२,६०५

चालू धन

१३३३,७१ लाख रुपये

जो कि बहुद्देशीय समिति की दशा में इस कारण पूरे नहीं होते कि उनके लिए कार्य-क्षेत्र अधिक विस्तृत रखना पड़ता है। शाही कृषि-कमीशन की रिपोर्ट के समय १९२६ में साधारण जनमत एकोद्देशीय समितियों के पक्ष में था। इसी क्रम में उत्तरदायित्व के प्रश्न पर भी मतभेद है। एकोद्देशीय समिति के समर्थकों का कहना है कि समिति का उत्तरदायित्व सहयोग के नियमों के अनुसार असीमित होना चाहिए और बहुद्देशीय के समर्थक सीमित उत्तरदायित्व के समर्थक हैं। उनका कहना है कि यदि उत्तरदायित्व सीमित होता तो बहुत लोग समितियों के सदस्य बनते।

कुछ लोगों की राय है कि बहुद्देशीय समिति, जो ऋण आदान-प्रदान का काम भी करती है, यदि वह इस योग्य है कि अपनी आवश्यकताओं के अनुसार समिति उत्तरदायित्व के आधार पर स्पष्ट स्वयं इकट्ठा कर सके तो ऐसी दशा में बहुत कम डर रह जाता है। यदि ऐसा नहीं है तो यह अधिक उचित है कि ऋण सबधी समिति पृथक् हो और बहुद्देशीय पृथक्।

इसके अतिरिक्त यह भी कहा जाता है कि चूंकि बहुद्देशीय समिति का काम दूसरी समितियों की अपेक्षा पेचीदा तथा कठिन होता है, इसलिए कई बार उसके काम में जो त्रुटियाँ पैदा हो जाती हैं, उनका शीघ्र पता नहीं लग सकता और जब लगता है उस समय समिति की दशा बहुत खराब हो चुकी होती है। दूसरे सदस्यों का समिति के कर्म में भाग लेना बहुत कम रह जाता है जो कि सहकारी भावना को शक्तिशाली बनाने के लिए परमावश्यक है। परन्तु वैसे सदस्यों का बहुद्देशीय समिति में मेल-जोल अधिक नहीं होता। कुछ लोगों का यह भी विचार है कि बहुद्देशीय की दशा में सहकारी विभाग का दखल बहुत रहता है और इससे हानि भी होती है।

उपरोक्त आपत्तियाँ उन लोगों की ओर से हैं जिन्हें सहयोग का अनुभव है और जिन्होंने इस ओर बहुत समय लगाया है, किन्तु यह आपत्तियाँ ऐसी नहीं जिनका निराकरण न किया जा सके। यह ठीक है कि बहुद्देशीय समितियाँ हर जगह और हर दशा में स्थापित नहीं की जा सकती। स्थानीय परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार ही आसानी से खोली जा सकती है, और उसके निष्ठातों को भी समझाया जा सकता है।

परन्तु यदि लोगों को अच्छी प्रकार बहुद्देशीय समिति के सिद्धान्त व कार्य-

क्रम समझाए जाय और पर्याप्त प्रचार किया जाय तो लोग यह सब समझ सकते हैं और काम करने को भी तैयार होंगे। वैसे तो जब प्रारम्भ में ऋण-सम्बन्धी समितियाँ स्थापित की गई थीं तो लोगों को समझने में काफी समय लगा और लोग उन समितियों को सदेह की दृष्टि से देखते थे। परन्तु धीरे-धीरे लोग उनके लाभ, समझने लगे और ये समितियाँ खासी सफल हुईं।

ऋण-सम्बन्धी समिति का ध्येय सदस्यों को ऋण से मुक्त करना होता है। और यह समाप्त भी हो सकता है। फिर समिति की पूँजी को लाभप्रद काम पर लगाना एक समस्या बन जाती है। यह एक ऐसा काम है जिसमें स्थायी रुचि नहीं रहती। तभी तो श्री लोबो प्रभु ने गोरखपुर यू० पी० की ऋण-सम्बन्धी समितियों के बारे में लिखा कि यह समितियाँ प्रारम्भ में 'ए' क्लास होती हैं। दो वर्ष के बाद 'बी' और फिर 'सी', और फिर इनकी समाप्ति हो जाती है।

हमारे ग्राम बिखरे हुए हैं। एक उद्देश्य के लिए पर्याप्त सख्या में सदस्य नहीं मिल सकते। पूँजी इकट्ठी नहीं होती, और वैतनिक कर्मचारी रखने के लिए पर्याप्त धन व आय नहीं होती। इसी कारण एकोद्देशीय समितियाँ आन्दोलन को जागरूक तथा सजीव बनाने में समर्थ न हो सकीं। तभी तो सहकारी योजना व पंचवर्षीय योजना ने इस बात पर जोर दिया कि बहुद्देशीय सहकारी समितियों का प्रचलन किया जाय। साधारण ग्रामीण अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भिन्न-भिन्न जगह नहीं जा सकते और न ही भिन्न-भिन्न कामों के लिए रुपया जुटा सकते हैं।

इस आन्दोलन का अभिप्राय तो लोगों में हर जगह फैलने तथा हर प्रकार से उनको उन्नत करने का है। यह तभी हो सकता है जबकि यह आन्दोलन लोगों को उनकी आवश्यकताओं की सब प्रकार की वस्तुओं को उपलब्ध कराने में समर्थ हो और उनकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले।

अतः प्रकट है कि शाही कृषि कमीशन के समय लोग एकोद्देशीय समितियों के पक्ष में थे, लेकिन थोड़े ही समय के बाद लोग बहुद्देशीय समितियों के पक्ष में होने प्रारम्भ हो गये। और अब तो कुछ समय से विचारधारा बहुद्देशीय के पक्ष में है। रिजर्व बैंक के कृषि-विभाग ने १९३७ में इनके पक्ष में राय दी। और १९३९ में रजिस्ट्रार सम्मेलन ने भी अपने सुझाव दिये कि प्रान्तों में बहुद्देशीय समितियों का प्रयोग प्रारम्भ करना चाहिए। सन् १९४५ में अकाल-कमीशन तथा

कई विशेषज्ञों ने भी बहुद्देशीय आन्दोलन का समर्थन किया है। रायला सीमा सहकारी जाच समिति (१९४६) ने भी बहुद्देशीय समितियों के प्रचलन पर जोर दिया है।

इतना ही नहीं ग्रामीण ऋण अधीक्षण समिति ने भी सहकारी आन्दोलन की इस मौलिक कमजोरी को पहचाना और एक एकीकृत कार्य-पद्धति की रूप-रेखा बनाई। उन्होंने सफलता के लिए निम्न परिस्थितियाँ बतलाई हैं—

“सहकारी ऋण के पुनर्गठन के लिए जो उपाय इस समय तक सोचे गए हैं या प्रयोग में लाए गए हैं उनका वर्णन यूँ हो सकता है कि वह ऋण सम्बन्धी सगठन की अन्दरूनी निर्बलताओं को हटाने के लिए ही थे। उनमें नागरिक व्यापार तथा वित्त सम्बन्धी परिस्थितियों द्वारा उत्पन्न कुव्यवस्थाओं का विचार तो दूर रहा, ग्रामीण सगठन के समूचे ढाँचे की निर्बलताओं का ध्यान भी नहीं रखा गया। इसलिए सहकारिता में किये गये प्रायः सारे प्रयत्न निर्बल को सबल के विरुद्ध सगठित करने में विफल रहे।

इस प्रकार दो अर्थ-नीतियों की कुव्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए पहले प्रयत्न करने के स्थान पर प्रयास वचत, विकसित जीवन तथा बहुद्देशीय कार्य की ओर ही रहा। मैदान इस तरह सबल और निर्बल के दरम्यान द्वन्द्व के लिए साफ हो गया, जहाँ खेल के नियम अधिकतर सबल के ही पक्ष में थे। इसलिए पहला काम इस अवस्था को दुरुस्त करने का है। दूसरे शब्दों में ऐसी परिस्थितियाँ लानी पड़ेंगी जिनमें सहकारिता सफलता से कार्य कर सके। संचालन की कोई विवेचना उस समय तक लाभप्रद नहीं होगी जब तक कि यह परिस्थितियाँ पहले पैदा न की जाय। सहकारिता के आगे दो बातों में से एक का वरण करने की ही छूट रह गई है कि या तो वह अनिश्चित काल तक अपनी सहायता करने में असमर्थता की दशा में चलती रहे या ऐसी सहायता स्वीकार करे जिससे कि न केवल वह अपनी ही सहायता कर सके वरन् उसे बाहर से किसी सहायता की आवश्यकता न रहे। इस सगठित व एकीकृत सहकारी कार्य पद्धति के उक्त कमेटी ने तीन मौलिक अंग बताए हैं—

(क) विभिन्न स्तरों पर राज्य की साभेदारी,

(ख) ऋण साख तथा अन्य आर्थिक कार्यों यथा व्यापार व निर्माण में पूर्ण ताल-मेल और सहयोग।

(ग) पर्याप्त मात्रा में कार्य-कुशल, जनता की आवश्यकताओं को पूर्ति में रुचि रखने वाले तथा भली प्रकार प्रशिक्षित कर्मचारीवर्ग की नियुक्ति ।

इस अध्याय में हमारा सम्बन्ध केवल सुभाव स० २ से ही है । इसके सम्बन्ध में अधिक विश्लेषण करते हुए उनका यह सुभाव है कि किसान व मजदूर की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु निर्माण, वस्तु क्रय-विक्रय, दुग्धोत्पादन, दुग्ध क्रय-विक्रय, पशुवश-वृद्धि तथा ग्रामोद्योगादि के कार्यों को सहकारिता द्वारा पूरा किया गया ।

उपरोक्त सक्षित विवरण से इतना तो प्रकट ही है कि केवल ऋण पक्ष की ओर ध्यान देने वाली एकांगी सहकारिता सफल नहीं हो सकती और न ही एक दूसरे अंग से पृथक् असम्बद्ध सकीर्ण सहकारिता ही सफल हो सकती है । परन्तु इसमें भी सन्देह नहीं कि आज तक बहुद्देशीय सहकारिता का ध्येय भी बड़ा ही सकीर्ण रहा है । कंट्रोल के दिनों वस्तु क्रय-विक्रय कार्य को ही आमतौर पर बहुद्देशीय कार्य कहा जाता रहा । हालांकि यह कार्य का एक पक्ष है । जब तक हम बहुद्देशीय कार्य का मूर्त-रूप हृदय में अंकित नहीं कर पाते, तब तक इस कार्य की सार्थकता अथवा सफलता को नहीं आका जा सकता । यदि हम बहुद्देशीय सहकारी समिति का विचार ही सकीर्ण कर दें तो वह शब्दों के मूलार्थ के ही विपरीत हो जायगी ।

सहकारिता एक पूर्णतया मानवीय कार्य-पद्धति है । इसमें न तो व्यक्ति पूर्णतया समाज में विलीन हो जाता है और न ही उसको इतना शक्तिशाली होने दिया जाता है कि समाज का शोषण कर सके । वह सर्वदा अपनी शक्ति समाज की शक्ति में ही समझने लगता है । इस प्रकार सहकारिता व्यक्ति की बहुमुखी आर्थिक व सामाजिक प्रवृत्तियों के समाजीकरण का प्रयास है । अतः हमें पहले मोटे तौर पर यह निश्चय करना पड़ेगा कि हमारी समाज की इकाई क्या हो । हम आमतौर पर 'ग्राम' को इकाई कह देते हैं । परन्तु भारत में ग्राम के शब्द से कोई एक-सी धारणा नहीं होती, क्योंकि एक या दो घरों से लेकर १०,००० की जनसंख्या तक हमें ग्राम मिलते हैं । ऐसी अवि-कसित तथा अनिश्चित धारणा से किसी भी आर्थिक कार्य का योजना-सम्पन्न ढंग से होना कठिन है । अतः पहले हमें ग्रामीण जनता की इकाई का मान नियत कर लेना चाहिए । यह मान ग्राम या ग्राम-समूह से न होकर जनसंख्या

मे होना चाहिए। जनसंख्या का मान परिस्थितियों के अनुसार कम-ज्यादा हो सकता है।

फिर इस प्रारम्भिक डकाई की बहुमुखी आर्थिक विकास की योजना बनाई जानी चाहिए। जिस प्रकार प्रबन्ध सम्बन्धी योजना पचायते बनाती है, उसी प्रकार आर्थिक योजना बनाने का उत्तरदायित्व उनपर होना चाहिए जिनका कि उसमें आर्थिक हित या स्वत्व भी हो। क्योंकि अपने व्यक्तिगत आर्थिक लाभालाभ की चिन्ता के बिना सब लोग कार्य में पूर्ण रुचि नहीं रखते। इसलिए हर ऐसी डकाई के लिए एक बहुद्देश्यीय सहकारी समिति गठित हो जिसमें सम्भवतः क्षेत्र के सब परिवार मदस्त्य हों। हिस्से का मूल्य यथावश्यकता १०) २० से १००) तक हो सकता है। समिति के रजिस्टर हो जाने के पश्चात् कार्यारम्भ करने से पूर्व समिति की प्रथम कार्यकारिणी समिति को चाहिए कि विभाग की मन्त्रणा से उक्त क्षेत्र के विकास के लिए एक योजना पूर्ण सर्वेक्षण के बाद बनाये। सर्वेक्षण में हर समिति को क्षेत्र के सम्भवतः निम्न आकड़े एकत्रित करने चाहिए —

- १ क्षेत्र की जनसंख्या, बाल, वृद्ध, स्त्री, पुरुष के व्योरे सहित,
- २ क्षेत्र की भूमि—बन, बजर, घामवाली, बाराणी व नहरी आदि के व्योरे सहित ;
- ३ क्षेत्र में कच्चा माल तथा मूल्यवान लकड़ी आदि जो पैदा होती हो ,
४. अन्नोत्पादन का व्योरा ,
- ५ ग्रामोद्योगों का व्योरा, उनमें जो आदमी जीविकोपार्जन करते हो आदि के व्योरे सहित ,
- ६ ग्रामीणों के ऋणों की सूची, प्रयोजनों सहित ,
- ७ पशुसंख्या, व्योरे सहित ,
- ८ व्याज की दर
- ९ जनता की आवश्यकताएँ जो उनके जीवन के लिए अत्यावश्यक हों।

सर्वेक्षण द्वारा उपलब्ध इन आकड़ों से ही योजना बनाने में सहायता मिल सकेगी। कृषि में क्या-क्या सुधार तथा उन्नति हो सकती है , कितनी जतना को कृषि के व्यवसाय से पूर्ण काम मिलता है , कितने व्यक्ति पूर्णतया उद्योगादि में लगाने पड़ेंगे , ऋण के लिए कितना प्रबन्ध चाहिए , वस्तु क्रय-विक्रय का कितना प्रबन्ध चाहिए , भण्डारों की कितनी आवश्यकता है , इस समस्त कार्य के लिए

कितनी धन-राशि चाहिए, उसका प्रबन्ध किस प्रकार होगा—आदि प्रश्न हैं जिनको समक्ष रखकर ही एक एकीकृत तथा शृंखला-बद्ध योजना बनाई जा सकती है। यह कार्य ही परमावश्यक है और इसी कार्य से सहकारी कर्मचारी-वर्ग की योग्यता का अनुमान हो सकता है। जब यह योजना बन जाय तो कार्य-कारिणी अथवा प्रबन्धक समिति को विभिन्न समितियों में विभक्त हो जाना चाहिए, यथा—प्रशासन-समिति, ऋण-समिति, उद्योग-समिति, व्यापार-समिति, आदि-आदि। प्रत्येक समिति को अपने-अपने कार्य को योजनानुसार अग्रसर करना चाहिए और विभाग के कर्मचारियों को भी सहकारिता के इस सामूहिक रूप को विकसित तथा पुष्ट करने में पूरा प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार की बहुद्देशीय सहकारी समिति जब मूल में होगी तभी सहकारिता एक समूचे, समग्र तथा एकीकृत रूप में विकसित होगी। इस प्रकार की बहुद्देशीय सहकारी समिति के विभिन्न अंगों का संगठन तथा आयोजन उसी प्रकार होना चाहिए जैसे कि विभिन्न अध्यायों में उनके सम्बन्ध में लिखा जा चुका है। यदि लगभग ५००० जनसंख्या के लिए इस प्रकार की बहुद्देशीय सहकारी समिति बनाई जाय तो उसके आय-व्यय का अनुमान निम्नरूपेण किया जा सकता है—

आय

१. आयात, निर्यात, अर्ध थोक व्यापार पर ६२५% दर से लगभग १ लाख के व्यापार का मुनाफा, यहाँ एक व्यक्ति का एक वर्ष का व्यापार २०) २० आका गया है— ६२००)
 - २ नकद आय पैदा करने वाली फसलों के व्यापार तथा उद्योग-धंधों की बिक्री द्वारा आय— ६०००)
 - ३ १०,०००) २० के लगभग हर वक्त रहने वाले ऋण का व्याज दर ६% प्रति वर्ष— ६००)
 - ४ फल, दूध, घी तथा उद्योग विभाग की आय— १०००)
- कुल योग २० १३, ८००)

व्यय

- १ मंत्री २००) २० वेतन पर २४००)
- २ क्लर्क ८०) २० वेतन पर ९६०)
- ३ स्टोरकीपर (भंडारी) ६०) वेतन पर ७२०)

४	विक्रेता ६०) रु० वेतन पर	७२०)
५	दो चपरासी ४०) रु० वेतन पर	८६०)
६	सामान स्टेशनरी आदि	२०००)
७	१०% के दर लाभाश	२०००)
८	२०,०००) रु० की सीमा से सुरक्षित कोष	१०००)
९	सहायता कोष	१०००)

कुल योग रु० ११, ७६०)

यह अनुमान कोई ऐसा नहीं जो अतिशयोक्ति-पूर्ण हो। परन्तु यह सब काम करने के लिए हिस्से बेचकर यदि पर्याप्त धन जमा न हो सके तो सरकार को हिस्सों में कुछ समय के लिए रुपया लगाना चाहिए। परन्तु सरकार द्वारा लगाया जाने वाला भाग-धन या तो रिजर्व बैंक द्वारा या सहकारी अधिकोषों के द्वारा आवे। क्योंकि सीधे सरकार द्वारा आने पर तथा प्रबन्ध विभागों अथवा सहकारी विभाग के कर्मचारी सरकार के प्रतिनिधि प्रबन्धक समितियों में होने से, लोकतन्त्रीय विचारों के अनुसार सहकारी भावना पनप नहीं सकती। सरकारी कर्मचारी अपना अधिकार तो बहुत समझते हैं परन्तु सहकारी भावना को उन्होंने समझा नहीं होता। इसका फल होता है कि सरकारी सहायता का प्रथमावस्था में दुरुपयोग और दूसरी में वह सरकारी कर्मचारी स्वयं तो छूट जाते हैं और शेष व्यक्तियों को गवन आदि के झुठटों में फसा देते हैं। यदि सहकारी अधिकोष भाग ले तो ऐसी परिस्थिति नहीं हो सकती। जब भाग अधिकोषों के द्वारा होंगे तो धन की वापसी की जिम्मेदारी उनपर होगी जो समितियों की अपेक्षा यह उत्तरदायित्व अच्छी तरह निभा सकेंगे। यदि किसी कारण-वश यह ठीक न समझा जाय तो यह हिस्से स्थानीय पचायत द्वारा आने चाहिए। सरकार पचायत को ऋण दे और पचायत का हिस्सा सहकारी समिति में हो। इस तरह करने से प्रारम्भ से ही सारे ग्राम की सहकारी समिति में उत्तरदायित्व-पूर्ण अभिरुचि हो जायगी। यह ऐसी चीज है कि इसके बिना सहकारिता पनप ही नहीं सकती।

इसमें सन्देह नहीं कि यदि इस प्रकार की प्रारम्भिक सहकारी समिति ने काम करना हो तो चालू धन एक लाख के लगभग चाहिए। यदि १००) रु० का

एक हिस्सा हो जिसका १०% पहले लिया जाय तो १००० परिवारों में २००० हिस्से बिकना कठिन नहीं होना चाहिए। इस प्रकार समिति को २०,००० रु० प्राप्त होगा। कुल जिम्मेदारी २,००,००० रु० की होगी। अतः अमानतो व ऋण द्वारा एक लाख रुपया व्यापार आदि हेतु जमा करना कठिन नहीं होगा। प्रारम्भ में २०,००० रु० से जितनी कमी रह जायगी वह सरकार के पचायतो द्वारा आने वाले भागों से पूरी की जानी चाहिए। ज्यों-ज्यों हिस्से बिकते जाय त्यों-त्यों सरकार का भाग लौटाया जा सकता है। और अन्त में पचायत का भी १'००० रु० के लगभग रहना चाहिए। इस तरह कार्य के सम्पादन में भी कोई कठिनाई नहीं रहेगी, क्योंकि काम के संगठन का ढंग जैसा कि पूर्व के अध्यायों में वर्णित है, पूर्णतया व्यावहारिक होगा।

: १० :

सहकारिता और सामाजिक विकास

सामाजिक विकास के सम्बन्ध में इतिहासवेत्ताओं तथा लेखकों की विभिन्न धारणाएँ हैं। फ्रांस के प्रसिद्ध लेखक रूसो का कहना है कि मानव स्वभाव से व्यक्ति ही है, और उसने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने, भिन्न प्रकार की भूख को मिटाने तथा प्राणरक्षा के लिए सामाजिक क्षेत्र में प्रवेग किया। उसने अपनी कुछेक स्वतन्त्रताओं का परित्याग करके उनके बदले दूसरे व्यक्तियों से सहायता प्राप्त की और इस प्रकार उसने सामाजिकता को अपनाया। उक्त लेखक ने अपनी पुस्तक का नाम भी 'सोशल कांटेक्ट' अर्थात् सामाजिक सविदा रखा।

दूसरे विचारकों का कहना है कि मानव स्वभाव से ही सामाजिक प्राणी है और वह समाज के बिना रह ही नहीं सकता। मानव की परिभाषा करते हुए उन्होंने लिखा कि "मानव एक सामाजिक प्राणी है।"

भारत के प्राचीन धर्मज्ञों ने तो ससार की उत्पत्ति का कारण यज्ञ बताया।

यज्ञ कर्म का अर्थ है सब प्राणियों का बहुत भला। अर्थात् ऐसे विचारको के अनुसार मानव का मूलभूत स्वभाव यज्ञ अर्थात् सामाजिकता है। एक और पक्ष है जिसका कहना है कि मूलतः मानवमात्र एक है, और उस मौलिक एकता से स्नेह की भावना का प्रादुर्भाव होता है, जिसमें दूसरे के लिए त्याग करने से व्यक्ति को सुख होता है। इसी स्नेह से सहकार्य की भावना का उदय होता है।

यह सब विचारशैलियाँ एक साथ सत्य की ओर अवश्य संकेत करती हैं कि मानव के लिए सामाजिकता आवश्यक भी है और वांछित भी। जहाँ हम एक तरफ 'आदमखोर' व्यक्तियों को देखते हैं, वहाँ दूसरी तरफ वह भी व्यक्ति है जो दूसरे के हित बिना कुछ भी बदले में लिए या लेने की आशा रखे, अपना जीवन तक भी बलिदान करने में आनन्द का अनुभव करते हैं। अतः अश्वरूप से दोनों पक्ष ही सत्य हैं। व्यक्ति समाज के हित के लिए अपनी परमावश्यक जरूरतों को भुला नहीं सकता। उसे रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, घर चाहिए। कामवासना की तृप्ति के लिए उसे एक साथी को ढूँढना पड़ता है। परन्तु यदि यह कहा जाय कि केवल एक सविदा के अधीन उसने समाज को अपनाया है तो यह पूर्णतया ठीक नहीं, क्योंकि मनुष्य काफी मात्रा में स्वभाव से ही सामाजिक प्राणी है। वह अकेला नहीं रह सकता। उसकी एक मानसिक भूख की तृप्ति समाज में ही हो सकती है। प्रेम, सेवा, वात्सल्य आदि कई उसकी मानसिक वृत्तियाँ हैं जो जाकर समाज में ही विकसित हो पाती हैं, और जिनके विकसित हुए बिना उसको एक मानसिक अवगुण्ठन, एक रुकावट, एक कमी अनुभव होती रहती है। अतः प्रकट है कि मनुष्य प्रारम्भिक दशा में स्वभाव से कुछ मात्रा तक स्वार्थपूर्ण व्यक्ति है और उसका समूचा विकास समाज में ही हो पाता है अन्यथा नहीं। जिस प्राणी का पूर्ण विकास ही समाज में सम्भव हो, उसके लिए समाज तथा उसका विकास कितनी महत्वपूर्ण वस्तु है, यह समझने की आवश्यकता ही नहीं रहती। और इस समाज का संगठन तथा विकास किस प्रकार से होना चाहिए? इस प्रश्न का सीधा-सादा उत्तर यह है कि जिस समाज में मानव, मानव के रूप में पूर्णरूप से विकसित हो सके, वही समाज सभ्य तथा सुसंस्कृत समझा जाना चाहिए।

मानव को यदि उपयुक्त परिस्थितियाँ न मिलें तो उसका विकास विकृत जाता है। जैसे समाज में आवश्यकता-पूर्ति के लिए व्यापार-संगठन का

प्रादुर्भाव हुआ। व्यापारी काफी समय तक समाज की इस सेवा को मुचारु रूप से करता रहा। समाज ने उसके ठीक ढंग में विकसित होने के लिए वातावरण पैदा नहीं किया। एक तरफ उस पर मन्देह किया जाने लगा, दूसरी तरफ उसे रुपया ऐठने के लिए सुविधा मिलने लगी। फल यह हुआ कि व्यापारी 'गार्डलाक' कहा जाने लगा। वह समाज का शोषक बन गया और सारे विश्व में किमान तथा मजदूर को व्यापारी व साहूकार से बचाना एक समस्या बन गई।

इसी प्रकार प्रारंभ में प्रजा को सुखी व मनुष्टु रखने के लिए राजा बनाया गया, परन्तु समाज ने उस पर पर्याप्त नियंत्रण नहीं रखा और वही राजा जार, पीटर, लुई १४, हलाकू खा, चगेजखा आदि-आदिके रूपों में प्रकट हुआ।

हमने रुपये को जन्म दिया अपने हित के लिए, परन्तु रुपया हमारा स्वामी बन गया। मानवता रुपये में विकने लगी। हमने मशीन बनाई अपनी सेवा के लिए, परन्तु वह भी हमारी स्वामिनी बन गई और लगी ग्रामो का शोषण करने। धर्म के उपदेश, कातून का भय व नियंत्रण, शिक्षा इत्यादि सब उपाय असफल से हुए दीखते हैं।

समाज बना, बटा, विकसित हुआ, पनपा, परन्तु उसने कोई ऐसा स्थायी संगठन नहीं बनाया जिसमें मानवता को पूर्ण रूप में विकसित होने की सुविधा मिलती। राबर्ट ओवन, रूसो, मार्क्स, थामस मूर इत्यादि सब एक ऐसे समाज के निर्माण के नुस्खे सोचते रहे। इतिहास उस बात का साक्षी है कि सबके नुस्खों की अपेक्षा यदि कोई नुस्खा ज्यादा लम्बे काल के लिया टिका है, और मानव-मानव ही जिनकी धारणा व जिनका क्षेत्र विस्तृत होता गया है, तो वह है राबर्ट ओवन का बनाया हुआ नुस्खा—सहकारिता।

जिस सहकारिता का वर्तमान युग में १०० वर्ष पहले कारखाने के शोषित मजदूरों की सहायता के लिए जन्म हुआ था, वह आज एक विश्वव्यापी आन्दोलन बन चुका है। उसने आज मानव-जीवन का कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं छोड़ा। माना जिस आज इस आंदोलन की ओर आया भले नेत्रों में निहार रहा है। समाजवाद (साम्यवाद) ही नहीं बरस प्रभरीण, उगलैउ जेने साम्राज्यवादी तथा पत्तीवादी दोनों को भी अब सहकारिता ने ही भविष्य दिखाई दे रहा है। "सोत्तल", "सनेर" और "मानवता" इनके तीन प्रधान सग हैं। और यही सग सहकारिता को मानव-मानव के लिए परमोपयोगी पद्धति बना देने हैं।

आचार्य विनोबा ने तो सहकारिता को और भी परिमार्जित तथा परिष्कृत करके सर्वोदय का एकमात्र वाहन बना दिया है। आज सहकारिता का क्षेत्र अर्थ न रहकर मानव-जीवन हो रहा है। आज 'कल्याणकारी राज्य' स्थापित करने के घोष उठते हैं। योजना का तुमुल नाद हो रहा है। हर कार्य में जनता की इच्छा को पहचानने की चेष्टा की जा रही है। उधर आणविक तथा उदजनवमों के निर्माण से एक वीभत्स विनाश मानव-समाज की ओर घूर रहा है। पूजीपति तथा शक्ति-सम्पन्न देशों को इन विनाशकारी पथों से हटाना कोई सुगम कार्य नहीं दीखता।

ऐसी स्थिति में मानव का चित्त व्याकुल हो रहा है। उसकी दैवी प्रवृत्तियों के विकसित होने में इस प्रकार की आसुरी परिस्थितियाँ विघ्न डाल रही हैं। यदि हमने मानव के विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना है तो प्रेम और स्वेच्छा से ही सब काम करने की नींव डालनी होगी।

"स्वेच्छया स्वीकृतो बन्धो निर्बन्धायोपकल्पते," वाली स्वतन्त्रता की स्थापना के लिए एक अनुशासनपूर्ण जीवन की परिपाटी डालनी होगी। योजना ऊपर से नीचे को जाने वाली न होकर ऊर्ध्वगामिनी बनानी होगी। इस प्रकार की परिस्थितियाँ समाज में तभी लाई जा सकती हैं जबकि हम सहकारिता द्वारा ही मौलिक इकाइयों का सगठन करें। जब प्रेम, स्वेच्छा तथा मानवता के नाते यह इकाइयाँ बनकर तहसील, जिला तथा प्रान्तीय सघों में मीनार की नाई बनती जायगी तभी एक ऐसा वातावरण बनेगा जिसमें मानवता और मानव का पूर्ण विकास हो पायगा।

सामाजिक विकास के लिए प्रथमावश्यकता होती है सामाजिक सगठन की। एक सामाजिक सगठन को सफलतापूर्वक चलाने के लिए उसमें व्यक्ति का स्वेच्छा से आना जरूरी है। किसी कानून अथवा हिंसा की शक्ति के दबाव के अधीन बना सगठन मानव की उन्नति नहीं कर सकता, क्योंकि विवशता का वातावरण उसके विरुद्ध विद्रोह की सतप्त ज्वालाओं को जन्म देता है। अतः व्यक्ति की अपनी इच्छा सामाजिक सगठन के लिए एक परमावश्यक आधार-शिला है। कानून द्वारा जबरदस्ती ठूसी गई पचायतें अथवा अन्य सगठन स्वेच्छा के परमावश्यक आधार बिना प्रगति नहीं कर सकते और वे पगु हो जाते हैं। इससे स्पष्ट है कि ऐसा सामाजिक सगठन सहकारिता के आधार पर ही निर्मित

कर सामाजिक विकास को संभव तथा सुलभ बना सकता है।

इस पुस्तक में हमने सहकारिता के आर्थिक जगत में व्यवहार होने का वर्णन किया है। इसमें सन्देह नहीं कि आज के युग का इतिहास बर्बर है। जीवन का पदचिह्न ही आज अर्थ रह गया है। वाइकिंग की उड़ान जोई हूट नहीं कि मानव केवल रोटी द्वारा ही नहीं जीता। उनके जीवन में प्रेम, स्नेह, त्याग, सेवा, तपस्या आदि और कई अन्य आवश्यक चीजें हैं। बिना मानव-जीवन गुणक तथा प्राणहीन-सा हो जायगा। मनुष्य के जीवन में एक ही चीज—उदर की, शरीर की और आत्मा की। मनुष्य केवल उदर की भूख को ही विशिष्ट समझते हैं। उसके बाद शरीर के इच्छा हैं। आत्मा की भूख में तो हम प्रायः विमुख से होकर उभे भूल चुके हैं। मनुष्य के बिना मानव तो गड़ जाने वाली दुर्गन्धयुक्त देहमात्र है। मनुष्य के जीवन में मनुष्यता है, वह आत्मा की भूख ही है। इस आत्मा की भूख को पूरा करने वाली भावनाएं ही मानव को मानव तथा एक विकासोन्मुख बनाने वाली हैं। हम आत्म-त्व को पहचाने बिना केवल उदर तृप्ति के लिए मनुष्य के निर्दिष्ट बाया मानव। किसी दिन भी आदमखोर बन सकते हैं। वह मनुष्य उदरार्ति तथा काम-वासना की तृप्ति के लिए किसी भी इच्छा मनुष्य के द्वारा कर सकता है। हम आत्म-तत्त्व के अस्तित्व को जो नहीं पहचानते उन्हें असुरी धृति वाला कहा जाता है। यही आसुरी तथा ईर्ष्या धृति का स्वरूप है।

राज्यों के तत्र इस सामाजिक विकास के ही प्रदर्शन हैं। दैवी सम्पत्ति को जब हम भूल जाते हैं, तभी सामाजिक पतन आरम्भ हो जाता है और मानव-समाज को बहुधा हिंसा के भयावह गड्ढे में धकेल दिया जाता है।

एक राष्ट्र का दूसरे से द्वेष, सन्देह तथा शोषण करने की इच्छा सब इसी कारण से होते हैं और यह इस बात का प्रमाण है कि हम दैवी सम्पत्ति से विमुख हो चुके हैं।

इस दैवी सम्पत्ति के उत्थान तथा जागरण के लिए विभिन्न मतों का प्रादुर्भाव हुआ। धर्म की प्रेरणा से मानव ने पर्याप्त मात्रा में तथा पर्याप्त काल तक दैवी सम्पत्ति को अपनाया। परन्तु धर्म उक्त सम्पत्ति का समाजीकरण न कर पाया। यह व्यक्ति तक ही सीमित रहा। इसका फल यह हुआ कि आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक जगत इससे अछूता रह गया। शक्ति अर्थ तथा राजनीति में थी। फल यह हुआ कि जब कभी राजनीति तथा अर्थ में दैवी-शक्ति-सम्पन्न व्यक्तियों की प्रधानता रही तब-तब समाज में दैवी सम्पदाओं को प्रोत्साहन मिलता रहा, और जब कभी यही शक्ति आसुरी शक्ति-सम्पन्न व्यक्तियों के हाथ चली गई तो प्रोत्साहन आसुरी सम्पदाओं को मिलता रहा और मानव मानव के रक्त का प्यासा बनता गया।

मानव-समाज आज भी आतंकित है। वह आणविक तथा उद्‌जन बमों की—भविष्य के गर्भ में छिपी हुई—वर्षा से डर रहा है। निर्बल का सबल, निर्धन का धनिक तथा मूर्ख व अपठित का बुद्धिमान व पण्डित द्वारा आज भी शोषण जारी है। कड़े कानूनों तथा करों के बोझ ने मानव को और अधिक निष्ठुर, चालाक तथा स्वार्थी बना दिया है। मानव-समाज व्याकुल तथा चंचल हो उठा है। वह चाहता है कोई ऐसा साधन—जहाँ मानव मानव की तरह सुख, सतोष तथा शान्ति से रह सके, जहाँ उसकी दैवी सम्पदाओं का विकास हो, जहाँ व्यक्ति-व्यक्ति का, जाति-जाति का, देश-देश का तथा धर्म-धर्म का द्वन्द्व न रह कर सारा विश्व एक समाज बन जाय और हमारा आपसी नाता हो मानवता। जब मानव-समाज इस ढंग से विकसित होकर आयोजित होगा तभी मानव व्यक्ति के रूप में अपनी दैवी सम्पदाओं को विकसित कर सकेगा।

प्रथम अध्याय में जो सहकारिता की परिभाषा दी गई है, उसके अनुशीलन से यह स्पष्ट ही है कि सहकारिता ही एक ऐसी पद्धति है जो सामाजिक, आर्थिक

तथा राजनीतिक क्षेत्रों में भी देवी सम्पदाओं के प्रोत्साहन के यत्नमय कार्य को चरितार्थ करती है। अतः समाज का यथोचित विकास तभी सम्भव है जबकि सहकारिता की पद्धति तथा विचार-प्रणाली को हर क्षेत्र में अपनाया जाय। सहकारिता एक साधन व पथ है, जिसका लक्ष्य सर्वोदय है। अतः सहकारिता का प्रवेश सामाजिकता में परमावश्यक है। अभी तक हमने राजनीतिक भ्रमावात से डरकर सहकारिता के क्षेत्र को सकीर्ण रखा है। परन्तु जब तक यह सकीर्णता की दीवारें गिरा नहीं दी जाती, तब तक न तो सहकारिता ही पनप सकती है और न सामाजिक विकास का लक्ष्य प्राप्त हो सकता है।

आज के युग की यह मांग है कि सहकारी पद्धति को ही हर सामाजिक कार्य में अपनाया जाय। अन्यथा हमारा सामाजिक विकास संभव नहीं होगा। जिस प्रकार ठीक ढंग से सामाजिक विकास के बिना देवी सम्पदाओं का व्यक्ति में विकास नहीं हो पाता, उसी तरह सहकारी पद्धति को अपनाये बिना देवी-सम्पदा सम्पन्न समाज विकसित नहीं हो सकता।

सामाजिक विकास स्वयमेव एक व्यापक विषय है। अतः इस छोटे से अध्याय में इसके सम्बन्ध में केवल संकेत मात्र ही किया जाना सम्भव हो सका है।

: ११ :

सहकारी-संगठन

विश्व तथा भारत की सहकारिता के इतिहास से यह प्रत्यक्ष दीखता है कि निर्वर्लो ने आत्म-निर्भरता, स्वावलम्बन तथा शोषण से संरक्षण के लिए सहकारिता के साधन को खोज निकाला था। परन्तु सहकारिता का यह प्रयोग अभी तक बिखरा रहा और भिन्न-भिन्न स्थलों पर भिन्न-भिन्न रूप में विकसित हुआ। कतिपय देशों ने इन एकांगी प्रयोगों को संगठित तथा एकीकृत करने का प्रयत्न किया है। भारत में सहकारी अधीक्षण (वैकिंग) का एकीकरण हुआ, परन्तु

शेष प्रयोग बिखरे हुए ही रहे। रिजर्व बैंक की ग्रामीण-साख-सर्वेक्षण समिति ने एकीकृत सहकारी सगठन को सहकारिता की सफलता का एकमात्र साधन बताया। परन्तु उस सगठन-मूत्र को व्यवहार में लाने की योजना में ऋण, व्यापार, कृषि आदि को एकीकृत करने के स्थान पर इन सब कार्यों को संगठित करने का ही प्रयास है। इसमें सन्देह नहीं कि कृषि, व्यापार, उद्योग, भण्डार तथा अधिकोप के पारस्परिक सम्बन्ध की आवश्यकता को आकर्षित करने के अन्त्यो-न्याश्रित तरीके से विकसित करने का कार्यक्रम बनाया गया है। और सहकारी समितियों तथा विभाग के कर्मचारी-समुदाय के प्रशिक्षण को भी विकसित करने पर काफी जोर दिया गया है। समय इतनी द्रुत गति में चल रहा है कि योजना बनाने वाले विद्वान भी जब कार्यक्रम बनाते हैं तो वह चाहते हैं कि नए आन्दोलन भी समय की गति के अनुपात से प्रगसर हो। परन्तु किसी भी पेट को ऊपर से आरोपित करना संभव नहीं, उसे तो बीज द्वारा भूमि में परिस्फुटित होकर, मूल पक्का करके ऊपर उठने की पद्धति आती है। भवन-निर्माण कला अभी तक तो बुनियाद से ऊपर को उसारने की है। और यदि ऊपर से कभी भवन-निर्माण किया जाने भी लगेगा, तो भी उसकी दृढ़ता तो मूल पर ही निर्भर होगी। यदि मकान पर छत न हो या छत टपकती हो, तो उसकी नींव भी कच्ची पड़ जाती है। अतः स्पष्ट है कि भवन नींव पर आधारित होता है और उस नींव तथा भवन की रक्षा उसकी छत द्वारा होती है। परन्तु हमारे राजनीतिक तथा सामाजिक आन्दोलन उठाने का काम अभी तक ऊपर से ही किया जाता है और यही कारण है कि बहुत अच्छे तथा जनता के हितार्थ परिचालित आन्दोलन जड़ नहीं पकड़ पाते। सहकारी आन्दोलन की भी यही दशा है। इसमें सन्देह नहीं कि एक आधी शताब्दी से इसका प्रयोग हमारे देश में चल रहा है और हर दशाब्दी में प्रयोग की सफलता का मूल्यांकन किया जाता रहा है। हर मूल्यांकन में परिणामस्वरूप निष्कर्ष आन्दोलन की असफलता ही निकलता रहा है।

ग्राम्य-ऋण-सर्वेक्षण समिति के सुभाव भी आन्दोलन को ऊपर से तथा राज्य की सहायता से पुष्ट करना चाहते हैं। और अपने इस प्रस्ताव की पुष्टी में उन्होंने निम्न तर्क उपस्थित किया है—

“सहकारी आन्दोलन वित्त के दृष्टिकोण से हमेशा निर्बल रहा है। इसके आगे दो ही विकल्प हैं कि या तो यह अनिश्चित काल तक निर्बल रहे

और अपनी सहायता स्वयं न कर सके या इसको बाहर से इतनी आर्थिक सहायता दी जाय कि अन्ततोगत्वा वह केवल अपनी सहायता ही न कर सके, वरन् उसे बाहर की किसी सहायता की भी आवश्यकता न रहे।”

यह सहायता यदि पर्याप्त, आन्दोलन को पुष्ट करने वाली तथा निहित-स्वार्थों के दबाव को सहन करने वाली होती है, तो यह सहकार से ही आनी चाहिए।

जहां तक रोग के निदान का सम्बन्ध है, वह तो पूर्णतया ठीक है। परन्तु जो आर्थिक सहायता सरकार से जिस ढंग से मिलने वाली है, और उसके उप-लक्ष्य में नियंत्रणादि के अधिकार जो सरकार को संस्था में मिलेंगे, उनसे क्या आन्दोलन मूल से लोकतन्त्री तथा सहकारिता के सिद्धान्तों पर विकसित होने को सहायता प्राप्त करेगा ? यह एक टेढ़ा प्रश्न है। क्योंकि आन्दोलन की उपादेयता से तो किसी को इन्कार नहीं हो सकता परन्तु जिनके आश्रय से यह आन्दोलन चलना है, उनकी योग्यता तथा क्षमता भी एक बड़ा ही महत्त्वशाली पक्ष है। दूसरा प्रश्न इस क्रम में यह उठता है कि क्या सहकारिता की पद्धति किसी एक वर्ग या व्यक्ति को त्याज्य कह सकती है, या उसका ध्येय सबका सहयोग प्राप्त करना है। स्वार्थवश कोई व्यक्ति यदि ऐसे आन्दोलन से दूर रहे या उसका विरोध करे तो और बात है, परन्तु ‘सहयोग’ जो साम्य-योग की मजिल तक पहुंचाने वाला सफल अहिंसात्मक, स्नेह-सम्पन्न केवल मात्र मार्ग है, में किसी व्यक्ति, वर्ग, जाति आदि के लिए सम्मिलित होना वर्जित नहीं हो सकता।

निहित स्वार्थों तथा शोषक वर्गों से संघर्ष करके अथवा कानून द्वारा उनकी शोषण-पद्धति पर रोक लगाकर किसान व मजदूर के भला करने की पद्धतियां विश्व में बहुत-सी प्रचलित हैं। इनका हिंसात्मक नर्तन हम रूस तथा ध्वंसात्मक फल अन्य कई देशों में देख चुके हैं। इन पर अधिक विचार न करते हुए हम उदाहरणार्थ स्वतन्त्रता के उपरान्त भूमि-समस्या को देखें तो एक ओर कानून द्वारा प्रयत्न हुआ, दूसरी ओर तैलगाना में क्रान्तिकारी आन्दोलन चला। इन कार्यों से द्वेष तथा संघर्ष की ज्वाला भड़की। और एक बार तो भय हो गया कि कहीं देश हिंसात्मक क्रान्ति की ज्वालाओं में परिवेष्टित न हो जाय। उसी समय सतत भूमि पर अहिंसात्मक विचार-पद्धति की अमृत वर्षा करने वाले सन्त विनोबा ने तैलगाना का रास्ता पकड़ा। और सहयोग की मौलिक भावनाओं

से अभिप्रेरित होकर उन निहित स्वार्थों के समक्ष समस्या-पूर्ति का प्रयत्न रखा जिनके विरुद्ध क्रान्ति का एक ववण्डर उठा था, और जो अपने उक्त स्वार्थों के बचाने की होड में मानो जीवन की वाजी लगाकर उठ खड़े हुए थे। हृदय परिवर्तन हुआ। आन्तरिक सहयोग की भावना जागृत हो उठी। स्नेह से श्रोतप्रोत भूदान का यज्ञमय कार्य गतिमान हो उठा। साम्यवादी, जो हिंसात्मक क्रान्ति के अनुगामी थे, हँसे, काग्रेसी जो कानून के अस्त्र को ही पूर्ण शक्ति सम्पन्न समझते थे, कुछ सदेहात्मक विवेचना करने लगे। परन्तु वही आन्दोलन आज सारे विश्व को एक नव-ज्योति दिखाने जा रहा है। वस्तुतः किसी भी आन्दोलन को केवल उसकी सफलता से नहीं बल्कि उसकी सिद्धान्त-परायणता से आका जाता है।

मानव स्वभाव से ही दैवी-सम्पत्ति सम्पन्न प्राणी है। वह द्वेष तब करता है जब हम उसके भावों का आदर करने के स्थान पर उनका तिरस्कार करते हैं। भूदान आन्दोलन ने यह सिद्ध कर दिया कि निहित-स्वार्थों को भी अहिंसा तथा स्नेह द्वारा जीता जा सकता है। उनके दैवी स्वभाव को जागृत किया जा सकता है। और वही निहित स्वार्थ-सम्पन्न-व्यक्ति हृदय परिवर्तन होने पर उदार होकर स्वयं समाज के हित में अपने अतिशय स्वार्थ का परित्याग कर देते हैं। कानून तो केवल ऐसे भावों के पुष्टिकरण का साधन मात्र हो सकता है, वह उनकी सहायता कर सकता है, ऐसे भावों को प्रोत्साहित कर सकता है परन्तु उसमें ऐसे भावों को जागृत करने की क्षमता नहीं होती।

ऐसे भावों तथा विचारों की जागृति के लिए प्रेरणा तो ऊपर से मिल सकती है, परन्तु जब वह आन्दोलन का स्वरूप धारण करे तब उसका मूल तथा उसपर प्रभुता जनता की दृढ़ चट्टान में होनी आवश्यक होती है। अतः प्रेरणा, सहायता, तथा प्रोत्साहन तो सरकार से प्राप्त होना आवश्यक है। परन्तु यह सब ऐसे ढंग से होना चाहिए कि आन्दोलन का मूल जनता में रहे तथा उसमें प्रभुता भी जनता की रहे।

दूसरे इस अहिंसात्मक आन्दोलन का एक आवश्यक अंग है स्वेच्छा। इसमें सदस्यों का सम्मिलन-सहयोग तथा इसमें वित्त का लगाना आदि कार्य स्वेच्छा से होने आवश्यक है। राज्य की आय करो द्वारा होती है। कर स्वेच्छा से नहीं दिए जाते। इन करो द्वारा प्राप्त धन जनता से स्वेच्छा द्वारा नहीं आता, अतः इस

प्रकार की आय में एक अनुपयुक्त भाव का समावेश रहता है ।

पिछले अध्याय में लिखा जा चुका है कि सरकार की आर्थिक सहायता प्रत्यक्ष रूप से न आकर अधिकोष द्वारा आय तो अधिक सुगम, लाभदायक तथा उपयोगी हो सकती है । परन्तु सबसे श्रेष्ठ तरीका तो विनोबा का सम्पत्ति-दान है जिस ढंग से समाज-हित के लिए धन का त्याग तथा निस्वार्थ-भाव से उपयोग किया जा सकता है १ और यदि ठीक ढंग से समस्या का हल ढूँढा जाय और जनता को समझाया जाय तो पर्याप्त मात्रा में जनता से धन प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होगी ।

ग्राम्य-साख-सर्वेक्षण समिति ने जिस एकीकृत प्रणाली का सुझाव दिया है वह वस्तुतः संगठित प्रणाली ही है, एकीकृत प्रणाली नहीं । व्यापार, भण्डार, कृषि, ऋण, उद्योग तथा अधिकोषण आदि के सम्बन्धों की विवेचना तथा उनकी स्थापना का तो प्रयत्न है परन्तु एकीकृत पद्धति में तो उनका सामंजस्य करना पड़ता है । और हर प्रकार की सहकारी समिति का मूल तो ग्राम की समिति है, जिसका बहुद्देशीय स्वरूप पिछले अध्याय में दिया जा चुका है । उस स्वरूप में अधिकोषण का वर्णन नहीं है । ग्राम्य-स्तर पर भी अधिकोषण का कार्य है जो ऋण के आदान-प्रदान से कुछ अधिक है । गावों में अधिकोषण का विशेष कार्य हुण्डियों का आदान-प्रदान होता है । चैको का काम तो ग्राम्य-स्तर पर कुछ उलभन वाला होगा । शनै-शनै विद्या-प्रसार तथा योग्यता-प्राप्ति पर यह कार्य भी हाथ में लिया जा सकता है । परन्तु हुण्डियों का जिला-स्तर तथा राज्य-स्तर के बैंक की योजना के अधीन हाथ में लिया जाना आवश्यक है । इससे एक ओर तो अधिकोषण-कार्य ग्राम्य-स्तर पर पहुँच जायगा और दूसरी ओर उक्त स्तर पर व्यापार आदि के सब कार्यों में बड़ी सहायता प्राप्त होगी । यह हुण्डिया महत्तम ऋण-सीमा द्वारा नियंत्रित होगी । अर्थात् कुल बैंक द्वारा प्रदत्त ऋण तथा प्राप्तव्य हुण्डियों की राशि महत्तम ऋण सीमा से बढ़ने न दी जायगी । इसके लिए एक खाता हर बहुद्देशीय सहकारी समिति का रखा जायगा । सहकारी संगठन की इस प्रकार की बहुद्देशीय सहकारी समिति मूल की इकाई होगी । यही वस्तुतः सारे सहकारी संगठन की नींव होगी । इस नींव पर ही ऊपर का भवन खड़ा किया जायगा ।

मूल के स्तर की यह सहकारी समितियाँ भले ही वह ग्राम की हो अथवा

नगर की, ऊपर ताल्लुका अथवा तहसील-स्तर में सगठित की जायगी। साधारण-तया तो इनका क्षेत्रीय सगठन प्रबन्ध सम्बन्धी ऐसे क्षेत्रीय विभाजन के अनुसार ही होना चाहिए परन्तु यह कोई पक्का नियम नहीं हो सकता। क्योंकि इस सगठन के लिए तो जनता की सुविधा पर प्रमुख विचार होगा। इस सुविधा के अनुसार ही उक्त क्षेत्रों को छोटा-बड़ा किया जा सकता है। यदि कार्य सुचारुतया सम्पादित होना हो तो लगभग १० प्रारम्भिक बहुद्देश्यीय सहकारी समितियों का इस स्तर पर एक सघ होना चाहिए। यह सघ सदस्य सहकारी समितियों के सब कार्यों को सगठित करेगा। जहाँ तक अधिकोषण का सम्बन्ध है इसके दो विचार हैं। एक तो यह कि अधिकोषण का कार्य पृथक् हो, परन्तु स्वतन्त्र रूप से हर तहसील या उक्त क्षेत्र में अधिकोष स्थापित करना अथवा जिला व राज्य के सहकारी अधिकोष की शाखा स्थापित करना इसलिए कठिन होगा कि वेतन आदि पर व्यय तो अधिक होगा और व्यवसाय पर्याप्त नहीं होगा। कुछ तहसीलें ऐसी हो सकती हैं जहाँ व्यवसाय हो, परन्तु वह व्यवसाय वही होगा जहाँ नगर हो और उस कार्य के लिए नागरिक अधिकोष हो सकते हैं। परन्तु इस स्तर पर यदि सघ का ही एक विभाग इस कार्य को सभाले तो उसके कई एक लाभ होंगे। इस स्तर पर सघ के कार्यों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हो सकता है।

- (१) प्रारम्भिक बहुद्देश्यीय सहकारी समितियों को परचून विक्री के लिए माल संग्रह करना तथा उन तक पहुँचाना,
- (२) प्रारम्भिक बहुद्देश्यीय सहकारी समितियों के उत्पादन के उस भाग का जो समिति क्षेत्र की आवश्यकताओं से अधिक हो, का संग्रह तथा विक्रय,
- (३) प्रारम्भिक समितियों के लिए वाछित मात्रा में ऋण उपलब्ध करवाना,
- (४) प्रारम्भिक समितियों के उद्योग तथा कृषि सम्बन्धी आवश्यक उपकरणों का प्रबन्ध करना। चूँकि आन्दोलन लोकतन्त्री होना चाहिए इसलिए प्रारम्भिक समितियों की मन्त्रणा तथा देख-रेख आदि का कार्य भी इन सघों के पास रहना चाहिए। अतः निम्न कार्य भी इन्हीं के क्षेत्र में रहेगा।
- (क) प्रारम्भिक समितियों को मन्त्रणा,
- (ख) प्रारम्भिक समितियों का हिसाब-किताब और उसकी जाच पड़ताल,
- (ग) प्रारम्भिक समितियों का परीक्षण व निरीक्षण,
- (घ) प्रशिक्षण का प्रबन्ध तथा सहकारी सम्मेलनों का आयोजन,

(ड) क्षेत्र के सहकारी कार्यों की योजना बनाना,

(च) सहकारी कार्य तथा ज्ञान के विकास हेतु अनुसन्धान क्षेत्र खोलना ।

इनमें सब कार्य आय वाले नहीं हैं। कुछ ऐसे कार्य हैं जो वर्तमान दशा में महत्वपूर्ण हैं। यह कार्य जब ये समितियाँ अथवा ऊपर के सघ करेगे तो उनको प्रारम्भिक दशा में सरकार से इसके लिए उपयुक्त आर्थिक सहायता मिलनी आवश्यक है। कुछ समय के पश्चात् इन सघों के पाम निधियाँ (फंड) जमा हो जायगी। इसी काम के लिए सदस्य-समितियों से शुल्क भी प्राप्त होता जायगा। इस स्तर पर आय-व्यय का अनुमान केवल साकेतिक हो सकता है। तो भी इस ओर सकेत करना इसलिए आवश्यक है कि पाठक इस सुझाव की व्यावहारिकता पर विवेचना-पूर्ण विचार कर सके।

आय—वार्षिक

१. सघ के थोक आयात व निर्यात व्यापार पर कमीशन द्वारा आय—	३०,०००)
(यह अनुमान ४०,००० जनसंख्या के लिए १० लाख लागत के वार्षिक व्यापार पर ३ प्रतिशत के दर पर किया गया है।)	
२ उद्योग-धन्धों तथा अन्य उत्पादन के व्यापार द्वारा—	३०००)
३ निरीक्षण, परीक्षण शुल्क लाभ के १०% पर १०००) की सीमा सहित	५०००)
४ एक लाख रुपया जो समितियों के पास ऋण रहेगा पर व्याज १% प्रति वर्ष के दर	१०००)
कुल जोड़	३९,०००

व्यय—वार्षिक

१ मन्त्री या सचिव २००) मासिक पर	२४००)
२ हिसाब रखने वाला १५०) मासिक पर	१८००)
३ निरीक्षक १५०) " "	१८००)
४ अकाउंटेंट १००) " "	१२००)
५ अधिकोषाधिकारी २००) " "	२४००)
६ विक्रेता ८०) " "	९६०)

१७ भण्डारी ८०)	मासिक पर	६६०)
८ ४ चपरासी ४०)	" "	१६२०)
६ शेष मिश्रित व्यय		५०००)
१० अनुसन्धान सम्मेलनादि		५०००)
११ प्रारम्भिक समितियों को लाभ		२०००)
१२ सुरक्षित कोष ५०,०००) की सीमा सहित		२५००)
१३ सर्व-सहायता कोष		२५००)
१४ भवन-निर्माण कोष		२५००)
१५ जिला सुरक्षित कोष		२०००)
कुल जोड़		३६,६४०)

जहां तक इस सघ के चालू धन का सबध है वह भाग-धन विक्रय, अमानतो, ऋण तथा सरकारी सहायता द्वारा सगृहीत होगा। इसका अनुमान मोटे तौर पर यो हो सकता है

१ सदस्य समितियों द्वारा भाग २५% भाग-धन के आधार पर	५०,०००)
२ अमानते	५०,०००)
३ ऋण	२००,०००)
४ तहसील पंचायतो द्वारा सङ्कार का भाग	१०,०००)
कुल जोड़	३१०,०००)

क्योंकि सघ की महत्तम ऋण सीमा आमतौर पर सत्वाधीन पूजी का दस गुणा होती है अतः दो-तीन लाख का ऋण कोई अधिक नहीं होगा और इस ऋण में से एक लाख तो ऋण में लगा रहेगा और ढाई लाख से वर्ष में दस लाख का व्यापार करना कठिन नहीं होना चाहिए।

जिला-स्तर—इस स्तर पर अधिकोषण कार्य एकीकृत नहीं रह सकेगा। क्योंकि यह कार्य इतना व्यापक तथा शेष कार्यों के लिए इतना आवश्यक है कि इसका कुशलतापूर्वक होना सारे आन्दोलन के लिए बहुत ही आवश्यक है। इस विषय पर पर्याप्त विचार सन्निहित अव्याय में किया जा चुका है कि जिला-स्तर के सहकारी अधिकोष पृथक् हो या वह राज्य सहकारी बैंक की शाखाएँ मात्र

हो। इनका इस स्तर पर जेप कार्यों के साथ इकट्ठा रखना अधिकोपण कार्य की कुशलता के हित में सहायक नहीं होगा। परन्तु इस स्तर पर भी अधिकोपण को छोड़ अन्य सब कार्यों का एकीकरण कई एक विचारों से उपयुक्त ही नहीं वरन् आवश्यक है। यह भी आवश्यक है कि जिला अधिकोप तथा जिला सहकारी मध का पारस्परिक सवध सजीव और दृढ़ रहे। इसके लिए सुभाव यह है कि जिला सहकारी मध की प्रबन्धक समिति के दो सदस्य जिला सहकारी अधिकोप की प्रबन्धक समिति पर और अधिकोप की प्रबन्धक समिति के दो सदस्य सहकारी मध की प्रबन्धक समिति पर होने चाहिए और दोनों मध्याग्रा की प्रबन्धक समितियों को एक सम्मिलित त्रैमासिक बैठक होनी चाहिए ताकि उनके कार्यों, योजनाओं तथा नीतियों में पूरा-पूरा ताल-मेल रहे।

अधिकोप के सवध में इस जगह केवल इतना ही लिखना पर्याप्त है कि जिला सहकारी अधिकोप की सदस्यता केवल तहसील स्तर के सहकारी मधों तथा नागरिक अधिकोपों तक ही सीमित रहनी चाहिए। व्यक्तिगत सदस्य वे केवल नाम के लिए ही होने चाहिए, ताकि मध्यस्थ-निर्णय का नाम बर्तनारियों आदि के विरुद्ध प्राप्त हो सके। यदि एक जिला में दस तहसील मध हों और इतने ही नागरिक अधिकोप हों तो जिला अधिकोप के २० सदस्य होंगे। एक मध यदि ५०००) के और एक नागरिक अधिकोप २५००) के भाग ले तो भाग-धन द्वारा जिला सहकारी अधिकोप को ७५,०००) प्राप्त होगा जो पर्याप्त होना चाहिए। सरकार भी जिला पंचायत द्वारा २५००) के भाग ले सकती है और उक्त जिला पंचायत के तीन प्रतिनिधि प्रबन्धक समिति पर लिए जा सकते हैं। माधारण अधिकोपण कार्य के साथ इस मध को नागरिक अधिकोपों तथा तहसील मधों के बैंकिंग कार्य का निरीक्षण भी करना होगा। यदि यह बैंक वर्ष में बीस लाख रुपये का लेन-देन करे और उसे उन पर १% प्रति वर्ष की प्राप्ति हो तो २०,०००) का लाभ होगा। भूमि प्रबन्धक अधिकोपण कार्य भी उन्हीं के साथ सम्पन्न रहना ठीक होगा। केवल आज इतनी आय में ही अधिकोप का सफलतापूर्वक चलना कठिन नहीं होगा।

का मन्दिर तो गरीर ही है। इसका भी अपने स्थान पर बड़ा ही महत्व है। दूसरा जिला-स्तर पर जो सहकारी सघ होगा वही आन्दोलन का इस स्थान पर गरीर होगा। जिला सहकारी विकास सघ का निर्माण जिला के अन्तर्गत तहसील अथवा ताल्लुका सहकारी सघों द्वारा होगा। जिलों के आकार का कोई निर्धारित स्वरूप नहीं है। इनके आकार बड़े भिन्न होते हैं। एक-एक जिला के ताल्लुके या तहसीलों की संख्या एक सी नहीं है। हो सकता है कि कभी समय आवे जब कि इन आकारों को किसी निश्चित धारणा की वजह से पुनः संगठित किया जाय परन्तु यह इस पुस्तक का विषय नहीं। अतः अनुमान के लिए दस तहसीलों अथवा दस तहसील-मगठनों के संगठन का ही एक जिला मगठन रखा गया है। जिला सहकारी विकास सघ के लिए हर तहसील सघ अपने भाग का २०% भाग रूप यदि दे तो दस तहसील सघों से एक लाख तक का भाग-धन एकत्रित होना कठिन नहीं होगा। यह मात्रा तहसील सघों की संख्या पर निर्भर होगी। चालू पूँजी के लिए इनका यही एक साधन होगा।

कुछ भाग जिला सहकारी अधिकोष भी लेगा परन्तु वैसे ही जिला अधिकोष में यह सघ भाग लेगा। अतः महत्तम ऋण-सीमा के निर्णय के लिए तो उसका लाभ हो जाएगा परन्तु वह रुपया सघ को अपने कार्य-हेतु उपलब्ध न होगा। १ लाख के भाग-धन पर सघ की महत्तम ऋण-सीमा १० लाख तक हो सकेगी। इस सघ के साधारणतया निम्न कार्य होंगे —

- (१) तहसील व ताल्लुका सघों का निरीक्षण एतदर्थ लाभ का ५% शुल्क लेना।
- (२) सदस्य सघों को परिवहन की सहायता पहुँचाना—अर्थात् ट्रक आदि का प्रवन्ध।
- (३) सदस्य-सघों की आवश्यकताओं के अनुसार उन्हें माल पहुँचाना और इस सेवा के लिए १% कमीशन लेना।
- (४) हर प्रकार की सहकारिता के लिए पर्याप्त विनिष्ट मंत्रणा तथा सहायता देना। इसके लिए सघ की विनिष्ट समितियाँ बनाना।
- (५) सहकारी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण का प्रवन्ध करना।

उपरोक्त १ व ३ स्रोतों से पर्याप्त आय हो सकती है। यदि सघों के व्यापार का ५०% भी जिसका सघ द्वारा हो तो ५० हजार आय थोक व्यापार द्वारा हो

सकती है और १० हजार की आय स्रोत (१) से हो सकती है। फिर परिवहन विभाग द्वारा भी काफी आय होगी। इतनी आय से सुचारु रूप से काम चलाना कठिन नहीं हो सकता।

राज्य-स्तर—इस स्तर पर एक राज्य-सहकारी विकास सघ होगा और एक राज्य सहकारी अधिकोष। राज्य-सहकारी अधिकोष की सदस्यता जिला सहकारी अधिकोषों तक ही सीमित होगी और सहकारी विकास सघ की जिला सहकारी विकास सघों तक। इस स्तर पर कार्यों का विशेष ध्यान देने की आवश्यकता नहीं क्योंकि इस विषय पर पहले के अध्यायों ने विचार किया गया है। राजकीय सहायता इस स्तर-अधिकोष को रिजर्व बैंक द्वारा और विकास सघ को सहकारी अधिकोष द्वारा आनी चाहिए। सदस्य सघों की आवश्यकताओं का माल प्राप्त करवाने की इस स्तर पर ५% से अधिक कमीशन नहीं होनी चाहिए। राज्य के सहकारी अधिकोष तथा सहकारी विकास सघ को आपस में भाग लेने चाहिए ताकि एक दूसरे की प्रबन्धक समिति पर एक दूसरे के प्रतिनिधि हो और ताल-मेल बना रहे। सहकारी-नीति निर्धारण के लिए एक सहकारी समिति का निर्माण होना चाहिए जिस पर राज्य सहकारी अधिकोष, राज्य-सहकारी विकास-सघ के प्रतिनिधि, सहकारी विभाग का उच्चाधिकारी तथा सहकारिता से सम्बन्धित सभी सदस्य हों। यह केवल परामर्शदातृ समिति होगी।

इस प्रकार ग्राम से राज्य तक एक सुसम्बद्ध संगठन बन जायगा। इनसे आगे सारे देश के लिए किसी संगठन की आवश्यकता नहीं दीखती। हा, देश की सहकारी नीति के निर्धारण के लिए एक अखिल देशीय परामर्शदातृ समिति का निर्माण राज्य की परामर्शदातृ समितियों द्वारा केन्द्र के सहकारी मंत्री के अधीन हो सकता है। उनका सम्बन्ध डीपी प्रकार की अन्य देशीय समितियों से स्थापित किया जा सकता है।

सहकारी संगठन को अब उचित महत्त्व देने का समय आ गया है। विन्व का मानव आज एक ऐसे संगठन के लिए तड़प रहा है। राजनीति तथा प्रबन्धन के विभिन्न विचारों के घण्टर, हठतालों के युग, आन्तरिक युद्धों की आग-आँध्रों में विन्व आज इन सोंज में है कि देश-देश, वर्ग-वर्ग तथा व्यक्ति-व्यक्ति के दूर-दूरान ईर्ष्या तथा द्वेष की खाई को पाटकर मानव को मानवता का पाठ पढ़ाया

जाय और यह सब सहकारिता के संगठन द्वारा ही सभव हो सकता है। परन्तु सहयोग अथवा सहकारिता जिस छिन्न-भिन्न अवस्था में है, उसी में रहने दी जाएगी तो यह अपने ध्येय को प्राप्त नहीं कर सकेगी।

: १२ :

सहकारी-विभाग

सहकारी आन्दोलन का प्रादुर्भाव विवश जनता में हुआ। कई देशों में तो इसके प्रवर्तकों को बड़ी यातनाएँ सहन करनी पड़ी। राबर्ट ओवन का इतिहास, अमरीका की कथाएँ, जारशाही रूस की कई घटनाएँ इस तथ्य की पोषक हैं। शासकों तथा राज्यों ने तो इसे तब अपनाया जब शासकों की तानाशाही, सामन्त-शाही, पूँजीवाद तथा किसान-मजदूर-शोषक नीति के विरुद्ध हिसापूर्ण क्रान्ति का भय उत्पन्न हो गया। इस भय के प्रभावाधीन तब शासकवर्ग ने सहयोग की कतिपय पद्धतियों को अपनाया। यह सब क्रान्ति को कुछ काल तक टालने के लिए किया गया। ऐसे विचारों के अधीन अपनाई गई सहकारिता वास्तविक सहयोग की मौलिक भावनाओं से कहीं दूर थी। इसलिए कि कहीं स्वतन्त्रता के वातावरण में सहकारिता सहयोग की भावनाओं को विकसित करके समाज को साम्ययोग की ओर ले जाकर कहीं शासन-निरपेक्ष समाज के ध्येय को निकट लाकर शासकवर्ग की सत्ता को शिथिल न कर दे। शासकवर्ग ने पूँजीवादियों, सामन्तों तथा शोषकवर्गों से साजिश करके सहकारिता को कानून के ऐसे बधनों में जकड़ दिया कि उसका विकास कुण्ठित हो गया।

प्रारम्भ से ही सहकारिता के प्रचलन के सम्बन्ध में दो विचार-धाराएँ चल रही हैं। एक यह कि सहकारिता शासन के नियन्त्रण से मुक्त रहकर विकसित होनी चाहिए और दूसरी यह कि सहकारिता को शासन की सहायता तथा शासन का नियन्त्रण प्राप्त होना चाहिए, इसके बिना उसका विकास सभव नहीं। और जब तक राजकीय सहायता द्वारा इसे पुष्ट न किया जाय तब तक यह पनप नहीं



सकती। वस्तुतः यह दोनों विचार-धाराएँ न तो पूर्णतया ठीक हैं और न ही पूरे तौर पर गलत। जब राज्य शासन सहकारिता-विरोधी नहीं बल्कि सहकारिता-पोषक है तो ऐसे समय में सहकारिता को शासन से किसी प्रकार के असहयोग की आवश्यकता नहीं। दूसरी ओर इस मौलिक विचार को नहीं भुलाया जा सकता कि सहकारिता प्रारम्भ से ही स्वावलम्बी होती है। और उसका परिवर्धन होता है स्वावलम्बन के द्वारा ही। जब राज्य कल्याणकारी तथा लोकतंत्री हो तो यह राज्य के अपने हित में है कि सहकारिता का विकास हो। परन्तु यह भी सहकारिता के विकास के हित में है कि उसके मौलिक गुणों तथा उसके मौलिक स्वभाव से उसका विच्छेद न किया जाय, उसको दूर न ले जाया जाय। सहकारिता सहायता चाहती है, मन्त्रणा की उसे आवश्यकता है। धार्मिक प्रेरणा-सम्पन्न प्रचारकों की आवश्यकता है। उसे आर्थिक तन्त्र में धन की भी आवश्यकता है परन्तु वह किसी प्रकार का, किसी व्यक्ति-विशेष अथवा वर्ग-विशेष का धन अथवा प्रशासनिक शक्ति के रूप में नियन्त्रण को सहन नहीं कर सकती। अकुश उसकी विकास गति को कुण्ठित अथवा अवरुद्ध कर देता है। अतः कानून और सरकार के सहकारी प्रगति में क्या कर्तव्य हो सकते हैं, इसका निर्धारण उपरोक्त विचारधारा के अनुसार ही होना आवश्यक है। हम 'सहकारिता का उदय और विकास' में देख चुके हैं कि भारत में भी कानून के बिना जो सहकारी संस्थाओं का प्रादुर्भाव तथा विकास हुआ या उसे कानून ने कुण्ठित किया, जैसे पंजाब के होशियारपुर जिले के पंजौर ग्राम की सहकारी समिति के इतिहास से विदित होगा। यदि सरकारी सहायता, कानून तथा सरकारी नियन्त्रण सहकारिता की प्रगति को कुण्ठित करे तो हमें विचार करना पड़ेगा कि इसका कारण क्या है ?

सहकारी आन्दोलन में जब हम मानव तथा मानवता को महत्व देते हैं और धन को नहीं, वहाँ यदि हम शासन की शक्ति को महत्व देंगे तो आन्दोलन की प्रगति अवश्य कुण्ठित होगी। क्योंकि सहकारिता तो स्नेह के बीज से मानव-हृदय की भूमि में स्वार्थ-त्याग की खाद की सहायता से उगती और पनपती है। वहाँ धन तथा शक्ति को कोई स्थान नहीं।

अतः सरकार को सहकारिता के विकास, प्रसार एवं पोषण में बड़ी सोच-समझ के साथ काम करना होगा। इसके कर्तव्यों का निश्चय करने में भूल

होने से समस्त आन्दोलन का बड़ा अनर्थ हो सकता है। ऐसा अनर्थ होते कई स्थानों पर देखा गया है। जहाँ तक सरकार द्वारा आर्थिक सहायता का प्रश्न है, उसके सम्बन्ध में पिछले अध्यायों में विचार किया गया है। इस अध्याय में सरकार के शक्ति सम्बन्धी नियन्त्रण, जो कि आमतौर पर सहकारी विभाग द्वारा होता है, पर ही विचार करना सगत होगा।

भारत में सहकारी विभाग ही सहकारिता का मूल-स्रोत समझा जाता है। प्रेरणा-शक्ति विभाग में ही निहित है और जहाँ कहीं जनता उक्त शक्ति को प्राप्त करने का प्रयत्न करती है वहाँ कानूनों की कड़ाई तथा विभाग का सत्ता के लिए मोह आकर अडचने डाल देता है। इसमें सन्देह नहीं कि शासन ने गत ५७ वर्षों में साधारणतया और स्वतन्त्रता के पश्चात् विशेष रूप से सहकारी आन्दोलन की बड़ी मूल्यवान् आर्थिक तथा नीतिपरक सहायता की है। परन्तु इस सहायता के होत हुए भी यदि आन्दोलन आगे नहीं बढ़ पाया तो इसके क्या कारण हैं। इन्हीं कारणों की खोज के लिए समय-समय पर समितियाँ बनती रही और इस पक्ष की ओर सब समितियों ने ध्यान दिया। इनकी सिफारिशों का सक्षिप्त पुनर्विवरण समस्या के भली प्रकार समझने तथा सुलझाने के लिए लाभप्रद होगा। इसी समस्या के बारे में मर्च १९१४ में मेल्केगन कमेटी ने लिखा था—

“रजिस्ट्रार के कर्मचारियों में वृद्धि होनी चाहिए। कृषि तथा उद्योग से सम्बन्धित विभाग के कार्यक्रम को सहकारिता से सम्बद्ध करना चाहिए और इनका अव्यक्त एक होना चाहिए। इसके लिए एक विकासाध्यक्ष रखना चाहिए, जिसके अधीन यह काम दिए जा सकते हैं। अभी तक इस विभाग को कृषि तथा शिक्षा की तरह महत्व प्राप्त नहीं हो सकता। हमने यह भी विश्वास पाया कि इस आन्दोलन को सरकार की गारंटी प्राप्त है। विभिन्न अविश्वासों को आमक सिद्ध करने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया जाता। सरकार को चाहिए कि सब अफसरों को यह स्पष्ट करे कि यह उनका कर्तव्य है कि कोई अमूलक धारणा जनता में न रहने पाय।”

इसके पश्चात् मर्च १९४६ में सहकारी योजना समिति ने भी इस सम्बन्ध अपने मुभाव दिए जो संक्षेप में इस प्रकार हैं —

“यदि सहकारी आन्दोलन का विकास इसलिए करना है कि इससे

देश का अधिक विकास हो, जनता का जीवन-स्तर ऊँचा हो और उसकी आवश्यकताएँ पूरी हो तो सहकारी विभाग के कर्मचारी ठीक ढंग के होने चाहिए। इन कर्मचारियों का साधारण जनता से सम्पर्क होना चाहिए और विकास-विभाग से भी इनका पूरा तालमेल होना चाहिए। यह कर्मचारी-समुदाय इतना योग्य होना चाहिए कि इस निरन्तर बढ़ते जाने वाले उत्तरदायित्व को वह सहर्ष और योग्यता से सभाल सके। कर्मचारियों तथा पदाधिकारियों के ओहदे हर राज्य में जहाँ तक सम्भव हो, एक से ही होने चाहिए।

“विभाग के नये सगठन में रजिस्ट्रार का महत्व बढ़ने वाला है अतः उसकी नियुक्ति देखभालकर होनी चाहिए। इस कार्य में उसकी विशेष रुचि होनी चाहिए। कार्यारम्भ करने के पूर्व उसे प्रशिक्षण मिलना चाहिए और दो वर्ष तक डिप्टी-रजिस्ट्रार या सह-रजिस्ट्रार के पद पर काम करने का प्रवसर दिया जाना चाहिए। यह अधिकार इण्डियन सिविल सर्विस या प्रान्तीय सहकारी सर्विस का होना चाहिए। इस पद का महत्व भी बढ़ा देना चाहिए और इसे उसी स्तर पर ले आना चाहिए जिस पर पुलिस या पी० डब्ल्यू० डी० के विभाग होते हैं। पद की अवधि दस वर्ष तक होनी चाहिए।

“सहकारी विभाग के कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण मिलना चाहिए। इनके पदों के ग्रेड आदि राजस्व विभाग के कर्मचारियों के बराबर होने चाहिए ताकि अच्छी शिक्षा तथा योग्यता वाले व्यक्ति इन पदों पर आने के लिए लालायित हो।

सगठन तथा प्रचार-हेतु गैर-सहकारी तत्वों का उपयोग करना अधिक लाभदायक होता है। निःशुल्क प्रचारकों की सेवाओं के क्रम को प्रोत्साहित करना इसमें जरूरी है।

“पर्यवेक्षण का कार्य राज्य-सहकारी-संघ द्वारा होना चाहिए और इसका खर्च निकालने के लिए राज्य को चाहिए कि उनको आर्थिक सहायता दे ताकि कार्य सुगमता से चले। सहकारी संघों को चाहिए कि अपने कार्य का विकेंद्रीकरण करके स्थानीय सहकारी-सगठनों तथा सहकारी-समितियों द्वारा पर्यवेक्षण करवाएं। बैंकों द्वारा पर्यवेक्षण की प्रथा को प्रोत्साहन

नहीं दिया जा सकता ।

“निरीक्षण का कार्य पूर्ववत् विभाग द्वारा ही होते रहना चाहिए । यह कार्य गैर-सरकारी सस्थाओं को धीरे-धीरे ही सौंपा जा सकता है । लेखा-परीक्षण का कार्य भी विधान के अनुसार रजिस्ट्रार का ही कर्तव्य रहना चाहिए । इस कार्य को गैर-सरकारी सस्थाओं को सौंपने का अधिकार भी रजिस्ट्रार को ही होना चाहिए, लेकिन परीक्षण तथा पर्यवेक्षण का कार्य एक ही व्यक्ति के पास रहने देना ठीक नहीं । सहकारी समितियों का श्रेणी-विभाजन गजट में प्रकाशित होना चाहिए । इसमें कोई सन्देह नहीं कि विकास के नये उत्तरदायित्व सहकारी सस्थाओं पर पड़ने से राज्य द्वारा पर्यवेक्षण कुछ काल तक स्वाभाविक ही होगा, परन्तु इसको धीरे-धीरे कम करते जाना चाहिए जिससे किसी समय यह पूर्णतया समाप्त हो जाय ।

“गैर-सरकारी सस्थाओं तथा विकास सम्बन्धी सस्थाओं तथा विभागों का भी सहकारी सस्थाओं के साथ पूर्ण तालमेल रहना चाहिए ।

“राज्य में एक सहकारी समिति बननी चाहिए । इस सस्था को चाहिए कि सहकारिता द्वारा आर्थिक विकास करने की योजनाएँ बनाये और उन्हें कार्य रूप में परिणत करने के लिए उपाय करे । सहकारी विभाग का मन्त्री इसका प्रधान बने और सहकारी विभाग का रजिस्ट्रार सेक्रेटरी तथा सह-रजिस्ट्रार की श्रेणी का अफसर सहायक मन्त्री । इसमें गैर-सरकारी सदस्यों की सरया अधिक होनी चाहिए । बैठक वर्ष में दो बार हो । साथ ही इसकी एक प्रबन्धक-कमेटी भी होनी चाहिए, जिसका सारा खर्च सरकार दे । इस समिति के दो भाग होने चाहिए—एक समिति के सब कार्यों पर नियंत्रण रखे और दूसरा राज्य शासन को मंत्रणा दे ।

“अखिल भारत सहकारी कौंसिल विभिन्न राज्यों को मंत्रणा दे ताकि विभिन्न प्रकार की सहकारिता के सम्बन्ध में विचार-विमर्श होता रहे । इस कौंसिल के खर्च के लिए प्रथम पाँच वर्षों में २० लाख रुपया सरकार द्वारा मिलना चाहिए ।”

इस विषय की चर्चा करते हुए प्रथम पंचवर्षीय योजना में इस प्रकार लिखा है—

“अन्तिम रूप में सहकारी समितियों की सफलता उनके अपने कार्यों के, चाहे वे उत्पादन, वित्त, ब्रय-विक्रय और वितरण या निर्माण के बारे में हो, संचालन की योग्यता तथा सदस्यों और समाज की तुष्टि पर निर्भर है।

“प्रायः सहकारी समितियों का संगठन तथा प्रबन्ध उन लोगों के द्वारा होता है जिनमें अनुभव तथा योग्यता की कमी होती है। कई एक सहकारी समितियों और देश में इस आन्दोलन की असफलता का यही कारण है। अतः सहकारी समितियों को चाहिए कि वे योग्य व्यक्तियों की भर्ती करें और मौजूदा कार्यकर्त्ताओं को अच्छी ट्रेनिंग दिलवायें।

“आमतौर पर सब राज्यों में सहकारी विभाग है और अब तक इन का काम केवल निरीक्षण, पड़ताल और प्रमाणीकरण तक सीमित रहा है। परन्तु अब जबकि सहकारिता आर्थिक योजना के लिए महत्वपूर्ण है, इसके लिए अधिकारियों को केवल आडिटर और इस्पेक्टर ही नहीं बनना है बल्कि सहकारिता का महत्व भी जनता को समझाना है।”

सहकारिता के विषय पर अन्तिम रिपोर्ट ग्राम्य-ऋण-सर्वेक्षण समिति की। इस अध्याय के विषय से सम्बन्धित इस समिति के प्रस्ताव इस प्रकार हैं —

- १) सहकारी समितियों के कर्मचारी समुदाय तथा राजकीय सहकारी विभाग के कर्मचारी वर्ग एक जैसे हो।
- २) राज्य सरकारों को चाहिए कि वह सहकारी कर्मचारीवर्ग को दो भागों में विभक्त करें—एक प्रशासनिक, दूसरे विशेषज्ञ। दोनों में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणियाँ यथावत रखी जावे, यथा—अर्थ-सवधी मामलों का मन्त्री, प्रबन्धक आदि।
- ३) इन सब वर्गों के प्रशिक्षण का प्रबन्ध केन्द्रीय सहकारी समिति के अधीन होना चाहिए।
- ४) सहकारी विभाग का मुख्याधिकारी रजिस्ट्रार होता है। इन अधिकारियों पर ही विभाग का प्रधान आधार होता है। सहकारी योजना समिति के अनुसार प्रस्ताव निम्न हैं—

“रजिस्ट्रार केवल विशेष योग्यता-सम्पन्न व्यक्ति नहीं होना चाहिए, परन्तु वह स्वभाव से इस प्रकार के लोक-तंत्रीय आन्दोलन को चलायाने की

क्षमता रखने वाला होना चाहिए। पद सभालने से पूर्व उसे पूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए और कम से कम दो वर्ष उसे डिप्टी अथवा सहायक रजिस्ट्रार के तौर पर काम करना चाहिए। प्रशिक्षण काल में इसे अन्य राज्यों तथा अन्य देशों का सहकारिता संबंधी अध्ययन करने का अवसर मिलना चाहिए।

“रजिस्ट्रार के बड़े उत्तरदायित्वों को समक्ष रखते हुए जरूरी है कि इस अधिकारी को पुलिस व पी० डब्ल्यू० डी० के विभागाध्यक्षों के समान दर्जा व सम्मान प्राप्त हो। इसकी पदावधि १० वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और उसे प्राप्तव्य वेतन वृद्धि इसी पद पर मिल जानी चाहिए।”

- (५) कृषि, कुटीर उद्योग तथा उद्योग आदि के कार्य सहकारिता से संबंधित होने चाहिए और यदि यह सब विकास आयुक्त के अधीन संगठित हो तो रजिस्ट्रार भी विकास-आयुक्त के अधीन हो जाना चाहिए।
- (६) पर्यवेक्षण-कार्य शिखरीय अधिकोप तथा केन्द्रीय अधिकोष के अधीन रहना चाहिए और जहाँ आन्दोलन विकसित हो चुका हो वहाँ एतदर्थ कर्मचारी-समुदाय भी शिखरीय सहकारी अधिकोष को ही रखना चाहिए। शेष राज्यों में यह कर्मचारीवर्ग राज्य रखे परन्तु यह कर्मचारी समितियों को उधार दे दिये जाने चाहिए।
- (७) हिमाव आडिट करना रजिस्ट्रार का वैधानिक कर्तव्य है। और उसे सब सहकारी समितियों के हिसाब वर्ष में एक बार आडिट करने पड़ते हैं। यह कार्य सरकार के अर्थात् रजिस्ट्रार के अधीन ही रहना चाहिए।
- (८) शिखरीय तथा जिला सहकारी अधिकोषों को साथ-साथ आडिट का प्रबन्ध करना चाहिए। यह कार्य वर्ष के मध्य में होना चाहिए। यह पूर्ण व्हीरे-वार होना आवश्यक नहीं परन्तु यह विभागीय आडिट से छ मास पश्चात् होना चाहिए।
- (९) आडिट-पद्धति सारे देश भर में एक जैसी होनी चाहिए और आदर्श होनी चाहिए।

सरकार के सहकारी आन्दोलन के सम्बन्ध का दूसरा अंग सहकारी अधिनियम है, परन्तु उस पर विचार सामूहिक तौर पर ही हो सकता है, क्योंकि उसका संबंध समूचे आन्दोलन से है। विभिन्न समितियों के प्रस्तावों के उपरि-

लिखित सिद्धान्तलोकन से प्रकट है कि आन्दोलन का मूल अभी जनता में जमा नहीं है और इस सारे आन्दोलन की आधार-शिला रजिस्ट्रार ही है। इसमें सन्देह नहीं कि भारत ने कतिपय विषय-प्रसिद्ध रजिस्ट्रार पैदा किये हैं यथा कैलवर्ट, स्ट्रिक्लैंड, डार्लिंग रायन आदि। परन्तु कुछ अच्छे रजिस्ट्रार पैदा करने पर भी इतने बड़े देश में हम रजिस्ट्रारों की परंपरा स्थापित नहीं कर सकेंगे। इसके कारणों की ओर समितियों ने ध्यान दिया है। परन्तु जब तक हम विभाग के कर्तव्यों का भली प्रकार निर्णय नहीं कर लेते तब तक ऐसी परंपराओं की स्थापना संभव नहीं। सहकारिता के सिद्धान्तों तथा इसके इतिहास पर यदि हम भली प्रकार विचार करें तो स्वयमेव इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि यदि इस आन्दोलन को दृढ़ चट्टान की तरह स्थापित करना है तो प्रचार व प्रेरणा द्वारा जनता-जनार्दन के हृदयों में सहकारिता के पावन भावों को जागृत करना होगा, उनका पोषण करना होगा। उनमें इस आन्दोलन के अधीन परिचालित समितियों को चलाने की योग्यता लानी होगी और अन्ततोगत्वा उनमें ही सारे आन्दोलन को निरन्तर विकसित करने तथा नियन्त्रित रखने के लिए उपयुक्त यन्त्र को निर्मित करना पड़ेगा।

अतः सरकार के आगे दो ही रास्ते हैं कि—

- (१) या तो वह आन्दोलन को स्वयं इस होड़ के युग में मथर गति से विकसित होने दे और विभाग के कार्य व कर्तव्य ऐसे ही रखे जैसे कि सामे निगमों में होते हैं अथवा—
- (२) सेवा-भाव से ओत-प्रोत प्रचारकों का एक दल विभाग में हो, जो सहकारिता को जनता का आन्दोलन एक निश्चित योजना के अधीन बना दे।

आज जब हमारे देश ने संविधान के अधीन सहकारिता को अपना ध्येय बना लिया है, सरकार का कर्तव्य ऊपर लिखे अनुसार होना चाहिए। सहकारिता को विकसित करने के लिए अब प्रतीक्षा नहीं की जा सकती। इस ध्येय की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। सर्वप्रथम कार्य तो जनता के सहकारी भावों को जागृत करना है। यह कार्य भी शासन को ही करना पड़ेगा। यह बड़ा ही गम्भीर, महत्वशाली तथा कठिन कार्य है। परन्तु बड़े शोक से कहना पड़ता है कि इस परमावश्यक यत्न की ओर उतना ध्यान नहीं दिया जितना कि इस कार्य के लिए आवश्यक था। सचने यही सोचा कि कर्मचारियों को साधारण-

प्रशिक्षण देने से यह काम हो जायगा परन्तु इन परीक्षाओं के पास करने तथा डिग्रियों के सम्बन्ध में सन् ३० में श्री पी० सी० राय ने ठीक ही कहा था “एक साधारण डिग्री अविद्या को छिपाने का चोला मात्र है।” और फिर इस कर्म-चारीवर्ग पर एक रजिस्ट्रार होता है जिसके सम्बन्ध में की गई सिफारिशों पर आज तक कभी अमल नहीं किया गया। पूर्व इसके कि विभाग अथवा कर्मचारी-वर्ग के सम्बन्ध में कुछ लिखा जाय, यह आवश्यक है कि हम गासन के इस आन्दोलन के प्रति कर्तव्यों को सूत्र-बद्ध कर ले—

- (१) शासन का आन्दोलन से सबध मन्त्रणा तथा सहायतापरक होना चाहिए।
- (२) शासन को चाहिए कि विभाग के कर्मचारियों में सहकारिता के प्रति पूर्ण निष्ठा उत्पन्न करे तथा उसको प्रोत्साहित करे।
- (३) मन्त्रणा तथा सहायता करते समय शासन देखे कि वह मन्त्रणा इस लोक-तन्त्रीय आन्दोलन को निर्बल तथा परावलम्बी बनाकर उसके स्वावलम्बी भावों को शिथिल न करे।
- (४) आन्दोलन का नियन्त्रण पूर्णतया लोकतन्त्रीय रहे।
- (५) समस्त आर्थिक समितियों को सहकारी ढांचे पर आयोजित करने में प्रोत्साहन दे।
- (६) सहकारिता में द्वन्द्व और मुकाबिले को स्थान नहीं, वह लोकतन्त्रीय तरीके से नियन्त्रित आर्थिक पद्धति पर आश्रित होती है अतः इस दिशा में राज्य नीतियों, अधिनियमों व साहित्य द्वारा इस मूलाधार का प्रचार करता रहे।
- (७) वास्तव में समस्त विभागों व कर्मचारियों को सहकारिता-समर्थक बनाया जाय।

यदि इन बातों पर सबका मतैक्य हो तो विभाग के कर्तव्यों तथा कार्यों का स्पष्टीकरण सुगम हो जायगा। आन्दोलन के साथ सरकार के सम्बन्धों तथा कर्मचारीवर्ग और आन्दोलन की आधारशिला रजिस्ट्रार ही है। रजिस्ट्रार का एक तो नामकरण भ्रम पैदा करने वाला है क्योंकि उक्त अधिकारी आर्थिक नीति में केवल उनके पंजीकरण का काम करता है, सहकारिता में उससे कहीं अधिक काम करना पड़ता है। अतः जब तक अधिकारी का यह नाम रहेगा सहकारी विभाग अपने वास्तविक कर्तव्यों को कभी भी पहचान नहीं सकता।

अतः इस सम्बन्ध में सुझाव यह है कि पञ्जीकरण का काम तो रजिस्ट्रार करे और भाषा में उसका नाम भले ही पञ्जीकार रहे परन्तु जो अधिकारी सारे आन्दोलन का अध्यक्ष हो उसका नाम "सहकारिता सचालक" अथवा "सहकारिता निर्देशक" अथवा "सहकारिता आयुक्त" रखा जाय। डैवलपमेंट कमिश्नर के अनुसार "कोऑपरेटिव कमिश्नर" अर्थात् "सहकारी आयुक्त" नाम भी रखा जा सकता है।

ग्राडिट करना

उक्त आयुक्त के अधीन एक अधिकारी पञ्जीकार अर्थात् रजिस्ट्रार होगा और दूसरा होगा चीफ ग्राडिटर। भारत में ग्राडिट करना विभाग का ही कार्य रहा है। यह कार्य पर्याप्त काल तक विभाग के अधीन रखना पड़ेगा। इसमें सन्देह नहीं कि अन्ततोगत्वा यह कर्तव्य सहकारी अधिकोप का होगा, परन्तु जब तक हमारा नैतिक उत्थान नहीं हो पाता और हम निस्वार्थ तथा निष्पक्ष होकर न्याय करने की आदत नहीं बना लेते तब तक विभागीय ग्राडिट आवश्यक ही रहेगा। परन्तु जिस प्रकार चार्टर्ड अकाउण्टेंट्स को सरकारी मान्यता रहती है इसी प्रकार पूर्व अध्यायो में वर्णित विधि के अनुसार प्रारम्भिक सहकारी समितियों तथा प्राथमिक सघों का ग्राडिट तो बैंक के अधीन रहेगा परन्तु ग्राडिटरो की नियुक्ति उक्त अधिकोप उन व्यक्तियों में से करेगा जो कि चीफ ग्राडिटर द्वारा अनुमोदित हों। इन ग्राडिटरो का साक्षात् समुदाय हो और स्थानान्तरण का विधान रहे। इन ग्राडिटरो के लिए एक प्राचरण पद्धति बनाई जाय जिस पर अमल न करने पर चीफ ग्राडिटर का अनुमोदन वापस ले लिया जाय और अनुमोदित सूची से नाम हट जाने पर वह पहले स्वयमेव मुक्त हो जाय। जहाँ तक जिला सहकारी सघों, जिला अधिकोषों, राज्य सहकारी विकास सघों, तथा राज्य सहकारी बैंकों के ग्राडिट का सम्बन्ध है वह मुख्य ग्राडिटर के अधीन रहेगा। वार्षिक पडताल तो चीफ ग्राडिटर स्वयं अथवा अपने स्टाफ द्वारा करे और छमाही ग्राडिट समितियों अथवा रजिस्टर्ड ग्राडिटरो द्वारा कराए।

और दूसरी शैली यह है कि जाच-पडताल का काम जिम्मात्मक हो, भूतों तथा अपराधों में भेद को समझ रखकर काम किया जाय। भूलों को सुधारा जाय। भविष्य के लिए उनको मन्त्रणा दी जाय। उनकी लेखा रखने की विधि में यथा-समय तथा यथावश्यक मन्त्रणा तथा सहायता दी जाती रहे। जहाँ जान-बूझ-

कर प्रसारित किया हो वही मामले को दण्डनीय समझा जाय। सहकारिता की भावना की पोषक पद्धति तो यही है। इस तरह आडिट का काम शासन तथा सस्थाओं द्वारा संगठित रूप से हो सकेगा।

पजीकरण

पजीकरण का केवल मात्र इतना काम है कि जो समितियाँ पजीकृत हो वह निगम हो जाती हैं और निगम के वैध अधिकार उसे प्राप्त हो जाते हैं। पजीकरण हेतु अधिक कर्मचारीवर्ग की आवश्यकता नहीं। यह कार्य राज्य के लिए केन्द्रित ही होना चाहिए। कार्य विकेंद्रित होने से पजीकरण की आवश्यकताओं में समानता नहीं रह सकती। पजीकार को नियमाधीन कुछ तालिकाएँ प्राप्त करनी चाहिए। विघटन की कार्रवाई भी इसी अधिकारी के अधीन रहनी चाहिए। पजीकार व उसके अधीनस्थ कर्मचारीवर्ग को सस्थाओं के निरीक्षण के अधिकार केवल इसलिए होने चाहिए कि वह पजीकरण की आवश्यकताओं की पूर्णता अथवा अपूर्णता को देख सके। इसलिए पजीकार के अधीन निरीक्षक अर्थात् इन्स्पेक्टर होने आवश्यक होंगे।

प्रशिक्षण

प्रशिक्षण सहकारी आन्दोलन के लिए बड़ा ही आवश्यक अंग है। यह कार्य जिस साधारण ढंग से आजकल किया जाता है उससे काम सफल होने वाला नहीं। इसके लिए एक बड़े विद्वान तथा सहकारी भावनाओं से ओतप्रोत अनुभवी व्यक्ति का होना आवश्यक है। इसके लिए सहकारी आयुक्त के अधीन एक सहकारी शिक्षा निर्देशक होना चाहिए। साहित्य निर्माण, प्रशिक्षण, सस्था संचालन, सहकारी-सम्मेलन, कार्यकर्ता तथा कर्मचारी शिक्षण आदि कार्य इस अधिकारी के अधीन रहना चाहिए।

प्रशिक्षण सस्याएँ तो इस अधिकारी के अधीन रहनी चाहिए परन्तु शेष प्रशिक्षण-कार्य विभाग के शेष अधिकारियों से एकीकृत रहना चाहिए। प्रशिक्षण पद्धति गांधी विचारधारानुसार आश्रम शैली से होनी चाहिए।

इस विभाग में सहकारी समितियों को कानूनी परामर्श की बड़ी आवश्यकता है और यहाँ पर कानूनी मंत्रणा भी सहकारितापरक होनी आवश्यक है। यह हर राज्य की योग्यता, आर्थिक-शक्ति तथा कार्य-भार पर निर्भर

होगा कि इस कार्य के लिए कोई पृथक् अधिकारी हो अथवा सहकारी शिक्षा निर्देशक ही इस कार्य के लिए उत्तरदायी रहेगा। साधारणतया सहकारी शिक्षा निर्देशक ही यदि वाहनी मंत्रणा प्रदान करने का कार्य भी करे तो ठीक ही रहेगा।

नामान्य संगठन

विभाग के उत्तरोत्तर अंगों का वर्णन इसलिए पृथक्-पृथक् किया गया है कि आमतौर पर आज तक इन्हीं अंगों को ही विभाग का समूचा कार्य समझा जाता रहा और जो आन्दोलन का वास्तविक और परम महत्वशाली अंग है उसके नाम और कार्य दोनों स्वरूपों में अवहेलना की जाती रही है। यह है विभाग के प्रचारात्मक, संगठनात्मक तथा मंत्रणात्मक कर्तव्य। यही कार्य है जो विभाग का नामान्य अंग सम्पादित करेगा। हम ऊपर देख चुके हैं कि अब तक भारत में इस जनकल्याणकारी आन्दोलन का केन्द्र-बिन्दु रजिस्ट्रार रहा है। यर्थ यह है कि राज्य की ओर से नियुक्त विभागाध्यक्ष पर ही वस्तुतः आन्दोलन का अस्तित्व निर्भर रहता है। यह कैसे नियुक्त हो ? इसका नियंत्रण कौन करे ? इसके लिए आवश्यक योग्यताएँ क्या हो ? नियुक्ति कितनी अवधि के लिए हो ? इसके अधिकार और कर्तव्य क्या हो ? आदि प्रश्न हैं जिन पर विचार होना आवश्यक तथा उपयुक्त ही है।

सहकारी संगठन के अध्याय में यह सुझाव दिया जा चुका है कि देशीय-स्तर पर एक सहकारी समिति होगी। सहकारी आयुक्त की नियुक्ति में इस समिति में मंत्रणा लेनी आवश्यक होगी। यह नियुक्ति सयोजन-सेवा-प्रायोग द्वारा होनी उपयुक्त नहीं। यदि इस अधिकारी की नियुक्ति ठीक ढंग से हो तो सारा कार्य सुचारु रूप से चल सकेगा। अतः इस पद के लिए निम्न बातों को ध्यान में रखना उपयुक्त होगा—

- (१) सहकारी-आयुक्त का दर्जा राज्य के अच्छे विभागाध्यक्षों से किसी भी दशा में न्यून न हो।
- (२) गामोद्योग का कार्य भी इसीके अधीन रहे।
- (३) न्यूनतम शिक्षा अर्थशास्त्र की विशेषता सहित एम०ए० या एल०एल०बी० हो।
- (४) न्यूनतम आयु ४० वर्ष हो।

आधुनिक सहकारिता

१५५ क्रम से कम ५ वर्ष सहकारी विभाग या किसी सहकारी संस्था में काम किया हो।

(६) सहकारिता पर कोई पुस्तक या खोजपूर्ण लेख लिखा हो।

(७) किसी सहकारी संस्था का संचालन किया हो।

उपरिलिखित योग्यता-सम्पन्न व्यक्ति की नियुक्ति १० वर्ष से कम अवधि के लिए नहीं होनी चाहिए और राज्य को रवय भी उक्त अवधि के अन्दर उसे कही तबदील नहीं करना चाहिए। इस अधिकारी पर नियन्त्रण सहकारी समिति का होना चाहिए। इस प्रकार के व्यक्ति की नियुक्ति से आधी से अधिक कठिनाइयां हल हो जायगी।

ग्रामोद्योग का काम सभालने के लिए सहकारी-आयुक्त के अधीन एक और निर्देशक रखा जायगा। उक्त आयुक्त के कर्तव्य तथा अधिकार काफी विस्तृत होंगे। इसके अधीन जिन अधिकारियों के वर्गन किये गये हैं वह सब सहकारी आयुक्त के पूर्ण नियन्त्रणाधीन रहेंगे। सामान्य कार्य के लिए आयुक्त का एक सहायक होना चाहिए जो योजना सम्बन्धी काम को देखे और शेष कार्य आयुक्त के अधीन रहे। इस के अधीन हर जिले में एक जिला सहकारी अधिकारी तथा उसके अधीन सहकारी प्रचारक रखे जाय। यह अधिकारी ग्राज के असिस्टेंट रजिस्ट्रार तथा इसपेक्टर के स्थान पर होंगे परन्तु इनके कर्तव्य रचनात्मक तथा यथानाम प्रचारात्मक होंगे। बुनियादी स्तर पर के कार्यकर्ता को आज सुपरवाइजर अथवा सब इसपेक्टर कहा जाता है। नई योजना में उसे सहकारी संगठनकर्ता कहना ही उचित होगा। इस तरह आडिट, पर्यवेक्षण, निरीक्षण, संगठन, प्रचार आदि सब कार्य आयुक्त के अधीन होते हुए भी एक अग का दूसरे पर रचनात्मक अकुण रहेगा और हर समिति तथा हर सहकारी कार्यकर्ता सामान्य विभाग को अपना सहायक सलाहकार तथा मित्र समझेगा। विभाग नौकरशाही की भावना से मुक्त होकर इस लोककल्याणकारी आन्दोलन के सुरम्य भवन का निर्माता और पोषक बन जायगा।

जहां तक सहकारी समितियों के कर्मचारी समुदाय का सम्बन्ध है उनका समस्त नियन्त्रण राज्य की सहकारी समिति द्वारा बनाये गए नियमों के अधीन होना चाहिए और उन्हीं नियमाधीन उनका स्थानान्तरण होना चाहिए। श्रेयस्कर तो यह होगा कि जहां तक संभव हो यह नियम अखिल देशीय सहकारी समिति द्वारा अनुमोदित हो ताकि शनै-शनै सारे देश के लिए समान सहकारी पद्धति का

विकास होता चले । इस समिति का व्यय शासन को वहन करना चाहिए ।

विभाग तथा कर्मचारी समुदाय के वर्गान मे प्रशिक्षण के विषय पर कुछ कहे बिना यह अध्याय अधूरा ही रहेगा । प्रशिक्षण के सम्बन्ध मे ग्रामीण-ऋण-सर्वेक्षण समिति ने जो प्रस्ताव किये हैं वह बडे ही उपयोगी तथा व्यावहारिक है । उन पर अब अमल भी होने लगा है । परन्तु उन प्रस्तावो मे यदि एक दो बातो का और समावेश कर लिया जाय तो वह और अधिक उपयोगी और व्यावहारिक हो सकते है । इसमे पहला तो यह है कि प्रशिक्षण हिन्दी भाषा तथा स्थानीय भाषा मे हो । केवल अंगरेजी मे प्रशिक्षण कार्यकर्ताओ के लिए ग्रामो मे उपयोगी सिद्ध नही हो सकता । दूसरा यह कि कार्यकर्ता को परीक्षा पास करने पर ही प्रशिक्षित समझ लेना भूल होगी । अतः हर कार्यकर्ता का प्रशिक्षण तब पूर्ण समझना चाहिए जब कि वह अपने पदानुसार तथा तत्सम्बन्धित सहकारी समिति मे एक वर्ष सफलतापूर्वक काम कर ले । तीसरा परमावश्यक अंग है कार्यकर्ताओ की जीवन शैली । उन्होने ग्रामो मे ग्रामीणो के साथ काम करना होता है । जब तक उनका रहन, सहन, आचार, वर्तवि ग्रामीणो जैसा तथा विकासोन्मुख न हो तब तक कार्यकर्ता सफल नही हो सकते । इस ध्येय की प्राप्ति की ओर भी पूरा ध्यान प्रशिक्षण काल मे ही देना होगा । सहकारी कार्यकर्ता जनता के ऐसे विश्वास-पात्र सेवक होने चाहिए जिनसे जनता हर मामले मे निःसकोच होकर सलाह ले सके ।

जब तक सहकारी विभाग को ऐसा नैतिक, रचनात्मक, लोकप्रिय तथा विश्वासोत्पादक रंग नही दिया जायगा तब तक इस आन्दोलन का सफल होना संभव नही दीखता ।

अभी तक हमारी पूर्ण मान्यता सहकारिता मे नही दीखती अथवा सहकारिता के साथ-साथ पूँजीवादी सस्थाओ के प्रोत्साहन तथा राष्ट्रीयकरण नीतियो का अवलम्बन नही हो सकता । यदि शासन ने सहकारिता को सफल बनाना है तो हर क्षेत्र मे सहकारी पद्धति को अपनाना पडेगा । विकास के बहुत से कार्य इस आन्दोलन के हवाले करने पडेगे ।

शनैः-शनैः आन्दोलननिधियो का विकास हर कार्य के लिए करके स्वावलम्बी होता जायगा । शासन शनैः-शनैः अपना योग शिथिल करता जायगा और अन्ततः

अन्दोलन पूर्णतया स्वावलम्बी और लोकतंत्री होकर शासन-तंत्र को भी नई दिशाओं की ओर प्रवाहित कर सकेगा ।

: १३ :

सहकारिता और पंचायत-राज

यह तो प्रकट ही है कि सहकारिता मानव के पारस्परिक स्नेह में उत्पन्न होकर निस्वार्थ पारस्परिक सहायता में परिस्फुटित होती है । यह जनता की सुदृढ भित्ति से ऊपर उठती है । इसका जीवन के हर क्षेत्र से अटूट सम्बन्ध है । सदाचार इसका प्राणदायक अंग है । इसके संरक्षण, परिवर्धन तथा पोषण के लिए एक अनुकूल राजनीतिक तथा प्रशासनिक वातावरण की आवश्यकता होती है । जब तक शासन-तंत्र अनुकूल न हो तब तक सहकारिता का पनपना तथा स्थायी होना असंभव ही होता है । राजाशाही एकतंत्रीय शासन, पूँजीवादी, सामन्तशाही व नौकरशाही सरकारों का मूलोद्देश्य ही भिन्न होता है । इनसे सहकारिता का संरक्षण व पोषण एक ऐसी बात है जिसकी आशा करना मृगतृष्णा ही है । लोकतंत्री शासन के सम्बन्ध में भी दो विचारधाराएँ हैं । एक तो ऊपर की सरकार का वयस्क-मत द्वारा निर्माण होता है और फिर वहाँ से शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया जाता है । दूसरी विचार-पद्धति वह है जो प्रारम्भिक शासनिक इकाई के शासन का निर्माण जनता की सहमति से करके वहाँ से आवश्यकतानुसार अधिक विस्तृत क्षेत्र के लिए शासन-तंत्र का निर्माण करती है और एतदर्थ प्रारम्भिक इकाई अपनी सुविधा तथा साम्प्रदायिक कार्यों के लिए अपनी शक्तियों का हस्तान्तरण करती है । ऊपर से सत्ता के विकेंद्रीकरण की धारणा मूलतः गलत है । क्योंकि लोकतंत्री पद्धति की प्रचलित धारणा में जनता, जिसमें पूर्ण प्रभुता निहित होती है, को केवल मत प्रदान के समय ही ध्याना जाता है, फिर उनका कोई जाग्रत सम्पर्क शासन-तंत्र से नहीं रहता । वह जनता की दैनिक समस्याओं से अपरिचित रहते हैं । ओर श्री डार्लिंग महोदय के कथनानुसार "ऊट की समस्या और अरब की और" वाली परिस्थिति-सी

हो जाती है। पचायत-राज की सरकारी पद्धति ही एक ऐसी पद्धति है जो सहकारिता की मौलिक धारणाओं तथा भावनाओं के पूर्णतया अनुकूल है। इसी प्रणाली के लक्षणों को व्यक्त करने हुए एक स्थान पर महात्मा गांधी ने लिखा है—

“ग्रन्थ ग्रामों को लेकर बने इस सगठन में उत्तरोत्तर प्रवृद्धमान और विकासोन्मुख क्षेत्रों का समावेश रहेगा। व्यक्ति इसका केन्द्र होगा। यह व्यक्ति ग्राम के लिए सदा अपने को मिटा देने के लिए तैयार रहेगा। इसी तरह ग्राम, समूहों के लिए मर मिटने को तैयार रहेगा। व्यक्तियों की इकाई से बनी समष्टि एक संयुक्त रूप में परिणत हो जायगी। उन व्यक्तियों में निराशा पैदा नहीं होगी, वे अत्याचारी नहीं होंगे, वे सदा विनयी होंगे, और सदा सागर की-सी व्यापक वृत्ति की महिमा के भागी रहेंगे, क्योंकि वे उसके एक अविभाज्य अंश हैं।”

यह सगठन किस प्रकार का होगा, उसकी भी सूत्र रूप में महात्मा गांधी ने व्याख्या की है—

“भारत के सात लाख ग्राम हैं। हर ग्राम का सगठन उसके वासियों की इच्छा से होगा। इस प्रकार देश के लिए चालीस करोड़ के स्थान सात लाख मत होंगे, अर्थात् हर ग्राम का एक मत होगा। यह ग्राम ही चुनाव द्वारा अपना जिला शासन नियुक्त करेंगे। यह जिला शासन एक राष्ट्रपति चुनेगा जो राष्ट्र का प्रधान होगा।”

पिछले अध्यायों में वर्णित सहकारी सगठन के ढांचे के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जायगा कि यह तब उपरिलिखित पचायती सगठन के अनुकूल है। जहाँ आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रों में सहयोग की मौलिक भावना को सहकारी तन्त्र विकसित करेगा, वहाँ प्रशासनिक न्याय तथा प्रबन्ध के क्षेत्रों में पचायती तन्त्र उसी योग को विकसित करेगा। एक तन्त्र दूसरे का पूर्णतया सहायक होगा।

वस्तुतः सहयोग की सामूहिक भावना के विकास के लिए यह दोनों अग्र अन्योन्याश्रित होते हुए परमावश्यक हैं। एक अग्र का दूसरे के बिना पनपना, विकसित होना तथा उन्नत होकर साम्ययोग की परमावस्था की ओर अग्रसर होना असंभव है।

पचायती तथा सहकारी सगठन इस तरह ग्राम से तहसील, तहसील से जिला,

आधुनिक सहकारिता

जिला से प्रान्त तक साथ-साथ विकसित होते जायगे। प्रान्त अथवा राज्य-स्तर पर सहकारिता तथा पचायती सगठनों के कर्तव्य काफी मात्रा में व्यक्त तथा भिन्न होंगे। तो भी हर स्तर पर यह आवश्यक होगा कि दोनों सगठनों का आपसी ताल-मेल रहे। इसके लिए व्यावहारिक यह क्रम रहेगा कि हर स्तर की सहकारी सभा की प्रबन्धक समिति में उसी स्तर की पचायत का और हर स्तर की पचायत में उसी स्तर की सहकारी समिति का प्रतिनिधि रहना चाहिए। राज्य तथा देश के मन्त्रिमण्डल में सहकारिता के महत्वपूर्ण विषय के लिए मंत्री होना चाहिए जो सहकारी सभा के प्रतिनिधियों में से होना आवश्यक है।

यह साथ-साथ चलने वाले दोनों सगठनों का पृथक् स्वरूप से अस्तित्व एक अन्तरिम काल की अवस्था है। जब सहकारिता तथा पचायती विचारधाराएं विकसित तथा उन्नत हो जायगी और प्रशासन-कार्य सामाजिक, आर्थिक तथा नैतिक कार्यों से भिन्न नहीं रहेगा तब यह दोनों सगठन एक हो जायगे। प्रशासन कार्य उस समय सहकारिता का ही एक अंग हो जायगा। और जब समाज साम्यावस्था को प्राप्त होगा तब ही सहकारिता तथा पचायत राज प्रणालियों का चरम लक्ष्य प्राप्त होगा।

इन पचायतों के तथा सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों का विवरण सम्बन्धित अधिनियम में रहेगा। निर्वाचन बहुमत द्वारा होगा, अथवा सहमति द्वारा अथवा नामजद करने से। यह व्यौरे की बातें हैं परन्तु सहमति ही एक ऐसी पद्धति है जो सहकारिता के सिद्धान्तों पर पूरी उतरती है और जहां तक संभव है इसी पद्धति का अनुसरण करना चाहिए।

सहकारिता और पचायत-राज को इसलिए एक दूसरे के निकट लाना आवश्यक है कि जिससे शनै-शनै ग्रामों का प्रबन्ध तथा अर्थ-सम्बन्धी ढाँचा स्वावलम्बी होता जाय और शनै-शनै इस ढाँचे का इतना एकीकरण हो जाय कि इनमें कोई भेद ही न रहे। ग्राम मानव समाज की एक ऐसी इकाई बन जाय कि ऊपर का हर प्रकार का सगठन इन पर ही आधारित हो और प्राचीन परिवार का स्थान ग्राम ले ले और व्यक्ति तथा समाज की ऐसी समष्टि बने कि वह नदी की नाई निरन्तर विकसित तथा प्रवाहित होती हुई सागर की शान्ति, असीमता तथा अपारता की ओर प्रवाहित होती रहे।

: १४ :

उपसंहार

किसी भी विषय को ले उसके सम्बन्ध में ज्ञान-जानकारी अपार और अगाध है। कोई भी यह दावा नहीं कर सकता कि उसे अमुक विषय का पूर्ण ज्ञान हो चुका। ज्यों-ज्यों अन्वेषण और खोज आगे बढ़ती है त्यों-त्यों उससे सम्बन्धित ज्ञान की विगलता अधिक व्यक्त तथा स्पष्ट होती जाती है। ठीक ऐसी ही दशा होती है जिस प्रकार कि अगाध समुद्र की वास्तविक स्थिति का पता ज्यों-ज्यों समुद्र में प्रवेश करो अधिक लगता जाता है।

इस अपार रूप के साथ-साथ अन्वेषण और खोज द्वारा एक और अनुभव होने लगता है, वह यह कि हर विषय का ज्ञान अततो गत्वा हमें मानव और मानवता के निकट ले जाता है। यह आभास होने लगता है कि समस्त विषयों का ज्ञान हमें एक अच्छा मानव बनने में सहायता देता है और सब ज्ञानों का अन्तिम ध्येय एक ही है। यह प्रत्यक्ष देखने लगता है और वह यह कि मानव को सुख और शान्ति की ओर अग्रसर किया जाय।

वस यही दशा सहकारिता सम्बन्धी ज्ञान की है। जब मैं इस पुस्तक को समाप्त कर रहा हूँ तो ऐसा मालूम होता है कि मातो मैने सहकारिता के वास्तविक तथ्य को समझने का केवल एक प्रयास मात्र किया है और इस प्रयास से सहकारिता के ज्ञान के प्रवेश-द्वार तक पहुँच पाया हूँ। यदि विषय का मनन जारी रहा तो इसके भावी ज्ञान का क्या स्वरूप होगा यह भविष्य ही बतला सकेगा। मुझे यह लिखते किंचित् मात्र भी सन्तोच नहीं कि सहकारिता अथवा सहयोग की हमारी आज तक धारणा बड़ी सकीर्ण रही है, हालांकि यह स्वयं एक उदार भावना की प्रतीक है। इसका उदय उदारता में ही होता है। यह उदारता में ही पोषित तथा विवसित होती है। परन्तु जब इसके क्षेत्र को वर्ग तथा कानून की बेड़ियों में जकड़ दिया जाता है, यह क्षुब्ध हो उठती है। पहले तो यह दब जाती है परन्तु फिर विस्फोट होता है। मानवता विद्रोह करती है। एक क्रान्ति आती है। कई बार हिंसा को भी साथ लाती है। तब सत्रस्त मानव अपनी मौलिक उदार वृत्ति को पुनः पाने के लिए तड़प उठता है। पुनः मानवीय सहयोग

आधुनिक सहकारिता



सहकारिता के ऐसे विप्लवकारी प्रयत्न में विवेक खो बैठता है। वह अपने कई एक भाइयों को ऐसी भावनाओं का शत्रु समझकर उनके सहार में व्यस्त हो जाता है। फ्रांस तथा रूसी क्रान्तियाँ एक ऐसे ही विस्फोट का फल थीं।

सहकारिता का हनन तथा पतन उस समय होने लगता है, जब कि व्यक्ति सत्ता सगृह करने लगता है। स्वार्थ की भावना बढ़ती जाती है। वह समाज की प्रभु सत्ता का तिरस्कार करने लगता है। वस इसी क्रम से स्नेह की पावन भावना से उत्पन्न सहयोग की भावना को हानि पहुँचती है। ससार में यह क्रम आदि-काल से चला आता है। यदि स्थायी तौर पर सहयोग नहीं पनप सका तो इसका कारण केवल यह रहा कि सहयोग तथा सहकारिता की कोई विनिष्ट पद्धति नहीं खोजी गई। केवल एक क्रान्ति तथा प्रति-क्रान्ति का क्रम चलता रहा।

क्रान्ति और प्रति-क्रान्ति के इस क्रम में विचारधारा को विकसित तथा परिष्कृत किया। यह श्रेय आज के युग को है जब कि सहकार की भावना एक पद्धति के रूप में विकसित हो रही है और मानव के लिए एक नया सन्देश दे रही है। राष्ट्रवाद, समाजवाद, साम्यवाद, सामन्तवाद, पूँजीवाद, आदि सब ऐसी पद्धतियाँ हैं जिनमें किसी व्यक्ति, किसी वर्ग, किसी जाति अथवा किसी देश को कुछ न कुछ मय अथवा खटका बना रहता है। जहाँ हिंसा का आश्रय किसी न किसी रूप में लेना ही पड़ता है। परन्तु आज से सौ वर्ष पूर्व हिंसा से आतंकित तथा त्रस्त समाज को सहकारिता ने ही ढाढस बधाई थी। तब से यह सन्देश विश्व के कोने-कोने में फैला। हर देश में इसने अपना भिन्न-भिन्न स्वरूप विकसित करके मानव को शान्ति और सुख का एक नया सन्देश दिया। समाज-शास्त्रियों तथा विद्वानों ने इस पर विचार किया, ग्रन्थ रचे और आज सहकारिता विश्व का सबसे अधिक व्यापक आन्दोलन है। परन्तु भारतीय स्वतन्त्रता के बाद आचार्य विनोबा ने सहकारिता को एक ऐसा व्यक्त स्वरूप दे दिया जिसने आज राजनीति, अर्थ तथा समाज-शास्त्रियों को अपनी ओर काँत कर लिया। “जीने दो और जियो” के विनोबा कृत सूत्र में सहकारिता मूल भाव निहित है। भूदान, सम्पत्ति-दान, श्रमदान, बुद्धि-दान, ग्राम-दान। ये सब सहकारिता के स्तम्भ हैं और इनके द्वारा ही सहकारिता का वास्तविक रूप विकसित होगा।

